

कर्नाटक राज्य

बनाम

भारत संघ और एक और

8 नवंबर, 1977

[न्यायमूर्तिगण एम. एच. बेग, सी. जे., वाई. वी. चंद्रचूड़, पी. एन. भगवती, एन. एल. अंतवालिया, पी. एन. सिंहल, जसवंत सिंह और पी. एस. कैलासम]

भारत का संविधान 1950-कला। 131 - किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त जांच आयोग-अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा दायर मुकदमा। 131 - यदि मुख्य रूप से सक्षम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ जांच आयोग का गठन कर सकती है-केंद्र सरकार की कार्रवाई, यदि संविधान के संघीय ढांचे का विनाशकारी है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण-यदि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को नष्ट करता है जिसके तहत मंत्री केवल राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार हैं-यदि यह अनुच्छेद के तहत विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। 194 ( 3 ) .

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की वैधता-धारा 3-आई. एफ. एस. का दायरा। 3 संविधान का भाग 11-जांच-"सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले" का उद्देश्य और दायरा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र होगा (क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या (ख) भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच दूसरी तरफ; या (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न (कानून या तथ्य का) शामिल है, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है।

कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए राज्य विधानसभा के कुछ विपक्षी सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने आरोपों को तुच्छ और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। 18 मई, 1977 की एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार एस के तहत नियुक्त की गई। 3 ( 1 ) जांच आयोग अधिनियम, 1952, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक व्यक्ति आयोग

अधिसूचना में निर्दिष्ट आरोपों की जांच करने के लिए। 23 मई, 1977 की अधिसूचना द्वारा भारत सरकार ने एस. 3 ( 1 ) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार, "कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले" को छोड़कर मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने इस न्यायालय में अनुच्छेद के तहत एक मुकदमा दायर किया। 131 संविधान से। पक्षकारसभक दलीलक आधार पर एहि न्यायालय द्वारा तीनटा मुद्दा तैयार कयल गेल छल। ये थे: ( 1 ) क्या सूट रखरखाव योग्य है? ( 2 ) क्या विवादित अधिसूचना एस के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों से परे है। 3 जांच आयोग अधिनियम, 1952? ( 3 ) भले ही अधिसूचना सेकंड के भीतर आती हो। 3 क्या जांच आयोग अधिनियम की धारा अपने आप में असंवैधानिक है?

वादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि: ( 1 ) केंद्रीय सरकार के पास अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के कथित प्रयोग में जांच आयोग का गठन करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है; (2) राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आयोग की नियुक्ति में केंद्र सरकार की कार्यवाही संविधान के संघीय ढांचे और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना के लिए विनाशकारी है; (3) सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत मंत्रपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है और राज्य के मंत्रियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा जांच का आदेश दिया जाता है, जब वे पद पर होते हैं तो यह विधानमंडल के प्रति मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को नष्ट कर देगा; (4) अनुच्छेद 194 (3) के आधार पर यह विधानसभा का विशेषाधिकार है (1 का नहीं)

(5) अपने किसी भी सदस्य के आचरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करना। 3 1952 के अधिनियम की इस तरह से कि केंद्र सरकार को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए। 3 स्वयं संविधान के भाग 11 के प्रावधानों के अधिकार से बाहर है और (6) क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। आयोग किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी (केंद्र सरकार) ने प्रारंभिक स्थिति को उठाया

इस आधार पर मुकदमे की रखरखाव के बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि ऐसे आयोग की नियुक्ति राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार को प्रभावित नहीं करती है; और (2) यह भी कि केंद्र सरकार सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करने में सक्षम है, (3) कि इसकी अधिसूचना में राज्य सरकार की अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी मामले, अर्थात् राज्य सरकार के मंत्रियों के आचरण को शामिल नहीं किया गया है।

( बहुमत के अनुसार बेग, सी. जे. चंद्रचूड़, भगवती और कैलाशम, जे. जे.)

( उन्तवालिया, शिंगल और जसवंत सिंह, जे. जे. असहमत) सूट रखरखाव योग्य है।

बी. ई. जी. सी. जे.

1 ( क) संबंधित राज्य, जो कार्रवाई की वैधता को चुनौती देता है

अपनी सरकारी शक्तियों के प्रयोग से जुड़े कृत्यों के संबंध में अपने एक या अधिक मंत्रियों के खिलाफ केंद्र सरकार को अनुच्छेद के तहत एक मुकदमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त हित होगा। 131 क्योंकि इसमें "राज्य" के रूप में राज्य से संबंधित दावे शामिल हैं। [ 94 सी-डी]

( ख) इस मामले में सरकारी प्रक्रिया पर विचार करना शामिल है।

केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों की शक्तियों की तुलना में राज्य सरकार और उसके मंत्रियों में निहित शक्तियां। यह संविधान के विशेष प्रावधानों के अर्थ और दायरे और प्रयोज्यता से संबंधित सवाल भी उठाता है, जिनके संचालन प्रत्येक राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन प्रावधानों को दी गई व्याख्याएं अनिवार्य रूप से संघ के लिए भी बहुत चिंता का विषय होनी चाहिए। [ 91 सी-डी]

( ग) भारत संघ, केंद्र सरकार के माध्यम से कार्य कर सकता है

कहा जाता है कि वे पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग-अलग राज्य, जो अपनी सरकारों और मंत्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक राज्य के लोगों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता है। जब संविधान की व्याख्या के प्रश्नों पर राज्य के प्रतिनिधियों और भारत के सभी लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो पूरे लोगों और विशेष रूप से संबंधित राज्य के लोगों के कल्याण को प्रभावित करता है,

यह स्वीकार करने के लिए बहुत तकनीकी तर्क है कि एक मुकदमा इसके तहत नहीं है

संविधान का अनुच्छेद 131। [ 91 ई-एफ] एसए

( घ) अनुच्छेद 131 को जब भी कोई राज्य या अन्य राज्य लागू कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या के प्रश्न पर संघ का मतभेद है ताकि इसका निर्णय सरकारी शक्तियों के दायरे या प्रयोग को प्रभावित करेगा जोये किसी राज्य की विशेषताएँ हैं। इसकी रखरखाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कार्रवाई यदि राज्य की शक्तियाँ जो कार्यकारी, विधायी और न्यायिक हैं विशेष व्यक्तियों के माध्यम से अभ्यास किया जाता है। [ 92 एफ-जी]

( ङ) राज्य और उसकी सरकार के बीच का अंतर, अधिक से अधिक, संपूर्ण और समग्र के एक अविभाज्य भाग के बीच एक। यह होगा राज्य या उसकी सरकार की ओर से दावों के संबंध में

कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दोनों अलग-अलग न्यायिक संस्थाएं हैं। यह मानते हुए कि ये स्पष्ट रूप से हैं अलग-अलग निकाय, सरकार का दावा राज्य का होगा।

( च ) यह तथ्य कि राज्य अपने मंत्रियों या अधिकारियों के माध्यम से कार्य नहीं कर सकता है।

कला के तहत एक मुकदमे की रखरखाव को प्रभावित करता है। 131 संविधान से। अनुच्छेद 166 (3)। सरकार के व्यवसाय के आवंटन के लिए प्रावधान करता है

"व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन-देन" के लिए मंत्री। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य केवल समग्र रूप से अपनी सरकार के माध्यम से कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि

नियमों द्वारा प्रदान किए गए अपने अलग-अलग मंत्रियों के माध्यम से। अनुच्छेद 166 (3) और 154 (1), एक मंत्री की आधिकारिक क्षमता और उस राज्य के बीच कोई विरोधाभास स्थापित करने की जगह, जिसके लिए वह कार्य करता है, केवल यह दर्शाता है कि एक मंत्री के रूप में, वह राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि या एक अंग है और इसलिए, उसे कला के उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी के रूप में माना जा सकता है। 154 ( 1 ) . परिणाम यह है कि एक मंत्री के आधिकारिक कार्यों को उस राज्य के कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता है जिसकी ओर से वह कार्य करता है। कला में कुछ भी नहीं है। 131 संविधान स्वयं उस राज्य को, जिसे अनिवार्य रूप से हमेशा अपने अधिकारियों या एजेंटों या मंत्रियों के माध्यम से कार्य करना चाहिए, केंद्र सरकार पर मुकदमा करने से रोकने के लिए, न केवल अपने किसी अधिकारी, एजेंट या मंत्री को केंद्र सरकार द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई से बचाने के लिए, बल्कि उससे निपटने के लिए अनन्य शक्ति के अपने दावे को प्राथमिकता देने के लिए और वादी ने मुकदमे के माध्यम से यही किया है। [ 92 एच; 93 डी]

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361, राजा सम्राट वी. शिवनाथ बेनरजी और अन्य, 72 एल. ए. 241 और संजीवी नायडू आदि। वी. की स्थिति मद्रास और अन्र। [ 1970 ] 3 एस. सी. आर. 505 निर्दिष्ट है।

गवर्नर-जनरल इन काउंसिल v. मद्रास प्रांत, [1943] एफसीआर पी। 1 , संयुक्त प्रांत बनाम। गवर्नर-जनरल इन काउंसिल, ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 58, अटॉर्नी-डेल और ओआरएस के संबंध में विक्टोरिया के लिए जनरल। वी. द कॉम राष्ट्रमंडल और ओआरएस। , 71 सी. एल. आर. 237 और अटॉर्नी-जनरल फॉर विक्टोरिया (एट द विक्टोरियन चैंबर ऑफ मैनुफैक्चरर्स का संबंध) v. राष्ट्रमंडल 1933-1934 (2) सी. एल. आर. 533 लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार की अधिसूचना वैध है। [ 94 जी]

2 ( क ) दोनों अधिसूचनाओं के अवलोकन से पता चलता है कि जबकि राज्य अधिसूचना

यह आयोग का गठन करने के लिए है जो यह जांच करता है कि क्या कुछ लेन-देनों द्वारा पहना गया पर्दा सही है और इसे पूरी तरह से कवर करता है, केंद्र सरकार की अधिसूचना स्पष्ट रूप से उसके द्वारा नियुक्त आयोग को स्पष्ट वैधता और नियमितता के पर्दे को फाड़ने में सक्षम बनाने के लिए है जो कुछ लेन-देनों द्वारा पहना जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों अधिसूचनाएँ

"उसी मामले" को शामिल किया जाए जैसा कि परंतुक (बी) से एस द्वारा विचार किया गया है। 3 ( 1 ) में से

अधिनियम। यदि राज्य अधिसूचना केवल सतही रूप से खरोचने के लिए है केंद्र सरकार की अधिसूचना के दौरान लगाए गए आरोपों की सतह क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इसकी जड़ या दिल की जांच करने के लिए है राज्य में राजनीतिक निकाय के साथ गलत हो गया, यह न्यायालय भी नहीं हो सकता था यह मानने के लिए कारण खोजने में तकनीकी या चतुर कि विषय-दोनों का मामला है पूछताछ काफी हद तक समान है। [ 36 जी-एच)

( ख ) चूँकि दोनों अधिसूचनाएँ उन मामलों में पूछताछ को अधिकृत करती हैं जो हैं - प्रकृति और उद्देश्य में काफी अलग, सेंटरल कॉम मिशन की जांच को राज्य सरकार की अधिसूचना के कारण बाधित नहीं कहा जा सकता है। परंतुक (बी) से एस के तहत विनिर्देशन। 3 ( 1 ) अधिनियम के तहत भले ही, किसी काफी अलग विषय-वस्तु से निपटने के लिए, तथ्य के केंद्रीय क्षेत्र या लेनदेन को नियंत्रित करने वाले नियम सामान्य हो सकते हैं। यदि उद्देश्य भिन्न हैं तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए तथ्य और कानून के सामान्य क्षेत्रों की जांच की अनुमति होगी। [ 39 बी]

3 ( क ) 1952 के अधिनियम के पीछे स्पष्ट उद्देश्य तंत्र को सक्षम बनाना है। लोकतांत्रिक सरकार का अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्य करना। इसे शायद ही सरकार के लोकतांत्रिक तरीकों को विफल करने के लिए एक अधिनियम के रूप में माना जा सकता है। [ 44 ई]

( ख ) सभी लोकतांत्रिक देशों में जब आरोप और अफवाहें फैलती हैं सार्वजनिक जीवन की अखंडता या अन्य मामलों के बारे में विश्वास का संकट सार्वजनिक महत्व, यह आवश्यक है कि जनता का विश्वास बहाल किया जाए और यह केवल अफवाहों की पूरी तरह से जांच और जांच करके ही किया जा सकता है और आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की जांच से या तो पता चल सकता है कि बुराई मौजूद है या वह अफवाहों में कोई बल नहीं है। दोनों ही मामलों में विश्वास बहाल हो जाता है। [ 40 एच)

( ग ) इंग्लैंड में जांच न्यायाधिकरण (साक्ष्य) अधिनियम 1921 पारित किया गया था। उन चुनिंदा संसदीय समितियों की प्रक्रिया को विस्थापित करने के लिए जिनका उपयोग तब तक

"उच्च स्थानों पर कथित गलत कार्यों की जांच करने के लिए" किया जाता था। राजनीतिक न्यायाधिकरण द्वारा जाँच का ऐसा तरीका पूरी तरह से असंतोषजनक पाया गया क्योंकि ऐसे निकाय कभी भी दलगत राजनीतिक प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकते थे।

इन समितियों की रिपोर्टों पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस होने लगी, सदन को दलगत आधार पर विभाजित किया गया था और बहुमत से मिनी को दोषमुक्त कर दिया गया था गंभीर सार्वजनिक अशांति को बदनाम किया गया था और 1921 का अधिनियम पारित किया गया था कुछ स्थायी जाँच तंत्र स्थापित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र में भीराज्य, जहाँ कांग्रेस समितियों की प्रणाली अभी भी प्रचलन में है, तदर्थ न्यायाधिकरण (जैसे वारेन आयोग) को किसी मामले से बचने के लिए नियुक्त किया जाता है।

कांग्रेस समितियों को भेजा जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोकतांत्रिक देश, न केवल आधुनिक प्रथा बल्कि कानून भी प्रदान कर सकते हैं 1952 के अधिनियम के तहत किस तरह की पूछताछ की जानी है। द. आयोग की कार्यवाहियों का परिणाम केवल एक रिपोर्ट में हो सकता है जिसे रखा जाना है। एस के तहत संबंधित विधानमंडल के समक्ष। 3 ( 4 ) अधिनियम से। अधिनियम में शामिल हैं।

आयोग के निष्कर्षों को प्रभावी बनाने या लागू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं कोई आदेश जो आयोग द्वारा किया जा सके। [ 41 सी-एच; 44 ईजे

4. सवाल यह है कि कोई राज्य सरकार है या उसका मुख्यमंत्री है या नहीं। उस विश्वास को पूरा करना जो संवैधानिक शक्ति एक के हाथों में रखती है राज्य सरकार और उसके प्रमुख यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए कि क्या कोई कला के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग। 356 बुलाया जाता है या नहीं, यह एक बात है जो केंद्र सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आती है। अवमानना क्या है?

कला द्वारा चढ़ाया गया। 356 जब यह राष्ट्रपति की "संतुष्टि" की बात करता है राज्यपाल की एक रिपोर्ट "या अन्यथा" कि क्या किसी विशेष स्थिति में उत्पन्न हुआ जिसमें राज्य सरकार को तदनुसार चलाया जा सकता है संविधान के प्रावधानों के साथ एक ऐसा मामला है जो सार्वजनिक होगा

महत्व। यदि राष्ट्रपति राज्य सरकार देना आवश्यक समझते हैं। या उसके मुख्यमंत्री को एक निष्पक्ष कॉम के सामने दाढ़ी रखने का अवसर अधिनियम के तहत गठित जांच मिशन, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के एक कला के तहत शक्ति के प्रयोग का तरीका। 356 पूरी तरह से क्या है द्वारा कवर नहीं किया गया है अनिवार्य रूप से संविधान के प्रावधानों में निहित है, यानी, करने की शक्ति कला द्वारा अपेक्षित संतुष्टि के उद्देश्यों के लिए जांच का आदेश दें। 356 .

5 ( क ) किसी भी कला के प्रावधान। 75 ( 2 ) या कला। 164 ( 2 ) बार के रूप में काम नहीं कर सकते अधिनियम के तहत स्थापित आयोगों द्वारा जांच की संस्था के खिलाफ। को। इस तरह के बार का अनुमान लगाना वस्तु के साथ-साथ मोड को गलत समझना होगा और इन अनुच्छेदों के संचालन के क्षेत्र के साथ-साथ उद्देश्य, दायरा और कार्य भी अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले आयोग। [ 53 एच ]

( ख ) मंत्रिपरिषद, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से द्वारा नियुक्त राज्यपाल, सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यह सामूहिक जिम्मेदारी सत्ता की शक्ति को कम या छोटा नहीं करती है। केंद्र सरकार एस के तहत एक आयोग नियुक्त करेगी। 3 अधिनियम से। सामूहिक उत्तरदायित्व का एक दायरा और संचालन का तरीका होता है जो इससे बहुत अलग होता है। एस के तहत एक जांच के उन। 3 अधिनियम का भले ही समान या समान हो कभी-कभी मामले दोनों को जन्म दे सकते हैं। एस के तहत मामलों की जांच की गई। 3 में से अधिनियम का किसी भी सामूहिक जिम्मेदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। का क्षेत्र एस के तहत जांच। 3 सामूहिक जिम्मेदारी से बहुत अलग है दूसरों के कार्यों के लिए सामूहिक रूप से या परोक्ष रूप से जिम्मेदार मंत्रियों का नि यदि कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है, तो जांच के तहत एस. 3 केंद्र सरकार द्वारा यह निर्धारित करने का आदेश दिया गया है कि वास्तव में कौन है कुछ कार्यों के लिए जिम्मेदार होना और उनके पीछे क्या मकसद होगा। [ 50 एफ ]

( ग ) चूंकि मंत्रिपरिषद केवल इसलिए पद पर रह सकती है जब तक यह विधानमंडल के अधिकांश सदस्यों का समर्थन और विश्वास जारी रखता है, तब तक पूरी मंत्रिपरिषद प्रत्येक मंत्री और उसके विभाग के निर्णयों और नीतियों के लिए राजनीतिक रूप से जिम्मेदार है। तो। जहाँ तक विधान सभा के प्रति मंत्रालय की जवाबदेही का संबंध है, पूरे मंत्रालय को एक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। कला का उद्देश्य। 164 ( 2 ) ,= जो इस सिद्धांत का प्रतीक है, वह तथ्यों का पता लगाना या पार्टी के लिए किसी मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री या मंत्री की वास्तविक जिम्मेदारी स्थापित करना नहीं है।

कुलर निर्णय या सरकारी कार्य। व्यक्ति का सिद्धांत और साथ ही सामूहिक मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी सबसे कुशलता से तभी काम कर सकती है जब मामले हों। साक्ष्य की उचित जांच और मूल्यांकन और प्रश्नों की चर्चा की आवश्यकता होती है के तहत नियुक्त आयोग के समक्ष कार्यवाही में शामिल हुए हैं= एस. 3 अधिनियम से।

=

6 (क) सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रवर्तन के लिए एकमात्र मंजूरी है -

जनमत का दबाव। इंग्लैंड में, यह सिद्धांत राजनीतिक निर्णय द्वारा समर्थित परंपरा के रूप में काम करता है, लेकिन हमारे लिए, यह सिद्धांत हमारे संविधान में ही कहा गया है। 75 (2) और 164 (2)। फिर भी, यहाँ भी यह परंपरा और जनमत पर निर्भर करता है, विशेष रूप से जैसा कि इसमें परिलक्षित होता है।

संसद या राज्य विधानमंडलों में, इसकी प्रभावशीलता के लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी संघ या राज्य सरकार में पद धारण करने वाले मंत्रियों के कानूनी दायित्व से अलग और स्वतंत्र रूप से मौजूद है। मन में। [ 52 एच]

(ख) जांच आयोग द्वारा की जाने वाली जांच से सुविधा या सहायता मिलनी चाहिए।

ठोस जनमत का निर्माण। एक मंत्री। व्यक्तिगत कार्रवाई, चाहे कभी भी हो, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू नहीं करती है जहां सरकार में उनके सहयोगियों को लापरवाही या किसी भी कर्तव्य के उल्लंघन का उचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। [ 53 सी-डी] संवैधानिक कानून-वेड और फिलिप्स 8 वीं संस्करण। पी। 87 . संवैधानिक और प्रशासनिक कानून प्रो. एस. ए. डी. स्मिथ, पीपी. 170-179 संदर्भित किया गया।

7. जाँच आयोग की अपनी कार्रवाई की एक कक्षा होती है जिसके भीतर यह आगे बढ़ सकता है ताकि कार्रवाई के अन्य रूपों या निवारण के तरीकों के साथ टकराव या बाधा न हो। जाँच आयोग का उद्देश्य वास्तविक तथ्यों का पता लगाना और उनकी खोज करना है। यह न तो अदालत में कार्रवाई का विकल्प है और न ही इसकी रिपोर्ट या निष्कर्ष अदालतों को उनके कर्तव्य से मुक्त कर सकते हैं। एक कॉम मिशन की नियुक्ति आम तौर पर मामले को अदालत में ले जाने के लिए पर्याप्त सबूतों की कमी की स्वीकारोक्ति है, जिसमें जनता की आवश्यकता और यह पता लगाने की इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया जाता है कि वास्तव में क्या गलत हुआ था और कैसे और कहाँ, यदि संभव हो तो। [ 53 जी-एच]

8. इस तर्क में कोई बल नहीं है कि मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं

लैचर एक अलग कानून द्वारा शासित होते हैं जो उन्हें सामान्य कानून के तहत देनदारियों से छूट देता है। अनुच्छेद 194 और 105 जो प्रत्येक सदन के साथ-साथ उसके सदस्यों की शक्तियों, निजी कानूनों और उन्मुक्त से संबंधित हैं, संसद या राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। इन अनुच्छेदों में इंगित की जाने वाली "शक्तियाँ" वे शक्तियाँ हैं जो प्रत्येक सदन के कार्य संचालन के लिए निर्भर करती हैं या आवश्यक हैं। [ 57 बी-सी]

9 (क) संविधान हर संभव का उल्लेख और निष्कर्ष नहीं निकाल सका।

कानून का विषय और यह ठीक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए है कि कला। 248 प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा गया था। इसलिए, कला। 248 सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ें पूरी तरह से s को शामिल करेंगे। 3 भले ही सूची I की प्रविष्टि 94 में ऐसा न हो। संवैधानिक कानून शब्द को न तो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है और न ही पूरी तरह से। उ. संविधान में केवल बुनियादी ढांचा-कार्य शामिल होने की उम्मीद की जा सकती है। सभी मामलों को पूरी तरह से निपटाना इसकी प्रकृति का हिस्सा नहीं है। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि सभी संवैधानिक कानूनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक कानून कहे जाने वाले नियमों के अंतर्गत क्या समझा जा सकता है और क्या नहीं समझा जा सकता है और क्या नहीं समझा जाना चाहिए, इसके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं हो सकता है। व्यवहार में, लिखित संविधान में भी जो कुछ सन्निहित है, वह कभी-कभी लोगों की विशिष्ट धारणाओं पर निर्भर करता है। यह उनके विचारों को दर्शाता है कि संवैधानिक दस्तावेज़ में जगह पाने के लिए किस चीज़ को इतना बुनियादी या मौलिक माना जाना चाहिए। संविधान की विषय-वस्तु इतनी सर्वग्राही होने की अपेक्षा करना कि कानून के प्रत्येक कल्पनीय विषय से पूरी तरह से निपटा जा सके ताकि संदेह के लिए कोई जगह न रह जाए, यह मानवीय रूप से अव्यवहारिक, यदि असंभव न हो, की अपेक्षा करना है। संविधान निर्माताओं की मानवीय दूरदर्शिता से सबसे अधिक उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करनी चाहिए जिसमें ऐसे विषय शामिल हो सकते हैं जिन पर संसद या राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, भले ही कानून आसानी से किसी विशिष्ट प्रविष्टि के लिए निर्दिष्ट न हो। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। [ 61 एच; 59 जी-एच; 61 बी-सी; डी-ई]

(ख) 'पूछताछ' शब्द का उपयोग सूची I की प्रविष्टि 94 और सूची की प्रविष्टि 45 में किया गया है।

III, बिना किसी सीमा के, हर तरह की जांच को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, चाहे किसी के द्वारा आपराधिक अपराध का खुलासा कथित तथ्यों द्वारा किया गया हो या नहीं। सूची III में प्रविष्टि 45 में उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को शामिल करने के लिए पूछताछ शामिल होनी चाहिए जो उन्हें आपराधिक कानून से संबंधित सूची III की प्रविष्टि 1 के दायरे में लाते हैं। प्रविष्टि 45 द्वारा कवर की गई "पूछताछ" के लिए केवल यह आवश्यक है कि वे [1978] 2 एस।

"सूची II या सूची III में निर्दिष्ट किसी भी मामले के उद्देश्य के लिए" होना चाहिए।

ए.

उपयोग की जाने वाली भाषा

निर्दिष्ट मामलों में से कोई भी पर्याप्त व्यापक है।

किसी भी गणना की गई वस्तु से यथोचित रूप से संबंधित किसी भी चीज़ को शामिल करने के लिए, भले ही

राज्यों में मंत्री पदों के धारकों द्वारा किया जाता है। अन्य विषय होंगे

सूची II में पाया गया। यह मानते हुए भी कि न तो प्रविष्टि 94 सूची I और न ही प्रविष्टि 45

सूची III में राज्यों में मंत्रियों के खिलाफ अधिनियमों से संबंधित पूछताछ शामिल होगी।

मंत्री शक्तियों के प्रयोग से जुड़ा हुआ। कला. 248 , प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ें

सूची 1 में अनिवार्य रूप से मंत्रियों के खिलाफ जांच शामिल है -

सार्वजनिक महत्व, क्या आरोपों में आपराधिक कानून का उल्लंघन शामिल है

बी.

या नहीं। एक विपरीत दृष्टिकोण का पूरी तरह से अस्वीकार्य परिणाम होगा

( ग ) चूंकि एस द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। 3 केंद्र और राज्य सरकार पर, दोनों अधिसूचनाओं के कैच के तहत स्थापित प्रकार की जांच शुरू करने की शक्ति सहित, व्यक्त संवैधानिक प्रावधानों द्वारा कवर किए जाते हैं, किसी भी बहिष्करण का कोई सवाल नहीं है, या तो आवश्यक निहितार्थ या किसी भी सिद्धांत द्वारा मूल संरचना का एक हिस्सा बनने या उससे बहने के लिए माना जाता है

संविधान, यहाँ उत्पन्न हो सकता है। न ही एस को इस तरह पढ़ना और व्याख्या करना संभव है। 3 अधिनियम के दो अधिसूचनाओं के तहत स्थापित प्रकार की पूछताछ को इसके दायरे से बाहर करने के बारे में। ऐसा करना सरकारी तंत्र और वस्तुओं के लिए शक्तियों के संभावित दुरुपयोग और विकृति के लिए प्रोत्साहन देना होगा।

सी.

कानून द्वारा समर्थित नहीं। इस तरह की शक्तियों के साथ संवैधानिक दायित्व होते हैं

उन्हें। इनका प्रयोग न्यासियों की शक्तियों और दायित्वों की तरह किया जाना चाहिए जो अपने न्यासों के उद्देश्यों से विचलित नहीं होने चाहिए। किसी मंत्री ने अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है या नहीं, यह निष्पक्ष और ईमानदार लोगों द्वारा कहीं भी

उसके खिलाफ की गई शिकायतों की न्यायसंगत और निष्पक्ष जांच के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है ताकि उसके परिणाम पहले आ सकें।

डी.

उन्हें। [ 64 ए-सी]

(घ) एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस नियम को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है जो स्पष्ट रूप से प्रदान की गई विधायी प्रविष्टि के भीतर आता है। इससे पहले कि सिद्धांत को बिल्कुल भी लागू किया जा सके, न्यायालय को कुछ ऐसा करने का एक स्पष्ट तरीका खोजना चाहिए जो एक कानून में प्रदान किया गया है, जो अपने आवश्यक निहितार्थ से, उसी काम को करने से बाहर कर सकता है, न कि किसी अन्य तरीके से कुछ और। यहाँ यह मामला होने की जगह, संविधान निर्माताओं का इरादा ई था कि वे विभिन्न मामलों की पूछताछ के लिए संसद द्वारा प्रावधानों के निर्माण को शामिल करें।

ऐसी वस्तुएँ जो किसी अन्य सीमा के संकेत के बिना सार्वजनिक महत्व के मामले हो सकते हैं, सिवाय इसके कि उन्हें सूची में पाए जाने वाले विषयों से संबंधित होना चाहिए।

कॉलकुहौन वी. ब्रूक्स, [1888] क्यू. बी. डी. 52 @65 संदर्भित।

(ई) यह प्रस्ताव कि संविधान में जिसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उसे जानबूझकर इसके दायरे से बाहर माना जाना चाहिए ताकि संवैधानिक संशोधन से कम कुछ भी उस पर कानून बनाने को अधिकृत न कर सके।

एफ.

वास्तव में एक "केसस ओमिसस" का आविष्कार करना है ताकि इस नियम को लागू किया जा सके कि जहाँ कानून में इतना अंतर है, वहाँ न्यायालय इसे नहीं भर सकता है। हालाँकि, नियम समान रूप से स्पष्ट है कि न्यायालय किसी कानून की इस तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है कि वह एक केसस ओमिसस पेश करे जहाँ वास्तव में कोई नहीं है। यदि संविधान स्वयं उस कमी को भरने के लिए कानून का प्रावधान करता है जिसे एक कमी के रूप में माना जाना चाहिए, तो ऐसा करने की मांग करने वाले कानून को अमान्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से प्रदान की गई विधायी शक्ति के कारण अपना इच्छित कार्य करता है। इस प्रकार बनाए गए प्रावधानों के उद्देश्य और इसे बनाने के लिए प्राधिकरण की घोषणा करते हुए, न्यायालय गण चूक की आपूर्ति नहीं करते हैं या किसी भी अंतराल को नहीं भरते हैं। यह संसद है जो ऐसा कर सकती है और

किया। [ 65 ए-बी]

द मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड v. वी. हेंडरसन ब्रदर्स, [1888]

13 ए. सी. 595 @602 संदर्भित।

10 ( क) लिखित संविधान अपनी प्रकृति से ही देश के मौलिक कानून के अवतार के रूप में न्यायालयों के लिए अपने व्यापक और बुनियादी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने भागों के अर्थ निर्धारित करना अनिवार्य बनाता है और

एच.

उद्देश्य। इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसकी स्पष्ट लाल वस्तुओं और इसके कार्यों को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए। यद्यपि न्यायालय, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, उन भागों का पूरक हो सकते हैं जहां संविधान का पत्र शांत है या सामान्य विधान कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) द्वारा इसके विकास के लिए जगह छोड़ सकता है।

7

या न्यायिक व्याख्या, वे संविधान की व्यापक या बुनियादी योजना के बारे में अपने स्वयं के कुछ सिद्धांतों को अभिव्यक्ति देने के लिए संविधान के किसी भी भाग के उचित रूप से स्पष्ट अर्थ को रद्द, पराजित या विकृत नहीं कर सकते हैं। यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। उपयोग की गई अभिव्यक्तियों की संदिग्धता को अदालतों द्वारा संविधान निर्माताओं द्वारा अपने सामने रखे गए व्यापक और बुनियादी उद्देश्यों के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपने निर्णयों को स्पष्ट और निश्चित करके ठीक किया जा सकता है। न्यायिक व्याख्या की शक्ति का विस्तार संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के साथ सीधे टकराव में होने वाले प्रावधानों को निर्धारित करने तक नहीं हो सकता है। न ही विधियों पर सीमाओं के मात्र सिद्धांत के आधार पर सीमाओं का आयात करके व्यक्त प्रावधानों में कटौती की जा सकती है। लैटिव शक्तियाँ। [ 66 सी-जी]

( ख) संविधान की व्याख्या के मामले में,

इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहां दो निर्माण संभव हैं,

न्यायालय को उसे अपनाना चाहिए जो उसे लागू करेगा और उसे खारिज कर देगा जो करेगा संविधान निर्माताओं के स्पष्ट इरादों को आहत करते हुए, कि न्यायालय

एक ऐसे निर्माण को अपनाना चाहिए जो उत्पादन करने वाले निर्माण के बजाय सामंजस्यपूर्ण हो इसके प्रावधानों के बीच एक संघर्ष, निर्माण जो सुचारू रूप से सुनिश्चित करेगा और संविधान का सामंजस्यपूर्ण कार्य करना और दूसरे से बचना जो करेगा।

मूर्खता की ओर ले जाता है या व्यावहारिक असुविधा को जन्म देता है या अच्छी तरह से स्थापित करता है

मौजूदा कानून के प्रावधान, कि कानून बनाने की शक्ति की प्रचुरता, विधायी प्रविष्टि द्वारा इंगित, व्यापक और उदार अंतर के रूप में दिया जाना चाहिए उचित रूप से संभव होने पर ढोंग करें। यदि कोई विषय एक के अंतर्गत नहीं आता है सूची II या सूची III में पाए जाने वाले विशेष रूप से सीमांकित क्षेत्र, यह सूची I में आएगा, जाहिरा तौर पर प्रविष्टि द्वारा इंगित अवशिष्ट क्षेत्र के आयाम के कारण

97, सूची I. विधायी प्रविष्टियाँ केवल विधायी कार्यों के संचालन के क्षेत्रों को दर्शाती हैं शक्ति जो वास्तव में संविधान के अनुच्छेदों में से एक द्वारा प्रदान की जाती है। इस न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि प्रविष्टि 97 को व्यापक सीमा दी गई है।

सूची I को कला के साथ पढ़ा जाता है। 248 संविधान का, संघीय को नष्ट कर देगा हमारे गणराज्य की संरचना। एक समान परीक्षण के आवेदन पर, शक्तियाँ एस द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया। 3 अधिनियम का, माना नहीं जा सका यह इस आधार पर अमान्य है कि राज्य का संघीय ढांचा खतरे में है। [ 68 सी; ई: 69 सी: 70 बी एंड डी]

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य [1950] एस. सी. आर. 88 और 119 से 120।

बिहार राज्य बनाम। कामेश्वर सिंह, [1952] एससीआर 889 और 980-81, 1. सी. गोलक नाथ वी। पंजाब राज्य [1967] 2 एससीआर 762 @791, के. के. कोचुनी बनाम। की स्थिति

मद्रास और केरल, [1960] 3 एस. सी. आर. 887 और 905, मोहम्मद। हनीफ वी. बिहार का राज्य%, [1959] एस. सी. आर. 629 @648, एम. पी. राज्य v. रानोजीराव शिंदे, [1963] 3 एससीआर

489 , प्रेम चंद गर्ग बनाम। आबकारी आयुक्त, यू. पी. [1963] सप्लीमेंट। 1 एससीआर 885 @ 911 देवदासन बनाम। भारत संघ, [1964] 4 एससीआर 680 @695, केशवानंद

भारती बनाम. केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी. 225 @426, (-1973 पूरक। एससीआर 1),

· सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, [1962] 3 एससीआर 842, जगन्नाथ बख्श

सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [1963] 1. एससीआर 220 @228-229 और भारत संघ बनाम।

एफ. एस. दिल्लीन, [1972] 2 एससीआर 33 का उल्लेख किया गया है।

( ग ) जब भी मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की गई है या

इसे लागू करना केवल संविधान की व्याख्या के सिद्धांत के रूप में है क्योंकि यह वास्तविक है।

ली मौजूद है और एक संविधान का नहीं है जो केवल व्यक्तिपरक रूप से मौजूद हो सकता है

अलग-अलग व्यक्तियों के मन संविधान के बारे में केवल सिद्धांतों के रूप में हैं।

इस सिद्धांत ने संविधान की सामग्री को नहीं जोड़ा। यह नहीं था, में सिद्धांत रूप से, जो कुछ भी था उससे कुछ भी काट लें। यह केवल बाहर लाने के लिए अभिप्रेत है

और जो पहले से ही वहाँ था उसका अर्थ समझाएँ। वास्तव में इसका उपयोग किया जाता था

सभी। अलग-अलग परिणामों के साथ इस उद्देश्य के लिए न्यायाधीश केवल इसलिए कि उनके

मूल संरचना का हिस्सा क्या था, इसके बारे में आकलन या निष्कर्ष

संविधान अलग था। यह सिद्धांत की सही व्याख्या है

संविधान की मूल संरचना। इसे केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब यह स्पष्ट हो,

सन्देह के क्षेत्र से परे, कि जिस पर प्रतिबंध के रूप में रखा गया है

अन्यथा स्पष्ट और पूर्ण विधायी शक्ति एक संवैधानिक के रूप में है

अनिवार्य है। [ 86 जी-एच ]

(घ) यदि यह मूल संरचना के बारे में सही दृष्टिकोण है, तो अंतर के एक तरीके के रूप में

केवल संविधान, तथाकथित संघवाद को विधायी पर एक बंधन के रूप में प्रस्तुत करना द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए शक्ति को किसी स्पष्ट प्रावधान में अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए

अदालतें। केशवानंद भारती के मामले का फैसला करने वाले अधिकांश न्यायाधीश

"संघवाद" को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं माना है

और उनमें से किसी ने भी इस संरचना के "संघीय" हिस्से के विस्तार पर चर्चा नहीं की है। निश्चित रूप से। कला को इंगित करना पर्याप्त नहीं है। 1 संविधान इस बात पर जोर देता है कि

रात 8 बजे।

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारा गणराज्य राज्यों का एक "संघ" है। "संघ" शब्द का उपयोग किया गया था

हमारे संघीय गणराज्य के विशिष्ट चरित्र का संदर्भ इसकी अभिव्यक्ति से प्रकट होता है

प्रावधान। अन्य स्पष्ट प्रावधानों से यह पता लगाना होगा कि यह "संघ" क्या है। इसका अर्थ है या इसके द्वारा निहित "संघवाद" की सीमा या प्रकृति क्या है। द.

संविधान स्वयं "संघ" शब्द का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता है। यह संभव नहीं है। ऐसे किसी भी बंधन की खोज करना जो एक आवश्यक निहितार्थ से रोक सके।

संसद द्वारा अधिनियम बनाने से एस। 3 अधिनियम से। [ 87 बी-डी ]

चंद्रचूड़ के अनुसार, जे.

मुकदमे की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति होनी चाहिए  
अस्वीकार कर दिया। कर्नाटक राज्य द्वारा लाई गई कार्यवाही बनाए रखने योग्य है।  
कला के तहत। 131 संविधान से। [ 100 सी.

( क ) उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारिता। 131 में से

एक संवैधानिक प्रावधान जो इस न्यायालय को अनन्य अधिकारिता प्रदान करता है -  
अपनी मूल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एक निश्चित प्रकृति के विवादों पर विचार करना,  
दीवानी अदालत को अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान के साथ तुलना नहीं की जा सकती  
ए

एक आम मुकदमा दायर करें ताकि कला के तहत एक मूल कार्यवाही पर लागू किया जा सके।  
131

एक सूट के नियम जो आमतौर पर एस के तहत परीक्षण योग्य होते हैं। 15 सी. पी. सी. द्वारा  
इसे चलाने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी का न्यायालय। संविधान में नहीं है

कला के तहत एक कार्यवाही का वर्णन करें। 131 सूट के रूप में लेकिन शब्दों और वाक्यांशों का  
उपयोग करता है

सामान्यतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए नियोजित

मनोरंजन करने और सूट आजमाने का पहला उदाहरण। यह किसी कारण की बात नहीं करता है  
एक्शन; इसके बजाय यह "विवाद" शब्द का उपयोग करता है। सब से ऊपर, कला। 131 है।

ए

इसके दायरे में आने वाले मामलों पर स्व-निहित कोड। बहुत शर्तों से

अनुच्छेद की एकमात्र शर्त जिसे लागू करने के लिए संतुष्ट किया जाना आवश्यक है

इस न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र यह है कि पक्षकारों के बीच विवाद निर्दिष्ट किया गया है।

खंड (ए) से (सी) में एक प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर अस्तित्व

या कानूनी अधिकार की सीमा निर्भर करती है। [ 97 ई-एच]

(ख) कला का सार। 131 यह है कि इसके बीच विवाद होना चाहिए

एक ऐसे प्रश्न के संबंध में पक्षकार जिस पर कानूनी प्रावधान का अस्तित्व या विस्तार है। सही निर्भर करता है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को चुनौती

जाँच आयोग नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार में स्पष्ट रूप से एक

सवाल जिस पर केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार है जाँच आयोग नियुक्त करना सरकार पर निर्भर करता है और यही पर्याप्त है

राज्य द्वारा कला के तहत लाई गई कार्यवाही को बनाए रखना। 131 कान का

व्यवस्था। संविधान ने उद्देश्यपूर्ण रूप से इस न्यायालय को एक न्यायशास्त्र शब्द प्रदान किया है जो उन विचारों से मुक्त है जो पहली बार के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित करते हैं जो नागरिक प्रकृति के मुकदमों को स्वीकार करता है और उनका परीक्षण करता है। कला के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद की प्रकृति। 131 रूप और सार दोनों में दावों की प्रकृति से अलग है जिसके लिए सामान्य मुकदमों में निर्णय की आवश्यकता होती है। [ 98 बी-डी]

(ग) संविधान का भाग XL विशेष रूप से निम्नलिखित के चित्रण के लिए समर्पित है -

संघ और राज्यों के बीच संबंध। कला का उद्देश्य। 131 होना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च शक्ति वाली मशीनरी प्रदान करें कि केंद्र सरकार

और राज्य सरकारें अपने अधिकार के संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्य करती हैं और एक दूसरे के संवैधानिक कार्यों का अतिक्रमण नहीं करती हैं या

शक्तियाँ।

इसलिए, प्रतिवादी की कार्य करने की संवैधानिक क्षमता को चुनौती

कला के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिए एक इच्छित तरीके से पर्याप्त है। 131 पार्टी

जब वादी विशेष रूप से अपने लिए उस अधिकार का दावा करता है। [ 98 एफ-जी]

(घ) कला के तहत एक कार्यवाही। 131 एक साधारण के विपरीत खड़ा है

सिविल सूट। जबकि एक साधारण दीवानी मुकदमे में द्वारा दावा किए गए अधिकार की अस्वीकृति

प्रतिवादी तदनुसार और अपने बल से वादी द्वारा दावा किए गए अधिकार, कला के तहत कार्यवाही को स्थापित नहीं कर सकता है। 131 केंद्र या राज्य सरकारों में निहित संवैधानिक शक्ति की सीमाओं का न्यायनिर्णायक हैं। दीवानी मुकदमे में वादी को अपने स्वयं के शीर्षक के बल पर सफल होना पड़ता है; कला के तहत एक कार्यवाही में प्रतिस्पर्धा। 131 यह दो या दो से अधिक शासनों के बीच होता है। दीवानी मुकदमे की तरह कोई तीसरा विकल्प नहीं है जिसमें वादी द्वारा दावा किया गया अधिकार न तो उसमें रह सकता है और न ही प्रतिवादी में, बल्कि अजनबी। कर्नाटक बनाम के बीच संवैधानिक शक्ति का सीमांकन और परिभाषा।

यूनियन (बेग, सी. जे.)

9

प्रतिद्वंद्वी दावेदार और केवल उन तक ही सीमित एक कार्यवाही है

कला के तहत। 131 अनिवार्य रूप से शामिल है। [ 98 एच एंड 99 ए-सी]

( ई ) प्रतिवादी के तर्क में कोई बल नहीं है कि यदि कोई राज्य शासन करता है

केंद्र सरकार के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती देता है

कार्रवाई का एक विशेष पाठ्यक्रम, कला। 131 आकर्षित नहीं होंगे। विवाद

राज्य सरकार का केवल यह नहीं है कि केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है

राज्य के आचरण की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त करना।

मंत्री लेकिन यह कि ऐसा अधिकार विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है, इसलिए,

न केवल केंद्र द्वारा दावा किए गए अधिकार से इनकार किया जाता है

सरकार लेकिन एक दावा है कि अधिकार विशेष रूप से राज्य में रहता है

सरकार। [ 99 डी-ई]

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1977 एस. सी. आई. 361 संदर्भित।

( च ) कला के तहत एक रिट। 226 के तहत कार्यवाही के लिए शायद ही एक विकल्प है

कला. 131. एक या अधिक राज्यों के बीच या सरकार के बीच विवाद

एक ओर भारत और एक राज्य का और दूसरी ओर दूसरे राज्य या अन्य राज्यों का दूसरा, अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय द्वारा ठीक से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 226. अधिक

कला में वर्णित प्रकृति के विवादों पर। 131 आम तौर पर तत्काल होने के कारण अपील करें। मूल कार्यवाही का निर्णय इस न्यायालय द्वारा हमेशा के लिए किया जाता है। [ 100 ए-बी]

2. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के दायरे में है -

एस. 3 ( 1 ) अधिनियम से। राज्य सरकार की आपत्ति है कि यह अपमानजनक है सीएल के खिलाफ। ( ख ) एस के लिए परंतुक का। 3 ( 1 ) अधिनियम का तथ्यपूर्ण रूप से निराधार है

और सैद्धांतिक रूप से अनुचित। [ 114 एफ; 101 एचजे

( क ) यह तर्क देना गलत है कि केंद्र सरकार ने उसी मामले की जाँच के उद्देश्य से जाँच आयोग जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग है पूछताछ करने का निर्देश दिया। [ 101 ई]

( ख ) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों पर विचार करना।

केंद्र सरकार और वे मामले जिनमें संबंधित आयोगों को पूछताछ करने का निर्देश दिया जाता है, यह स्पष्ट है कि उद्देश्य और उद्देश्य

दोनों में से पूछताछ मूल रूप से अलग है। राज्य का मुख्य उद्देश्य आयोग की नियुक्ति में सरकार यह पता लगाने के लिए है कि क्या यह अनुचित है या नहीं। अत्यधिक भुगतान किए गए, अनुचित अनुग्रह दिखाए गए, अनियमितताएँ या

आधिकारिक कार्य आदि के संचालन में धोखाधड़ी हुई थी और दूसरा -

यदि कोई चूक है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं, इसका पता लगाएं।

उपरोक्त और किस हद तक "। दूसरी ओर आयोग ने

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को विशेष रूप से यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या

मुख्यमंत्री ने विभिन्न मामलों में पक्षपात और भाई-भतीजावाद का अभ्यास किया।

अधिसूचना में उल्लिखित मामले। [ 100 जी; 101 डी-ई]

( ग ) इसके अलावा, यह शायद ही कभी संभव है कि राज्य सरकार ऐसा करेगी।

भ्रष्टाचार, पक्षपात के कृत्यों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करना और अपने मुख्यमंत्री की ओर से भाई-भतीजावाद। [ 101 जी]

3 ( ए ) एस के एक सादे पढ़ने पर। 3 ( 1 ) अधिनियम के अनुसार, यह मानना असंभव है कि

इस धारा को केंद्र सरकार को अधिकृत करने के रूप में नहीं माना जा सकता है

आचरण की जांच के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करें

किसी राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री का। [ 102 बी]

( ख ) धारा 3 (1) को सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। कोई औचित्य नहीं है

धारा की शक्ति को सीमित करने के लिए धारा के प्रावधानों को पढ़ने के लिए

केंद्र सरकार जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी

के मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में व्यक्तियों का आचरण केवल  
संघ सरकार। यह खंड केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि -

जनता के किसी भी निश्चित मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करें।

महत्व। यह निर्विवाद है कि राज्य सरकार के मंत्रियों का आचरण

उनके आधिकारिक कार्यों के कथित निर्वहन में एक निश्चित धारणा नहीं है।

सार्वजनिक महत्व का विषय। इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्रीय I  
सरकार के पास [1978] 2 एस. सी. आर. के संबंध में तथ्य एकत्र करने की शक्ति भी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10

राज्य विधानमंडल के एक वर्ग द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री। [ 102 ई-एफ]

( ग ) वह तर्क जो एस। 3 ( 1 ) सामूहिक के सिद्धांत के खिलाफ अपराध करेंगे

जब तक इसका संकीर्ण रूप से अर्थ नहीं लगाया जाता है, तब तक जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है। जो भी हो।

जाँच आयोग, मंत्रिपरिषद के निष्कर्ष हो सकते हैं

चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, वे सामूहिक रूप से जवाबदेह बने हुए हैं

या लोक सभा या विधान सभा के प्रति उत्तरदायी।

न तो आयोग की नियुक्ति और न ही आयोग द्वारा अस्वीकृति

जाँच के लिए उसे भेजे गए सभी या किसी भी आरोप का आयोग

मंत्रिपरिषद को उन निकायों के प्रति कम जवाबदेह बनाएं। द.

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) और 164 (2) का उद्देश्य यह प्रावधान करना है कि -

संबंधित विधानमंडल को। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कृत्यों के लिए भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या पक्षपात जिसके खिलाफ सदस्यों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं

एक व्यक्तिगत मंत्री, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से आयोजित किया जा सकता है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी। यदि कोई व्यक्तिगत मंत्री अपने पद का उपयोग करता है

भ्रष्टाचार के कृत्यों को करने का अवसर या दिखावा, वह व्यक्तिगत रूप से होगा

अपने गैरकानूनी कृत्यों के लिए जवाबदेह और सामूहिक जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं

ऐसे मामले में मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है। [ 105 सी; 103 एफ-एच]

( घ ) मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सार है -

कि मंत्रिमंडल किसी भी मामले में की गई प्रत्येक कार्यवाही के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रालयों से। दूसरे शब्दों में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

केवल उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो एक मंत्री करता है या उचित रूप से कहा जा सकता है

अपने आधिकारिक कार्यों के वैध निर्वहन में प्रदर्शन करना। [ 104 बी]

ए. संजीवी नायडू आदि। मद्रास और अन्र राज्य।, [ 1970 ] 3 एससीआर 505,512

संदर्भित किया गया।

( ई ) संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में कि आचरण

विधानमंडल के किसी सदस्य की जाँच केवल विधानमंडल द्वारा की जाएगी, यह मानना असंभव है कि जांच आयोग की नियुक्ति के तहत

यह अधिनियम विधानमंडल के विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप करता है। अंग्रेज़ी हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों से संबंधित पूर्ववर्ती जो प्रासंगिक हैं

कला के तहत। 194 ( 3 ) राज्य के तर्क का समर्थन न करें। [ 105 डी]

( च ) संसद द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्ति -

एस के तहत जांच आयोग नियुक्त करें। 3 ( 1 ) अधिनियम के उद्देश्य के लिए भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के आरोपों के संबंध में तथ्यों का पता लगाना

किसी वर्तमान मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ अंतर-मंत्री का गठन नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार के कार्यकारी कार्यों के प्रति संवेदनशीलता या यह कि यह केंद्र सरकार को राज्य के कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है।

कार्यकारी। [ 109 एफ-जी]

( छ ) अधिनियम के प्रावधानों और योजनाओं की जांच से पता चलता है कि

अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग विशुद्ध रूप से एक तथ्य खोजने वाला निकाय है जिसमें कोई नहीं है

बाध्यकारी या निश्चित निर्णय देने की शक्ति। समुदाय के व्यापक हित के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक महत्व के संवेदनशील मामलों की जांच एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग द्वारा की जानी चाहिए जिसके निष्कर्ष लोगों के विश्वास को कम कर सकते हैं। यदि रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करने का फैसला करती है। इसकी वैधता हो सकती है

संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में निर्णय लिया जाना। लेकिन, जब तक वह चरण नहीं आ जाता, तब तक यह मानना मुश्किल है कि केंद्र सरकार कोई प्रयास कर रही है

राज्य से।

कार्यकारी कार्यों पर नियंत्रण या पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र

[ 108 बी-सी]

विधायी

( ज ) विवादित अधिनियम को अभाव से ग्रस्त नहीं माना जा सकता है।

की प्रविष्टि 45

संसद में इसे अधिनियमित करने की क्षमता। सूची I, सूची III की प्रविष्टि 94 और इनमें विफल रहने पर, सूची I की प्रविष्टि 97 को अधिनियम को बनाए रखना चाहिए। [ 112 बी]

( i ) श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. टेंडो! कर और अन्य इस

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसद को सूची I की प्रविष्टि 94 और सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 45 के तहत कानून पारित करने की विधायी क्षमता है। शब्द "। जाँच आयोगों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करने वाले अधिनियम को पारित करने की शक्ति को कवर करने के लिए दोनों प्रविष्टियों में होने वाली जाँच आयोजित की जानी चाहिए।

कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.)

11

बैठक के संचालन में जांच आयोग नियुक्त करने की शक्ति

राज्य सरकारों के मंत्री कोल के सिद्धांत के खिलाफ अपराध नहीं करते हैं

व्याख्यानात्मक उत्तरदायित्व या विधान सभा के विशेषाधिकारों के विरुद्ध, और,

क्योंकि यह केंद्र सरकार को नियंत्रण की शक्ति भी प्रदान नहीं करता है राज्य कार्यपालिका पर, प्रावधान को एक वैध अभ्यास माना जाना चाहिए

संसद की विधायी क्षमता। [ 111 बी-सी]।

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य, [1959]

एस. सी. आर. 279,293 स्वीकृत।

एम. वी. राजवाडे बनाम डॉ. एस. एम. हसन और अन्य।, एयर 1954 नाग। 71 और

ब्रजनंदन सिन्हा बनाम। ज्योति नारायण, [1955] एससीआर 955,975 का उल्लेख किया गया है।

( 1 ) प्रविष्टि 97 एक अवशिष्ट प्रविष्टि की प्रकृति में है और शब्द "कोई अन्य"

जो पदार्थ उसमें दिखाई देता है, उसका अर्थ है गणना किए गए पदार्थों के अलावा कोई अन्य पदार्थ। सूची I "में"। यदि प्रविष्टि 94, सूची I अधिनियम को शामिल नहीं करती है, तो प्रकृति की पूछताछ

अधिनियम द्वारा विचार किया गया विवरण "किसी अन्य मामले" के अंतर्गत आएगा।

सूची I की प्रविष्टि 97 में होने वाली. यदि सूची III की प्रविष्टि 45 और संपूर्ण

राज्य सूची को विचार से बाहर रखा जाना चाहिए, यह अधिनियम "एक मामले" से संबंधित होगा।

सूची II या सूची III में गणना नहीं की गई है। [ 111 जीजे

( के) यह तर्क कि केंद्र सरकार को नियुक्त करने का अधिकार देकर

के वर्तमान मंत्रियों के आचरण की जांच के लिए एक आयोग

राज्य सरकार और संसद ने केंद्र-राज्य संबंधों पर कानून बनाया है

जो एक संवैधानिक विषय है, बिना किसी बल के है। अधिनियम केवल उन्हें

केंद्र सरकार को कोल के लिए जांच आयोग नियुक्त करने का अधिकार

अपने मन और रिपोर्ट को सूचित करने की दृष्टि से तथ्यों को व्याख्यान देना कमीशन किसी पर भी बाध्यकारी नहीं है। यदि कोई कानून विधायिका के भीतर है



राज्य के मंत्री और अन्य मंत्री और केंद्र सरकार के पास नहीं है  
 उसी की जाँच करने या उसके लिए जाँच आयोग का गठन करने की शक्ति  
 उद्देश्य, स्पष्ट रूप से राज्य की शक्ति की सीमा के रूप में एक विवाद उठाता है और  
 केंद्र सरकार में एक उच्चतर या समन्वित शक्ति का अस्तित्व  
 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आचरण की जांच करना  
 अपने सरकारी कार्यों के निर्वहन में राज्य। इस तरह का विवाद  
 राज्य और भारत संघ की संबंधित शक्तियों की सामग्री की पुष्टि करता है  
 और दोनों संस्थाओं और राज्य के बीच अंतर संबंध महत्वपूर्ण है  
 उसमें रुचि रखते हैं। राज्य बहुत चिंतित है कि क्या इसका आचरण  
 सरकारी कार्यों के निर्वहन में मंत्री परिषद से पूछताछ की जा सकती है।

2-

1042 एससीआई 77 [1978] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12

केवल अपनी स्वयं की एजेंसी के माध्यम से या द्वारा जांच के अधीन किया जा सकता है  
 भारत संघ। राज्य को यह कहने का अधिकार होगा कि संघ ने  
 दुरुपयोग की जांच करने के लिए अपनी अनन्य शक्ति का अतिक्रमण करने का कोई अधिकार  
 नहीं अपनी मंत्रिपरिषद द्वारा सरकारी शक्ति। परिषद के अलावा  
 मंत्रीगण, राज्य भी सक्षम रूप से यह दावा कर सकते हैं कि  
 मंत्री, इसकी ओर से कार्य करते हुए, शक्ति के अधीनता से मुक्त हैं  
 केंद्र सरकार मंत्रियों के रूप में उनके आचरण की जांच करेगी। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता

मंत्रिपरिषद के संबंध में दावा राज्य के लिए किया जा सकता है  
 और राज्य इसके अस्तित्व को लेकर विवाद उठा सकता है। प्रतिरक्षा। [ 121  
 बी-ई]

ना.

अटॉर्नी-विक्टोरिया बनाम के लिए जनरल। राष्ट्रमंडल, 71 सी. एल. आर. 237 और  
 अटॉर्नी-विक्टोरिया बनाम के लिए जनरल। राष्ट्रमंडल, 52 सी. एल. आर. 533 का उल्लेख  
 किया गया।

(ख) किसी विवाद के संबंध में दो सीमाएँ जिन्हें सामने लाया जा सकता है।

कला के तहत सर्वोच्च न्यायालय। 131 ये हैं: पार्टियाँ और विषय

द.

बात है।

अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि संघीय या अर्ध-संघीय संरचना विवादों में।

भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हो सकता है या दांव

दो या दो से अधिक राज्यों में, समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया जाना चाहिए

ऐसे विवाद और वह मंच देश का सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। लेख

131 केवल तभी आकर्षित होता है जब विवाद के पक्षकार की सरकार होती है

दोनों तरफ यूडिया या एक या एक से अधिक राज्य थे। उप के रूप में सीमा

जेक्ट मैटर इन शब्दों में निहित है "यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है कि क्या  
 कानून या तथ्य का है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है" जो  
 इंगित करता है कि विवाद एक कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा को प्रभावित करने वाला  
 होना चाहिए न कि राजनीतिक स्तर पर विवाद जिसमें कोई कानूनी पहलू शामिल न हो। [ 115  
 जी-एच]

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361 का उल्लेख किया गया।

( ग ) भेद शर्त के आधार पर तर्क में दो भ्रान्तियां हैं।

राज्य और राज्य सरकार: एक राज्य और राज्य सरकार के बीच एक अपेक्षाकृत कठोर, जल-कठोर अंतर खींचने में और दूसरा अनुमान लगाने में

कि यह केवल वहाँ है जहाँ वादी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है कि मुकदमा कला के तहत बनाए रखा जा सकता है। 131. [ 117 बी-डी]

( घ ) यद्यपि सैद्धांतिक रूप से राज्य और राज्य के बीच अंतर मौजूद है।

सरकार (और इसे एस में मान्यता मिलती है। 3 ( 58 ) और एस। 3 ( 60 ) जीन राल खंड अधिनियम, 1897) के संवैधानिक अधिकारियों ने बताया है कि

यह अंतर एक नैतिक और बौद्धिक व्यक्ति के रूप में दिए गए मानव व्यक्ति और उसके भौतिक भौतिक शरीर के बीच के अंतर के समान है। 'राज्य' शब्द से उस राजनीतिक व्यक्ति या इकाई को समझा जाता है जिसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है और 'सरकार' शब्द से उस एजेंसी को समझा जाता है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा को तैयार किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और निष्पादित किया जाता है। इस प्रकार सरकार राज्य के तंत्र के रूप में कार्य करती है और जो इस तंत्र को संचालित करते हैं वे राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। पुनः, राज्य स्वयं एक आदर्श व्यक्ति है, अमूर्त, अदृश्य और अपरिवर्तनीय है और सरकार इसकी अभिकर्ता है। यदि राज्य सरकार वह अभिकर्ता है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो राज्य को असंबद्ध नहीं कहा जा सकता है जब इसके किसी भी अधिकार या क्षमता या कमी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह कहना पूरी तरह अवास्तविक होगा कि चूंकि राज्य सरकार राज्य से अलग है, इसलिए राज्य सरकार में इसकी कोई भी कार्रवाई या क्षमता या कमी राज्य को प्रभावित नहीं करेगी और राज्य को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसा करना राज्य और राज्य सरकार के बीच अभिन्न संबंधों की अनदेखी करना होगा। कोई भी कार्रवाई जो राज्य सरकार या मंत्रियों के रूप में उनकी क्षमता को प्रभावित करती है, वह एक ऐसा मामला उठाएगी जिसमें राज्य का संबंध होगा। [ 117 डी-एच]

( ई ) जब इसका कोई अधिकार या क्षमता या कमी किसी संस्थान को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

या राज्य की ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति, यह एक ऐसा मामला उठाता है जिसमें राज्य शामिल या संबंधित है। इन परिस्थितियों में, राज्य किसी भी तरह से प्रभावित होगा, यदि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने

ऐसी क्षमता जो उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के मामले में हो,

केंद्र सरकार द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग के अधीन हैं।

यदि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को एक विशेष तरीके से राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश जारी करती है, तो राज्य स्पष्ट रूप से प्रभावित होगा यदि ऐसा निर्देश असंवैधानिक है और इसके खिलाफ शिकायत करने का हकदार होगा।

यदि कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.)

13

केंद्र सरकार बिना किसी संवैधानिक अधिकार के यह जांचने के लिए आगे बढ़ती है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा कैसे किया जाता है और क्या इसका उपयोग उचित तरीके से किया जाता है।

स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार होगा

केंद्र सरकार। [ 118 ई-जी ]

( च ) यह कला की प्रयोज्यता की अनिवार्य शर्त नहीं है। 131 कि वहाँ

इससे पहले कि वादी कुछ कानूनी अधिकार का उल्लंघन कर सके

अनुच्छेद के तहत एक मुकदमा दायर करें। अनुच्छेद की आवश्यकता यह है कि विवाद

वह होना चाहिए जिसमें एक प्रश्न शामिल हो "जिस पर अस्तित्व या विस्तार कानूनी अधिकार निर्भर करता है "। कानूनी अधिकार वादी या वादी का हो सकता है

प्रतिवादी। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक है कि अस्तित्व या विस्तार

पक्षों के बीच विवाद में कानूनी अधिकार का मुद्दा होना चाहिए। [ 118 एचजे

( छ ) अनुच्छेद 131 कार्यवाही के किसी विशेष तरीके को निर्धारित नहीं करता है।

उसके द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने नियम इस बात पर विचार करते हैं कि इसके तहत अदालत की मूल अधिकारिता अनुच्छेद को एक ऐसे मुकदमे के माध्यम से लागू किया जाएगा जिसकी आवश्यकता नहीं है लेख। अनुच्छेद एक की व्याख्या करते समय शायद अनजाने में प्रभावित होता है कार्रवाई के कारण की धारणा को आयात करने के लिए जो एक सूट में जर्मन है और इसे पढ़ें अनुच्छेद केवल उन मामलों तक सीमित है जहां वादी का कुछ कानूनी अधिकार है इसका उल्लंघन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई का कारण है।

लेकिन कला में किसी मुकदमे या कार्रवाई के कारण का कोई संदर्भ नहीं है। 131. वह लेख के चरित्र के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है विवाद जिसे न्यायनिर्णयन के लिए उसके समक्ष लाया जा सकता है। आवश्यकताएं कार्रवाई का कारण, जो एक मुकदमे में इतना आवश्यक है, आयात नहीं किया जा सकता है कला के दायरे और दायरे को समझते हुए। 131. [ 115 ई और 119 बी-सी]

( ज ) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए एकमात्र आवश्यक आवश्यकता कला. 131 यह है कि विवाद किसी भी प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार इस बात पर निर्भर करता है कि कानूनी अधिकार है या नहीं।

अधिकार का दावा एक या दूसरे पक्ष द्वारा किया जाता है और यह आवश्यक नहीं है कि कुछ मुकदमा दायर करने से पहले वादी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाना चाहिए। उस अनुच्छेद के तहत। [ 119 ई-एफ]

( (i) कला में "अधिकार" शब्द का प्रयोग किया जाता है। 131 एक सामान्य अर्थ में और सहमत नहीं

अपने सख्त अर्थ के लिए। अपने संकीर्ण अर्थों में एक अधिकार सहसंबंध का गठन करता है

कर्तव्य के बारे में लेकिन इसके सामान्य अर्थों में न केवल सही स्ट्रिक्टो सेंसु शामिल है बल्कि "कोई भी कानून के शासन द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया लाभ या लाभ। वह शब्द।

" सही "के चार अलग-अलग अर्थ हैं: ( i) राइट स्ट्रिक्टो सेंसु (ii) स्वतंत्रता (iii)

शक्ति; और (iv) प्रतिरक्षा। अपने सख्त अर्थों में 'अधिकार' को ब्याज के रूप में परिभाषित किया गया है।

जिसकी कानून दूसरों पर संबंधित कर्तव्य लागू करके रक्षा करता है। स्वतंत्रता "

दूसरे के अधिकार से छूट है और इसका सहसंबंध "कोई अधिकार नहीं" है;

" शक्ति "दूसरे के कानूनी संबंधों और इसके सहसंबंध को बदलने की क्षमता है।

दायित्व है। " प्रतिरक्षा "दूसरे की कानूनी शक्ति से छूट है और

इसका सहसंबंध अक्षमता है। [ 119 एच एंड 120 एजे

( जे) कला में 'अधिकार' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 131 सामान्य अर्थ में। यदि राज्य

विशेष रूप से किसी विशेष मामले पर कानून बनाने का अधिकार होने का दावा

इस आधार पर कि यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आता है

और भारत संघ राज्य के इस अधिकार पर सवाल उठाता है, विवाद होगा

पद के सख्त अर्थ में राज्य के किसी भी अधिकार से संबंधित नहीं, लेकिन ऐसे मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य की 'स्वतंत्रता' के लिए और यह आएगा

सीधे कला की शर्तों के भीतर। 131. यहाँ तक कि सत्ता से संबंधित विवाद भी

किसी राज्य की विधान सभा को समाप्त करने या भंग करने के लिए भारत संघ का

यह अनुच्छेद 131 के दायरे में आएगा। [ 120 सी-डीजे

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361, अटॉर्नी

विक्टोरिया बनाम के लिए जनरल। राष्ट्रमंडल, 71 सी. एल. आर. 237 और वकील

विक्टोरिया बनाम के लिए जनरल। राष्ट्रमंडल, 52 सी. एल. आर. 533 का उल्लेख किया गया।

उन्तवालिया, शिंगल और जसवंत सिंह, जेजे। ( असहमति)  
सूट रखरखाव योग्य नहीं है।

[

126 डी] [1978] 2 एस. सी. आर.

14

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( क ) राज्य अपने आप में एक आदर्श व्यक्ति है, एक कानूनी इकाई है, अपरिवर्तनीय है, अदृश्य और अपरिवर्तनीय। सरकार वह एजेंसी है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा को तैयार किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और निष्पादित किया जाता है। [ 123 एल।

( ख ) भारत संघ के बीच विवाद के अस्तित्व के संबंध में कला में। 131 पूर्व के लिए भारत सरकार यह दर्शाती है कि विवाद भारत सरकार के पास हो सकता है लेकिन विवाद के दूसरे पक्ष को होना चाहिए केवल राज्य हो और राज्य का कोई अंग न हो, अर्थात् कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका। संविधान के अनुच्छेद 300 में कहा गया है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा किया जा सकता है और किसी राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा किया जा सकता है।

यह केवल एक सक्षम प्रावधान है। सरकार के अधिकार पर एक प्रवेश कुछ परिस्थितियों में, राज्य के कानूनी अधिकार पर एक अतिक्रमण हो सकता है, और यदि किसी राज्य के कानूनी अधिकार पर कोई आक्रमण होता है तो एजेंसी के माध्यम से कौन सी कार्रवाई शुरू की जाएगी, वह राज्य सरकार हो सकती है। लेख 300 केवल मुकदमे के पक्षकार का वर्णन करने का तरीका निर्धारित करता है। लेकिन असली सूट की रखरखाव के लिए जवाब कला से पाया जाना है। 131 स्वयं।

[ 123 एफ-जी]

( ग ) अनुच्छेद 131 विशेष रूप से यह नहीं बताता है कि किसका कानूनी अधिकार है

विवाद में शामिल स्थिति का संबंध किस संबंध में होना चाहिए। कहने के लिए कि अनुच्छेद के अनुप्रयोग के लिए यह पर्याप्त है कि वादी प्रश्न करता है

प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया कानूनी या संवैधानिक अधिकार सही नहीं हो सकता है।

आम तौर पर और आम तौर पर किसी भी मुकदमे में प्रतिस्पर्धा कानूनी अधिकार के बीच होती है।

वादी और प्रतिवादी का। लेकिन मुख्य रूप से वादी को स्थापित करना होता है मुकदमे में सफल होने का उसका कानूनी अधिकार। यदि प्रतिवादी अपनी कानूनी स्थिति स्थापित करता है

ठीक है, मुकदमा विफल हो जाता है। यदि कोई भी पक्ष कानूनी अधिकार स्थापित करने में विफल रहता है, फिर भी

अभिव्यक्ति "कला में उपयोग किए गए कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार। 131 है। इसका उद्देश्य यह परिणाम लाना था। यह न तो आवश्यक था और न ही उचित था।

को

अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि विवाद में कोई भी प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर वादी का कानूनी अधिकार निर्भर होना चाहिए। [ 124 बी; ई-एफ]

( घ ) यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक मंत्री एक अधीनस्थ अधिकारी है

राज्यपाल। इस मामले में स्थापित जांच राज्य या राज्य के खिलाफ नहीं है।

सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ जिनके लिए यह है

कला के तहत उच्च न्यायालय में जाने के लिए खुला है। 226 संविधान और उच्च

न्यायालय ने तब अधिनियम की शक्तियों के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा होगा।

कला के तहत न्यायालय। 131 ए. लेकिन, यह किसी भी तरह से राज्य को आह्वान करने का अधिकार नहीं देता है

अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता। 131. [ 125 ए-बीएल  
राजस्थान राज्य और अन्य। वी. भारत संघ, ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361,  
राजा

सम्राट वी। शिवनाथ बनर्जी और अन्य।, 72 भारतीय अपील, 241 और ए. संजीवी  
नायडू आदि। वी. मद्रास और अन्र राज्य।, [ 1970 ] 3 एस. सी. आर. 505 निर्दिष्ट  
को।

( ई ) इस तर्क में कोई बल नहीं है कि यह केवल राज्य सरकार है।

और केंद्र सरकार को नहीं जिसके तहत जांच का आदेश देने का अधिकार है  
एस. 3. एक प्राधिकरण की शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है। ( केंद्रीय  
सरकार) और दूसरी (राज्य सरकार), लेकिन जब तक कि शक्ति का प्रयोग न हो  
एक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया गया विवाद कानूनी अधिकार पर प्रभाव डालता है  
दूसरा पक्ष, बाद वाला अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आ सकता है। 131 और बस इतना कहें कि  
क्योंकि यह ऐसा करने की अपनी शक्ति के भीतर था, इसका कानूनी अधिकार अवैध द्वारा  
प्रभावित होता है

दूसरे पक्ष द्वारा शक्ति का प्रयोग। सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या  
आवश्यक निहितार्थ से दूसरे पक्ष के कानूनी अधिकार को प्रभावित करता है। मान लीजिए।

उदाहरण के लिए, यदि संसद प्रविष्टि 8 (मादक शराब) के तहत एक कानून पारित करती है।

सूची II और उस कानून के अनुसरण में, एक निवासी के खिलाफ एक आदेश देता है

राज्य, आदेश खराब है क्योंकि एक अमान्य कानून के तहत जारी किया गया है

संसद। ऐसे मामले में राज्य सरकार इसके तहत मुकदमा दायर नहीं कर सकती है।

कला. 131 केवल इसलिए कि आदेश इसके निवासी के खिलाफ एक के तहत किया गया था

कानून जो राज्य के विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करता हो। तत्काल मामले में, संबंधित मंत्री  
विवादित अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अधिसूचना ने  
किसी भी तरह से राज्य सरकार को प्रभावित या बाधित किया है

प्रभाव देने से लेकर इसकी अधिसूचना तक।

[ 125 बी; डी-जी] कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

15

( च ) इसके अलावा, यदि एक सीमित अर्थ के दायरे को नहीं दिया जाना था

मुकदमा जो कला के तहत दायर किया जा सकता है। 131 बहुत विसंगत परिणाम सामने आ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत या अन्यथा की गई कोई भी कार्रवाई

किसी राज्य में रहने वाले किसी भी नागरिक या किसी अधिकारी के खिलाफ, अनुच्छेद के तहत मुकदमा दायर करके चुनौती दी जा सकती है। 131 राज्य द्वारा इस आधार पर कि केंद्र सरकार की कार्रवाई अधिकार से बाहर है और बिना किसी कानूनी अधिकार के है। ए.

मन्त्री, राज्य का एक अधिकारी होने के नाते, उसे प्रभावित करने वाला आदेश अनुच्छेद के तहत राज्य को मुकदमे का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। 131. [ 126 बी-सी]

( बहुमत के साथ सहमति)

2 ( क ) अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है और न ही

क्या प्रावधान किसी भी कारण से संवैधानिक रूप से अमान्य हैं। [ 137 सी]

( बी )। भारतीय संविधान ऐसा नहीं है। चरित्र में संघीय, लेकिन चरित्रहीन रहा है

प्रकृति में अर्ध-संघीय के रूप में चित्रित। भले ही केंद्र और राज्यों के कार्यकारी और विधायी कार्यों को परिभाषित और वितरित किया गया है, लेकिन इसके माध्यम से दोनों क्षेत्रों में केंद्र के हाथों में एक धागा या लगाम है।

केंद्र और राज्यों की अनन्य विधायी शक्तियों के अलावा, दोनों के पास सूची III की प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां हैं। अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है (अनुच्छेद। 248, सूची I की प्रविष्टि 97)। समवर्ती सूची में मामलों के संबंध में संसद का एक प्रमुख हाथ है (कला। 254)। कुछ परिस्थितियों में, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है -

राज्य सूची के मामले (अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253)। अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत

सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हों। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जो कमजोर संघीय ढांचे और राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण हाथ को दर्शाती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद धारण करता है।

अपनी खुशी में। वह समय-समय पर राज्य के प्रशासन के बारे में केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। सूची III में प्रविष्टि 45 संसद को पूछताछ के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है। सूची-2 में निर्दिष्ट किसी भी विषय के प्रयोजन के लिए। संसद के पास संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है (अनुच्छेद। 2) और नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों और सीमाओं के परिवर्तन के लिए एक कानून बना सकता है यदि मौजूदा राज्य (अनुच्छेद। 3)। [ 128 ए-डी; 129 सी-ई]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। भारत संघ [1964] 1 एस. सी. आर. 371 निर्दिष्ट

को।

( ग ) सूची III की प्रविष्टि 45 के तहत बनाया गया कानून जांच को शामिल कर सकता है।

राज्य सरकार की किसी भी कार्यकारी कार्रवाई में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या कुशासन जैसे मामले। इस तरह की जांच न तो राज्य की विधायी शक्ति में हस्तक्षेप करती है और न ही इसकी कार्यकारी कार्रवाई में। अधिनियम के तहत उसके तहत नियुक्त आयोग द्वारा जांच, जो एक तथ्य खोजने वाला निकाय है, तथ्यों का पता लगाने के उद्देश्य से है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को किसी राज्य के मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्य खोजने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। [ 131 बी-सी)

( घ ) अधिनियम के तहत स्थापित जांच में कोई अभियोजन नहीं है, कोई ढांचा नहीं है।

एक औपचारिक आरोप, जांच आयोग के समक्ष कोई अभियुक्त नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी पर्यवेक्षी या अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य का कोई दुरुपयोग होता है। केंद्र केवल मुख्यमंत्री, मंत्री या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यों को जानने और उनका पता लगाने में रुचि रखता है। [ 132 ए-बी; सी]

( 3 ) यह कहना सही होगा कि राज्य सरकार के मंत्री हैं -

केंद्र सरकार के अनुशासनात्मक नियंत्रण में नहीं। लेकिन यह कहना असंगत और विसंगत होगा कि केवल राज्य सरकार ही अपने या अपने मंत्रियों के खिलाफ जांच आयोग नियुक्त करने में सक्षम है। यह संभावना नहीं है कि मंत्री, पद पर रहते हुए, अपने कथित कुकर्मों की जांच के लिए

जांच आयोगों का गठन करेंगे, भले ही यह माना जाए कि यह संभव है, यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि उनकी शक्ति अनन्य है और अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्ति को बाहर करती है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार की शक्ति अनन्य है। यह सह-व्यापक हो सकता है

)

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16

और ऐसी स्थिति को अभिनिर्धारित किया जाता है और एस के लिए परंतुक में प्रदान किया जाता है। 3 ( 1 ) अधिनियम से। अधिनियम या संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य के कथित कुशासन के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच आयोग का गठन करने की केंद्र सरकार की शक्ति को बाहर करता हो। तथ्यों को सुनिश्चित करने के बाद, संविधान या कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम में किसी मंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। [ 132 एफ-एच]

( 4 ) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है

राज्य के मंत्रियों को जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होने से रोकना। वास्तव में, यह एक राजनीतिक प्रथा से थोड़ा अधिक है जो अनिवार्य और अपरिहार्य है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों को बाध्य करते हैं, भले ही वे मंत्रिमंडल में विपरीत दिशा में तर्क देते हों, और यह कि टीम को इसके कुछ सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने से कमजोर नहीं होना चाहिए कि वे सरकार की नीति को अस्वीकार करते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि मंत्रिपरिषद को एक साथ खड़ा होना होगा या गिरना होगा, प्रत्येक सदस्य किसी अन्य की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। [ 134 ई]

" ए. एच. बिर्च द्वारा "प्रतिनिधि और जिम्मेदार सरकार"।

" सरकार और कानून "टी. सी. हर्टली और जे. ए. सी. गिरफ़िथ द्वारा।

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। बख्शी गुलाम मोहम्मद, [1966] पूरक।

एस. सी. आर. 401 संदर्भित।

( 5 ) सूची III की प्रविष्टि 45 के तहत संसद को दी गई शक्ति स्पष्ट है।

और सूची II के किसी भी मामले के संबंध में पूछताछ के लिए एक कानून पारित करने के लिए स्पष्ट। ऐसा होने पर, आई. एम. प्लाइड प्रोहिबिशन के सिद्धांत द्वारा शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है। निहित निषेध के सिद्धांत को निश्चित रूप से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के न्यायालयों द्वारा और केशवानंद भारती के मामले में इस न्यायालय के भारी बहुमत द्वारा खारिज कर दिया गया था। एकमात्र तरीका जिससे न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि विधायी शक्ति की निर्धारित सीमाओं को पार कर दिया गया था या नहीं, वह उस साधन की शर्तों को देखना है जिसके द्वारा सकारात्मक रूप से विधायी शक्ति का निर्माण किया गया था और जिसके द्वारा वे नकारात्मक रूप से प्रतिबंधित हैं। [ 136 ई ]

श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण, [1976] 2 एस. सी. आर. 347, वेब

वी. आउट्रिम \_ [1907] ए. सी. 81 द अमालगामेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स एंड द एडिलेड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड और अन्य, 28 राष्ट्रमंडल कानून रिपोर्ट, 129. द स्टेट ऑफ विक्टोरिया एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 122 राष्ट्रमंडल विधि रिपोर्ट, 353 और परम पूज्य केशवानंद भारती श्री पदगलवारू बनाम। केरल राज्य, [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1 संदर्भित।

( 6 ) इस तर्क में कोई सार नहीं है कि द्वारा नियुक्त आयोग

केंद्र सरकार का उसी मामले की जांच करना, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही एक आयोग का गठन किया जा चुका है, एस का उल्लंघन है। 3 ( 1 ) ( ख ) अधिनियम। राज्य सरकार की अधिसूचना में मुख्यमंत्री या सरकार के किसी अन्य मंत्री के कथित भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और कुशासन के मामलों की जांच के लिए कोई आयोग नियुक्त नहीं किया गया है। राज्य आयोग द्वारा जांच के लिए संदर्भित आइटम "अनुबंधों, ऋण अनुदान, स्थलों के आवंटन, फर्नीचर की खरीद, खाद्यान्न के निपटान आदि से संबंधित कुछ मामलों में की गई अनियमितताएं या अतिरिक्त भुगतान" थे। उन खंडों में से किसी में भी, क्या यह कथित अनियमितताओं या गलत प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वर्णित नहीं है। मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री के किसी भी कथित कदाचार, भ्रष्टाचार या कुशासन का कोई संदर्भ नहीं है। इसके विपरीत, केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में संदर्भ की शर्तें अनुलग्नक I में उल्लिखित विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए हैं, जिनमें से एक राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा कवर किया गया है। अनुलग्नक II में विशिष्ट मामलों के संबंध में, कुछ सामान्य मामले हो सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा जांच का विषय हैं, लेकिन अनुलग्नक II में मामलों के संबंध में, अधिसूचना में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की अधिसूचना में शामिल किसी भी मामले को शामिल

नहीं किया गया है। इसलिए, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ऐसे मामलों को अपनी जांच के दायरे से बाहर करने के लिए सक्षम होगा।

[ 137 ई-एफ] कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.)

17

प्रति कैलासम, जे. (सहमत)

1 ( क) सूट रखरखाव योग्य है। जब कार्यकारी कार्य का अभ्यास

अपने अधिकारियों के माध्यम से राज्य के राज्यों में केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप करती है हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य का कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है।

[ 168 जी; 167 ए]

( ख) राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की सहायता और सलाह से। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग किया जाता है। विवादित अधिसूचना के अनुसार जांच आयोग नियुक्त किया गया था

सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने का उद्देश्य,

अर्थात्, मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और शासन की मानसिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए।

राज्य से। इसलिए, जांच के दायरे में अनिवार्य रूप से राज्य की कार्यपालिका का कार्य शामिल होगा। तत्काल मामले में विवाद प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य के कामकाज से संबंधित है। संविधान के तहत और इसलिए राज्य के कानूनी अधिकार प्रभावित होते हैं। [ 166 डी-एफ]

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361 निर्दिष्ट।

( ग) भारत सरकार अधिनियम, 1858 में केवल पूर्ण साम्राज्य का प्रावधान किया गया था।

प्रशासन में किसी भी लोकप्रिय भागीदारी के बिना नियंत्रण। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार प्रांतों में द्वैतन्त्र की शुरुआत की।

इस अधिनियम के तहत प्रांत केंद्र और केंद्र के प्रतिनिधि थे।

विधायिका ने पूरे भारत के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति बरकरार रखी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने सरकार की एकात्मक प्रकृति को बदल दिया।

1919 के अधिनियम के तहत एक संघीय संरचना में विलय और प्रांतों को बनाया गया इकाइयों के रूप में। 1935 के अधिनियम ने केंद्र और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया।

प्रांत; संघीय सूची जिसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संघीय कानून है

लैचर के पास कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ थीं, प्रांतीय सूची में शामिल थे -

प्रांतीय विधायिकाओं के पास कानून बनाने की शक्ति थी। संविधान के तहत राज्य कई मामलों में केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं। संघ का गठन राज्यों और संघ के बीच किसी संधि के परिणामस्वरूप नहीं हुआ था। संविधान की विभिन्न विशेषताएँ हैं

जो इसे सख्ती से संघीय नहीं बनाते हैं। इसे विभिन्न रूपों में वर्णित किया गया है

संरचना में संघीय या संघीय या एक मजबूत केंद्रीय प्रणाली के साथ संघीय प्रणाली। में।

संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना, संघ के पक्ष में एक मजबूत झुकाव है। विवादों के निपटारे के लिए

केंद्र और राज्यों के बीच एक तंत्र भी प्रदान किया जाता है

स्वयं संविधान। [ 140 सी; 141 सी; 142]

(घ) यह निर्धारित करने में कि केंद्र और राज्यों की संबंधित शक्तियाँ क्या हैं।

हैं, संविधान पर गौर करना होगा। चूँकि राज्य डील नहीं हैं केंद्र सरकार के द्वार और संघ दोनों के लिए शक्ति का स्रोत

साथ ही राज्यों के संविधान होने के कारण, केंद्र सरकार कर सकती है

उन राज्यों पर किसी भी शक्ति का प्रयोग न करें जिनके लिए संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है।

ट्यूशन। केंद्र सरकार के पास कोई प्रमुख शक्ति नहीं है। [ 143 बी]

अतिबाड़ी चाय कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य और अन्य। [ 1961 ] 1 एससीआर 809,

ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य [1963] 1 एससीआर 491। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। भारत संघ [1964] 1 एस. सी. आर. 371 और केशवानंद भारती [1973] सप. एस. सी. आर. 1 संदर्भित।

( ई ) अनुच्छेद 254 (1) के तहत जब राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रावधान या किसी प्रावधान के साथ टकराव में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में किसी भी मौजूदा कानून का समवर्ती सूची, तब संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होगा और राज्य कानून तिरस्कार की सीमा तक शून्य होगा। [ 149 सी]

( च ) किसी कानून को अप्रिय घोषित करने से पहले यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि

क्या निर्माण द्वारा संघर्ष को टाला जा सकता है। [ 149 सी]

( छ ) सातवीं अनुसूची की सूची I में अनुच्छेद 248 (1) और प्रविष्टि 97

यह स्पष्ट है कि अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है और जब कोई मामला [1978] 2 एस. सी. आर.

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून बनाने के लिए सूची II या सूची III में शामिल नहीं है, संसद को उस मामले या कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन सूचियों का कार्य विधायिका को शक्तियां प्रदान करना नहीं है; वे केवल विधायी क्षेत्र का सीमांकन करते हैं। चूंकि संविधान में संघ को सूची के संदर्भ में राज्य के सरकारी कार्यों की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस मामले में उठाई गई समस्या का समाधान नहीं होगा। [ 149 सी-डी]

परिषद में गवर्नर जनरल v. रैले निवेश कंपनी [1944]

एफ. सी. आर. 229,261 और भारत संघ बनाम एच. एस. दिल्लीन [1972] 2 एस. सी. आर. 33 संदर्भित।

(ज) संविधान के निर्माण के सर्वमान्य बुनियादी सिद्धांत

जैसा कि तय किए गए मामलों द्वारा निर्धारित किया गया है कि जब कोई सवाल उठता है कि क्या निर्धारित सीमाओं को पार कर दिया गया है, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका उस साधन की शर्तों को देखना है जिसके द्वारा सकारात्मक रूप से विधायी शक्तियों का निर्माण किया गया था और जिसके द्वारा नकारात्मक रूप से वे प्रतिबंधित हैं। यदि जो किया गया है वह सकारात्मक शब्दों के सामान्य दायरे के भीतर कानून है जो शक्ति देता है, और यदि यह किसी स्पष्ट शर्त या प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है जिसके द्वारा वह शक्ति सीमित है, तो यह किसी भी न्यायालय के लिए आगे की जांच करने या उन शर्तों और प्रतिबंधों को रचनात्मक रूप से बढ़ाने के लिए नहीं है। यदि पाठ स्पष्ट है तो पाठ निर्णायक है। जब पाठ अस्पष्ट होता है, तो अधिनियम के संदर्भ और योजना का सहारा लिया जाना चाहिए। फिर भी एक और अच्छी तरह से स्वीकृत सहायता

निर्देश यह है कि किसी अधिनियम के पीछे का इतिहास कानून के अर्थ का पता लगाने के लिए स्वीकार्य है, कानून की पूर्व स्थिति के लिए वैध रूप से सहारा लिया जा सकता है, बुराई को दूर करने की मांग की जा सकती है और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कानून विकसित किया गया था। [ 150 एच; 151 ए]

(i) व्याख्या का सुनहरा नियम कि शब्दों को कॉन्स्टी में समझने में

कुछ अपवादों को स्वीकार करते हुए, विधायी शक्ति प्रदान करने वाली शिक्षा, सबसे उदार संरचना को शब्दों पर रखा जाना चाहिए। यदि दो अनन्य क्षेत्राधिकारों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए यह आवश्यक पाया जाता है तो शब्दों को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया जा सकता है। इसके अलावा, किसी कानून के शब्दों की व्याख्या करने में मुख्य उद्देश्य उपयोग किए गए शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए इरादे का पता लगाना है, यानी "इसे बनाने वालों के इरादे" का पता लगाना है। [ 154 एफ-जी]

आर. वी. बुराह [1878] 3 ए. सी. 889 और प्रांत के लिए महान्यायवादी

ऑटारियो और अन्य। वी. अटॉर्नी-कनाडा के डोमिनियन के लिए जनरल और एक अन्य [1912] ए. सी. 571 573 में, द अमालगामेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स बनाम। द एडिलेड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड और अन्य। 28 सी. एल. आर. 129, वेब बनाम. आउट्रिम

[ 1907 ] ए. सी. 81 विक्टोरिया राज्य v. द कॉमन-वेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 122 सी. एल. आर. 353, लियांज बनाम। आर. [1967] ए. सी. 259 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। निरिपेंद्र नाथ बागची [1966] 1 एस. सी. आर. 771 संदर्भित।

( जे ) अनुच्छेद 256 और 257 राज्यों और संघ के दायित्वों को सूचीबद्ध करते हैं।

और कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 (ए) (संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत) भारत सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने का अधिकार देता है। इन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, संविधान में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को कोई निर्देश देने का प्रावधान नहीं है। चूंकि संविधान में कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है जो केंद्र सरकार को राज्य के सरकारी कार्यों की जांच करने में सक्षम बनाता है, इसलिए सामान्य विधान द्वारा शक्ति ग्रहण नहीं की जा सकती है, लेकिन संवैधानिक संशोधन का सहारा लेना चाहिए। [ 152 सी-डी; एफ; एच ]

( के ) संविधान मौलिक कानून होने के कारण इसके तहत कोई कानून पारित नहीं किया गया है।

केवल विधायी शक्ति संविधान में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है जब तक कि संविधान में ही उस प्रभाव को व्यक्त करने की शक्ति नहीं दी गई हो। ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो स्पष्ट रूप से कानून द्वारा संविधान में संशोधन का प्रावधान करते हैं। लेकिन जहां संसद को कानून बनाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यह सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संविधान में नहीं जोड़ा जा सकता है। [ 153 बी-सी ]

आई. सी. गोलक नाथ और अन्य। वी. पंजाब और अन्र राज्य। [ 1967 ] 2 एस. सी. आर. 762

संदर्भित किया गया।

( 1 ) सूची III में प्रविष्टि 45 (पूछताछ. किसी भी उद्देश्य के लिए)

सूची II या सूची III में निर्दिष्ट मामलों को कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सीजे) के रूप में व्यापक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए।

19

केंद्र और राज्य सरकार को दूसरे द्वारा सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग की जांच शुरू करने के लिए एक प्रावधान लागू करने की शक्तियां प्रदान करना। [ 155 सी-डी]

रिवर वियर कमिश्नर बनाम। एडमसन [1877] 2 ए. सी. 743 743, आर. एम. डी.

चमरबागवाला बनाम। भारत संघ [1957] एस. सी. आर. 930 और बंगाल आई. एम. म्यूनिटी कंपनी लिमिटेड v. बिहार राज्य [1955] 2 एस. सी. आर. 603 संदर्भित।

( m) प्रविष्टि 45 सूची III के तहत प्रदत्त शक्ति का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता है -

ऐसा तरीका जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यदि संसद द्वारा अधिनियमित कोई कानून केंद्र सरकार को इसके दुरुपयोग की जांच करने का अधिकार देता है

राज्य सरकार के एक मंत्री द्वारा सरकारी कार्य, राज्य के पास सूची III के मामलों से संबंधित एक केंद्रीय मंत्री द्वारा सरकारी मानसिक शक्तियों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए इसे सशक्त बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। इस तरह की व्याख्या संघ और राज्यों के सामंजस्यपूर्ण कामकाज के लिए अनुकूल नहीं होगी। [ 155 डी-ई]

( एन) वे निर्णय जिन पर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव के लिए भरोसा किया

टियोर। कि "सार्वजनिक महत्व की निश्चित बात" शब्द राज्य के सरकारी कार्यों के दुरुपयोग की जांच को बढ़ावा देंगे, उस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं। एम. वी. राजवाडे बनाम डॉ. एस. एम. हसन और अन्य, जिन्हें आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था, केवल एक तथ्य-खोज निकाय था जिसका उद्देश्य सरकार के दिमाग को निर्देश देना था और जांच का दायरा एस के दायरे में आता था। 3 क्योंकि यह सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले से संबंधित है न कि किसी मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री के सरकारी कार्यों के दुरुपयोग की जांच से। श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर और अन्य ने यह अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तियों का कार्य और आचरण इतना खतरनाक हो सकता है जो सार्वजनिक कल्याण को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार सार्वजनिक महत्व का एक निश्चित मामला बन सकता है। लेकिन कोई भी निर्णय इस में उत्पन्न होने वाले बिंदु को समाप्त नहीं करता है।

मामला, अर्थात्, क्या "सार्वजनिक महत्व की निश्चित बात" शब्दों का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसमें राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के दुरुपयोग की जांच करने का अधिकार शामिल है। पुनः जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि एक व्यक्ति के कार्यों की जांच, जो मुख्यमंत्री नहीं रह गया था,

सार्वजनिक महत्व का विषय बना रह सकता है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पिछले कार्यों की जांच, जिन्होंने जनता के कल्याण को प्रभावित किया है, सार्वजनिक महत्व के मामले होंगे और यह अप्रासंगिक था कि क्या उन कार्यों को करने वाला व्यक्ति अभी भी सत्ता में था और उन्हें दोहराने में सक्षम था। [ 158 ए-एच ]

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य [1959]

एस. सी. आर. 279, जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम बख्शी गुलाम मोहम्मद, [1966] सप। एससीआर 401 और एम. वी. राजवाडे बनाम। डॉ. एस. एम. हसन और अन्य आई. एल. आर. [ 1954 ] नाग। 1 अप्रयोज्य रखा गया।

( असहमति )

2. विवादित अधिसूचना राज्य के अपने सीमित क्षेत्र में कार्य करने के अधिकार को बाधित करती है और एस के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों से परे है। 3 अधिनियम से। [ 168 जीजे ]

( ए ) यदि एस। 3 जाँच आयोग अधिनियम, 1952 का अर्थ एक प्रमुख के आचरण में जाँच आयोग की नियुक्ति के रूप में किया जाता है। मंत्री पद पर रहते हुए, इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार, जो संसद की प्रतिनिधि है, को उन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा जिन पर संसद ने कभी विचार नहीं किया होगा। इस तरह के निर्माण का परिणाम राज्य सरकार को सूची II और सूची III के मामलों के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों के संचालन की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करने के बराबर होगा। [ 161 एच ]

( ख ) परंतु के साथ पठित धारा 3 (1) यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम का उद्देश्य उपयुक्त सरकारों यानी केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से जांच आयोग नियुक्त करने में सक्षम बनाना है। केंद्र सरकार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I, सूची II या सूची III में उल्लिखित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संविधान की सूची II और सूची III में उल्लिखित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है। दोनों केंद्रीय सरकार [1978] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और राज्य सरकार के पास सूची II और सूची III में प्रविष्टियों से संबंधित जांच आयोग नियुक्त करने की शक्ति है, ऐसे अवसर उत्पन्न हो सकते हैं जब अतिव्यापी हो सकते हैं। इस तरह की आकस्मिकता से बचने के लिए प्रो विसोस (ए) और (बी) से एस। 3 ( 1 ) अधिनियम बनाते हुए कि जब केंद्र सरकार मूल रूप से एक जांच आयोग नियुक्त करती है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उसी मामले में एक और जांच आयोग नियुक्त नहीं करेगी, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग काम कर रहा है और केंद्र सरकार उसी मामले की जांच के लिए एक अन्य आयोग नियुक्त नहीं करेगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग काम कर रहा है। ये प्रावधान एक ही मामले की जांच के लिए दो अलग-अलग आयोगों की नियुक्ति करने वाली दोनों सरकारों द्वारा किसी भी संघर्ष से बचने के उद्देश्य से हैं। [ 163 डी-ई]

( ग ) तत्काल मामले में न्यायालय को दो अधिसूचनाओं में जाने और यह निर्धारित करने के लिए नहीं कहा जाता है कि केंद्र की अधिसूचना में कौन सी वस्तु है।

सरकार राज्य सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती है। [ 168 जी]

मौलिक न्यायनिर्णय: 1977 का मूल सूट संख्या 8।

एल. एन. सिन्हा, आर. एन. बायरा रेड्डी, अधिवक्ता। जनरल।, वादी की ओर से एस. सी. अग्रवाल, वीनू भगत और नारायण नेत्तर।

एस. एन. कक्कर, सॉलिसिटर जनरल, सोली जे. सोराबजी, अतिरिक्त महान्यायवादी। सॉलिसिटर जनरल, आर. एन. सचथे, ई. सी. अग्रवाल और गिरीश चंद्र, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

निम्नलिखित निर्णय दिए गए:

बी. ई. जी, सी. जे. - " भारत, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद का पहला अधिदेश जिसके लिए हम

विधायी और कार्यकारी शक्ति ", और, दूसरी बात, कि यदि अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार की अधिसूचना को शामिल करते हैं, तो वे हैं - "संविधान की शर्तों के साथ-साथ संघीय संरचना के अंतर्निहित और संविधान की एक अलंघनीय बुनियादी विशेषता के रूप में स्वीकार किए जाने" के उल्लंघन के लिए अधिकार से परे है। परिणामस्वरूप, वादी "कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और सरकारी मानसिक शक्ति के दुरुपयोग" के आरोपों की जांच करने वाले एक सदस्यीय आयोग, भारत संघ

और श्री ए. एन. ग़्रोवर को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत कार्य करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करता है।

कर्नाटक बनाम। यूनियन (बेग, सी. जे.)

21

वादी राज्य का मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी को वापस कर दिया गया था

1972 में राज्य में हुए चुनाव में मतदाताओं द्वारा बहुमत से; कि विधानमंडल में बहुमत पार्टी ने श्री देवराज उर्स को अपने नेता के रूप में चुना, जिन्होंने तब अनुच्छेद 163 के अनुसार अपनी सरकार का गठन किया।

संविधान की; कि, इस प्रकार स्थापित सरकार, जिसे राज्य विधानमंडल की इच्छा और निर्णय माना जाना चाहिए,

हाल के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में श्री देवराज उर्स ने 26 में से जीत हासिल करके शानदार सफलता हासिल की।

28 सीटों में से ताकि जनता पार्टी, जो केंद्र में सत्ता में है,

यह माना जाना चाहिए कि मतदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन यह है

सीधे, राज्य में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करने वाले केंद्रीय जांच आयोग की नियुक्ति के माध्यम से

कर्नाटक, और, इस प्रकार, लोकतांत्रिक तंत्र में हस्तक्षेप करना द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार का नियंत्रण और पर्यवेक्षण

स्वयं संविधान।

26 अप्रैल, 1977 को केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा।

राज्य के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक राज्य विधानमंडल में विपक्षी दल के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक ज्ञापन में निहित आरोपों को संप्रेषित करते हुए उन्हें अपनी टिप्पणी करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने 13 मई, 1977 को एक उत्तर दिया जिसकी एक प्रति शिकायत के साथ संलग्न की गई थी।

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में शिकायत की है कि "निंदात्मक प्रोपा"

गंडा को अधिकांश आरोपों की सच्चाई या अन्य विवेकपूर्ण आरोपों या पिछले इतिहास के किसी भी सत्यापन के बिना जारी किया गया है। वे बताते हैं कि प्रसारण और प्रेस रिपोर्टों ने उन्हें गृह मंत्री के पत्र के साथ प्राप्त होने से पहले ही उन्हें भेजे गए आरोपों की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा: यह मानना उचित है कि बदनामी के इस अभियान का उद्देश्य मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, मेरे सहयोगियों और मेरी छवि को धूमिल करना है, ताकि हाल के लोकसभा चुनावों में राज्य के मतदाताओं द्वारा आपकी पार्टी को पूरी तरह से खारिज किए जाने के तुरंत बाद, यदि संभव हो, तो राज्य में आपकी पार्टी के लिए सत्ता हासिल करने का प्रयास किया जा सके। आक्षेप यह था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जोड़-तोड़ के आरोपों का पूरा उद्देश्य उन्हें और उनकी सरकार को बदनाम करना था।

कांग्रेस पार्टी को राज्य के लोगों से जो समर्थन मिला था, उसे नष्ट करने के लिए उसे जनता के आकलन में नीचा दिखाया गया। इस प्रकार यह वास्तव में द्वेष का आरोप था।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह को लिखे अपने पत्र में यह भी स्वीकार किया

कहा जाता है कि वे हमारे संविधान में सन्निहित हैं और उन्हें "राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता की आधारशिला" के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा: संविधान केंद्र और राज्य के विभिन्न अंगों के लिए सभी शक्तियों का स्रोत है और इसके तहत सभी कार्यों और सभी शक्तियों का प्रयोग करता है।

केंद्र या राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संविधान की संघीय योजना के तहत विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के वितरण की योजना के अनुरूप होना चाहिए और उसके अधीन होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह को लिखे अपने पत्र में भी स्वीकार किया

मंत्री, कि संविधान "कुछ असाधारण परिस्थितियों में [1978] 2 एस. सी. आर. के पक्ष में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई असाधारण परिस्थितियाँ,  
द्वारा हस्तक्षेप के लिए, तत्काल मामले में मौजूद था।

केंद्र

जाहिर है, मुख्यमंत्री का मतलब था कि इसके लिए कोई जगह नहीं थी

जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी की धारणा के लिए प्रावधान करता है  
सरकार के कार्य और संघ की संसद द्वारा

राज्य विधानमंडल के कार्य, बशर्ते "राष्ट्रपति संतुष्ट हो

किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा कि

ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार नहीं हो सकती है

संविधान के संदर्भ में किया गया "।

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन के सिद्धांतों की सहायता का भी आह्वान किया

जो उनके अनुसार, संविधान की पूरी योजना में व्याप्त है, ताकि मुख्यमंत्रियों और अन्य राज्य  
मंत्रियों को केवल उस राज्य विधानमंडल द्वारा जवाबदेह ठहराया जा सके जिसके लिए वे  
जिम्मेदार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि "सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली एक बुनियादी विशेषता  
है।

भारतीय संविधान "। उनके अनुसार, इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिस्तरीय कार्यों पर सभी  
नियंत्रण केवल राज्य विधानमंडलों में निहित हैं और केंद्र सरकार में नहीं, बेशक, अपवादों के  
अधीन।

स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया। राज्य सरकार की कार्यवाहियों के संबंध में, उन्होंने शिकायत की  
कि केंद्र सरकार द्वारा जांच या पर्यवेक्षी कार्यों की धारणा "एक अतिरिक्त सहायक एजेंसी, चाहे  
वह कितनी भी उच्च क्यों न हो, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के मूल चरित्र को नष्ट कर देगी  
और राज्य के विधानमंडल और उसके लोगों को उनकी पसंद की सरकार रखने के संवैधानिक रूप से  
गारंटीकृत अधिकार से वंचित कर देगी।" उन्होंने दावा किया कि राज्य को "संविधान के तहत  
राज्य के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आने वाले" मामलों से संबंधित आरोपों की जांच करने का  
विशेष अधिकार है। उन्होंने संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय योजना में अनुचित हस्तक्षेप करके  
राष्ट्रीय हित के लिए खतरों के खिलाफ चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्होंने

उनके खिलाफ कार्यवाही का उद्देश्य माना जाता है और उनके विपक्ष के अधिकार, उन 36  
आरोपों पर असर डालने वाली सभी सामग्री को रखने के लिए बहुत ही उचित रूप से प्रस्तुत

किए गए, जिनमें से उन्होंने स्वीकार किया कि 23 उनसे संबंधित हैं। उन्होंने इन आरोपों से खुद को मुक्त करने की पेशकश की। उन्होंने बताया कि उनके सहयोगियों से संबंधित 4 आरोपों पर विधायिका में चर्चा की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही 3 आरोपों की जांच कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि इन्हें फिर से खोला जाए। उन्होंने 5 मई 1976 को लोकसभा में पूर्व राज्य मंत्री श्री ओम मेहता के भाषण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कुछ ज्ञापन भेजे गए थे, जिनमें बहुत पहले 1973 में विधानसभा के कुछ सदस्यों द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। उस बयान के अनुसार, 99 आरोप थे जिनमें से 16 मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से संबंधित थे। कहा जाता है कि श्री मेहता ने घोषणा की थी कि तय प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों में तथ्य की कमी पाई गई थी।

कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

23 .

मुख्यमंत्री से आमंत्रित टिप्पणियां देखी गई थीं। मुख्यमंत्री ने तब व्यक्ति के साथ काफी विस्तार से व्यवहार किया

शुल्क लेते हैं।

हमारे समक्ष वाद में, यह इंगित किया गया था कि प्रकृति के आरोप

अब केंद्र सरकार द्वारा एक व्यक्ति आयोग को भेजा गया है

1972 के चुनावों के बाद से दोनों विधान सभा के पटल पर बने हुए थे प्रकृति और कहीं और। इसने यह भी कहा कि उन्हें समझाया गया था और

बार-बार विधानमंडल के पटल पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने

शिकायत की कि एक नए आरोप के बाद वही आरोप दोहराए गए थे

सरकार ने केंद्र में पदभार ग्रहण कर लिया था।

शिकायत में यह भी कहा गया था कि किसी भी संदेह को दूर करने के लिए

राज्य में जनता के मन में, और, जारी रहने को देखते हुए

न्यायिक जाँच के लिए आंदोलन, और, उच्चतम के अनुसार और सर्वोत्तम परंपराएँ, राज्य सरकार, एक अधिसूचना द्वारा,

सरकार की

दिनांक 18 मई, 1977 के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया गया

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1)। की एक प्रति साथ राज्य सरकार की अधिसूचना संलग्न की गई थी।

शिकायत के

आरोप था कि इसकी एक प्रति गृह मंत्री को भी भेजी गई थी

18 मई, 1977 को।

वादी की दलीलों में से एक यह है कि राज्य सरकार

18 मई, 1977 की अधिसूचना, जिसके लिए अपना आयोग नियुक्त किया गया है सभी मामलों और अनियमितताओं की जांच करें, जिनमें परिवर्धन हो सकते हैं।

जिसके बारे में और अधिक जानकारी दी जा सकती है, उसमें सभी शामिल हैं।

जिसकी सूचना के तहत ग़्रोवर आयोग द्वारा जांच की जा सकती है 23 मई, 1977 का अधिसूचना, जिसमें विशेष रूप से मामले शामिल नहीं हैं

18 मई की कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत,

1977. रिलायंस को अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रावधान (बी) पर रखा गया है।

जो केंद्र सरकार को किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करने से रोकता है

मिशन "आयोग के रूप में लंबे समय के लिए एक ही मामले में जांच करने के लिए

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति तब तक कार्य कर रहा है जब तक कि केंद्रीय

सरकार की राय है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए

दो या दो से अधिक राज्यों को "।

भारत संघ की ओर से दायर लिखित बयान में कहा गया है

2 पैरा के क्रमवार जवाब देने से पहले निम्नलिखित प्रारंभिक आपत्तियाँ

शिकायत में ग्राफ। प्रारंभिक आपत्तियाँ इस प्रकार हैं:

" 1. कर्नाटक राज्य का मुकदमा कायम नहीं है।

आक्षेपित अधिसूचना एस. ओ. संख्या 365 (ई) के रूप में सक्षम दिनांक 23 मई 1977 को जांच आयोग का गठन किया गया

वादी-राज्य को प्रभावित नहीं करता है। आक्षेपित अधिसूचना द्वारा

आयोगों की धारा 3 के तहत जांच आयोग इस उद्देश्य के लिए जांच अधिनियम, 1952 का गठन किया गया है।

भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के आरोपों की जांच करना,

सरकार के खिलाफ पक्षपात और सरकारी शक्ति का दुरुपयोग

मुख्यमंत्री और राज्य के कुछ अन्य मंत्री कर्नाटक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है। जाँच इसके खिलाफ है

मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से

और कर्नाटक राज्य के खिलाफ नहीं। पूछताछ, बल्कि मैं हूँ

सी.

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24

ए.

राज्य के हित में कि इस तरह का भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, लाभप्रद हो

राज्य में अनुष्ठान का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कर्नाटक राज्य

प्रस्तावित जाँच में प्रत्यक्ष रूप से रुचि नहीं है

मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ

एफ.

राज्य। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति

और मंत्री स्वयं राज्य से अलग होते हैं।

. बी.

2.- भारत के संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों आदि के बीच किसी भी विवाद शर्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, यदि विवाद में कानून या तथ्य का कोई प्रश्न शामिल है या जो कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। भारत सरकार और राज्य के बीच कोई विवाद नहीं होने के कारण यह मुकदमा विचारणीय नहीं है। कोई कानूनी अधिकार नहीं है

सी:

वादी-वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए राज्य। .

भारत संघ ने इस बात से इनकार किया कि ग़ोवर आयोग द्वारा अब जिन मामलों की जांच की जानी है, वे पिछले आरोपों और आरोपों को पुनर्जीवित करते हैं जिनका निपटारा कर दिया गया था। जांच आयोग की संस्था में दुर्भावना से इनकार किया जाता है। अधिनियम के सभी प्रावधानों की वैधता का दृढ़ता से बचाव किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डी का आदेश दिया गया जांच काफी सक्षम है और राज्य सरकार की अधिसूचना में शामिल नहीं है। इस बात से इनकार किया जाता है कि संविधान में सन्निहित संघीय योजना या लोकतांत्रिक सिद्धांत इस तरह के जांच आयोग की स्थापना से प्रभावित होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार के जांच आयोग को एक उचित और पूरी तरह से निष्पक्ष तथ्य खोजने की प्रक्रिया को सक्षम बनाने का आदेश दिया गया था ताकि केंद्र सरकार में से कोई भी

ई.

या कोई अन्य प्राधिकारी या यहाँ तक कि जनता के सदस्य भी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार, इस तरह से कार्य कर सकते हैं जो संविधान है; उचित और पूरी तरह से उचित है। किसी भी मामले में, राज्य के मामलों के संबंध में किसी राज्य के मुख्यमंत्री का आचरण और जिस तरह से उन्होंने अपने आधिकारिक पद का उपयोग किया, केंद्र सरकार के अनुसार, सार्वजनिक महत्व के ऐसे मामले थे जिनमें केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष तथ्य खोजने की जांच का आदेश देने में काफी सक्षम थी।

एफ.

ब्याज।

अभिवचनों के उपरोक्त समूह पर, निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया गया था -

यह न्यायालय:

- " 1. क्या सूट रखरखाव योग्य है?
2. क्या विवादित अधिसूचना के अधिकार समाप्त हो गए हैं?

जी.

कॉम मिशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार?

3. यदि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को विवादित अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेरित करती है, तो क्या यह धारा स्वयं असंवैधानिक है।

कारणों से तय किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रश्न

एच.

पहले से ही इंगित, दो जांचों की प्रकृति से संबंधित है, एक राज्य सरकार द्वारा और दूसरी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। यदि दोनों अधिसूचनाओं में काफी हद तक "एक ही मामले" को शामिल किया गया है, तो यह कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) हो सकता है।

25

अन्य प्रश्नों से निपटना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पक्षों ने इस प्रश्न पर अपने मामलों पर पूरी तरह से तर्क दिया है, भले ही इस पर कोई अलग या विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया गया हो। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलों में इस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया है। उन्होंने इस धारणा पर तर्क दिया है कि इस पर निर्णय मामले में अन्य मुद्दों के मुकदमे में निहित है। इसलिए, हम इसे पहले एक प्रारंभिक प्रश्न के रूप में अलग से उठाएंगे, जिसे हमें अन्य मुद्दों को उठाने से पहले तय करना चाहिए। इस प्रश्न के निर्धारण का उपरोक्त बनाए गए तीन मुद्दों में से प्रत्येक को तय करने के उद्देश्यों के लिए तर्क किए गए मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भले ही प्रश्न ऊपर बनाए गए तीन मुद्दों में से प्रत्येक के निर्णय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन पूरे मामले में सही दृष्टिकोण के लिए आधार को स्पष्ट करने के लिए इस पर निर्णय लेना आवश्यक लगता है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर हम केवल

इसलिए निर्णय लेने से बच सकते हैं क्योंकि शुरुआत में इस पर कोई विशिष्ट मुद्दा अलग से नहीं बनाया गया था। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न को मुद्दे में रखा गया है और पार्टियों द्वारा पूरी तरह से समझा और बहस की गई है, इस पर एक अलग और विशिष्ट मुद्दा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी, इसके महत्वपूर्ण महत्व के कारण, हम इसे अब अलग से और विशेष रूप से निम्नानुसार तैयार करते हैं: क्या राज्य और केंद्र सरकार दोनों की पूछताछ अधिनियम की धारा 3 (1) के परंतुक (बी) के अर्थ के भीतर 'एक ही मामले' से संबंधित है ताकि केंद्र या केंद्र सरकार द्वारा जांच पर रोक लगाई जा सके जब तक कि राज्य आयोग काम कर रहा है? राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18-5-1977, निम्नानुसार है:

" कर्नाटक सरकार "

कर्नाटक सरकार सचिवालय

विधान

सौध

बैंगलोर, 19 मई,

1977

सूचना

जहाँ सदनों के पटल पर आरोप लगाए गए हैं

संघ से संबंधित कुछ मामलों में किए गए प्रतिबद्ध/अतिरिक्त भुगतान  
का अनुदान, स्थलों का आवंटन, फर्नीचर की खरीद, निपटान

भूखंड, भूमि

खाद्यान्न आदि:

जबकि राज्य सरकार की राय है कि इसकी आवश्यकता है

उक्त आरोप की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए श्री

गैशन:

अब, इसलिए, उप द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की धारा (1)

( 1952 का केंद्रीय अधिनियम 60) कर्नाटक सरकार एतद्द्वारा

न्यायमूर्ति श्री मीर इकबाल हुसैन, कर्नाटक के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

उच्च न्यायालय कथित आरोपों की जांच करने के उद्देश्य से जांच आयोग होगा, विशेष रूप से नीचे निर्दिष्ट और एक अवधि के भीतर राज्य सरकार को उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

इस अधिसूचना की तारीख से चार महीने:

[ 1978

] 2 एससीआर।

26

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

I. मेसर्स को अनुचित या अत्यधिक भुगतान किया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा उन्हें दिए गए अनुबंधों के संबंध में निर्मला इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी और

लिफ्ट सिंचाई के लिए कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड

गैशन या जलापूर्ति योजना?

II. क्या मेसर्स को कोई अनुचित या अत्यधिक भुगतान किया गया था। बालाजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिमिटेड, उन्हें दिए गए अनुबंधों के संबंध में

( 1 ) हेमवती परियोजना के दाहिने किनारे पर मिट्टी के बांध का निर्माण श्रृंखला संख्या 7890 से 8510 तक।

( 2 ) नदी के दाहिने किनारे पर सिंचाई जलमार्ग का निर्माण

हेमवती बांध;

( 3 ) के बाएँ तट सिंचाई जलमार्ग का निर्माण

हेमवती बांध;

( 4 ) श्रृंखला संख्या 4400 'से 5740' तक हेमवती परियोजना के चिनाई बांध का निर्माण जिसमें अतिप्रवाह खंड और सुरक्षात्मक कार्य शामिल हैं;

( 5 ) हेमवती के स्पिलवे बांध का निर्माण

परियोजना;

( 6 ) हारंगी के चिनाई बांध का निर्माण

परियोजना?

III. क्या कोई अनुचित या अत्यधिक भुगतान किया गया था या मेसर्स को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। चेनेज 2025 मीटर से हेमावती राइट बैंक अर्थ डैम के निर्माण के लिए उन्हें दिए गए अनुबंध के संबंध में नेचिपदम कंस्ट्रक्शन कंपनी। 2405 मीटर तक। और चेनेज 1750 मीटर। 2025 मीटर तक?

IV. क्या कोई अनुचित या अत्यधिक भुगतान किया गया था या मेसर्स को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। शंकरनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए उन्हें दिए गए अनुबंधों के संबंध में

( 1 ) संयुक्त बोर्ड प्रशासनिक का निर्माण

प्रभाग भवन;

( 2 ) दोनों में हिडकल बांध के दाहिने किनारे के मिट्टी के हिस्से का निर्माण 10,000 से 11,000 तक पहुंच गया है।

और 11,100 से 14,700?

V. क्या कोई अनुचित या अत्यधिक भुगतान किया गया था या मेसर्स को अनुचित पक्ष दिखाया गया था। ई. आई. सी. आई. एल. ने उन्हें दिए गए अनुबंधों के संबंध में

( 1 ) बम से हेड रेस सुरंग का निर्माण

मानहल्ली बांध को उछाल बिंदु तक ले जाता है;

( 2 ) सर्ज टैंक और प्रेशर शाफ्ट का निर्माण?

VI. क्या मेसर्स को कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। घनश्याम कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, 25,000 टन बाजरे की बिक्री में रु। 73.50 , 1972 में प्रति क्विंटाल?

पी. कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

VII. क्या मेसर्स को कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। कृष्ण आटा मिलें अपने परिसर के बगल में भूमि के पट्टे के संबंध में, 30 साल की अवधि के लिए 200 'x 200' मापने के लिए?

VIII. क्या कोई अनुचित या अत्यधिक भुगतान किया गया था या मेसर्स को कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। शाह कंस्ट्रक्शन कॉम अलमट्टी बांध के निर्माण के लिए उन्हें दिए गए अनुबंध के लिए अपने दावों के निपटारे में लगी हुई है?

IX. क्या मेसर्स को कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। पूर्णिमा बिजली की आपूर्ति के लिए उन पर ऑर्डर देने में इलेक्ट्रॉनिक्स दीर्घकालिक उपकरण जैसे इंटरकम आदि।

X. क्या इसमें कोई अनापत्ति या धोखाधड़ी हुई थी राज्य सहकारी विपणन संघ के दौरान सौदे अवधि 1971-72 और 1972-73?

XI. क्या इसके द्वारा कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया है इमारत का नेतृत्व करने में सरकार या के. एस. टी. आर. सी. मैसूर में कैटीन के लिए मैसूर में केएसआरटीसी बस स्टैंड?

बारहवीं। क्या सरकार द्वारा कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था या के. एस. टी. आर. टी. सी. में विश्राम कक्षों को पट्टे पर देने में के. एस. टी. आर. सी. मैसूर से श्री प्रेम कुमार?

तेरहवीं। क्या कृषि उद्योग निगम की निधियाँ गलत तरीके से गडग सहकारी कपड़ा मिलों को भेज दिया गया, हुलकोटी, गडग, धारवाड़ जिला?

XIV। क्या मेसर्स को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। नवरसा

उर्वरक खरीद में उर्वरक और क्या भुगतान किया गया था बिना भी बनाया गया?

स्टॉक की प्राप्ति के

XV. क्या जे. सी. रोड पर जगह थी

श्री एम. बी. को

पट्टे पर दिया गया

लाल और एन. वी. वेंकटप्पा इसके विपरीत

शहर के हित

बैंगलोर नगर निगम का?

सोलहवाँ। क्या बोमेना की धारा संख्या 15 में भूमि का अनुदान हाली गाँव, नेलमंगला तालुक, बैंगलोर जिला बनाया गया था नियमों के विपरीत?

XVII। राजमहल विलास और पैलेस ऑर्चर्ड में क्या स्थान हैं लेआउट अनियमित रूप से आवंटित किए गए थे?

अठारवाँ। क्या एक हजार टन की खरीद श्री अतीक अहमद, मालिक, तमिलनाडु से धान राज्य के कहने पर मांड्या राइस मिल्स, मांड्या सरकार और उसके बाद के निपटान प्रतिकूल थे - राज्य के हित?

XIX। क्या मॉडल तैयार करने के लिए अनुबंध और के. आर. मार्केट, बैंगलोर के री-मॉडलिंग के लिए डिज़ाइन मेसर्स को अनियमित रूप से सम्मानित किया गया था। कारेकर और सुंदरम?

3-1042

एससीआई/77 [1978] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28

XX. क्या श्री सी. एम. के स्वामित्व वाली भूमि का रूपांतरण।

बैंगलोर उत्तरी तालुक के नरसीपुरा गाँव में दिनशाँ और उनका परिवार ( 'दिनशाँ एस्टेट' के रूप में जाना जाता है) क्योंकि गैर-कृषि भूमि में नहीं था नियमों के अनुसार?

XXI। क्या कोई अनियमितताएँ या अनियमितताएँ हुई हैं कर्नाटक फिल्म विकास के प्रशासन में प्रतिबद्ध 1971 से निगम?

निर्माण के लिए आवंटित

XXII। चाहे सीमेंट हो या स्टील।

सरकारी हरिजन छात्रावास

बैंगलोर में इमारत

शहर को अन्य उद्देश्यों की ओर मोड़ दिया गया था?

XXIII। क्या फर्नीचर की खरीद के लिए आदेश वर्षों के लिए स्वास्थ्य विभाग 1972-73, 1973-74 रखा गया था उन फर्मों के साथ अत्यधिक दरों पर जो न तो फर्नीचर विक्रेता थे न ही अनुमोदित पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं?

XXIV। क्या स्टेइनलेस स्टील के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र इस अवधि के दौरान फर्जी फर्मों या काल्पनिक व्यक्तियों को जारी किए गए थे।

1 मार्च 1974 से 30 जून 1974 तक?

XXV। क्या फार्गो और बेडफोर्ड चेसिस की खरीद अगस्त 1972 में केएसआरटीसी द्वारा निगम के खिलाफ था रुचियाँ?

XXVI। क्या अभिकर्ताओं, उप-अभिकर्ताओं की नियुक्तियाँ और विश्वेश्वरैया आयरन द्वारा वर्षों 1967-77 के दौरान विक्रेता और सीमेंट के वितरण के लिए स्टील लिमिटेड, भद्रावती स्टील और क्या वे कंपनी के हितों के प्रतिकूल थे?

XXVII। क्या अभिकर्ताओं, उप-अभिकर्ताओं की नियुक्तियाँ और मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा वर्षों के लिए डीलर 1967-77, पेपर के वितरण के लिए भद्रावती कॉम के लिए प्रतिकूल थे पैनी की रुचियाँ?

XXVIII। क्या अनुचित या अत्यधिक भुगतान किया गया था श्री एम. एस. रमैया, ठेकेदार को अनुबंध के संबंध में तालाकाले बांध के निर्माण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और शरवती घाटी का हिस्सा हैं सहायक कार्य, जो परियोजना।

XXIX। क्या निर्माण में कोई दोष थे खराब डिजाइन, उप-मानक सामग्री के उपयोग के कारण तालाकाले बांध ठेकेदार की लापरवाही या जानबूझकर कमीशन के कारण या कोई भी व्यक्ति?

XXX। क्या अन्यायपूर्ण या अत्यधिक भुगतान किया गया था एम/एस। उन्हें दिए गए अनुबंध के संबंध में तारापुर एंड कंपनी लिंगन्ना मक्की मिट्टी के बांध में ऊपर और नीचे दोनों धाराओं में चट्टान भरने का काम?

XXXI। क्या इसमें कोई अनियमितता या अनुचितता थी

पेरियापटना तालुक में मेसर्स को 3000 एकड़ भूमि का अनुदान।

ओरिएंटल एरोमेटिक्स?

कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

29

XXXII। क्या श्री भूमा पर कोई अनुग्रह किया गया था शराब की खुदरा बिक्री का अधिकार देने के मामले में रेड्डी 1968 में?

XXXIII। चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं, यदि उपरोक्त के संबंध में कोई और किस हद तक?

आदेश द्वारा और के नाम पर

कर्नाटक के

राज्यपाल।

एस. डी./- जी. वी.

के. आर. ए. ओ,

सरकार के मुख्य सचिव

को।

इस अधिसूचना के प्रकाशन के लिए संकलक, कर्नाटक राजपत्र राजपत्र में असाधारण विवरण और 200 प्रतियों की आपूर्ति।

प्रतिलिपि बनाएँ:

सरकार के सभी सचिव,

पंजीयक, कर्नाटक उच्च न्यायालय एक आवरण के साथ

पत्र "।

केंद्र सरकार की अधिसूचना dt. 23-5-1977 के रूप में पढ़ें

निम्नलिखित है:

" भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-2-भाग-3-उप-भाग-2

गृह मंत्रालय

कार्मिक विभाग और ए. आर.

सूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1977

S.C.365 (ई)-जहां केंद्र सरकार की राय है कि सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, अर्थात्, मुख्यमंत्री और कर्नाटक राज्य के कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात या सरकारी शक्ति के दुरुपयोग के आरोप, इसके बाद निर्दिष्ट किए गए हैं;

इसलिए अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय

सरकार एतद्वारा एक जांच आयोग की नियुक्ति करती है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री ए. एन. ग्रोवर नामक एक सदस्य होता है।

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30

2. आयोग के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार होंगी -

निम्नलिखित है:

(क) निम्नलिखित आरोपों की जांच करना, अर्थात्:

(i) ऐसे आरोप। ज्ञापन में निहित

दिनांक 11 अप्रैल, 1977, कुछ मेम से प्राप्त हुआ  
कर्नाटक राज्य विधानमंडल के सदस्य और संबोधित  
प्रधान मंत्री को, जैसा कि अनुलग्नक I में निर्दिष्ट किया गया है;

(ii) ज्ञापन में निहित ऐसे आरोप

जैसा कि अनुलग्नक II में निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन इसमें

शामिल नहीं हैं

अधिसूचना द्वारा कवर किया गया कोई भी मामला

मुख्य सचिवालय में कर्नाटक सरकार

नहीं। डी. पी. ए. आर. 7 जी. ए. एम. 77 दिनांक 18 मई,

1977;

(ख) किसी भी अनियमितता, अनुचितता या उल्लंघन की जांच करना।

उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कानूनों के अलावा अन्य कानून

कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से

में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी व्यक्ति का भाग

उपरोक्त आरोप;

(ग) किसी अन्य मामले की जांच करना जो उत्पन्न होता है, या है

किसी कार्य, चूक या उससे संबंधित या आनुषंगिक

उपरोक्त आरोपों में निर्दिष्ट लेन-देन;

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के अनुलग्नक में, "मुख्य

मंत्री "का अर्थ है श्री देवराज उर्स, मुख्यमंत्री

कर्नाटक राज्य ।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. आयोग अपनी जांच पूरी करेगा और आयोग को रिपोर्ट देगा ।

1 दिसंबर, 1977 को या उससे पहले केंद्र सरकार ।

5. और जबकि केंद्र सरकार की राय है कि

आयोग द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति के संबंध में

और मामले की अन्य परिस्थितियाँ, कि उप के सभी प्रावधान

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की धारा (2), उप-धारा (3),  
उप-धारा (4) और उप-धारा (5)

आयोग पर लागू किया जाना चाहिए, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करने का निर्देश देती है ।

( 1 ) उक्त धारा 5 के, कि उक्त उप-धारा के सभी प्रावधान

उस धारा की धारा (2), (3), (4) और (5) कॉम मिशन पर लागू होगी ।

अनुलग्नक I

1. क्या मुख्यमंत्री पक्षपात और भाई-भतीजावाद करते थे

अपने ही भाई श्री डी. कम्पराज उर्स को 1974 में सरकार के मुख्य सचिव श्री आर. जे. रेबेलो  
के स्थान पर कर्नाटक राज्य फिल्म उद्योग विकास निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया  
और बाद में प्रबंध निदेशक की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निदेशक-प्रभारी के रूप  
में नियुक्त किया गया ।

2. क्या मुख्यमंत्री ने उत्पाद शुल्क की नीलामी का निर्देश दिया था

हाल ही में हुए लोकसभा कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) की पूर्व संध्या पर पांच जिलों में  
दुकानें बंद

31

फरवरी, 1977 के महीने में चुनाव, भ्रष्ट उद्देश्यों के साथ, हालांकि नीलामी मई, 1977 के महीने में होनी थी, और क्या यह चुनाव के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से किया गया था।

3. क्या मुख्यमंत्री ने रुपये जारी किए थे। 50.60 लाखों में

मुख्यमंत्री के अध्यक्ष के तहत इस उद्देश्य के लिए गठित उप-समिति के निर्णय पर आई. बी. एच. से "विज्ञान की समझ" खरीदें और संबंधित मंत्री के आदेशों पर भी निर्णय लें।

4. क्या मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों को बचाने का दोषी था,

विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारी,

श्री शेषगिरी राव, सहायक अभियंता और श्री शिवन्ना, एक क्लर्क, जिनके खिलाफ सतर्कता आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अभियोजन आदेश पारित किए गए थे। क्या मुख्यमंत्री ने अपने दम पर आदेश को संशोधित किया और किसी भी विचार के लिए अभियोजन वापस ले लिया।

5. क्या श्री हनुमंत रेड्डी, अधीक्षण अभियंता,

सतर्कता आयोग की इस सिफारिश के विरुद्ध कि उन्हें पदच्युत किया जाना चाहिए और उनसे कुछ राशि वसूल की जानी चाहिए, मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था और क्या मुख्यमंत्री ने भी संबंधित मंत्री के आदेशों को रद्द कर दिया था और क्या मुख्यमंत्री की ऐसी कार्रवाई किसी भी विचार के लिए थी।

6. क्या मेसर्स को निम्नलिखित भुगतान किए गए थे। शंकर

अरायना कंस्ट्रक्शन कंपनी। :

( i) रुपये का अनुग्रह भुगतान। 6.37 मलप्रभा में लाखों  
परियोजना;

1

( ii) रुपये का अतिरिक्त भुगतान। 12.00 घाट में लाखों

ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के इरादे से प्रभा परियोजना।

7. क्या निधियों का कोई दुरुपयोग और मनगढ़ंत कार्य

समाज कल्याण विभाग के खाते कोनी के साथ बनाया गया था

तत्कालीन मंत्री श्री एन. रचैह की वसीयत रु। 30.00 लाख और क्या इस संबंध में कोई धोखाधड़ी की गई थी

बात कही।

8. क्या विक्रेताओं के रूप में काल्पनिक व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी

के आदेश पर मैसूर सेल्स इंटरनेशनल द्वारा चंदन के साबुन में मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री और भुगतान किया गया।

कमीशन के माध्यम से गले लगाने की राशि।

9. क्या शक्तियों और पद का घोर दुरुपयोग श्री द्वारा किया गया था

एच. एम. चन्ना बासप्पा, पूर्व लोक निर्माण मंत्री-प्रभारी  
विभाग और बिजली (अब स्वास्थ्य मंत्री)

वह आवासीय स्थल जो उन्हें न्यास बोर्ड द्वारा आवंटित किया गया था

एक वाणिज्यिक साइट में प्रवेश करना और अपने परिवार के साथ एक कंपनी शुरू करना निदेशकों के रूप में।

[ 1978 ] 2 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32

10. क्या कोई पक्षपात दिखाया गया था या क्या था।

मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री श्री अजीज सैत के अनुचित प्रभाव में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नए चेसिस के लिए नए टायरों की खरीद और बॉडी बिल्डिंग कॉन ट्रैक्ट में कोई भ्रष्टाचार।

11. क्या कोई भाई-भतीजावाद और पक्षपात और दुरुपयोग था

अनुबंधित गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण के मामले में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री द्वारा शक्ति प्रदान करना और कुछ दलों को जानबूझकर लाभान्वित करना जिनके साथ मुख्यमंत्री के दूसरे दामाद भागीदार थे।

12. क्या नामांकन में कोई पक्षपात दिखाया गया था

श्री के. वी. राव अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बोर्ड के सदस्य के रूप में।

13. क्या मेसर्स को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। बालाजी एंजी-।

मुख्यमंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण वाले बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा दुमलूर ले में आवास और शहरी विकास निगम की निम्न आय समूह योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकार करके निर्माण कंपनी से संपर्क करना।

14. क्या इन तीनों को 20 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था।

वित्त मंत्री श्री एम. वी. घोरपड़े के पुत्रों ने भूमि अनुदान नियमों और भूमि सुधार अधिनियम और भूमि राजस्व अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

15. क्या सत्ता का कोई दुरुपयोग किया गया था, या कोई गड़बड़ी की गई थी

हुबली-धारवाड़ निगम क्षेत्र में बोरोका कपड़ा मिलों को भूमि प्रदान करने के संबंध में नगरपालिका प्रशासन मंत्री श्री डी. के. नाइकर द्वारा वचनबद्ध।

## संलग्नक II

चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्य का कोई अन्य मंत्री

कर्नाटक निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात या सरकारी शक्ति के दुरुपयोग का दोषी था, अर्थात्:

( 1 ) के लिए आरक्षित 20 एकड़ सरकारी भूमि का अनुदान

होम्मनहल्ली, नेलमंगला तालुक में मवेशियों का चराना,

बैंगलोर जिला, मुख्य मंत्री के दामाद को

श्री एम. डी. नटराज, के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए

भूमि राजस्व संहिता और दावों की अवहेलना

स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदक;

( 2 ) सबसे अधिक 4 बड़े मूल्यवान आवास स्थलों का आवंटन

बैंगलोर का पॉश इलाका, राज महल विलास एक्सटेंशन,

श्री देवराज उर्स और उनके परिवार के सदस्यों को सुपर में

अन्य आवेदकों के सही दावों का सत्र;

( 3 ) मेसर्स निर्मला इंजीनियरिंग को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया

निर्माण कंपनी, सरकारी धन जारी करके कर्नाटक बनाम यूनियन (बेग, सी.

जे.)

33

इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित मंत्री ने

सिफारिश के आधार पर फर्म पर मुकदमा चलाने का निर्णय

सतर्कता आयोगों के संशोधन।

( 4 ) रुपये का अतिरिक्त भुगतान। 98.88 मेसर्स बालाजी को लाख

इंजीनियरिंग कंपनी, हेमवती परियोजना में, इसके विपरीत

पक्ष लेने की दृष्टि से अनुबंध की शर्तों का उल्लेख

ठेकेदार को पकड़ना;

( 5 ) मेसर्स नेचिपदम कंस्ट्रक्शन के पक्ष में दिखाया गया

हेमवती परियोजना में सहयोग करें, उच्चतम स्वीकार करके  
ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के इरादे से और

रुपये की सीमा तक अतिरिक्त भुगतान करना। 3.5 लाख;

( 6 ) रुपये का अतिरिक्त भुगतान । 1 मेसर्स टिसिल कॉन को करोड़ रुपये के लाभ के लिए काली पनबिजली परियोजना में ट्रैक्टर ठेकेदार;

( 7 ) चाहे लगभग 5,000 टन चावल, द्वारा खरीदा गया हो  
तमिलनाडु सरकार से कर्नाटक सरकार  
सरकार-से-सरकार के आधार पर अनुमति दी गई थी  
एक निजी पक्ष द्वारा विपणन किया जाएगा, श्री एच. आर. अथू  
अहमद, खाद्य विभाग की जानकारी के बिना  
मैसूर राज्य सहकारी विपणन के बजाय  
संघ जैसा कि पहले सहमति थी, के एकमात्र इरादे के साथ  
निजी पक्ष को लाभान्वित करना;

( 8 ) एक काल्पनिक सहकारी समिति को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया  
270 एकड़ कृषि भूमि के रूपांतरण के संबंध में  
दिनशाँ एस्टेट को गैर-कृषि उद्देश्य में कहा जाता है

भूमि के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन  
अधिनियम और भूमि राजस्व अधिनियम;

सुधार

( 9 ) क्या एक घनश्याम को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था

2500 टन बाजरे की रुपये की दर से बिक्री । 73.50 पी ।

निविदाएं बुलाए बिना और श्री को अनुमति दिए बिना प्रति कुंतल  
घनश्याम महाराष्ट्र राज्य में बाजरा बेचेंगे

रुपये की दर से । 125.00 समय के दौरान प्रति कुंतल

कर्नाटक में सूखा ।

10 ) क्या अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था या रियायत दी गई थी

एम/एस को बनाया गया। कराकर और सुंदरम, वास्तुकार,  
के. आर. मार्केट इन सुपरसेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कॉन  
समर्पित मंत्री।

11 ) क्या अनुचित पक्ष दिखाया गया था, या रियायत रियायत दी गई थी  
एम/एस को बनाया गया। शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठेकेदार, में  
आलमट्टी में ऊपरी कृष्णा परियोजना।

12 ) क्या मेसर्स को अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था। कृष्ण का आटा  
बैंगलोर शहर में मूल्यवान भूमि देने में मिल, जो  
भूमि बच्चों के उद्यान के लिए थी, नाममात्र किराए पर  
संबंधित मंत्री के आदेशों पर शासन करना।

[ 1978 ] 2

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( 13 ) क्या धन का कोई दुरुपयोग हुआ था

कर्नाटक राज्य फिल्म उद्योग विकास निगम

यह रु. की राशि है। 10.00 लाख, जब मुख्य मंत्री  
टेर स्वयं उस निगम के अध्यक्ष थे और

चाहे निगम का व्यवसाय, उसके सदस्य,

लेनदार या कोई अन्य व्यक्ति या अन्यथा धोखाधड़ी के लिए

उधार या गैरकानूनी उद्देश्य।

( 14 ) क्या कोई अनुचित अनुग्रह किया गया था, मेसर्स को दिखाया गया। पूर्णिमा

इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंगलोर, इलेक्ट्रॉनिक की खरीद में  
अनुशंसा का स्थान लेकर उपकरण (इंटरकॉम)

विभाग के प्रमुख की नियुक्ति और निगम के आदेश  
समर्पित मंत्री।

( 15 ) क्या कार के धन का कोई दुरुपयोग हुआ है

नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ को  
श्री एच. एस. ने कई करोड़ रुपये का निवेश किया।  
श्रीकंठैया, गृह राज्य मंत्री, जब वे थे  
" उस संघ का निवासी और क्या इसका व्यवसाय  
संघ को धोखा देने के इरादे से आयोजित किया गया था कि  
संघ, उसके सदस्य, लेनदार, या कोई अन्य व्यक्ति या  
अन्यथा धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए।

( 16 ) क्या श्री सत्य पाल ने कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया था

परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अली द्वारा  
श्री सत्य पाल की एक बार अस्वीकृत निविदा को स्वीकार करना  
कर्नाटक राज्य में कैटीन के लिए अपनी इमारत को पट्टे पर देना  
सड़क परिवहन निगम बस स्टैंड, मैसूर और  
क्या उसी मंत्री द्वारा कोई अनुचित पक्ष दिखाया गया था  
श्री सत्य पाल के पुत्र श्री प्रेम कुमार को पट्टे पर  
कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांस के अपने रिटायरिंग रूम  
मैसूर में बंदरगाह निगम।

( 17 ) क्या चार फर्मों को कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था,

अर्थात्, अखिल भारतीय एजेंसियां, विद्युत इंजीनियरिंग कं.,

खरीद में त्रिशूल एंटरप्राइजेज और मैसूर वुड्स  
रुपये मूल्य का फर्नीचर। 29.00 नीचे 1973-74 में लाखों

स्वास्थ्य मंत्री श्री एच. सिद्धा द्वारा आई. पी. परियोजना वीराप्पा।

( 18 ) क्या मंत्री द्वारा कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था

1974 में लघु उद्योग राज्य मंत्री श्री कौलाजी,  
पक्षों को अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने में कई  
जो काल्पनिक और फर्जी हैं।

( 19 ) क्या मुख्यमंत्री द्वारा अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था

और परिवहन मंत्री श्री अजीज सैत 1973-74 में,  
एम/एस के लिए। सलाह के खिलाफ 150 चेसिस खरीदने का फार्गो का फैसला  
कर्नाटक राज्य के मुख्य यांत्रिक अभियंता  
सड़क परिवहन निगम।

( 20 ) क्या मंत्री द्वारा कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया गया था

उद्योग, श्री एस. एम. कृष्णा, कागज के आवंटन में,  
राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के सीमेंट और इस्पात से लेकर गैर-सरकारी उद्योगों  
तक  
उसके रिश्तेदारों सहित पारंपरिक विक्रेता/एजेंट।

कर्नाटक बनाम। यूनियन (बेग, सी. जे.)

35

( 21 ) क्या रुपये का अतिरिक्त भुगतान। 30.00 लाखों की कमाई हुई थी।

बैंगलोर में विशाल इमारत परिसर  
अनुबंध करें।

( 22 ) क्या मेसर्स को कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया था। बालाजी इंजीनियरिंग कंपनी ने रु। 80.00 लाखों में

ठेकेदार का पक्ष लेने के इरादे से हारंगी परियोजना।

( 23 ) क्या श्री के. एच. पाटिल, तत्कालीन कृषि मंत्री थे

प्रकृति और वन, सत्ता के किसी भी दुरुपयोग का दोषी था या

हुक्केरी टेक्सटाइल मिल्स के संबंध में अनुचित पक्षपात या

गैजेट सहकारी वस्त्र मिल्स, या दोनों।

( 24 ) क्या कोई अनुचित पक्ष दिखाया गया था या कोई भ्रष्टाचार किया गया था

श्री चिक्के कौड़ा, तत्कालीन मंत्री द्वारा प्रतिबद्ध

वेतन के संबंध में पशुपालन और कृषि

रु. की राशि। 3.00 एम/एस को लाख। नवरसा फरती

लाइज़र।

( 25 ) क्या सत्ता का कोई दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हुआ था

नगर निगम मंत्री श्री डी. के. मैकर द्वारा प्रतिबद्ध

भूमि आवंटन के संबंध में प्रशासन

जे. सी. रोड से श्री एम. बी. लाल और श्री एम. वी.

वेंकटप्पा।

( सं. 375/16/77-

एवीडी-III)

आर. के.

त्रिवेदि

सचिव

पहली बात जो एक को प्रभावित करती है, दो टिप्पणियों के नंगे पढ़ने पर

तथ्य यह है कि जहां राज्य अधिसूचना किसी विशेष कार्य या किसी व्यक्ति के हिस्से के किसी भी उल्लेख से बचने के लिए ईमानदारी से प्रतीत होती है, केंद्र सरकार की अधिसूचना का पूरा उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की शुद्धता और संयोग से अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की जांच करना प्रतीत होता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के उद्देश्य और उप-विषय इसके अनुलग्नक 1 और 2 को देखकर स्पष्ट हो जाते हैं, जिसमें जांच किए जाने वाले लेन-देन का विवरण दिया जाता है। अनुलग्नक 1 की पहली पाँच मदें और अलग-अलग लेन-देन, जिनमें से प्रत्येक में राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस तरह से प्रमुख भूमिका निभाई है, जिससे उनकी अनन्य जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। अन्य लेन-देनों में, जैसे कि मद 10, 11 और 13 में, मुख्यमंत्री को दूसरों के साथ भाग लेते हुए दिखाया गया है। और, उल्लिखित शेष लेन-देनों में, आरोप किसी विशेष व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं डालते हैं, लेकिन वे पक्षपात, भाई-भतीजावाद और जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की सच्चाई को उजागर करने के लिए बनाए गए प्रतीत होते हैं। केंद्र सरकार की अधिसूचना का अनुलग्नक 2 एक बयान से शुरू होता है जो दर्शाता है कि इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री, [1978] 2 एस. सी. आर.

36

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाई-भतीजावाद, पक्षपात या सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग में लिप्त। कई लेन-देनों में जो आइटम 1 से 25 के रूप में सूचीबद्ध हैं। दूसरी ओर, राज्य सरकार की अधिसूचना में, किसी भी अत्यधिक या अनुचित भुगतान, या पक्षपात, या गबन, या अनियमित दुर्लभता के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का उल्लेख किए बिना, विभिन्न कंपनियों या 32 शीर्षों के तहत पक्षों के पक्ष में कुछ अनुबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद यह जांच के एक अलग मद के रूप में यह सवाल बताता है कि पहले उल्लिखित चूक, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन थे। दूसरे शब्दों में, कुछ खामियों में उनके हिस्से के अलावा कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री की जिम्मेदारी की जांच राज्य अधिसूचना के तहत नियुक्त आयोग द्वारा नहीं की जा सकी। और, ऐसा लगता है कि राज्य की अधिसूचना अपने आयोग को उल्लिखित लेनदेन के संबंध में जांच करने का अधिकार देती है, यह है कि क्या इसमें कोई अत्यधिक भुगतान या अनियमितता शामिल थी। इसलिए, यह "चूक" के लिए जिम्मेदारी की बात करता है जैसे कि कोई यह मान सकता है कि कोई बेईमान मकसद नहीं था। राज्य अधिसूचना में नियमों के पालन या गैर-पालन के सवाल पर

जोर दिया गया है, इस सवाल के साथ कि क्या कुछ भुगतान उचित थे। और, जिम्मेदारी को लागू करने का सवाल केवल इन लेन-देनों के दौरान "खामियों" तक ही सीमित है।

भले ही कोई लेनदेन पूरी तरह से इसके अनुसार किया गया हो

नियम, फिर भी, भ्रष्टाचार या बेईमानी से दूषित पक्षपात का कार्य हो सकता है। अधिक लेन-देन में अधिक योग्य पक्षों की तुलना में कम योग्य दलों को जानबूझकर प्राथमिकता दी जा सकती है। नियमों का पालन करना या कागज पर यह दिखाना मुश्किल नहीं है कि सबसे योग्य पक्ष को अनुबंध का लाभ मिला है। विलेख में, यहां तक कि पद के योग्य पक्ष को भी सरकार या उसके मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अनुबंध या लाभ प्राप्त हो सकता है जो

इसके लिए बिना किसी चीज के अवैध संतुष्टि प्राप्त की है

कभी भी रिश्वत के बारे में सरकार के अभिलेखों पर उपस्थित होना

संबंधित मंत्री द्वारा प्राप्त। इसलिए, इस तथ्य के अलावा कि दोनों अधिसूचनाओं में उल्लिखित वस्तुएं ज्यादातर एक-दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि राज्य अधिसूचना के उद्देश्य किसी भी अधिसूचना की अवैधता या अनियमितता की जांच से परे नहीं जाते हैं।

लेन-देन और केवल संबंधित व्यक्तियों की "जिम्मेदारी" यह इंगित करने के लिए कि वे क्या थे। यदि कोई ऐसा कहता है, तो राज्य अधिसूचना एक आयोग का गठन करने के लिए है जिसे यह जांच करनी होती है कि क्या कुछ लेन-देनों द्वारा पहना गया पर्दा सही है और इसे पूरी तरह से शामिल करता है, लेकिन केंद्र सरकार की अधिसूचना स्पष्ट रूप से नियुक्त आयोग को स्पष्ट वैधता और नियमितता के पर्दे को भी फाड़ने में सक्षम बनाने के लिए है जो कुछ लेन-देनों द्वारा पहना जा सकता है। यह ग़्रोवर आयोग को कुछ (ज्यादातर अन्य) लेन-देनों के पीछे की वास्तविकता या सार, यदि कोई हो, की जांच करने और उसका पता लगाने के लिए अधिकृत करता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से केवल चिपकाने के लिए नहीं है

रेज़

उन व्यक्तियों पर उल्लिखित लेन-देन के लिए दायित्व जो वास्तव में दोषी हो सकते हैं, भले ही दोनों अधिसूचनाओं में उनमें से कुछ को पुरुष कहा जा सकता है। हमें नहीं लगता कि ऐसी अधिसूचनाओं को न्यायसंगत या निष्पक्ष रूप से "एक ही मामले" को शामिल करने के रूप में कहा जाएगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (1) के परंतुक (बी) द्वारा विचार किया गया है, क्योंकि कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.)

37

राज्य आयोग उपस्थिति या सतह की जांच करने के लिए है, जबकि केंद्रीय आयोग से इस बात की गहराई से जांच करने की उम्मीद है कि इसके पीछे या नीचे क्या हो सकता है।

यदि कोई अनियमितता है तो यह निश्चित रूप से राज्य के लिए चिंता का विषय है।

या उसकी सरकार या मंत्री द्वारा किसी विशेष लेन-देन में अवैधता की गई है। लेकिन, यह स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने में अधिक सहायक होगा कि यह क्यों किया गया है। और, इसके लिए यह पता लगाना और भी महत्वपूर्ण होना चाहिए कि कौन, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर क्यों न हो, वास्तव में उस अनियमितता के लिए जिम्मेदार है या नहीं।

किसी भी

बेईमानी या भ्रष्टाचार राज्य में उच्चतम स्तर पर संचालित हुआ है, भले ही फॉर्म उचित और नियमित हो। यदि राज्य अधिसूचना केंद्र सरकार की अधिसूचना के अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाती है, तो शायद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिक गंभीर मामलों के प्रति राज्य की उदासीनता किसी उद्देश्य या महत्व के बिना नहीं है। फिर भी, हम राज्य सरकार के उद्देश्यों या इस तथ्य पर कोई निर्णय पारित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के सदस्यों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण विशेषताओं को राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा छोड़ दिया गया है, भले ही उस अधिसूचना का उद्देश्य काफी प्रामाणिक और उचित था। हालाँकि, हम सोचते हैं कि राज्य अधिसूचना बहुत दूर नहीं जाती है। लेकिन, केंद्र सरकार की अधिसूचना आगे बढ़ती है। यह स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाता है, जो

को

हो सकता है कि लगाए गए आरोपों ने इस तरह से काम किया हो जो उन्हें न केवल सैद्धांतिक रूप से जिम्मेदार बनाता है बल्कि वास्तव में भ्रष्टाचार का दोषी बनाता है।

किसी भी राज्य या सरकार की नीतियों की सफलता के लिए,

देश के किसी भी हिस्से में, जिस पर इसका अधिकार है, इसे संवैधानिक आदेशों को पूरा करने में सक्षम दिखाया जाना चाहिए।

कोन

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के भाग IV में शामिल किया गया है ताकि हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत बुनियादी मानवाधिकारों को वास्तविकता बनाया जा सके न कि एक चमत्कार। यह, हमारे लोगों की जनता के लिए, पूरे संविधान का मूल उद्देश्य है जिसे निराश नहीं होने दिया जा सकता है। यदि लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन नहीं किया जाना है और ऐसा प्रतीत होना है कि राज्य के मामलों के प्रभारी, उच्चतम स्तर पर, संदेह से परे होने चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे संविधान के उच्च उद्देश्यों और हमारी गरीबी से पीड़ित जनता की गंभीर जरूरतों के संदर्भ में उनकी अपनी वास्तविक और पूरी तरह से निर्विवाद अखंडता सुनिश्चित और स्पष्ट हो। हम भ्रष्टाचार के आरोपों को हल्के में नहीं ले सकते। हमारा मानना है कि जब कहीं भी सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं तो राज्यों और संघ के हित विरोधी नहीं होते हैं। संपूर्ण जनता के साझा हितों की सेवा के लिए, जिनकी ओर से हमारा संविधान बोलता है, राज्य और संघ अलग नहीं हो सकते हैं। उन्हें उद्देश्य और कार्य में एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। यह है।

के रूप में

यह महत्वपूर्ण है कि उच्च स्थानों पर व्यक्तियों के खिलाफ अनुचित और दुर्भावनापूर्ण हमलों और आरोपों को उजागर किया जाना चाहिए और इसके पीछे की वास्तविकता वे इस बात के लिए उजागर हैं कि इसकी क्या कीमत है, क्योंकि यह है कि उचित शिकायतों को निवारण के पर्याप्त साधन खोजने चाहिए ताकि हमारे देश के लाखों मूक लोगों के हितों को अनैतिकता से उचित रूप से बचाया जा सके।

जहाँ भी मिले। यदि, जैसा कि हम इस मामले में पाते हैं, राज्य अधिसूचना

है।

केवल लगाए गए आरोपों की सतह को सतही रूप से खरोचने के लिए, [1978] 2 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जबकि केंद्र सरकार की अधिसूचना कर्नाटक राज्य में राजनीतिक निकाय के साथ क्या गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके मूल या केंद्र की जांच करने के लिए है, हम यह मानने के लिए कारण खोजने में बहुत अधिक तकनीकी या चतुर नहीं हो सकते हैं कि दोनों पूछताछों का विषय काफी हद तक समान है। जाहिर है, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता था। ऊपर पूरी तरह से दिए गए दोनों अधिसूचनाओं को पढ़ने से यह पता चलता है।

इस कैस्क की परिस्थितियों में, यह अधिक सुंदर हो सकता है

कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री अपने तकनीकी आरोपों को माफ कर देंगे, जैसा कि वे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में पूछताछ करने के लिए किसी भी आयोग को अधिकार क्षेत्र में पाए जाने पर सभी सामग्री को सामने रखने का वचन देते हैं। वह सम्मानपूर्वक सामना करने और उन आरोपों को पीछे हटाने के लिए उपयुक्त व्यवहार कर सकते थे, जो उनके अनुसार, काफी लंबे समय से उनके खिलाफ बार-बार लेकिन अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाए गए हैं। इस प्रकार वह सक्षम हो सकता है यह स्थापित करने के लिए कि वह अपने राज्य, उसके निवासियों और वास्तव में पूरे देश के हितों की सेवा कर रहा है, यदि उसके दावे सही हैं।

वादी ने कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया है कि ग़्रोवर आयोग

सायन की अध्यक्षता कभी भी निर्विवाद सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता वाले व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती है जो इस न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। वादी की ओर से पेश श्री लाल नारायण सिन्हा ने बहुत स्पष्ट रूप से और उचित रूप से स्वीकार किया है कि वह मामले में सच्चाई की कमी को सफलतापूर्वक दबा नहीं सकते हैं।

इसका मतलब है

अपनी अधिसूचना जारी करने में केंद्र सरकार का हिस्सा।

यह प्रश्न कि क्या आयोग या तो अनावश्यक है, राजनीतिक युद्ध के एक हथियार के रूप में, साथ ही इस मामले में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में किसी भी संदेह को अनिश्चित के रूप में खारिज किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को स्वयं यह स्वीकार करना चाहिए कि परिस्थितियों के कारण एक आयोग की नियुक्ति आवश्यक हो गई थी, जो समान

मामलों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, जो उनके सार्वजनिक महत्व के कारण जांच के योग्य थे।

हम पाते हैं कि केंद्र सरकार की अधिसूचना में ही इसका उल्लेख नहीं है

इसके दायरे से वे आरोप जो उचित रूप से राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयोग के दायरे में आते हैं। हम उन मामलों से संबंधित नहीं हैं जिन्हें बाद में जोड़ा जा सकता है ताकि राज्य आयोग द्वारा जांच का दायरा बढ़ाया जा सके। हमारा मानना है कि अधिनियम की धारा 3 (1) के परंतुक (बी) के प्रावधान राज्य सरकार को ऐसे मामलों को जोड़ने से रोकेंगे जो पहले से ही केंद्र सरकार की अधिसूचना में शामिल हैं। हालाँकि, हम इसे ग़्रोवर आयोग पर छोड़ देते हैं कि वह यह निर्धारित करे कि जब भी उसे इस तरह की आपत्ति का सामना करना पड़े, क्या राज्य आयोग द्वारा किसी विशेष मामले की पहले से ही उचित जांच की जा रही है।

ऊपर हमने जो देखा है, उसे देखते हुए शायद यह होगा

कर्नाटक सरकार के लिए स्वयं अपनी अधिसूचना वापस लेना उचित है यदि वह सोचती है कि राज्य सरकार के कुछ सदस्य उन मामलों पर दो कॉम मिशनों द्वारा पूछताछ का सामना करने से अनुचित रूप से शर्मिंदा होंगे जिनके कुछ संबंध हो सकते हैं या यहां तक कि

कुछ

सामान्य क्षेत्र। वास्तव में, एक अनुभाग के केंद्र तक पहुंचने के लिए, इसका सर राउंडिंग या सतही कवच, जो कि राज्य आयोग कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) है।

39

कुछ लेन-देनों के संबंध में पूछताछ की जा सकती है, इन लेन-देनों के मूल तक पहुंचने से पहले उन्हें छेदना पड़ सकता है, या कुछ हद तक पार करना पड़ सकता है। जैसा कि हम मानते हैं कि दोनों अधिसूचनाएं उन मामलों में जांच को अधिकृत करती हैं जो प्रकृति और उद्देश्य में काफी भिन्न हैं, ग़्रोवर आयोग द्वारा जांच को अधिनियम की धारा 3 (1) के परंतुक (बी) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना के कारण बाधित नहीं कहा जा सकता है, भले ही

में विचलन को देखते हुए काफी अलग विषय वस्तु

लेन-देन को नियंत्रित करने वाले तथ्य या नियमों के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं -

आम है। यदि उद्देश्य अलग-अलग हैं तो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए तथ्य और कानून के सामान्य क्षेत्रों की जांच की अनुमति होगी।

नियुक्ति में राज्य सरकार के उद्देश्यों पर संदेह किए बिना

इसका अपना आयोग शायद हम यह देख सकते हैं कि, शामिल मामले में

मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ लगाए गए इस तरह के आरोप

अगर राज्य का अपना आयोग ऐसा करता तो बेहतर होता

दूर से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि केवल प्रत्याशा में स्थापित किया गया है

बाहरी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से जांच जो, संभवतः, अधिक निष्पक्ष  
और उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है, या, बाधा डालने के लिए या

केंद्र सरकार आयोग की कार्यवाही को शर्मिंदा करना। इन आधारों पर उत्पन्न होने  
वाली शंकाओं को दूर किया जाएगा

राज्य अधिसूचना को वापस लेना। यद्यपि त्वरित कार्यवाही

राज्य सरकार काफी सराहनीय और प्रामाणिक लग सकती है।

संदर्भ और परिस्थितियों में अपना आयोग नियुक्त करना

ऊपर बंद, इसका निरंतर अस्तित्व ठीक वैसा प्रभाव नहीं दे सकता है

अपरेट के विश्लेषण पर हमने जो ऊपर रखा है, उसके बाद दो आयोगों के  
उद्देश्यों की सामग्री के आधार पर निर्णय लिया गया

दो

किसी भी मामले में, विषय वस्तु, महत्वपूर्ण रूप से नहीं

अधिसूचनाएँ।

उसी के साथ, केंद्र सरकार आयोग आगे बढ़ सकता है

इसका

जांच यदि अन्य आपत्तियाँ हैं, जिनकी अब हम जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार की अधिसूचना की वैधता के लिए वास्तव में घातक नहीं हैं केशन।

केंद्र सरकार की वैधता पर वे अन्य आपत्तियाँ

अधिसूचना का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान के प्रावधानों को व्यक्त करें संघीय संरचना, कार्यपालिका और विधायिका के वितरण से संबंधित राज्य और संघ के बीच शक्तियाँ, किसी राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी मंत्रपरिषद, ऐसी शर्तें जिनके तहत वे पद धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं खारिज किया जाए, राज्य विधानमंडल का उनके ए. सी. पर अनन्य नियंत्रण राज्य सरकार के कार्यों और आचरण का उल्लंघन किया जाता है यह, ताकि, अगर यह सब किया जा सकता है, शक्तियों की घड़ी के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रेरित, यह अधिनियम का प्रावधान, वस्तुतः, अमान्य है। दूसरा, और निम्नलिखित तार्किक और स्वाभाविक रूप से प्रस्तावों के सेट से, उनकी आवश्यकताओं के रूप में इसके परिणामस्वरूप, अधिसूचना केंद्र द्वारा उल्लंघन का गठन करती है जिस सरकार को बुनियादी विशेषताओं का हिस्सा माना जाना चाहिए या संविधान की मूल संरचना जो विनाश को सीमित नहीं करती है कार्यकारी आदेश जारी करके या तो संघवाद या लोकतंत्र का गठन। तीसरा ली, प्रस्तुतियों के अंतिम उल्लिखित सेट के तर्क को एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं के रूप में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह संशोधन [1978] 2 ए. सी. आर. की प्रक्रिया से बाहर है।

40

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित, यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए  
संसद की विधायी क्षमता से बाहर होना

संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245-255 द्वारा पठित

के साथ

अनुसूची 7 में विधायी सूचियों के प्रावधान। चौथा, यह सुगम है।

निहित, वैकल्पिक रूप से, कि, किसी भी मामले में, एक आवश्यक निहितार्थ

संविधान के स्पष्ट प्रावधान यह है कि द्वारा एक नियंत्रण

केंद्र सरकार सरकारों का दिन-प्रतिदिन का कार्य

भाग में पाई जाने वाली विधायी प्रक्रिया को अपनाकर राज्यों में संविधान के  
ग्यारहवें भाग का एक ऐसा परिणाम होना चाहिए जिसे केवल प्राप्त किया जा सके

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन द्वारा। पाँचवाँ,  
यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही दिन-प्रतिदिन के साथ हस्तक्षेप हो

राज्यों में सरकारी तंत्र के काम करने पर प्रतिबंध नहीं है

संविधान की मूल संरचना, फिर भी, ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें हस्तक्षेप को  
विशेष रूप से निर्धारित किया गया है

द.

लेख 352-360 में निहित आपातकालीन प्रावधान

भाग

संविधान का XVIII, हस्तक्षेप का कोई अन्य तरीका

राज्य सरकारों के संचालन, जो स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं  
स्वयं शिक्षा को साधारण विधायी आयोग के बाहर माना जाना चाहिए।

संसद की पीठ।

छठा, वादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि,

किसी भी स्थिति में, अधिनियम के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए या  
अंतर किया जाना चाहिए पूर्वनिर्धारित, यदि आवश्यक हो तो उन्हें पढ़कर, हस्तक्षेप  
को रोकने के लिए

राज्य सरकार के संचालन के साथ केंद्र सरकार द्वारा या

सभी प्रस्तुतिकरण पुरुषों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रियों का आचरण ऊपर  
बताया गया है।

यह सच है कि वादी के विद्वान वकील वापस लौटते रहे

वह वास्तव में बुनियादी या अलंघनीय विशेषताओं के रूप में क्या रखना चाहते थे

संविधान के बारे में, फिर भी, वह स्पष्ट रूप से उसे प्रतिबद्ध करने के लिए अनिच्छुक महसूस  
करते थे स्वयं इस दृष्टिकोण से कि अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो एक

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन जो माना गया है

लोकतंत्र और संघवाद दोनों को शामिल करना। जाहिरा तौर पर, यह कुछ परिवर्तनकारी  
स्थिति इस अहसास से उत्पन्न हुई कि अधिनियम के पास हो सकता है

बहुत कम, यदि कुछ भी है, तो सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों के साथ करना

लोकतांत्रिक सरकार, और यह कि हमारे संविधान की संरचना में जो भी संघवाद पाया जा सकता  
है, उसके बावजूद इसमें इतनी दृढ़ता से एकात्मक विशेषता है कि जब इन प्रावधानों की  
समग्रता की जांच की जाती है, तो आत्मविश्वास से यह कहना मुश्किल हो जाता है कि इस तरह  
के संविधान में कितना संघवाद है, क्या इसके वे हिस्से जो हमारे संविधान के संघीय तत्वों पर  
हावी प्रतीत होते हैं, जो इसके संघवाद के रूप में वर्णित की तुलना में अधिक बुनियादी या  
महत्वपूर्ण नहीं हैं, और क्या अधिनियम के तहत संभावित कार्रवाई, संभवतः उपचार खोजने की  
दृष्टि से, मंत्रियों द्वारा सरकारी मामलों के संचालन में जो भी बेईमानी या भ्रष्टाचार पाया जा

सकता है, वह वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार को नष्ट करने या बाधित करने के बजाय सुरक्षा या सहायता के लिए नहीं हैं।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि सर गिरिल सैल्मन, लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील, जांच न्यायाधिकरण पर एक व्याख्यान में कहा गया "।

" सभी देशों में, निश्चित रूप से उन लोगों में जो स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और अफवाहें फैलती हैं जिससे देश भर में विश्वास का संकट पैदा होता है सार्वजनिक जीवन की अखंडता या अन्य मामलों के बारे में कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.)

41

महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा शायद ही कभी होता है।

लेकिन जब ऐसा होता है तो यह आवश्यक है कि जनता का विश्वास होना चाहिए इसे बहाल किया जाए, क्योंकि इसके बिना कोई भी लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं रह सकता है।

इस विश्वास को पूरी तरह से ही प्रभावी ढंग से बहाल किया जा सकता है।

अफवाहों और आरोपों की जांच और जांच करना सत्य को खोजने और स्थापित करने के लिए। सच हो सकता है

दिखाएँ कि बुराई मौजूद है, इस प्रकार इसे जड़ से उखाड़ने में सक्षम बनाता है,

या कि अफवाहों और आरोपों में कोई आधार नहीं है

जिससे जनता परेशान हुई है। किसी भी मामले में,

आत्मविश्वास बहाल हो जाता है "।

ऊपर उल्लिखित व्याख्यान में, यह बताया गया था कि ट्रिब्यु

इंग्लैंड को

जांच (साक्ष्य) अधिनियम, 1921 को पारित किया गया था।

समितियाँ

उस प्रक्रिया को विस्थापित करें जिसके द्वारा चुनिंदा संसद का उपयोग "उच्च स्थानों पर कथित गलत कामों की जांच करने के लिए" किया गया था। प्रवर समिति की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा: राजनीतिक न्यायाधिकरण द्वारा निवेश का ऐसा तरीका पूरी तरह से असंतोषजनक था। होने के नाते

प्रगतिशील लोगों को इसके बारे में कुछ भी करने में हमें लगभग 300 साल से थोड़ा अधिक समय लगा। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो अभी भी हमारी तुलना में अधिक प्रगतिशील है, वे अभी भी लगभग एक ही विधि का उपयोग करते हैं। हमारी संसदीय समितियों की तरह कांग्रेस की जांच समितियों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दलों की संबंधित ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसे निकाय कभी भी दलगत राजनीतिक प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक कदाचार के आरोपों की जांच करने वाले किसी भी न्यायाधिकरण में यह एक बहुत ही वास्तविक दोष है, विशेष रूप से जांच के विषय के रूप में।

इसमें अक्सर अत्यधिक राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। उन्होंने कहा: " द.

संसदीय समितियों द्वारा इंग्लैंड में इस तरह की जांच का इतिहास

वर्तमान शताब्दी की शुरुआत में ऐसा हुआ जो के रूप में जाना जाने लगा मार्कोनी  
घोटाला। 1912 में लिबरल में पोस्ट मास्टर जनरल

सरकार ने अंग्रेजी मार्कोनी कंपनी द्वारा एक निविदा स्वीकार की

राज्य के स्वामित्व वाले वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशनों का निर्माण

साम्राज्य। व्यापक अफवाहें फैलीं कि सरकार

भ्रष्ट रूप से मार्कोनी कंपनी का पक्ष लिया था और वह कुछ प्रोमी

सरकार के सदस्यों ने अनुचित रूप से लाभ उठाया था

लेन-देन। में नियुक्त चयन संसदीय समिति

इन अफवाहों को निहित करना इसकी संबंधित शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है  
लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टियाँ। लिबरल की बहुमत रिपोर्ट

समिति के सदस्यों ने पाया कि सरकार के ये सदस्य घोर अनुचितता का दोषी था।  
जब रिपोर्ट आई

हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस, सदन ने सख्ती से विभाजित किया

पार्टी लाइनों और बहुमत ने मंत्रियों को सभी दोषों से मुक्त कर दिया।

इस तरह के मामले की जांच का यह अंतिम उदाहरण है।

संसद की एक चयन समिति "। दूसरे शब्दों में, "ऐसा इसलिए था क्योंकि

इंग्लैंड में मामलों के एक राजनीतिक न्यायाधिकरण द्वारा जांच के कारण

गंभीर सार्वजनिक अशांति को बदनाम किया गया था कि जांच न्यायाधिकरण

( साक्ष्य) अधिनियम, 1921 पारित किया गया था, कुछ स्थापित करने की दृष्टि से

स्थायी जाँच तंत्र उपयोग के लिए उपलब्ध होगा जब पुनः

पूछते हैं "। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अमेरिका में भी तदर्थ [1978] 2 एस. सी. आर.

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42

न्यायाधिकरणों को कभी-कभी नियुक्त नहीं किया जाता है ताकि किसी मामले से बचा जा सके।

उदाहरण के लिए, एक कांग्रेस समिति के पास भेजा गया, जैसे कि वारेन राष्ट्रपति  
कैनेडी की हत्या की जांच के लिए आयोग।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक देशों में न केवल आधुनिक

1952 के हमारे अधिनियम के तहत संचालित किया जाना था। की प्रस्तावना हमारे  
अधिनियम से पता चलता है कि इसका उद्देश्य "नियुक्ति के लिए प्रावधान करना" था

जाँच आयोग और ऐसे आयोगों को सी. आर. सौपने के लिए

शक्तियों को कम करें"। अधिनियम की धारा 1, उप-धारा (2) इंगित करती है कि इसका विस्तार पूरे भारत में है, लेकिन इसके लिए एक परंतुक कुछ ऐसी सीमाएं रखता है जिनके अधीन इसका संचालन किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर का संबंध इस बात से है कि इस राज्य के लिए स्थापित जांच सातवीं अनुसूची की सूची II या सूची III में ऐसी प्रविष्टियों से संबंधित मामलों से संबंधित होनी चाहिए जो राज्य पर लागू हो सकती हैं। अधिनियम में किसी अन्य राज्य के संबंध में ऐसी कोई सीमा नहीं है।

अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है:  
अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

" 2. इस

(क) "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है -

( (i) केंद्र सरकार, किसी आयोग के संबंध में

उसके द्वारा किसी भी मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया

सूची I में सूचीबद्ध किसी भी प्रविष्टि से संबंधित

या सातवीं अनुसूची में सूची II या सूची III

संविधान; और

( (ii) आयोग के संबंध में राज्य सरकार

उसके द्वारा किसी भी मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया

सूची II में उल्लिखित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित या

संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची III:

बशर्ते कि राज्य के संबंध में

जम्मू और कश्मीर, इन खंडों का प्रभाव होगा

इस संशोधन के अधीन कि

(क) उपखंड (i) में शब्दों के लिए और

अंक "सातवें में सूची I या सूची II या सूची III

संविधान की अनुसूची "शब्द और आंकड़े

" सातवीं अनुसूची में सूची I या सूची III

जम्मू राज्य पर लागू होने वाला संविधान  
और "कश्मीर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उसके उपखंड (ii) में, शब्दों के लिए और  
सातवीं अनुसूची में अंकों की सूची II या सूची III  
संविधान के लिए ", शब्द और आंकड़े" सूची III  
संविधान की सातवीं अनुसूची में लागू  
जम्मू और कश्मीर राज्य को केवल "होगा  
प्रतिस्थापित;

(ख) "आयोग" का अर्थ है जाँच आयोग।

धारा 3 के तहत इंगित किया गया; कर्नाटक बनाम।

यूनियन (बेग, सी. जे.)

43

(ग) "विहित" का अर्थ है जिसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया है।

यह अधिनियम "।

अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:

" 3. ( 1 ) उपयुक्त सरकार, यदि यह अफीम की हो सकती है

यह नहीं कि ऐसा करना आवश्यक है, और होगा, यदि कोई संकल्प इस संबंध में लोक  
सभा द्वारा पारित किया जाता है, या

मामला हो सकता है, राज्य की विधान सभा, द्वारा

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना एक आयोग की नियुक्ति करती है

किसी भी अवज्ञा की जाँच करने के उद्देश्य से जाँच

सार्वजनिक महत्व की बात की और इस तरह के कार्य करना                      में विनिर्दिष्ट किए जाने  
वाले समय के भीतर

अधिसूचना, और इस प्रकार नियुक्त आयोग करेगा                      जाँच करना और तदनुसार कार्य  
करना:

बशर्ते कि जहां ऐसा कोई आयोग रहा हो

किसी भी मामले की जांच के लिए नियुक्त

( क ) केंद्र सरकार द्वारा, कोई राज्य सरकार नहीं

सेन के अनुमोदन के अलावा, शासन करेगा  
त्राल सरकार, एक और आयोग नियुक्त करें

एक ही मामले में तब तक पूछताछ करें जब तक कॉम

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मिशन है

कार्य करना;

( ख ) राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा

किसी अन्य आयोग की नियुक्ति नहीं करेगा।

एक ही मामले में तब तक पूछताछ करें जब तक

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग है -

कार्य करना, जब तक कि केंद्र सरकार

राय है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए

दो या दो से अधिक राज्यों के लिए।

( 2 ) आयोग में एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं।

उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, और जहाँ

आयोग में एक से अधिक सदस्य होते हैं जिनमें से एक

उन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

( 3 ) उपयुक्त सरकार किसी भी स्तर पर



इस तरह के बयान देकर गलत सबूत देना "। लेकिन, यह संरक्षण उन प्रश्नों के उत्तर में दिए गए बयानों के लिए नहीं है जो आयोग द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, या उन मामलों पर दिए गए हैं जो जांच के विषय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। अधिनियम में आयोग के निष्कर्षों को कोई प्रभाव देने या किसी भी आदेश को लागू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है जो आयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच के परिणामस्वरूप किया जा सकता है। वास्तव में, अधिनियम के तहत एक आयोग को किसी के खिलाफ केवल वही आदेश देने का अधिकार है जो साक्ष्य को जोड़ने से संबंधित है, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, और वे जो आयोग को "आयोग या उसके किसी सदस्य को बदनाम करने के लिए सोचे गए कार्यों" से बचाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। आयोग की कार्यवाहियों का परिणाम केवल एक रिपोर्ट में हो सकता है जिसे एस के प्रावधानों के तहत संबंधित विधान के समक्ष रखा जाना है। 3 ( 4 ) अधिनियम से। इसलिए, इस अधिनियम के पीछे स्पष्ट उद्देश्य लोकतांत्रिक सरकार के तंत्र को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाना है। इसे शायद ही सरकार के लोकतांत्रिक तरीकों को विफल करने के लिए एक अधिनियम के रूप में माना जा सकता है।

यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ सरकार की एकात्मक प्रणालियाँ अप्रचलित हैं। वहाँ है

सीमित उद्देश्यों के लिए स्थानीय स्वशासन की शक्तियों का हस्तांतरण। हमारे देश में, शीर्ष पर, संसद के प्रति उत्तरदायी एक केंद्रीय या संघ सरकार है, और नीचे, राज्य विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी राज्य सरकार हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी शक्तियों के दायरे में कार्य करती है जो दो श्रेणियों में विभाजित हैं-अनन्य और समवर्ती। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अनन्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय सरकार है। और, सभी राज्यों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की एक प्रणाली है, जो राज्य अधिनियमों के तहत काम कर रही है। इस प्रकार, हम अपने देश में सरकार की तीन स्तरीय प्रणाली की बात कर सकते हैं जिसमें केंद्र या केंद्र सरकार है। यह कुछ विषयों के साथ शीर्ष पर आता है जो विशेष रूप से सामान्य रूप से या सामान्य समय में संबंधित राज्यों पर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन, राज्यों के क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी आपात स्थितियों में केंद्रीय शक्ति के क्षेत्र में आ सकती हैं। और, यदि किसी विषय को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसे पूरे देश की चिंता के रूप में माना जा सकता है, तो संविधान निर्माताओं ने खुद इसे या तो विशेष रूप से केंद्रीय विधायी सूची I में या अनुसूची VII में उल्लिखित मदों की समवर्ती विधायी सूची III में रखा है।

हमारी संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं।

संसद। लोक सभा का उद्देश्य किसी संघ की स्वतंत्र इकाइयों के रूप में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना नहीं है (अनुच्छेद 79)।

इसे करनाटका वी. यूनियन (बेग, सी. जे.) करना है।

45

राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 525 से अधिक नहीं है और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोगों के बीस से अधिक प्रतिनिधि नहीं हैं (अनुच्छेद 81)। वहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले भारत के लोगों का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि उनके हितों और अधिकारों को उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों द्वारा अच्छी तरह से देखा और संरक्षित किया जा सके। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मामलों में उनके विशेष ज्ञान या अनुभव के लिए नामित किया जाता है। कला, विज्ञान या समाज सेवा, और राज्यों के 238 से अधिक प्रतिनिधि और एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के साथ प्रत्येक राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित और केंद्र शासित प्रदेशों से संसद द्वारा बनाई गई कानून द्वारा निर्धारित तरीके से (अनुच्छेद 80)। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों का प्रतिनिधि भेजना निश्चित रूप से संघीय सिद्धांत की मान्यता है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार सभी से बाहर है

प्रत्येक राज्य से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप। उस हस्तक्षेप की सीमा और जिन परिस्थितियों में यह संभव है, उन्हें निर्धारित करने के लिए हमें अपने संविधान के अन्य प्रावधानों की ओर रुख करना होगा।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 245 (1) क्षेत्रीय संचालन प्रदान करता है।

संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून। अनुच्छेद 246 (1) यह अधिनियमित करता है कि सातवीं अनुसूची की सूची I के आइटम संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सूची II के आइटम संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्ति के भीतर, लेकिन

सूची III में शामिल लोगों को समवर्ती होना चाहिए। हालांकि, अनुच्छेद 248 संसद को उन मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है जो समवर्ती या राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं। यह वही है जिसे आम तौर पर "अवशिष्ट शक्ति" के रूप में कहा जाता है। इसके अलावा, पार्लियामेंट के पास मामलों के लिए भी कानून बनाने की प्रबल शक्तियां हैं।

सीमित अवधि के लिए राज्य सूची यदि राज्य परिषद अपने कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में या आपातकाल की घोषणा के जारी रहने के दौरान ऐसा करना आवश्यक है (अनुच्छेद 249 और 250)। समवर्ती सूची में पाई जाने वाली किसी वस्तु पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता का

समाधान संसद द्वारा बनाए गए कानून (अनुच्छेद 254) के पक्ष में किया जाना है। और, संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352-360 में निहित दूरगामी शक्तियाँ,

राष्ट्रपति को न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और विधायी शक्तियों पर बाधाओं के रूप में उनके संचालन को निलंबित करने में सक्षम बनाता है, बल्कि राज्य विधानमंडल के कार्यों को भी निलंबित कर सकता है जो संसद और राज्य सरकारों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा लिया जा सकता है। यह सच है कि आपातकालीन शक्तियाँ इतनी कठोर हैं कि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, हमारे सामने आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग या शक्तियों के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं आया है। हम यहाँ केवल उस सीमा पर विचार कर रहे हैं जो आगे रखी गई है।

सरकार की संघीय और लोकतांत्रिक विशेषताएँ। जो हो भी सकता है और नहीं भी।

निलंबन करने में सक्षम। जैसा कि वर्तमान में संविधान है, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, जिनकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाता है

इस मामले में किसी भी पक्ष द्वारा हमारे सामने, आपातकाल की अवधि के लिए हमारे संविधान में एक संघीय ढांचे की झलक को भी पूरी तरह से हटा सकता है।

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46

प्रशासनिक संबंधों पर भाग 11 के अध्याय 2 पर एक नज़र

संघ और राज्यों ने हमें निर्देशों के लिए प्रावधान दिखाए हैं

जो सामान्य समय में भी राज्य सरकारों को दिया जा सकता है

केंद्र सरकार द्वारा। अनुच्छेद 256-257 में "सरकार" के रूप में वर्णित है। में से भारत  
"। अनुच्छेद 256 अधिनियमित करता है:

" 256. प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति इस प्रकार होगी -

द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया गया

संसद और कोई भी मौजूदा कानून जो उस राज्य में लागू होते हैं,  
और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा  
किसी राज्य को ऐसे निर्देश देना जो उसे प्रतीत हों

भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक होना चाहिए।

अनुच्छेद 257 (1) को निष्पादन की सीमा को स्पष्ट करने के लिए भी उद्धृत किया जा सकता है।  
राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियाँ। :

" 257 ( 1 ) प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति होगी -

इस प्रकार प्रयोग किया जाता है ताकि अभ्यास में बाधा या पूर्वाग्रह न आए

संघ की कार्यकारी शक्ति और कार्यकारी शक्ति

संघ का विस्तार इस तरह के निर्देश देने तक होगा -  
एक राज्य जो भारत सरकार को प्रतीत हो

उस उद्देश्य के लिए आवश्यक "।

संघ की सामान्य कार्यकारी शक्तियों का विस्तार भारतीय है।

संविधान के अनुच्छेद 73 (1) के अनुसार:

" 73 ( 1 ) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन,

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा

( क ) उन मामलों के लिए जिनके संबंध में संसद ने

कानून बनाने की शक्ति; और

( ख ) ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और न्यायशास्त्र के प्रयोग के लिए

जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकता है

किसी संधि या समझौते के आधार पर;

बशर्ते कि उप में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति

खंड (क) में स्पष्ट रूप से उपबंध किए जाने के अलावा, ऐसा नहीं होगा।

संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में,  
कोई राज्य उन मामलों के लिए जिनके संबंध में विधानमंडल  
राज्य के पास कानून बनाने की भी शक्ति है।

और, अनुच्छेद 162 में दी गई राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार और सीमाएँ इस प्रकार हैं:

" 162. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन,

किसी राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार इन मामलों तक होगा -

जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को शक्ति है

कानून बनाएँ:

बशर्ते कि किसी भी मामले में जिसके संबंध में

किसी राज्य के विधानमंडल और संसद के पास ऐसा करने की शक्ति होती है

कानून, राज्य की कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी -

और द्वारा सीमित, द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई कार्यकारी शक्ति

इस संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा  
संघ या उसके प्राधिकरण।

कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

47

केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों का व्यापक दायरा था

इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम में कुछ समय पहले विचार किया गया था। भारत संघ (1), जहां प्रासंगिक संवैधानिक दृष्टिकोण की जांच करने के बाद, हम में से एक ने उस संदर्भ में अवलोकन किया जिसे केंद्र सरकार में गृह मंत्री द्वारा राज्य सरकार को राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए दिए गए "निर्देश" के रूप में समझने की मांग की गई थी:

" मैं यह बता सकता हूँ कि रिले के विभिन्न पहलू हैं

संघ और राज्यों के बीच मतभेद

संविधान के प्रावधान। मैं यहाँ उल्लेख कर सकता हूँ

जो संघ द्वारा 'निर्देश' देने से संबंधित हैं

कला के कारण राज्य सरकारों को सरकार। 365

प्रदान करता है:

\$ 365 . जहाँ कोई राज्य इसका पालन करने या करने में विफल रहा हो।

के अभ्यास में दिए गए किसी भी निर्देश को प्रभावी बनाना

संघ की किसी के अधीन कार्यकारी शक्ति

इस संविधान के प्रावधानों के लिए यह विधिसम्मत होगा

राष्ट्रपति ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें राज्य सरकार को उसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

इस संविधान के प्रावधानों के साथ '

अनुच्छेद 256 और 257 में विभिन्न विषयों का उल्लेख है।

जिस पर केंद्र सरकार कार्यकारी निर्देश दे सकती है

संविधान हमें बताता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों पर लागू होता है जिन पर संसद को अधिकार है -

कानून बनाएँ'। संविधान का अनुच्छेद 248 छूट देता है। संसद में सक्रिय रूप से कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ

समवर्ती या राज्य में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर

सूचियाँ. संविधान के अनुच्छेद 256 में ऐसे मामले शामिल हैं जहाँ

राष्ट्रपति के अभ्यास में निर्देश देना चाह सकते हैं

संघ की राज्य सरकार को कार्यकारी शक्ति

द्वारा बनाए गए मौजूदा कानून द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में संसद जो उस राज्य पर लागू होती है। लेकिन, कला। 257 ( 1 )

एक व्यापक दायित्व अधिरोपित करता है

अभ्यास के लिए

राज्य

ए पर

इसकी शक्तियाँ इस तरह से कि exe के अभ्यास में बाधा न डालें

संघ की विच्छेदन शक्ति जो, जैसा कि दिखाई देगी

कला. 73 संविधान, कला के साथ पढ़ा जाता है। 248 इसमें शामिल हो सकते हैं

यहाँ तक कि एक ऐसा विषय जिस पर कोई मौजूदा कानून नहीं है लेकिन

जिसे संसद द्वारा कुछ कानून बनाना संभव है। यह हो सकता है,

इसलिए, यह तर्क दिया जाना चाहिए कि हालांकि, संविधान स्वयं

विशेष रूप से निर्धारित नहीं करता है जब डिसोलू की शक्ति

राज्यपाल की सलाह पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए -

राज्य में मंत्रिपरिषद, फिर भी अगर उस पर एक निर्देश

मामला केंद्र सरकार द्वारा उचित रूप से दिया गया था

राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह इसे पूरा करे। वह समय।

राज्य विधानसभा के विघटन के लिए इसके अंतर्गत नहीं आता है -

( 1 ) ए. आई. आर. 1977 एस. सी. पी. 1361 , 1383-84 .

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48

संविधान का कोई विशिष्ट प्रावधान या बनाया गया कोई कानून

विषय पर। हालाँकि, यह संघ सरकार के लिए संभव है अपनी अवशिष्ट कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए

इसे एक उपयुक्त निर्देश के मुद्दे के लिए एक उपयुक्त विषय समझें। जब यह विचार करता है कि राजनीतिक स्थिति में

देश ऐसा है कि देश में एक नया चुनाव आवश्यक है।

राजनीतिक स्थिरता का भय या विश्वास स्थापित करने के लिए

सरकार में लोग। एक राज्य का "। ( पी। 1383-84 ) .

उस मामले में, संघवाद की सीमा पर विचार करने के बाद

हमारा

संविधान का भी पालन किया गया था (पी। 1383):

" अगर तब हमारा संविधान एक केंद्र सरकार बनाता है

जो उभयचर है 'इस अर्थ में कि यह या तो चल सकता है

संघीय या एकात्मक स्तर पर, आवश्यकताओं के अनुसार

किसी मामले की स्थिति और परिस्थितियाँ, वह प्रश्न जो

हम इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित हैं कि क्या कोई मूल्यांकन

'स्थिति' जिसमें केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए

संघीय या एकात्मक स्तर पर स्थिर के लिए मामले हैं

स्वयं केंद्र सरकार या इस न्यायालय के लिए विचार करना और

तय करें। गणराज्य के प्रत्येक अंग से अपेक्षा की जाती है कि

अपनी शक्तियों की सीमाओं को जानें। न्यायपालिका आती है

आम तौर पर केवल तभी जब अधिकारातीत कार्रवाई का कोई सवाल हो

शामिल है, क्योंकि संबंधित अधिकार से संबंधित प्रश्न

इसका डोमेन "।

ऊपर दिए गए पहले उद्धरण में, जिसके बारे में कहा गया था

"केंद्र सरकार की अवशिष्ट कार्यकारी शक्ति", अनुरूप

संसद की "अवशिष्ट" विधायी शक्तियों पर भरोसा किया गया था

केंद्र के कथित "निर्देश" के समर्थन में। मामले में हमारे सामने यह निश्चित रूप से आग्रह किया जा सकता है कि

सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सरकार है। या इसके मुख्यमंत्री गाड़ी चलाते हैं या नहीं इस विश्वास को दूर करना कि कौन सी संवैधानिक शक्ति हाथों में है

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग यह आवश्यक है या नहीं, यह निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जो इसके भीतर निहित है।

द.

केंद्र सरकार की शक्तियाँ। अनुच्छेद 356 की बात करता है

द.

"राज्यपाल की रिपोर्ट से राष्ट्रपति की संतुष्टि" या

राज्य का कार्य प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है संविधान से। ऐसा मामला निश्चित रूप से एक मुद्दा होगा

सार्वजनिक महत्व। यदि राष्ट्रपति को यह देना आवश्यक लगता है राज्य सरकार। या उसके मुख्यमंत्री को सुनने का अवसर मिले।

अधिनियम के तहत गठित एक निष्पक्ष जांच आयोग के समक्ष। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग का ऐसा तरीका पूरी तरह से संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा निहित नहीं है। वास्तव में, ऐसी प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्ष और उचित होगी। और, प्रावधानों की वैधता का न्याय करने में उन काल्पनिक स्थितियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है जिन पर वे लागू हो सकते हैं, न कि केवल अदालत के समक्ष मामले में मौजूद लोगों को। हमें नहीं लगता कि संविधान के स्पष्ट प्रावधानों की जांच वादी के मामले को आगे बढ़ाती है।

कर्नाटक वी. यूनिन (बेग, सी. जे.)

49

दूसरी ओर, केंद्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों पर भी भरोसा कर सकती है।

संविधान के प्रावधानों में अनिवार्य रूप से निहित माना जा सकता है, अर्थात् अनुच्छेद 356 द्वारा अपेक्षित संतुष्टि के उद्देश्यों के लिए जांच का आदेश देने की शक्ति। और हमें लगता है कि अधिनियम द्वारा समर्थित तंत्र का उपयोग यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि क्या अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई वास्तव में आवश्यक है।

हालाँकि, रिलायंस को प्रावधानों पर दृढ़ता से रखा गया था

हमारे संविधान के प्रमुख रचनाकारों में से एक, डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में, संविधान की स्थापना "दोहरी राजनीति" है, जिसके द्वारा, जैसा कि राजस्थान राज्य (उपरोक्त) के मामले में समझाया गया था, उनका अर्थ समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार "एकात्मक और संघीय दोनों" गणराज्य था। हमारी यह "दोहरी राजनीति" ऐतिहासिक दुर्घटनाओं का एक कारण है, या, किसी भी तरह से, उन परिस्थितियों के अलावा, जो वास्तविक संघों में परिणित होती हैं, जिसमें संघात्मक इकाइयों की एक अलग पहचान और सरकारी स्वतंत्रता की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि केंद्र सरकार की शक्तियों के सख्ती से सीमांकित क्षेत्र के साथ एक संघ के अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। एक संघीय राजनीति केंद्रीय प्राधिकरण को केवल विदेशी मामलों और रक्षा जैसे मामलों में सहयोग के अधिक सख्ती से सीमित क्षेत्र तक सीमित करने की सीमा तक सीमित करती है ताकि यह सीमित क्षेत्रों में सहकारी कार्रवाई का एक तंत्र स्थापित कर सके जिसे शायद ही एक सरकार के रूप में कहा जा सकता है। एक वास्तविक संघ राजनीतिक इकाइयों का एक संयोजन है जो केंद्रीय प्राधिकरण को राज्य कार्रवाई के सख्ती से विकृत क्षेत्रों से बाहर रखने के लिए दृढ़ता से पालन करता है, लेकिन एक केंद्रीय या संघीय "सरकार" है। संघवाद की स्थापना की सीमा कार्यकारी, विधायी और न्यायिक क्षेत्रों में सीमांकन की सीमा पर निर्भर करती है। सही मायने में संघीय संविधान में यह सीमांकन बहुत सावधानीपूर्वक व्यापक और विस्तृत तरीके से किया जाता है। सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई हैं। इस प्रकार हमें अपने संविधान की जांच करनी होगी।

यह निर्धारित करने के लिए कि यह कितना यहाँ पाया जाता है।

निस्संदेह, हमारे इतिहास के लंबे समय के दौरान, हमारी सफलताएँ

बुद्धिमान शासक पूरे देश पर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अपना शाही प्रभाव स्थापित करके भारत की एकता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वास्तव में अंग्रेज ही थे जो इस तरह के उद्देश्य को वास्तविकता देने में सफल रहे। और, यहाँ तक कि उन्होंने सरकार की प्रणालियों के दोहरेपन को भी बनाए रखा। गवर्नर के अधीन एक ब्रिटिश भारत था

राज्यपालों के अधीन विभिन्न प्रांतों की नियति की अध्यक्षता शाही उप-अभिकर्ताओं के रूप में करते हैं, लेकिन सभी उनकी ओर से कार्य करते हैं।

अ.

सम्राट जिनकी सरकारों ने वेस्टमिंस्टर और व्हाइटहॉल से शासन किया। और, देश के अन्य हिस्सों में एक विदेशी सम्राट के प्रति निष्ठा रखने वाले भारतीय राजकुमारों द्वारा शासन किया जाता था, जिनके अधिकार के लिए वे उनकी संप्रभुता या उनके वायसराय के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे। इन दोनों भागों को बुनने की कोशिश की गई थी।

1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक संघीय राजनीति में एक साथ। एक संघीय न्यायालय सहित संघीय सिद्धांत इसमें सन्निहित थे ताकि दो अलग-अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों और प्राधिकरणों के समूहों को एक साथ लाया जा सके और उनका समन्वय किया जा सके। लेकिन, संविधान (1978) के बाद 2 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50

हमारे गणराज्य में, रियासतों का क्रमिक रूप से विलुप्त होना और केवल एक केंद्रीय निर्देश के तहत उनके अधिक प्रभावी और प्रभावी संचालन के उद्देश्यों के लिए सरकार की एजेंसियों के दोहरेपन के साथ एक ही राजनीति में भारत का एकीकरण हुआ। यह कमोबेश कम से कम केंद्रीय पर्यवेक्षण के तहत श्रम विभाजन के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग था। दूसरे शब्दों में, केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार के अंगों की द्वैतता या दोहराव किसी भी अलगाववादी भावनाओं के आधार पर शक्तियों के सही मायने में संघीय सीमांकन को नहीं दर्शाता है जो भारतीय जनता की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल सकता है, जिसके लिए हमारी संविधान सभा के सदस्य विशेष रूप से कुछ स्पष्ट रूप से विनाशकारी परिणामों के साथ देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद उत्साही रूप से समर्पित लग रहे थे।

हालांकि, हम अपने संविधान के स्पष्ट प्रावधानों की जांच कर सकते हैं।

राज्यों में सरकार के अंगों से संबंधित शिक्षा जो, निस्संदेह, कुछ उद्देश्यों के लिए पूर्ण-स्तरीय अलग राज्यों का रूप देती है। प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होता है जो उस राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन, सभी राज्यपाल, हालांकि अपने-अपने राज्यों के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने का वचन देते हैं, लेकिन वे जनता के प्रति अविभाजित निष्ठा रखते हैं। संविधान और कानून "। उनमें से प्रत्येक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करता है, जिसे वह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी प्रस्तावित कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए अपना प्रतिनिधि भेजता है। राज्यपाल का अधिकार, उनकी नियुक्ति के वारंट के तहत, राष्ट्रपति को पता चलता है, जिन्हें वह इस्तीफा देने पर अपना इस्तीफा सौंपना होता है।

अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की बात करता है।

राज्यपाल को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख मंत्री, सिवाय इसके कि इस संविधान द्वारा या उसके तहत उन्हें अपने या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने की आवश्यकता है। अब, सैद्धांतिक रूप से सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद निश्चित रूप से "राज्य की विधान सभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी" है (देखें - अनुच्छेद 164 (2))। लेकिन, यह "सामूहिक उत्तरदायित्व", जैसा कि हमारे सामने गलती से तर्क देने का प्रयास किया गया है, एस के तहत एक आयोग नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम या छोटा नहीं करता है। 3 अधिनियम से। वास्तव में, इस "सामूहिक जिम्मेदारी" का एक दायरा और संचालन का तरीका है जो एस के तहत जांच से बहुत अलग है। 3 भले ही एक ही या समान मामले, कभी-कभी, दोनों को जन्म दे सकते हैं: सामूहिक उत्तरदायित्व मूल रूप से राजनीतिक मूल और संचालन का तरीका है। यह उन मामलों में भी उत्पन्न हो सकता है जिनमें अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं हो सकती है। और, अधिनियम की धारा 3 के तहत जांच किए गए मामलों का किसी भी "सामूहिक प्रतिक्रिया" पर कोई असर नहीं हो सकता है।

बिलीटी "।

सामूहिक जिम्मेदारी का उद्देश्य पूरे शरीर को बनाना है।

सामूहिक रूप से मंत्री पद धारण करने वाले व्यक्तियों का, या, यदि कोई ऐसा कहे, तो दूसरों के ऐसे कृत्यों के लिए "परोक्ष रूप से" जिम्मेदार होना, जैसे -

चाप

उनकी सामूहिक इच्छा के लिए संदर्भित ताकि, भले ही कोई व्यक्ति इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार न हो, फिर भी, उसे साझा करने वाला माना जाएगा:

‘कर्नाटक वी. यूनियन (बेग; सी. जे.)

51

उन लोगों के साथ जिम्मेदारी जिन्होंने वास्तव में कुछ किया होगा गलत है। दूसरी ओर, हमारे समक्ष मामले में, के तहत जांच ग़्रोवर आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 3 का आदेश दिया गया है केंद्र सरकार ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वास्तव में कौन जिम्मेदार है कुछ कार्यों के लिए और उनके पीछे क्या मकसद हो सकता है। द. इस जांच का क्षेत्र उससे बहुत अलग है जिसमें "सामूहिक" उत्तरदायित्व "कार्य। "सामूहिक उत्तरदायित्व" की व्याख्या करते हुए, इंग्लैंड में समझे जाने वाले, संवैधानिक मामलों पर दो लेखक (देखें): " जेफ़री मार्शल द्वारा संविधान की कुछ समस्याएं। और ग्रीम सी. मूडी) कहते हैं: ( पी पर। 71):

" यदि औपचारिक संवैधानिक व्यवस्था में जिम्मेदारी ली जाती है ऐसा प्रतीत होता है कि सामूहिक सरकारी अधिकार दिए गए हैं उत्तरदायित्व, के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं होना चाहिए। मंत्री-मंडल के अंदर और बाहर के मंत्री। रेज़ होना इस अर्थ में दायित्व केवल परिणामों को साझा करना है।

उत्तरदायित्व-अर्थात् इस नियम के अधीन होना कि नहीं सरकार का सदस्य उचित रूप से सदस्य बना रह सकता है।

और अलग हो जाते हैं। स्वयं अपनी नीतियों से (अवसरों को छोड़कर)

जब सरकार सदन में स्वतंत्र मतदान की अनुमति देती है) ",

वे जोड़ते हैं: \*

" सरकार के सामूहिक जवाब का सार

व्यवहार्यता को अपनी नीति प्रस्तुत करने के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

और हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष अपनी नीति का बचाव करना, और विश्वास के मुद्दे पर हारने पर इस्तीफा दें "।

प्रत्येक मंत्री अपने लिए अलग से जिम्मेदार हो सकता है और हो सकता है।

निर्णय और कार्य और चूक भी। लेकिन, कौंसिल के रूप में

मंत्री वर्ग केवल तब तक पद पर रह सकता है जब तक वह आदेश देता है।

विधानमंडल के अधिकांश सदस्यों का समर्थन और विश्वास

राज्य की प्रकृति, पूरी मंत्रपरिषद को आयोजित किया जाना चाहिए

प्रत्येक के निर्णयों और नीतियों के लिए राजनीतिक रूप से जिम्मेदार होना

मंत्री और उनके विभाग के जिनके होने का अनुमान लगाया जा सकता है

पूरे मंत्रालय का समर्थन। इसलिए, पूरा मंत्रालय,

कम से कम नीतिगत मामलों से जुड़े मुद्दों पर, के रूप में माना जाना चाहिए

एक इकाई जहाँ तक विधान सभा के प्रति उसकी जवाबदेहिता है निर्वाचकों को प्रस्तुत करना संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि

संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में अंतर्निहित सिद्धांत। पुर। इस प्रावधान का उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना या वास्तविक स्थिति को स्थापित करना नहीं है।

मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री या मंत्री की जिम्मेदारी

विशेष निर्णयों या सरकारी अधिनियमों के लिए। यह अधिक हो सकता है। उचित रूप से किया गया, जब गलत कार्यों या निर्णयों की शिकायत की जाती है, अधिनियम के तहत पूछताछ के माध्यम से। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक मामले की जाँच करने के लिए संसदीय समितियों की प्रक्रिया कानूनी या नैतिक रूप से गलत कार्य असंतोषजनक पाया गया और अस्वास्थ्यकर। व्यक्तिगत और साथ ही सामूहिक मंत्रों का सिद्धांत जिम्मेदारी सबसे कुशलता से तभी काम कर सकती है जब मामलों की आवश्यकता हो। साक्ष्य की उचित जांच और मूल्यांकन और प्रश्नों की चर्चा संलिप्तता हुई है, जहां यह आवश्यक है, कार्यवाही में के अधीन नियुक्त आयोग के समक्ष। 3 अधिनियम से।

[ 1978 ] 2 एससीआर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52

संवैधानिक कानून पर पाठ्य पुस्तकों के लेखकों ने संकेत दिया है कि कैसे

संसद के प्रति सामूहिक मंत्री जिम्मेदारी, जिसका अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक उद्देश्य और प्रभाव है, संसद के प्रति मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बाद में विकसित हुई जो मूल और संचालन में राजनीतिक भी थी। यह सच है कि एक व्यक्तिगत मंत्री, इंग्लैंड में, जहां मंत्रियों की व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिक्रिया क्षमता का सिद्धांत विकसित किया गया था, या तो पूरे मंत्रिमंडल के अधिकार के बिना या सम्राट के समर्थन के बिना, या राजा के आदेश के तहत, जो कानून की नजर में, कोई गलत नहीं कर सकता था, उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकता था। लेकिन, एक महाभियोग के अलावा, जो अप्रचलित हो गया है, या एक सदन की अवमानना के लिए सजा, जो केवल एक सीमित प्रकार के अपराधों का गठन करती है, संसद अपराधी को दंडित नहीं करती है। उसके कानूनी दायित्व को स्थापित करने के लिए कानून की सामान्य अदालतों का सहारा लेना अनिवार्य है।

संसद के प्रति जिम्मेदारी का मतलब केवल यह है कि मंत्री हो सकता है

अधिवेशन द्वारा त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया। एहि दायित्वसँ सामूहिक उत्तरदायित्वक सिद्धान्त उत्पन्न भेल। इस प्रकार, "संवैधानिक कानून" पर वेड और फिलिप्स में, 8 वीं संस्करण।, पी। 87, हम पाते हैं; "जैसे ही यह माना गया कि एक भी मंत्री संसद की इच्छा के विरुद्ध पद पर नहीं रह सकता है, वैसे ही बाद में यह स्पष्ट हो गया कि सभी मंत्रियों को पद पर बने रहना चाहिए। संसद में एक साथ खड़े हों या गिरें, अगर सरकार को गाड़ी बनना था

कई सलाहकारों के बजाय एक एकता के रूप में

संप्रभु के अलग से कार्य करने पर जोर दिया "। सामूहिक उत्तरदायित्व के इस विकास का वर्णन 1878 में लॉर्ड सैलिसबरी द्वारा किया गया था:

" मंत्रिमंडल में पारित होने वाले सभी सदस्यों के लिए जो

इस्तीफा न देना पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से जिम्मेदार है

और बाद में उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह एक में सहमत हो गया

एक समझौते के लिए मामला, जबकि दूसरे में उसे राजी किया गया था उनके सहयोगियों द्वारा। यह केवल इस सिद्धांत पर है कि निरपेक्ष

जिम्मेदारी काबी के प्रत्येक सदस्य द्वारा ली जाती है।

नेट, जो, एक निर्णय पर पहुंचने के बाद, सदस्य बना रहता है

यह, कि संसद के प्रति मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी बनाए रखा जा सकता है और सबसे आवश्यक सिद्धांतों में से एक

संसदीय उत्तरदायित्व स्थापित किया गया। "

जिम्मेदारी का पूरा सवाल निरंतरता से संबंधित है।

कार्यालय में किसी मंत्री या सरकार का। एक मंत्री के अपने कार्य या चूक या उसके प्रभारी विभाग में अन्य लोगों के लिए, जिसे वह नैतिक रूप से जिम्मेदार महसूस कर सकता है, या जिसके लिए अन्य लोग उसे नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकता है। इस तर्क के विस्तार से, जो पहले अलग-अलग मंत्रियों पर लागू होता है, उभरता है

"सामूहिक उत्तरदायित्व" का सिद्धांत जिसे हम अपने संविधान के अनुच्छेद 75 (2) और 164 (2) में अधिनियमित पाते हैं। इसके प्रवर्तन के लिए एकमात्र प्रतिबंध जनमत का दबाव है जो विशेष रूप से सदस्यों द्वारा राजनीतिक समर्थन वापस लेने के संदर्भ में व्यक्त किया गया है।

संसद या राज्य विधानमंडल, जैसा भी मामला हो।

प्रो. एस. ए. डी. स्मिथ अपने संविधान में बताते हैं और

प्रशासनिक कानून, 1971, पी। 170 17 9 से, सिद्धांत में काम करता है

एक अस्पष्ट नैतिक-सह-राजनीतिक क्षेत्र, कभी-कभी एक भारतीय को मजबूर कर देता है

श्री प्रोफुमो के मामले की तरह, और कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) पर, मंत्री का इस्तीफा देना।

53

समग्र रूप से मंत्रिमंडल किस हद तक हो सकता है, एक विशेष मामले की परिस्थितियाँ, जिसके लिए जिम्मेदार माना जाता है

विशेष निर्णय या कार्रवाई या निष्क्रियता। इंग्लैंड में, सिद्धांत

राजनीतिक निर्णय द्वारा समर्थित परंपरा के मामले के रूप में कार्य करता है, जैसा कि

संविधान स्वयं, लेकिन यह, फिर भी, परंपरा पर निर्भर करता है और जनमत पर, विशेष रूप से जैसा कि संसद या संसद में परिलक्षित होता है

राज्य विधानमंडल, यथास्थिति, अपनी प्रभावशीलता के लिए। द.

इस प्रकार सिद्धांत कानूनी दायित्व से अलग और स्वतंत्र रूप से मौजूद है। संघ या राज्य सरकार में पद धारण करने वाले मंत्री का दायित्व

मन में।

जाँच आयोग द्वारा जाँच को सुविधा प्रदान करनी चाहिए या

सुदृढ़ जनमत के निर्माण में सहायता करना। यही उद्देश्य था

लॉर्ड डेनिंग की अध्यक्षता में जांच आयोग

प्रोफुमो अफेयर। तथ्य यह है कि संबंधित मंत्री कोन था

गलत बयान के लिए सदन के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होना इससे आयोग द्वारा मामलों की जांच को रोका नहीं जा सका

जिस पर उन्होंने बयान दिया था। उसके व्यक्तिगत कार्य, कैसे

कभी भी, सामूहिक प्रतिक्रिया के सिद्धांत को अमल में नहीं लाया योग्यता क्योंकि सरकार में उनके सहयोगी उचित रूप से नहीं कर सके

लापरवाही या किसी भी कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी ठहराया जाए।

ए कॉनिमिसन ऑफ इन्क्वायरी का मतलब ठीक से नहीं हो सका,

जैसा कि है।

कभी-कभी संदेह किया जाता है, केवल सफेद-धोने वाले मंत्री या प्रतिनिधि के लिए यदि संभव हो, तो वास्तविक तथ्यों का पता लगाने और खोज करने के बजाय कार्रवाई करें।

यह अभियोजन के एक तरीके के रूप में काम करने के लिए भी नहीं है और बहुत

उत्पीड़न कम। इससे पहले की कार्यवाही विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकती है।

के लिए। कार्यवाहियाँ जो किसी न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए

. न्यायनिर्णयन के साथ-साथ दंड देने की शक्तियों के साथ

या राहत प्रदान करना। इसकी रिपोर्ट या निष्कर्ष अदालतों को राहत नहीं दे सकते हैं।

जिनके द्वारा निपटाए गए मामलों को स्वयं निर्धारित करना पड़ सकता है

आयोग। वास्तव में, एक की कानूनी प्रासंगिकता या साक्ष्य मूल्य

आयोग की रिपोर्ट या उन मुद्दों पर निष्कर्ष जो किसी न्यायालय के पास हो सकते हैं

अपने लिए निर्णय लेना बहुत संदिग्ध है। एक कॉम की नियुक्ति

किसी मामले की जाँच करने के लिए जाँच का मिशन, जो आदेश में होना चाहिए

किसी भी मामले में, कानून की अदालत में जाना आम तौर पर एक स्वीकारोक्ति है

पर्याप्त साक्ष्य की कमी-जैसा कि नियुक्ति के मामले में

दिवंगत राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या-इसे अदालत में ले जाने के लिए जनता की  
आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के प्रयास के साथ संयुक्त

पता लगाएँ कि वास्तव में क्या गलत हुआ था और यदि संभव हो तो कैसे और कहाँ।

अतः जाँच आयोग का अपना एक कार्य होता है जिसे पूरा करना होता है। फिल। इसकी  
अपनी किर्या की एक कक्षा है जिसके भीतर यह आगे बढ़ सकता है।

कार्रवाई के अन्य रूपों या तरीकों के साथ संघर्ष या बाधा न डालने के लिए

या तो निष्पक्ष और निष्पक्ष नहीं हैं या अन्य कारणों से असंतोषजनक हैं जैसा कि वारेन  
आयोग की रिपोर्ट के मामले में कहा गया था।

अनुच्छेद 75 (2) या अनुच्छेद 164 (2) के प्रावधान नहीं हो सके।

आयोगों [1978] 2 एस. सी. आर. द्वारा जांच की संस्था के खिलाफ अवरोधक के रूप में कार्य  
करना।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54

अधिनियम के तहत स्थापित। संविधान के अनुच्छेद 75 (2) और 164 (2) दोनों में पाए जाने  
वाले सिद्धांतों के उद्देश्य के साथ-साथ संचालन के तरीके और क्षेत्र और अधिनियम के तहत  
स्थापित जांच आयोगों के उद्देश्य, दायरे और कार्य को भी गलत समझना होगा।

कुछ संवैधानिक पक्ष खोजने के लिए कुछ हताश प्रयास में

ग्रोवर आयोग ने जिन जाँचों पर रोक लगाई है

वादी के विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद 194 (3) पर भरोसा किया। अनुच्छेद 194 के  
विशेष खंड (3) को अनुच्छेद 194 के अन्य खंडों के साथ-साथ अनुच्छेद 194 (1) द्वारा इंगित  
संविधान के शेष प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। हम यहाँ पूरे अनुच्छेद 194 को  
निर्धारित कर सकते हैं जो इस प्रकार है:

" 194 \* ( 1 ) . इस संविधान के प्रावधानों के अधीन

विधान-मंडल की प्रक्रिया, स्वतंत्रता होगी  
प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में भाषण ।

( 2 ) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य नहीं होगा

के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी  
विधानमंडल में उनके द्वारा कुछ भी कहा गया या कोई वोट दिया गया  
लैटर या उसकी कोई समिति, और कोई भी व्यक्ति  
द्वारा या उसके तहत प्रकाशन के संबंध में इतना उत्तरदायी हो  
ऐसे विधानमंडल के किसी सदन का अधिकार  
रिपोर्ट, कागज, वोट या कार्यवाही ।

( 3 ) अन्य मामलों में, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और अधिकार

किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की इकाइयाँ, और  
किसी सदन के सदस्यों और समितियों का  
ऐसा विधानमंडल ऐसा होगा जो समय-समय पर  
समय को विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा परिभाषित किया जाएगा, और, जब  
तक  
इस प्रकार परिभाषित, हाउस ऑफ कॉम के होंगे  
यूनाइटेड किंगडम की संसद के सदस्य, और  
प्रारम्भ में इसके सदस्यों और समितियों के  
इस संविधान का ।

( 4 ) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान

उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होता है जो इस आधार पर  
संविधान को बोलने का अधिकार है, और अन्य  
सदन की कार्यवाही में भाग लेना बुद्धिमानी होगी ।

किसी राज्य का विधानमंडल या उसकी कोई समिति  
जैसा कि वे उस कानून के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं

प्रकृति "।

अनुच्छेद 194 इस स्पष्ट के साथ अनुच्छेद 105 की शर्तों को दोहराता है।

अंतर यह है कि जहां अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों पर लागू होता है, वहीं अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों पर लागू होता है। इन दोनों अनुच्छेदों में से प्रत्येक प्रत्येक सदन के साथ-साथ इसके सभी सदस्यों और समितियों की "शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों" के विषय में न केवल उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए बल्कि संविधान के अन्य सभी प्रावधानों के लिए भी है। इन अनुच्छेदों से यह स्पष्ट है कि वे संसद या कर्नाटक v की विधायी शक्तियों पर लागू नहीं होते हैं।

यूनियन (बेग, सी. जे.)

5.5 .

राज्य विधान मंडल जिन पर संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक विशेष रूप से विचार किया जाता है। अनुच्छेद 105 और 194, क्रमशः संसद के सदनों या राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों से संबंधित नहीं हैं, प्रत्येक सदन की ऐसी शक्तियों के दायरे में सीमित हैं जो एक सदन के रूप में अलग से कार्य कर सकते हैं। इसमें सदन के साथ-साथ इसके सदस्यों के रूप में प्रत्येक सदन की प्रतिभूतियां और विशेषाधिकार भी शामिल हैं।

लागू करने के लिए व्याख्या का सही सिद्धांत है "एक समाज नहीं",

या, दूसरे शब्दों में, "शक्तियाँ" शब्द को इसका अर्थ और रंग नहीं मिलता है केवल  
इसके संदर्भ से बल्कि संघ में उपयोग किए जाने वाले अन्य शब्दों से भी

इसके साथ।

यह उस अध्याय से स्पष्ट है जिसमें अनुच्छेद 194 इस प्रकार आता है -

साथ ही शीर्षक और इसके सीमांत नोट का अर्थ है "शक्तियाँ"

यहाँ जो संकेत दिए गए हैं वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे ऐसी शक्तियाँ हैं जो

व्यवसाय के संचालन के लिए निर्भर और आवश्यक हैं

हर घर। इन्हें सदन में भी विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

सभी उद्देश्यों के लिए इंग्लैंड में कॉमन्स। उदाहरण के लिए, यह नहीं हो सकता है

यह पूरी तरह से संप्रभु विधानमंडल का हिस्सा है। हमारे कानून के तहत यह वह संविधान है जो संप्रभु या सर्वोच्च है। संसद

साथ ही भारत में किसी भी राज्य के प्रत्येक विधानमंडल को केवल इस तरह के कानून मिलते हैं। मूल शक्तियाँ जो संविधान इसे प्रदान करता है। इसी तरह, प्रत्येक

संसद के सदन या राज्य विधानमंडल का विधायी में ऐसा हिस्सा है।

शक्ति जो स्वयं संविधान द्वारा उसे सौंपी गई है। इन शक्तियों राज्य विधानमंडल के किसी सदन को प्रदान किए जाने वाले अधिकार कानून से अलग होते हैं।

संसद या किसी राज्य विधानमंडल की मूल शक्तियाँ जिनके लिए,

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हमारे संविधान में अलग-अलग प्रावधान हैं। हमें अनुच्छेद 194 के शब्दों से परे जाने की आवश्यकता नहीं है।

संविधान के अन्य प्रावधान, स्पष्ट रूप से इस तरह के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सायन।

ए.

अगर हम ऐसा कहें, तो इसमें अभी भी काफी भ्रम है

कुछ लोगों के मन परिभाषित शक्तियों के दायरे के बारे में,

राज्य विधानमंडल के एक सदन के अपमान और उन्मुक्ति " ताकि कभी-कभी यह कल्पना की जा सके कि राज्य विधानमंडल का एक सदन

लैचर के पास कुछ न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जो काफी अलग हैं। इसकी अवमानना के लिए सजा की मान्यता प्राप्त शक्तियों से या

इसकी नियुक्ति द्वारा की जा सकने वाली जाँच की शक्ति

स्पष्ट रूप से समझा कि, इंग्लैंड में भी, जहाँ संविधान है काफी हद तक पारंपरिक, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग सीधे

महाभियोग जैसी शक्तियों सहित विधायिका के सदन  
 वास्तव में, व्यावहारिक रूप से अप्रचलित हैं। सत्ता में जो कुछ भी बचा है एक  
 बार संसद के उच्च न्यायालय से खुशी हुई, जब राजा कर सकते थे  
 स्वयं संसद के एक भाग के रूप में संसद के सदनों के साथ बैठते हैं, न्याय का  
 प्रशासन करना अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केंद्रित है, उदाहरण के लिए  
 लॉ लॉर्ड्स की एक समिति के माध्यम से।  
 इंग्लैंड में संसद के सदन की प्रत्येक शक्ति के अधीन है -  
 संसद का एक अधिनियम। जिस अधिनियम से हमारा संबंध है वह एक [1978] 2 एस. सी.  
 आर. है।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

\* 56

हमारी संसद का अधिनियम। हमें संदर्भ द्वारा खुद को संतुष्ट करना होगा  
 हमारे समक्ष अधिनियम की शर्तें विधायी क्षमता के भीतर हैं संसद। लेकिन, अगर हम  
 अपने संविधान के प्रावधानों की अनदेखी कर सकते हैं  
 विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित, जो कि  
 अनुच्छेद 194 (3) पर आधारित तर्कों का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि हमें छोड़ दिया  
 जाएगा।  
 हमारी विधायी क्षमता निर्धारित करने के लिए कोई यार्ड-स्टिक नहीं  
 संसद। इस दृष्टिकोण को केवल इसलिए लेना बेतुका होगा क्योंकि  
 इंग्लैंड में यही स्थिति है। इंग्लैंड में कोई भी सवाल नहीं कर सकता था।  
 कानून बनाने की शक्ति संप्रभु संसद में निहित है। अगर हम उस सिद्धांत को यहाँ  
 लागू कर सकते हैं हमारे सामने अधिनियम पर्याप्त होगा

इसकी वैधता के खिलाफ सभी तर्कों का विवेकपूर्ण जवाब।

अगर यह सिद्धांत हमारे देश में प्रो के कारण लागू नहीं होता है  
हमारे संविधान के दृष्टिकोण, जो संविधान की अदालतों के न्यायाधीशों का गठन करते हैं  
संसद के अधिनियमों की भी राष्ट्रीयता, हमें प्रावधानों का परीक्षण करना होगा  
हमारे अपने संविधान के स्पष्ट प्रावधानों पर अधिनियम

और हाउस ऑफ कॉमन्स की गलत रूप से मानी गई शक्तियों पर नहीं इंग्लैंड में जो  
कभी भी प्रावधानों को अनदेखा या अमान्य नहीं कर सकता था

वहाँ की संसद द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम हालांकि यह निर्णायक भूमिका निभा सकता  
है यदि वह चाहे तो इसके निरसन में भूमिका निभाएँ।

"शक्तियों" और "विशेषाधिकारों" के बारे में भ्रम का एक स्रोत  
इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ कॉमन्स को लंबे समय तक हटाने की मांग की गई थी  
इससे पहले सर एस्किन मे द्वारा जब उन्होंने अपनी "संसदीय" में बताया था  
प्रक्रिया और अभ्यास ", 1844 में, कि कोक का उक्ति और ब्लैकस्टोन का  
विचार, जिनके अनुसार सामान्य कानून अदालतें न्याय नहीं कर सकती थीं  
"लेक्स पार्लियामेंट" से संबंधित मामले, इस आधार पर कि "उच्च  
संसद का कोई उच्च न्यायालय नहीं है ", 17 वीं में भी पुराना था  
शतक इंग्लैंड। उन्होंने इस तरह के विचारों के बारे में कहा:

" ये विचार उस समय के थे जब अंतर दांव पर लगा था  
संसद के न्यायिक और विधायी कार्यों में  
अप्रचलित या केवल खींचा जाना शुरू होता है और जब अलग किया जाता है  
कॉमन्स से लॉर्ड्स का गठन बहुत कम पूरा हुआ था  
सत्रहवीं शताब्दी की तुलना में। उच्च के बारे में विचार

संसद का न्यायालय और इसकी शक्तियाँ जो विरोधी होती जा रही थीं  
कोक के समय में रद्द किया गया, बहुत दूर तक दोहराया जाता रहा।

आधुनिक संविधान के तथ्य। लेकिन बहुत उलझन रह गया जिसे वाक्यांश के उपयोग से खारिज नहीं किया गया था

" संसद के विशेषाधिकार "।

सर एर्स्कन ने इसके परिणामस्वरूप तीन धारणाओं का संकेत दिया अंग्रेजी संवैधानिक इतिहास के दौरान यह "विचार का भ्रम" है। उन्होंने लिखा:

" विचार के इस भ्रम से तीन धारणाएँ उत्पन्न होती हैं:

- ( 1 ) कि अदालतें, उच्च न्यायालय से हीन होने के कारण संसद, के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकती है विशेषाधिकार के मामले पर कोई भी सदन।

1

कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

57

- ( 2 ) कि लेक्स एट कॉनसेउटुडो पार्लियामेंट एक अलग है कानून, और इसलिए, न्यायालयों के लिए अज्ञात।
- ( 3 ) कि प्रिवी की घोषणा करने वाले किसी भी सदन का संकल्प न्याय एक न्यायिक मिसाल है जो अदालतों पर बाध्यकारी है।

अब, वादी के लिए विद्वान वकील ने जो सुझाव दिया, वह था

कि एक विधानमंडल के प्रति जवाबदेह मंत्री एक अलग कानून द्वारा शासित होते थे जो उन्हें सामान्य कानून के तहत देनदारियों से छूट देता था। इंग्लैंड में यह कभी भी कानून नहीं था। और, यहाँ ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) में उल्लिखित हाउस ऑफ कॉमन्स की "शक्तियों" और "विशेषाधिकारों" से संबंधित भ्रम के आधार पर कुरान संविधान इस तरह के तर्कों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। हमारे संविधान में संसद के साथ-साथ राज्य

विधानमंडलों में भी केवल विधायी शक्ति निहित है। ! संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदन किसी पर या किसी भी मामले का प्रत्यक्ष रूप से मुकदमा नहीं चला सकता है, जैसा कि न्याय न्यायालय कर सकता है, लेकिन यह अपने अधिकार की अवमानना के मामलों में अर्ध-न्यायिक रूप से आगे बढ़ सकता है और अपने "विशेषाधिकार" से संबंधित प्रस्ताव ले सकता है।

लेग "और" प्रतिरक्षा "क्योंकि, ऐसा करने में, यह केवल हटाने की मांग करता है

इसके विधायी कार्यों के उचित निष्पादन में बाधाएं। लेकिन,

यदि अधिकारिता का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला यहाँ आता है या नहीं, यह सामान्य अदालतों द्वारा उचित प्रो में तय किया जाना है

आहार। उदाहरण के लिए, किसी आपराधिक अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र, जैसे

हत्या के रूप में, जो सदन के भीतर भी की जाती है, सामान्य अपराधी में निहित होती है

न्यायालयों में और न कि संसद के किसी सदन में या किसी राज्य विधानमंडल में। में।

श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण ('), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

संसद का कोई सदन किसी भी कथित "शक्तियों" का प्रयोग नहीं कर सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 के तहत गठित किए गए हैं। अनुच्छेद 329 के अनुपालन में अधिनियमित। इसी तरह, उचित प्रावधान

उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्तियों के लिए, जिन्हें शक्ति के साथ निवेश किया गया है

एक ऐसी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित करें जो उचित और

मामलों पर तथ्यों का पता लगाने के लिए न्यायसंगत और नियमित और कुशल

सार्वजनिक महत्व का, अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है। यदि ऐसे प्रावधान हैं -

विधायी क्षमता से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों द्वारा कवर किया गया

संसद और केंद्रीय सूची I या समवर्ती में से एक मद

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है

अन्य प्रावधानों के लिए जो, कड़ाई से बोलते हुए, प्रासंगिक नहीं होंगे

कम उन पर कुछ अपवाद स्पष्ट रूप से बनाने के लिए भरोसा किया जा सकता है

ऐसी विधायी क्षमता के विरुद्ध कार्य करना।

वादी के विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 वाले अध्याय 2, भाग 11 के प्रावधानों पर भी भरोसा किया है। यहाँ, हम संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 (1) पाते हैं जिनकी हम पहले ही जाँच कर चुके हैं ताकि प्रत्येक राज्य को आवश्यक निर्देश देने की भारत सरकार की शक्ति की सीमा को सामने लाया जा सके। वहाँ उपयोग किया जाने वाला "राज्य" शब्द संभवतः केवल एक भौगोलिक इकाई या क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकता था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1, उप-अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद 3 के बीच अंतर करते हैं।

राज्य और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 300, कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में, राज्य की सरकार को राज्य का कानूनी प्रतिनिधि बनाता है।

( 1 ) [ 1976 ] 2 एस. सी. आर. 347

1 [ 1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58

एक राज्य। एक निर्देश केवल एक कानूनी इकाई को दिया जा सकता है न कि एक कानूनी इकाई को।

भौगोलिक या एक क्षेत्रीय इकाई। इसलिए, "राज्य" के लिए "निर्देश", चूंकि इन शब्दों का उपयोग अनुच्छेद 256 और 257 में किया गया है, इसलिए अनिवार्य रूप से इसका अर्थ होना चाहिए।

राज्यों को कानूनी संस्थाओं के रूप में निर्देश जिनके पास कानूनी प्रतिनिधित्व होना चाहिए टाइम्स। राज्य सरकारों के साथ व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अपने-अपने राज्यों के प्रतिनिधि। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?

एक संविधान जो हमारा है, कहता है कि केंद्र सरकार को नहीं लेना चाहिए

3 ब्याज, और, परिणामस्वरूप, कोई भी कार्रवाई जो इसका स्वाद लेती है

राज्य सरकार के सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप? में।

राज्य विधानसभाओं के विघटन के मामले में हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे विषय पर कुछ विस्तार से इस न्यायालय के विचार

इस देश में हमारे पास किस तरह का संघ है

"एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह" के रूप में, या, किसी भी दर पर, शक्तियों के साथ

केंद्र सरकार को पर्यवेक्षण और यहाँ तक कि अधिनिर्णय भी दिया गया,

कुछ परिस्थितियों में, राज्य सरकारों को अस्थायी रूप से बहाल करने के लिए

सामान्य स्थिति में आना या राज्य प्रशासन में ईमानदारी, अखंडता और दक्षता का संचार करना।

जहाँ अच्छी सरकार की इन अनिवार्यताओं की आवश्यकता हो सकती है।

न तो संविधान का अध्याय द्वितीय भाग 11,

संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, न ही कोई

संविधान के अन्य भाग को निषेध का संकेत माना जा सकता है।  
किसी भी विधायी शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध। वास्तव में, ए

संसद की

भाग XI में अध्याय II पर नज़र डालने से पता चलता है कि, लेखों के अलावा

256 और 257 (1), यह केवल कुछ विशेष मामलों से संबंधित है, जैसे कि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों, जलमार्गों और रेलवे, निर्माण का अधिभोग

राष्ट्रीय या सैन्य महत्व की वस्तुओं के लिए किया जाना,  
का निर्वहन, कुछ मध्यस्थता, पूरे समय मान्यता

कुछ शक्तियों

कुछ सार्वजनिक अधिनियमों और न्यायिक कार्यवाहियों का भारत का क्षेत्र

संघ और प्रत्येक राज्य से संबंधित विवादों का निर्धारण

जल, और कुछ अन्य मामले जिनके बीच समन्वय शामिल है

राज्यों। यह नहीं कहा जा सकता कि यह उन सभी मामलों को समाप्त कर देता है जिनमें शामिल हो सकते हैं

विशेष राज्यों के साथ-साथ संघ के हित। वहाँ है।

यहाँ या हमारे संविधान के किसी भी प्रावधान में कुछ भी नहीं है

जो, एक आवश्यक निहितार्थ से, शर्तों को लागू करने के लिए कहा जा सकता है

भाग 1 द्वारा वितरित विधायी शक्तियों के प्रयोग पर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में तीन सूचियों के साथ पढ़ा गया।

इसलिए, इस तरह के प्रश्न का निर्धारण विशेष रूप से प्रो द्वारा किया जाना चाहिए।

यहाँ विधायी शक्तियों के साथ और प्रशासनिक संबंध के साथ नहीं दिशाएँ या निर्देश। यह सच है कि उन शक्तियों का इस तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

संविधान को विस्थापित करने या संशोधित करने के बारे में। लेकिन, जब तक उनके पास वह नहीं है

प्रभाव, प्रावधानों के पूरक और उचित निर्वहन को सुविधाजनक बनाने के लिए

संवैधानिक शक्तियों को सामान्य से अधिक नहीं माना जा सकता है।

विधायी शक्ति।

विधान के विशेष रूप से केंद्रीय विषयों की सूची I में प्रविष्टि 94

इस प्रकार पढ़ता है:

" 94. के उद्देश्य के लिए पूछताछ, सर्वेक्षण और सांख्यिकी

इस सूची में से कोई भी मामला:

यह सच है कि संघ सरकार के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले मामले मेंट और राज्य सरकार का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

यूनियन (बेग, सी. जे.)

संघ सूची में कहीं भी। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि यहां उल्लिखित "पूछताछ", भले ही वे सर्वेक्षण और आंकड़ों से परे हों, फिर भी, "इस सूची के मामलों" तक ही सीमित होनी चाहिए। इसे प्रस्तुत किया गया था। कि ऐसी "पूछताछ" में सरकारी शक्तियों का हवाला देते हुए मंत्रियों के आचरण को शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा आचरण सूची में किसी भी मद के तहत नहीं आता है, लेकिन ठीक से बोलते हुए, "प्रशासनिक संबंधों" पर अध्याय में जगह मिलनी चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि केंद्र सरकार वास्तव में एक जांच आयोग की स्थापना करके सरकारी कार्यों के निष्पादन में राज्यों में मंत्रियों के आचरण पर एक प्रकार के अनुचित अनुशासनात्मक अधिकार और नियंत्रण का प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी-एक ऐसा विषय, जिसे उचित रूप से केवल "संवैधानिक कानून" के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता था और जिसका उल्लेख हमारे संविधान के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से पाया जाना चाहिए था ताकि इसके लिए अपनाए गए साधनों के माध्यम से इस तरह के नियंत्रण को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके।

हमें नहीं लगता कि "संवैधानिक कानून" शब्द या तो हो सकता है।

स्पष्ट रूप से या संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है, हालांकि इसकी प्रकृति को मोटे तौर पर इस तरह से दर्शाया जा सकता है जिस तरह से पाठ-पुस्तक लेखकों ने इसे करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, प्रोफेसर ई. सी. एस. वेड और गॉडफ्रे फिलिप्स (देखें): संवैधानिक कानून, 8 म संस्करण. पृष्ठ 4) कहता है:

" संवैधानिक की कोई कठोर और तेज़ परिभाषा नहीं है।

कानून। शब्द के आम तौर पर स्वीकृत उपयोग में इसका अर्थ है

नियम जो प्रमुख अंगों की संरचना को विनियमित करते हैं

सरकार और एक दूसरे के साथ उनके संबंध, और बाधा

उनके प्रमुख कार्यों का खनन करें। "

दूसरे शब्दों में, इसमें केवल बुनियादी ढांचे का काम शामिल होने की उम्मीद की जा सकती है। सभी नियंत्रित मानसिक मामलों से पूरी तरह निपटना इसकी प्रकृति का हिस्सा नहीं है।

चूंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेखकों ने उद्धृत किया

ऊपर कहा गया है कि "संविधान का कोई अलग अस्तित्व नहीं है क्योंकि यह देश का सामान्य कानून है"। उन्होंने आगे कहा: " कानून का एक सामान्य निकाय है जो संविधान, आंशिक रूप से वैधानिक, आंशिक रूप से सामान्य कानून और आंशिक रूप से सम्मेलन बनाता है। इंग्लैंड में "संवैधानिक कानून" के रूप में पारित होने वाले सभी नियमों को अदालतों के माध्यम से लागू

करने योग्य नियमों के साथ जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि जिन सम्मेलनों को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता है, उन्हें भी जाहिर तौर पर इसके हिस्से के रूप में माना जाता है क्योंकि उनमें आचरण के नियम भी होते हैं। इस प्रकार, सभी "संवैधानिक कानून" को इस शब्द के सामान्य रूप से स्वीकृत अर्थ में लिखा या "कानून" होने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में, "संवैधानिक कानून" नामक नियमों के अंतर्गत क्या समझा जा सकता है और क्या नहीं समझा जा सकता है और क्या नहीं समझा जाना चाहिए, इसके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं हो सकता है। व्यवहार में, यह पाया जाएगा कि लिखित संविधान में भी जो कुछ सन्निहित है, वह कभी-कभी इसे बनाने वाले लोगों की विशिष्ट धारणाओं पर निर्भर करता है। यह उनके विचारों को दर्शाता है कि संवैधानिक दस्तावेज़ में जगह पाने के लिए क्या इतना बुनियादी या मौलिक माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1893 के स्विस संविधान के प्रावधानों में से एक "कसाइयों के मांस के लिए जानवरों को चिपकाने" पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि उन्हें पहले आश्चर्यचकित नहीं किया गया हो। "संवैधानिक कानून" की सामान्य धारणाओं के अनुसार, इस तरह के विषय को इसमें जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। कुछ लोगों का मानना है कि

5-

1042 एससीआई/77 [1978] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

60

किसी देश की सरकार की संरचना की रेखाएँ। बाकी,  
कानून" का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं

"संवैधानिक

साधारण विधायी शक्तियाँ।

प्रो. के. सी. व्हीयर ने अपने "आधुनिक संविधान" में एक अध्याय लिखा है।

"संविधान में क्या होना चाहिए", जिस पर वे टिप्पणी करते हैं:

" विभिन्न देशों के संविधानों पर एक नज़र

यह एक बार में दिखाता है कि लोग जो सोचते हैं उसमें बहुत अंतर है

इसे संविधान में शामिल करना आवश्यक है। नॉर्वे के लोग

वे सब कुछ कहने में सक्षम थे जो वे लगभग बीस में कहना चाहते थे

पाँच पृष्ठ; भारतीयों ने लगभग दो सौ पचास पर कब्जा कर लिया

1950 के उनके संविधान के पृष्ठ। एक प्रमुख रेखा

संविधान को मानने वालों के बीच विभाजन पाया जाता है।

मुख्य रूप से और लगभग विशेष रूप से एक कानूनी दस्तावेज के रूप में

जिसके लिए, इसलिए, कानून के नियमों के लिए एक जगह है लेकिन व्यावहारिक रूप से और कुछ नहीं, और जो एक संविधान के बारे में सोचते हैं

एक प्रकार के घोषणापत्र, विश्वास की स्वीकारोक्ति, एक बयान के रूप में आदर्शों का, एक 'भूमि का चार्टर', जैसा कि श्री पोड्सनप ने इसे कहा था।

उन्होंने कहा कि "आदर्श या सर्वश्रेष्ठ की एक आवश्यक विशेषता"

संविधान का रूप यह है कि यह सबसे कम संभव होना चाहिए। और,

संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने 1819 में कहा

मैककुलोच बनाम। मैरीलैंड ('):

" एक संविधान जिसमें सभी का सटीक विवरण हो

उपखंड जिनमें से इसकी महान शक्तियाँ स्वीकार करेंगी, और सभी में से

जिन साधनों से उन्हें निष्पादित किया जा सकता है,

एक कानूनी संहिता की प्रोलिक्सटी में भाग लेंगे, और कर सकते हैं शायद ही मानव मन द्वारा अपनाया जाए। यह फायदेमंद होगा।

शायद जनता द्वारा कभी नहीं समझा जाएगा। इसकी प्रकृति, वहाँ आगे, यह आवश्यक है कि केवल इसकी महान रूपरेखा को चिह्नित किया जाना चाहिए,

इसकी महत्वपूर्ण वस्तुओं को नामित किया गया है, और छोटी सामग्री

जो उन वस्तुओं की रचना करते हैं, उनकी प्रकृति से पता लगाया जा सकता है

वस्तुएँ स्वयं "।

यह सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके अनुरूप होने की कोशिश नहीं की

ऊपर बताए गए मानक। यह काफी हद तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हमारे संविधान बनाने के तरीके के कारण था। हमने एक साफ स्लेट के साथ शुरुआत नहीं की। हम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में सन्निहित योजना को अपने प्रारंभिक बिंदु के रूप में स्वीकार करते हैं, जो स्पष्ट रूप से हमारे देश के शासन के लिए कानूनी नियमों का एक व्यापक और त्रुटिहीन सेट प्रदान करने के प्रयास में है। इस पर, जापान सहित विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए सिद्धांतों, कभी-कभी परस्पर विरोधी, और पृथ्वी के सभी कोनों से एकत्र किए गए न्यायिक ज्ञान और अनुभव के परिणामों वाले प्रावधानों का एक समूह उत्कीर्ण किया गया था, ताकि हमारे पास एक संविधान हो, जैसा कि श्री ग्रैनविल ऑस्टिन ने "भारतीय संविधान: एक राष्ट्र की आधारशिला", विभिन्न रंगों के कोट जैसा दिखता है।

( 1 ) 4 , एल. एड. 579.

कर्नाटक वी. यूनिन (बेग, सी. जे.)

61

हमारा संविधान लंबा और काफी अधिक जटिल हो सकता है।

संवैधानिक मामले पूरी तरह से, पर्याप्त विवरणों के साथ, ताकि इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश न रहे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है. जैसे कि कानून का एक विषय आवश्यक पक्ष के साथ कहा जाना था। कुलार, एक अभियुक्त व्यक्ति के लिए एक आरोप की तरह। ..... अगर असंभव नहीं तो मानवीय रूप से अव्यवहारिक की उम्मीद करना है। और, इस तरह की अपेक्षा की कथित तर्कसंगतता और "संवैधानिक कानून" या "संविधान" की कुछ शिथिल रूप से तैयार की गई व्यापक परिभाषा पर एक तर्क तैयार करने के लिए, हमें यह समझाने के लिए कि संविधान में दी गई कानून के विषय के रूप में जो इतनी निर्दिष्ट और पहचान योग्य नहीं है, उसे कम से कम सामान्य विधान के विषय के रूप में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, हालांकि यह संविधान के संशोधन द्वारा अनुमेय हो सकता है, इसके अतिरिक्त, हमें बहुत अवास्तविक लगता है। किसी भी तरह से, हमारा संविधान अनुच्छेद 368 के अलावा अन्य माध्यमों से पूरक मानसिक संवैधानिक कानून के विकास या विकास को बाधित नहीं करता है।

अत्यधिक विशिष्टता सुसंगत नहीं है, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है,

किसी बुनियादी या राज्य के "संरचनात्मक" कानून के रूप में वर्णित किए जाने की आम तौर पर स्वीकृत धारणाओं के साथ, जो इसके व्यापक रूप को चित्रित करता है।

केवल बुनियादी विशेषताएँ। संविधान निर्माताओं की मानवीय दूरदर्शिता से सबसे अधिक उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें कानून बनाने की उस अवशिष्ट शक्ति के लिए प्रावधान करना चाहिए जो उन विषयों को शामिल कर सके जिन पर, संवैधानिक ढांचे के अनुरूप, संसद या राज्य के कानून संवैधानिक पैटर्न के आधार पर कानून बना सकते हैं, भले ही कानून आसानी से किसी विशिष्ट प्रविष्टि के लिए निर्दिष्ट न हो। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था।

मद 97 पार्लिया की अवशिष्ट विधायी शक्तियों से मेल खाती है।

अनुच्छेद 248 के अधीन। वह इस प्रकार है:

" 97. कोई अन्य विषय जो सूची II या सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

III जिसमें कोई भी कर शामिल है जिसका उल्लेख उन सूचियों में से किसी में भी नहीं है।

यह अनुच्छेद 248 को प्रभावी बनाता है। निस्संदेह, अनुच्छेद 248 का सहारा लें, पढ़ें

मंत्रियों के आचरण की जांच पर कानून के खिलाफ रोक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी राज्य सरकार ने

निश्चित रूप से हमारे विपक्ष में ऐसा कोई स्पष्ट और विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है।

एक.

शीर्षक। और, यह देखना मुश्किल है कि कोई कुछ जरूरतों से कैसे उठ सकता है।

पूरी तरह से अलग-अलग विषयों से संबंधित प्रावधानों का गंभीर निहितार्थ।

हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जब यह लागू होता है

जिन प्रावधानों से हमें इसके खिलाफ एक प्रतिबंध का अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है या

पूछताछ जैसे विषय पर कानून पर सीमा, कि हमारे विपक्ष

शीर्षक-निर्माताओं के पास इस तरह का कोई प्रतिबंध या सीमा थी, यहाँ तक कि दूर से भी

दिमाग। ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रस्ताव के बीच कोई कानूनी या तर्कसंगत संबंध नहीं है।

बाधा या सीमा निर्धारित की गई और लेखों में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे निर्भर थे। पर। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, संविधान निर्माता ऐसा नहीं कर सकते।

हर संभव विषय का हमेशा उल्लेख करें और समाप्त करें। हम सोचते हैं कि ऐसी स्थिति से ठीक-ठीक निपटने के लिए अनुच्छेद 248 पढ़ा जाता है। प्रविष्टि 97 के साथ जोड़ा गया था। इसलिए, हम सोचते हैं कि अनुच्छेद 248 में [1978] 2 एस. सी. आर. पढ़ा गया है।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62

सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ अधिनियम की धारा 3 को पूरी तरह से शामिल किया जाएगा, भले ही

सूची I का मद 94 नहीं है

वैकल्पिक रूप से, सातवीं की समवर्ती सूची III की प्रविष्टि 45 संघ की ओर से अनुसूची पर भरोसा किया गया था। यह मद इस प्रकार है निम्नलिखित है:

" 45. किसी भी उद्देश्य के लिए पूछताछ और आँकड़े

सूची II या सूची III में निर्दिष्ट मामले।

सूची III की मद 45 के अंतर्गत आने के लिए जाँच का विषय निम्नलिखित से संबंधित होना चाहिए -

सूची II या सूची III में निर्दिष्ट वस्तुओं में से एक। यदि दोनों में से कोई भी वस्तु 94 नहीं है और सूची I की 97 और न ही सूची III की मद 45 जो पूछताछ को संदर्भित करती है।

पुनः

सूची II में विषयों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 3 को भी शामिल किया जा सकता है, यह

अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करेगा कि ऐसा अधिनियम, यह मानते हुए कि धारा 3 एक राज्य मंत्री के आचरण के खिलाफ एक जांच को कवर करने के लिए था अपने पद के आधार पर प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। अगर ऐसा है तो तर्क सही था, धारा 3, की गई धारणा पर, गिर जाएगी पूरी तरह से संसद और दोनों की विधायी क्षमता से बाहर राज्य विधानमंडलों को क्योंकि कोई विधायी शक्ति नहीं होगी

लाल किसी भी विधानमंडल पर ऐसे विषय से निपटने के लिए जो वह नहीं हो सकता था किसी भी सूची में किसी भी प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया। वास्तव में, अगर हमारे पास सही है वादी के लिए विद्वान वकील का तर्क इसके रूप में खड़ा था अंत में लिया गया, यह ठीक वही है जो हमें स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है।

यह तर्क दिया गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि राज्य सरकारों और उनके मंत्रियों द्वारा सरकारी मामलों का संचालन विशेष रूप से विषय है

राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार के नियंत्रण के लिए केवल संसद द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के कारण हम पहले ही जांच और व्याख्या कर चुके हैं।

वादी के लिए विद्वान वकील की ऐसी दलीलों को स्वीकार करना

राज्यों और केंद्र सरकारों दोनों में मंत्रियों को इस आधार पर कानूनी जवाबदेही के दायरे से पूरी तरह बाहर रखना है कि वे केवल राजनीतिक रूप से जिम्मेदार थे और उपयुक्त विधानसभाओं द्वारा नियंत्रित किए जा सकते थे, तब भी जब वे आधिकारिक शक्तियों के कथित प्रयोग के दौरान, बेईमानी और भ्रष्ट तरीके से कार्य करते हैं और यहां तक कि आपराधिक कृत्य भी करते हैं।

अवैध अपराध। इसका मतलब यह होगा कि अगर किसी मंत्री को रिश्वत भी मिलती है, जैसा कि हम वास्तव में उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, वह कर सकता है

साधारण न्यायालयों में जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा या आपराधिक कार्यवाही के अधीन नहीं किया जाएगा। यदि उनके आचरण की किसी भी कानून के तहत कोई जांच केवल इसलिए संभव नहीं थी कि जिस कार्य की शिकायत की गई थी, वह एक मंत्री द्वारा अपने मंत्री पद के आधार पर

निहित शक्ति के कथित प्रयोग में किया गया था, तो उन्हें अन्य नागरिकों पर लागू कानून की सामान्य प्रक्रियाओं से ऊपर एक विशेषाधिकार प्राप्त पद पर रखा जाएगा। केवल मंत्रालय का पद संभालने से किसी भी जांच से छूट मिलेगी। इस प्रकार वह सामान्य कानून से ऊपर एक कानूनी रूप से गैर-जिम्मेदार तानाशाह बन जाएगा।

यह निर्धारित करता है कि क्या किसी अपराधी के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला है

अपराध के तथ्यों की आवश्यक रूप से जाँच या जाँच की जानी चाहिए। लेकिन, विधानमंडल के सदन, जिसके वे सदस्य हैं, द्वारा की गई जांच को छोड़कर हर प्रकार की जांच और जांच पर रोक है, पहला कदम कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) है।

63

किसी भी गंभीर अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को सीमित सीमा में बंद कर दिया जाएगा। किसी भी अधिनियम के तहत आगे किसी भी कानूनी कार्यवाही का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। वादी के विद्वान वकील द्वारा जिन संवैधानिक दृष्टिकोण पर भरोसा किया गया था, उनका ऐसा परिणाम, हमारी राय में, हमारे संविधान निर्माताओं के चिंतन के भीतर संभव नहीं हो सकता था। वास्तव में, इस तरह का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 के स्पष्ट और बहुत ही हितकारी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा।

हम अनुमान लगाना पसंद करते हैं और मानते हैं कि 'पूछताछ' शब्द, जैसा कि में उपयोग किया जाता है

सूची I की मद 94 और सूची III की मद 45, उनकी प्रकृति या उनके चरित्र या उद्देश्यों के विनिर्देश पर किसी भी सीमा के बिना, हर तरह की जांच को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, चाहे किसी के द्वारा आपराधिक अपराध का खुलासा कथित तथ्यों द्वारा किया गया हो या नहीं। सूची III में प्रविष्टि 45 में उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को शामिल करने के लिए पूछताछ शामिल होनी चाहिए जो उन्हें आपराधिक कानून से संबंधित सूची III की प्रविष्टि I के दायरे में लाते हैं, मद 45 में शामिल "पूछताछ" के लिए केवल यह आवश्यक है कि वे

होना चाहिए।

" सूची II या सूची III में निर्दिष्ट किसी भी मामले के उद्देश्य के लिए।

काफी है

उपयोग की जाने वाली भाषा-"निर्दिष्ट मामलों में से कोई भी"-किसी भी गणना से यथोचित रूप से संबंधित किसी भी चीज़ को शामिल करने के लिए व्यापक है।

वस्तुएँ

भले ही राज्यों में मंत्री पदों के धारकों द्वारा किया गया हो।

अन्य

सूची I की प्रविष्टि 97 में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक महत्व के मामलों पर मंत्रियों के खिलाफ जांच शामिल होनी चाहिए, चाहे आरोप शामिल हों। आपराधिक कानून का उल्लंघन या नहीं। एक विपरीत दृष्टिकोण, मेरी राय में राज्य सरकारों में मंत्रियों को व्यावहारिक रूप से कानून से ऊपर रखने का पूरी तरह से अस्वीकार्य परिणाम होगा। हमें करना चाहिए।

दुबला

एक व्याख्या के खिलाफ जिसके परिणाम हैं,

वे

संसद या राज्य विधान के एक स्पष्ट अधिनियम से प्रवाहित होने पर, अनुच्छेद 14 के साथ टकराव के प्रावधान को अमान्य कर दिया होता।

यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उद्देश्यों के लिए भी

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण की जांच के लिए संसद का एक अधिनियम अनुच्छेद 124 के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पारित किया गया था, ताकि उचित जांच के माध्यम से और पूछताछ में, अनुच्छेद 124 (4) के तहत बचाव शुरू करने से पहले "एक न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण" प्रदान किया जा सके। ( 1968 का न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 51 देखें। इसलिए, न्यायाधीश भी,

जिन्हें निराधार या दुर्भावनापूर्ण आरोपों से संरक्षित किया जाना है, क्योंकि उन्हें ऐसे निर्णय देने होते हैं जो आवश्यक रूप से किसी मामले के दो या दो से अधिक पक्षों में से कम से कम एक को अप्रसन्न करते हैं, वे अधिक गोपनीय स्थिति में नहीं हैं। यह सच है कि, जैसा कि किसी ने देखा

है, शायद हमारे देश में सार्वजनिक पदों पर रहने वालों के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें एक शादी में कॉनफेटी की प्रचुरता होती है, फिर भी, हम इस कारण से अधिनियम के तहत पूछताछ को समाप्त नहीं कर सकते हैं। विधिवत नियुक्त निष्पक्ष आयोग के समक्ष इस तरह की पूछताछ का सामना करने का दायित्व उन खतरों में से एक है जिसका सामना मंत्री पद पर बैठे व्यक्तियों को करना पड़ता है। वे शायद इस विचार से सांत्वना पा सकते हैं कि पूरी तरह से और निष्पक्ष पूछताछ सक्षम व्यक्तियों द्वारा की जाती है

जो उच्च न्यायिक पद पर रहे हैं, उन्हें हटाने का सबसे अच्छा साधन है

ऐसे आरोप जो वास्तव में निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं।

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

64

जैसा कि हम सोचते हैं कि धारा 3 द्वारा केंद्र को प्रदत्त शक्तियाँ

और दोनों अधिसूचनाओं में से प्रत्येक के तहत स्थापित प्रकार की जांच शुरू करने की शक्ति सहित राज्य सरकारें, ऊपर उल्लिखित स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में आती हैं, किसी भी बहिष्करण का कोई सवाल, या तो आवश्यक निहितार्थ या संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बनने या उससे निकलने के लिए प्रतिपादित किसी भी सिद्धांत द्वारा, यहां उत्पन्न नहीं हो सकता है।

न ही हम जो दृष्टिकोण अपना सकते हैं,

अधिनियम की धारा 3 को पढ़ें और इस प्रकार व्याख्या करें कि दोनों अधिसूचनाओं के तहत स्थापित प्रकार की पूछताछ को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। ऐसा करने के लिए सरकारी तंत्र और शक्तियों के संभावित दुरुपयोग और विकृत करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा जो कानून द्वारा आवश्यक नहीं हैं। ऐसी शक्तियाँ अपने साथ संवैधानिक दायित्वों को वहन करती हैं। इनका प्रयोग न्यासियों की शक्तियों और दायित्वों की तरह किया जाना चाहिए जो अपने न्यासों के उद्देश्यों से विचलित नहीं होने चाहिए। चाहे किसी मंत्री ने अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया हो या नहीं किया हो, निष्पक्ष और ईमानदार लोगों द्वारा कहीं भी न्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के बाद ही इसका पता लगाया जा सकता है।

उसे

उनके खिलाफ की गई शिकायतों की निष्पक्ष जांच की गई है ताकि इसके परिणाम उनके सामने आ सकें। पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि वादी के विद्वान वकील द्वारा बार-बार इस सिद्धांत पर भरोसा किया गया था, जिसके समर्थन में क्रॉफर्ड के "सांविधिक निर्माण" (1940 एडन। अनुच्छेद 195 पी। 334-335 ) विद्वान वकील के उप-मिशन के आधार के रूप में यह भी उद्धृत किया गया था कि संविधान द्वारा जो स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, उसे अनिवार्य रूप से उन चीजों को बाहर करना चाहिए जिनके लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। यह तर्क "एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिवो अल्टेरियस" निर्माण के सिद्धांत का गलत उपयोग करने का प्रयास है। इससे पहले कि इस सिद्धांत को किसी भी स्थिति में लागू किया जा सके, न्यायालय को एक स्पष्ट तरीका खोजना होगा

कुछ ऐसा करना जो एक कानून में प्रदान किया गया है, जो अपने आवश्यक निहितार्थ से, उसी चीज को करने से बाहर कर सकता है और किसी अन्य तरीके से कुछ और नहीं। इसके अलावा, जैसा कि उपरोक्त चर्चा में बताया गया है, संविधान निर्माताओं का इरादा विभिन्न उद्देश्यों की जांच के लिए संसद द्वारा प्रावधान करने को शामिल करना था, जो सार्वजनिक महत्व के मामले हो सकते हैं, बिना किसी अन्य सीमा के संकेत के, सिवाय इसके कि वे सूचियों में पाए जाने वाले विषयों से संबंधित होने चाहिए। मैंने यह भी संकेत दिया है कि अधिनियम की धारा 3 जैसा प्रावधान, किसी भी मामले में, संविधान के अनुच्छेद 248 और 356 के साथ पठित अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत क्यों आता है, भले ही सभी उप-क्षेत्र जिनसे यह संबंधित हो, सूचियों में निर्दिष्ट नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार, हमारे संविधान में अधिनियम की धारा 3 जैसे अधिनियम को शामिल करने के लिए स्पष्ट प्रावधान है। इसलिए, स्पष्ट रूप से प्रदान की गई विधायी प्रविष्टि के भीतर आने वाली चीजों को बाहर करने के लिए "एक्सप्रेसियो यूनियस" नियम को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है। उस उक्ति को उपयुक्त रूप से एक "उपयोगी सेवक लेकिन एक खतरनाक स्वामी" के रूप में वर्णित किया गया है (प्रति लोप्स एल. जे. कोलकुहौन बनाम में। ब्रूक्स (1)। जिन सीमाओं या शर्तों के तहत निर्माण का यह सिद्धांत संचालित होता है, उन्हें अक्सर उन लोगों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है जो इसे लागू करने का प्रयास करते हैं।

( 1 ) [ 1888 ] 21 क्यू. बी. डी. पी. 52 @ 65 .

कर्नाटक बनाम। यूनियन (बेग, सी. जे.)

65

कमजोर और व्यापक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कि क्या है

नहीं।

संविधान में विशेष रूप से उल्लिखित को विचार-विमर्श करके इसके दायरे से बाहर माना जाना चाहिए, ताकि संविधान संशोधन से कम कुछ भी इस पर कानून बनाने को अधिकृत न कर सके।

को

एक "केसस ओमिसस" का आविष्कार करें ताकि इस नियम को लागू किया जा सके कि जहां कानून में इतना अंतर है, वहां न्यायालय इसे नहीं भर सकता है। हालाँकि, नियम समान रूप से स्पष्ट है कि न्यायालय किसी कानून की इस तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है कि "एक मामला चूक पेश करने के लिए" जहां वास्तव में कोई नहीं है (देखें): द मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड v. पेंडरसन ब्रदर्स (1)। यदि हमारा संविधान स्वयं उस कमी को भरने के लिए कानून का प्रावधान करता है जिसे एक कमी के रूप में माना जाना चाहिए, तो ऐसा करने की मांग करने वाले कानून को कैसे अमान्य माना जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निहित विधायी शक्ति का प्रयोग करके अपना इच्छित कार्य करता है? प्रावधानों के उद्देश्य की घोषणा करने में। इस प्रकार बनाए गए और इसे बनाने के लिए प्राधिकरण, न्यायालय एक शगुन प्रदान नहीं करते हैं या किसी अंतराल को बिल्कुल नहीं भरते हैं। संसद ही ऐसा कर सकती है।

और

किया है। यह मान लेना कि संसद ऐसा करने में अक्षम है, एक असमर्थनीय सिद्धांत या किसी की कल्पना की कल्पना को प्रतिस्थापित करना है कि संविधान किसी तरह से रास्ते में खड़ा है-जिसे केवल एक स्पष्ट संवैधानिक बाधा ही प्राप्त कर सकती है।

यह मुझे विचार करने के लिए अगले प्रश्न पर लाता है: वहाँ हैं?

सामान्य रूप से या विशेष रूप से हमारे संविधान के निर्माण से संबंधित कोई विशेष नियम? और अगर कोई

ऐसे नियम, क्या उनका आवेदन अधिनियम की धारा 3 को लागू करने की संसद की शक्ति पर, हमारी स्वीकृति के लिए वादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिबंधात्मक निर्माण का समर्थन करेगा? ये

महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतीत होते हैं जिनके उत्तर यदि संभव हो तो कुछ स्पष्टता के साथ देने की आवश्यकता है।

एक लिखित संविधान, किसी भी अन्य अधिनियम की तरह, एक में सन्निहित है

दस्तावेज़। सभी दस्तावेजों की व्याख्या और निर्माण के कुछ सामान्य नियम हैं जो निस्संदेह संविधान पर भी लागू होते हैं। फिर भी, एक संप्रभु गणराज्य के संविधान की प्रकृति, जो समय की कसौटी, बदलती परिस्थितियों के तनाव और दबावों को सहन करने और सहन करने के लिए है, सभी सरकारी शक्तियों के प्रयोग को लगातार नियंत्रित करने के लिए, और एक राष्ट्र के छोटे महत्व को निर्धारित करने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है ताकि न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्र के अपने सामने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने में अनुचित रूप से विफल न हो।

नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा संविधान

देश वह है जो छोटा और अस्पष्ट दोनों है। जाहिर है, उनका मतलब था कि एक संविधान में राष्ट्र की बदलती जरूरतों, अपने भाग्य के उतार-चढ़ाव, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विकास और विस्तार के लिए आसानी से अनुकूलित होने की क्षमता होनी चाहिए। यदि संविधान इस कार्य को करने में असमर्थ है तो यह विफल हो जाता है। प्रो. विलिस, जिनके "संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक कानून" पर काम को इस न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया है, ने कहा है (पी। 19):

" हमारा मूल संविधान एक आधार नहीं था, बल्कि एक आधार था

डेर। एक काल का संविधान नहीं रहा है

( 1 ) [ 1888 ] 13 ए. सी. 595 @602 [1978] 2 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66

एक और अवधि का संविधान। जैसा कि एक अवधि में सफलता होती है दूसरा, संविधान बड़ा और बड़ा होता जा रहा है।

अमेरिकी संविधान की यह लोच या अनुकूलन क्षमता हो सकती है

इसकी स्थायित्व के लिए खाता।

हालांकि, एक लिखित संविधान, जो हमेशा एक में सन्निहित है

दस्तावेज़, आवश्यक रूप से निर्माण की बुनियादी तोपों के अधीन होना चाहिए

दस्तावेजों का गठन, फिर भी, इसकी प्रकृति ही फंडा के अवतार के रूप में है

देश का मानसिक कानून, जिसे किसी राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाया जाना है, न्यायालयों के लिए अर्थ निर्धारित करना अनिवार्य बनाता है।

इसके भागों को इसके व्यापक और बुनियादी उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए।

यह दृष्टिकोण इस प्रकार के दस्तावेजों के निर्माण के मूल सिद्धांत से प्रवाहित होता प्रतीत होता है: कि सर्वोपरि

या

मुख्य वस्तुएँ और उद्देश्य, जो विषय-वस्तु से स्पष्ट होते हैं, यहाँ और वहाँ अस्पष्ट रूप से अंतर्निहित छोटे उद्देश्यों पर प्रबल होने चाहिए। द.

दूसरे शब्दों में, संवैधानिक दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसके घोषित उद्देश्यों और इसके कार्यों को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए। राष्ट्र की गतिशील आवश्यकताएँ, जिन्हें एक संविधान को पूरा करना चाहिए, केवल शब्दों या शब्दार्थ संबंधी झगड़ों के साथ पांडित्यपूर्ण खेल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय, एक न्यायिक शक्ति की आड़ में काम करते हुए, जो निश्चित रूप से संविधान बनाने तक का विस्तार करता है, इस अर्थ में कि वे इसके उन हिस्सों में इसका पूरक हो सकते हैं जहाँ संविधान का पत्र चुप है या सामान्य कानून या न्यायिक द्वारा इसके विकास के लिए जगह छोड़ सकता है।

उचित रूप से

व्याख्या, वास्तव में संविधान की व्यापक या बुनियादी योजना के बारे में अपने स्वयं के कुछ सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए संविधान के किसी भी भाग के स्पष्ट अर्थ को रद्द, पराजित या विकृत कर सकती है।

संविधान के पीछे का सिद्धांत जिसे संज्ञान में लिया जा सकता है

व्याख्या के उद्देश्यों के लिए गिनती, यहाँ तक कि भरने के लिए भी

संविधान के पत्र में कुछ जानबूझकर अस्पष्टता या अनिश्चितता के कारण जिन्हें "अंतराल" कहा गया है या खाली छोड़ दिया गया है, उन्हें स्वयं व्यक्त प्रावधानों से एकत्र किया जाना चाहिए।

में से

संविधान। उपयोग की गई अभिव्यक्तियों की संदिग्धता को न्यायालय द्वारा संविधान निर्माताओं द्वारा अपने सामने रखे गए व्यापक और बुनियादी उद्देश्यों के आलोक में यदि आवश्यक हो तो उनके अर्थों को स्पष्ट और निश्चित करके ठीक किया जा सकता है। और, ये अर्थ, उन उद्देश्यों या उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें प्रत्येक राष्ट्र के संविधान को पूरा करना चाहिए, समय की बदलती आवश्यकताओं के साथ बदल सकते हैं।

शक्ति।

में से

न्यायिक व्याख्या, भले ही इसमें वह शामिल हो जिसे "अंतर-न्यायिक" कानून निर्माण कहा जा सकता है, संविधान के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष या उन्हें अस्तित्व से बाहर करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट प्रावधान जिन चीजों को अधिकृत करते हैं, उन्हें आयात सीमा से कम नहीं किया जा सकता है: विधायी शक्तियों पर सीमाओं के एक मात्र सिद्धांत पर आधारित।

ऊपर दिए गए निर्माण के सामान्य सिद्धांतों का विवरण,

इस न्यायालय की पूर्व घोषणाओं से यह साबित होता है-कुछ संविधान में उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट रूप से व्यक्त अर्थों पर जोर देते हैं, जिनसे विचलित नहीं किया जा सकता है, अन्य संविधान निर्माताओं के सर्वोपरि उद्देश्यों और उद्देश्यों पर जोर देते हैं, कुछ कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) पर जोर देते हैं।

न्यायालयों के साथ टकराव में शून्य कानून घोषित करने की निस्संदेह शक्ति  
 संवैधानिक प्रावधान, अन्य की पूर्णता की ओर इशारा करते हैं संसद को संविधान द्वारा  
 प्रदत्त विधायी शक्तियाँ और  
 इस न्यायालय की कुछ पिछली घोषणाओं पर जहां जोर दिया गया है स्वाभाविक रूप से  
 विशेष के अनुसार मामले से मामले में भिन्न होगा  
 जिस संदर्भ में निर्माण के कुछ नियम विचार के लिए उत्पन्न हुए।

कनिया, सी. जे., ने स्पष्ट रूप से एक मूल रूप से ध्वनि दृष्टिकोण निर्धारित किया,  
 यदि मैं ए. के. गोपालन बनाम में संविधान की व्याख्या के लिए इसे बहुत सम्मान के साथ  
 चिह्नित कर सकता हूं। मद्रास राज्य (1), जब उन्होंने कहा:

" संविधान लॉर्ड के निर्माण के संबंध में

जेम्स वी में राइट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल (1936)

614 में ए. सी. 578) ने कहा कि "एक संविधान नहीं होना चाहिए

किसी भी संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थ में समझाया गया। 99 ' मिस्टर जस्टिस

हिगिंस इन अटॉर्नी-जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स बनाम। शराब बनाने का सामान

कर्मचारी संघ (1908 6) कॉम। एल. आर. 469 @611-12,

हमें प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखने के लिए मजबूर करें

जिस कार्य की हम व्याख्या कर रहे हैं-यह याद रखने के लिए कि यह एक कॉन्स्टी है

ट्यूशन, एक तंत्र जिसके तहत कानून बनाए जाने हैं और नहीं

एक मात्र अधिनियम जो घोषणा करता है कि कानून क्या होना है। इन री में

1938 का मध्य प्रांत और बरार अधिनियम XIV (1939 एफसीआर)

18 ( 1937 ) , सर मौरिस ग्वायर, सी. जे., इन्हें अपनाने के बाद

सेवा ने कहा: ' विशेष रूप से क्या यह एक संघीय संविधान के बारे में सच है

न्यायक्षेत्र के अपने अच्छे संतुलन के साथ शिक्षा। मुझे लगता है कि  
 एक व्यापक और उदार भावना को उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए जिनका यह कर्तव्य है

इसकी व्याख्या करना है; लेकिन मैं इससे यह नहीं कहता कि वे स्वतंत्र हैं।  
कानूनी या संवैधानिक सिद्धांत को फैलाना या विकृत करना या यहाँ तक कि  
चूक की आपूर्ति या सुधार के उद्देश्य से  
गलतियाँ की गईं '। राज्य के लिए काफी अधिकार है  
यह कि न्यायालय किसी अधिनियम को अमान्य घोषित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं  
क्योंकि उनकी राय में यह एक ऐसी आत्मा के खिलाफ है जो माना जाता है  
संविधान में व्याप्त लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया। कहाँ?  
मौलिक कानून सीमित नहीं है, या तो शब्दों में या द्वारा  
आवश्यक निहितार्थ, प्रदत्त सामान्य शक्तियाँ  
विधायिका के तहत हम एक सीमा घोषित नहीं कर सकते हैं  
की आत्मा में कुछ खोज करने की धारणा  
संविधान जिसका लिखित में उल्लेख भी नहीं है।  
किसी भी सामान्य सिद्धांत पर सर्वसम्मति को सीमित करना मुश्किल है।  
न्यायिक अंतर द्वारा संप्रभु विधायी शक्ति की शक्ति  
स्थिति, जहाँ तक लिखित के व्यक्त शब्दों को छोड़कर  
संविधान यह अधिकार देता है। यह भी कहा गया है कि यदि  
शब्द सकारात्मक हों और अस्पष्टता के बिना, कोई अधिकार नहीं है  
किसी न्यायालय द्वारा केवल उसी आधार पर किसी संविधि को खाली करने या निरस्त करने के  
लिए।  
लेकिन, यह केवल व्यक्त संवैधानिक प्रावधानों में सीमित है  
विधायी शक्ति और एक की अस्थायी इच्छा को नियंत्रित करना  
( 1 ) [ 1950 ] 1 एस. सी. आर. 88 @119 से 120।

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68

स्थायी और सर्वोपरि कानून द्वारा बहुमत  
राष्ट्र का जानबूझकर ज्ञान कि कोई एक सुरक्षित और

न्याय न्यायालयों के घोषित करने के अधिकार के लिए ठोस आधार

इससे आगे का अधिकार जूडी के हाथों में देना होगा।

सहायक शक्तियाँ बहुत बड़ी हैं और या तो अपने लिए बहुत अनिश्चित हैं

निजी अधिकारों की सुरक्षा या संरक्षण।

बिहार राज्य में v. कामेश्वर सिंह (1), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

जहां दो निर्माण संभव हैं, "न्यायालय को उसे अपनाना चाहिए जो उसे लागू करेगा और उसे  
खारिज कर देगा जो संविधान निर्माताओं के स्पष्ट इरादे को बाधित करेगा"।

एक अन्य सिद्धांत जिसे इस न्यायालय ने बार-बार निर्धारित किया है,

जिन मामलों में दो निर्माण यथोचित रूप से संभव हो सकते हैं, वे हैं कि उन्हें एक ऐसा निर्माण  
अपनाना चाहिए जो संवैधानिक प्रावधानों के बीच टकराव पैदा करने वाले निर्माण के बजाय  
सामंजस्यपूर्ण हो। 1. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (2); के. के. कोचुनी बनाम। मद्रास  
और केरल राज्य (3); मोहम्मद। हनीफ वी. राज्य बिहार (1); एम. पी. बनाम राज्य रनोजीराव  
शिंदे (5); प्रेम चंद गर्ग बनाम। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश (6), देवदासन बनाम। भारत  
संघ (7)।

अदालतों को निर्माण को अपनाने की सलाह दी गई है "जो होगा

संविधान के सुचारू और सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करना और दूसरे से बचना जो  
बेतुकेपन की ओर ले जाएगा या व्यावहारिक असंगतता को जन्म देगा मौजूदा कानून के  
निषेधात्मक या सुस्थापित प्रावधान बनाना (देखें): केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य (8)।

केशवानंद भारती के मामले में (उपरोक्त) सी. जे. ने कहा कि

संविधान का अर्थ निकालने का तरीका -

" किसी को इसे एक सामान्य कानून के रूप में नहीं समझना चाहिए। द.  
संविधान, शासन के लिए एक तंत्र स्थापित करने के अलावा  
मेंट, प्रस्तावना में एक महान और भव्य दृष्टि है।

इसी मामले में जे. खन्ना ने टिप्पणी की:

" संविधान को केवल कानूनी दस्तावेज नहीं माना जा सकता है।

इसे वसीयत या समझौते के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही संविधान  
एक वाद या दो के बीच एक मुकदमे में दायर एक लिखित बयान की तरह  
वादियों।

XX

XX

XX

· XX

XX

- ( 1 ) [ 1952 ] एस. सी. आर. 889 980-81 पर।  
 ( 2 ) [ 1967 ] 2 791 पर एस. सी. आर. 762।  
 ( 3 ) [ 1960 ] 3 905 पर एस. सी. आर. 887।  
 ( 4 ) [ 1959 ] 648 पर एस. सी. आर. 629।  
 ( 5 ) [ 1968 ] 3 एस. सी. आर 489  
 ( 6 ) [ 1963 ] पूरक। ( 1 ) 911 पर एस. सी. आर. 885।  
 ( 7 ) [ 1964 ] 4 695 पर एस. सी. आर. 680।  
 ( 8 ) [ 1973 ] 4 426 पर एस. सी. सी. 225 (1973 पूरक S.C.R.1)।

कर्नाटक बनाम। यूनियन (बेग, सी. जे.)

69

यह विभिन्न अंगों की रूपरेखा प्रदान करता है

राज्य, अर्थात् कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।  
एक संविधान की आशाओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है

लोग "।

बार-बार, इस न्यायालय ने घोषणा की है कि एक व्यापक और उदार विपक्ष

संविधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को बहुत अधिक शाब्दिक व्याख्या के पालन पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए (उदाहरण के लिए देखें सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड v. भारत संघ, (1), संविधान का।

विशेष रूप से, कानून बनाने की शक्ति की प्रचुरता, एक द्वारा इंगित

विधायी प्रविष्टि को यथासंभव व्यापक और उदार व्याख्या दी जानी चाहिए। इस प्रकार, जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2) इस न्यायालय ने कहा:

..... यह व्याख्या का एक प्राथमिक मूल नियम है।

कि संविधान में उपयोग किए गए शब्द जो कानून प्रदान करते हैं  
मूल सत्ता को सबसे उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए और यदि

वे व्यापक आयाम के शब्द हैं, उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए

उस आयाम को प्रभाव देने के लिए। यह जगह से बाहर होगा

चौड़े शब्दों पर एक संकीर्ण या प्रतिबंधित निर्माण करना

एक संविधान में आयाम। में प्रयुक्त एक सामान्य शब्द

अ.

वर्तमान की तरह प्रविष्टि का अर्थ सभी तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

सहायक या सहायक मामले जो निष्पक्ष और तर्कपूर्ण हो सकते हैं  
सक्षम रूप से इसमें शामिल होने के लिए आयोजित किया जाए।

भारत संघ में v. एच. एस. दिल्ली, (3) सीकरी, सी. जे., चर्चा के बाद

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष विषय संघ या राज्य सूची के अंतर्गत आता है, भारत और कनाडा दोनों में अपनाए गए परीक्षणों को देखा गया

( पी पर। 51):

" हमें ऐसा लगता है कि यह कला का कार्य है। 246 ( 1 ) , के साथ पढ़ें

प्रविष्टियाँ 1-96 सूची I संसद को सकारात्मक शक्ति देने के लिए है इन प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाएँ। वस्तु प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं है

संसद किसी मामले पर कानून बनाने से, भले ही अन्य प्रावधान हों संविधान के दृष्टिकोण इसे ऐसा करने में सक्षम बनाते हैं। तदनुसार,

हम 'किसी अन्य मामले' में होने वाले शब्दों की व्याख्या नहीं करते हैं। प्रविष्टि 97 सूची I का अर्थ एक्सक्लू के माध्यम से उल्लिखित विषय है

सायन। ये शब्द वास्तव में निहित मामलों को संदर्भित करते हैं

प्रत्येक प्रविष्टि 1 से 96 तक। शब्द 'कोई अन्य बात'

उपयोग किया जाना था क्योंकि प्रविष्टि 97 सूची I प्रविष्टियों का अनुसरण करती है 1-96

सूची I. यह सच है कि विधान के क्षेत्र का सीमांकन किया गया है -

प्रविष्टियाँ 1-96 सूची I, लेकिन सीमांकन का मतलब यह नहीं है कि यदि

प्रविष्टि 97 सूची I अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करती है जिनसे हमें इनकार करना चाहिए

इसे प्रभाव दें। जो भी संदेह हो सकता है

प्रविष्टि 97 की व्याख्या पर सूची I को व्यापक रूप से हटा दिया गया है। कला की शर्तें। 248. इसे व्यापकतम संभव शब्दों में तैयार किया गया है।

इसकी शर्तों पर पूछा जाने वाला एकमात्र प्रश्न है: क्या बात है?

सूची II या सूची III में शामिल किए जाने पर कानून बनाने की मांग की गई या क्या वह कर लगाया जाना चाहिए जिसका उल्लेख सूची II या सूची में किया गया है

( 1 ) [ 1962 ] 3 एस. सी. आर. 842

- ( 2 ) [ 1963 ] 1 एस. सी. आर. 220 @228-229।  
 ( 3 ) [ 1972 ] 2 एस. सी. आर. 33

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

70

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

III? सूची I के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए।

जवाब नकारात्मक में है, तो यह इस प्रकार है कि संसद ने  
 कर के उस मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति।

यह देखा जाएगा कि दिल्ली के मामले (ऊपर) में अपनाया गया परीक्षण था

कि यदि कोई विषय सूची II या सूची III में पाए जाने वाले विशेष रूप से सीमांकित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है, तो यह सूची I में आएगा, जाहिरा तौर पर प्रविष्टि 97, सूची I, कानूनी प्रविष्टियों द्वारा इंगित अवशिष्ट क्षेत्र के आयाम के कारण केवल विधायी शक्ति के संचालन के क्षेत्रों को दर्शाता है जो वास्तव में संविधान के अनुच्छेदों में से एक द्वारा प्रदान किया जाता है। यह बताया गया कि विधायी शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 248 को "व्यापक संभव शर्तों में तैयार किया गया है"।

की वैधता

उस मामले में संपत्ति कर अधिनियम को बरकरार रखा गया था। यह तर्क कि संविधान के अनुच्छेद 248 के साथ पठित सूची I की प्रविष्टि 97 को दी गई एक विस्तृत श्रृंखला, हमारे गणराज्य के "संघीय ढांचे" को नष्ट कर देगी, वहां खारिज कर दिया गया था। इसी तरह के परीक्षण के आवेदन पर, अधिनियम की धारा 3 द्वारा केंद्र सरकार को दी गई शक्तियों को, जो अब हमारे सामने हैं, इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि राज्य की संघीय संरचना उस दृष्टिकोण से खतरे में है जिसे हम इस न्यायालय के पिछले निर्णयों के साथ स्वीकार कर रहे हैं।

इसके बाद मैं कुछ विशेष विशेषताओं का उल्लेख कर सकता हूँ जिन्हें माना जा सकता है।

हमारे संविधान के व्यापक उद्देश्यों और उद्देश्यों को इंगित करने के लिए।

हमारे संविधान में न केवल एक उन्नत प्रस्तावना है

भारत के सभी लोगों की अनुमानित इच्छा, जिसकी कल्पना की गई थी

एक इकाई के रूप में, लेकिन भाग III में मौलिक अधिकारों के एक समूह के रूप में।  
निर्देशात्मक

संविधान के भाग IV में राज्य नीति के सिद्धांत, एक मोटे तौर पर अलग

कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का गठन

सरकार की शाखाएँ, एक व्यावहारिक संघवाद जो, वितरित करते हुए संसद और  
राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों को लागू करना,

एक समवर्ती क्षेत्र के साथ भी, और सरकारी क्षेत्रों को इंगित करता है राज्य  
और केंद्र सरकारों की शक्तियाँ, जैसा कि पहले से ही भारत में है, आच्छादित हैं

ऊपर वर्णित, दृढ़ता से 'एकात्मक' विशेषताओं द्वारा, विशेष रूप से द्वारा प्रदर्शित

संसद में अवशिष्ट विधायी शक्तियों को दर्ज करना, और सेन में त्राल सरकार,  
राज्य राज्यपालों की नियुक्ति की कार्यकारी शक्ति, और मुख्य

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायाधीश, उचित निर्देश देने की शक्तियाँ

राज्य सरकारों के लिए, और यहाँ तक कि राज्य विधानमंडलों को विस्थापित करने के लिए  
असाधारण परिस्थितियों या आपात स्थितियों में प्रशासन और सरकारें

दुनिया में बिल्कुल समान एकात्मक विशेषताएं हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसी  
प्रणाली को एक अर्थ में "संघीय" करार दिए जाने का अधिकार है।

केवल कार्यों के सुविधाजनक विभाजन से अधिक कुछ भी ओपेरा सामान्य  
समय में। "पर्यवेक्षण" का कार्य निश्चित रूप से यह है कि

केंद्र सरकार का वह सब कुछ जो इसका तात्पर्य है।

यह देखा जा सकता है कि द्वारा विचार की गई बुनियादी निष्ठा

कानूनी रूप से संविधान स्वयं संविधान के बारे में है जिसके बारे में

इस न्यायालय ने एक बार (विरेंद्र सिंह और अन्य में) कहा था। वी. राज्य का

यू. पी. (1)।

एक समय पर नए आदेश का जन्म हुआ

उसी स्रोत से निकलने वाली नई निष्ठा के साथ

( 1 ) [ 1955 ] 436 पर एस. सी. आर. 415।

}

कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

71

सभी, एक ही आधार पर संप्रभु इच्छा पर आधारित  
भारत के लोग जिनके पास कोई वर्ग, कोई जाति, कोई नस्ल, कोई पंथ नहीं है,  
कोई भेदभाव नहीं, कोई आरक्षण नहीं "।

संविधान, जैसा कि इसकी प्रस्तावना स्पष्ट करती है, एक संप्रभु है।

गणराज्य। यह जिस कानूनी संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें कानूनी विधायी संप्रभुता शामिल है, जिसमें किसी भी विषय पर कोई भी कानून बनाने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। इसलिए, किसी भी कानून को लागू करने की ऐसी विधायी शक्ति गणतंत्र के किसी विधायी अंग में निहित होनी चाहिए। इसे इन अंगों के बाहर कहीं भी नहीं रखा जा सकता है। दिल्ली के मामले (ऊपर) में तैयार किए गए परीक्षण को लागू करने के लिए अकेले संसद के पास अनुच्छेद 248 के कारण साधारण बहुमत से कानून बनाने की शक्ति होगी।

सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ें, यदि यह न तो सूची II में आता है और न ही सूची III में।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादी की ओर से विवाद, यदि स्वीकृत हो

टेड, किसी भी मामले पर स्वयं विधान की शक्ति को निष्कासित कर देगा

एक मंत्री द्वारा सरकारी मामलों के संचालन की जांच करना

विधायी सूचियों से राज्य सरकार में और इसे इसके तहत रखें

अनुच्छेद 368। इसका मतलब है कि, हालांकि के स्पष्ट प्रावधान

संविधान, जिसकी व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए, प्रथम होगा।

अधिनियम की धारा 3 जैसे प्रावधान को प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत करें, फिर भी, हमें करना चाहिए

पार्लिया द्वारा इस तरह के अधिनियम के खिलाफ एक संवैधानिक निषेध का संकेत देता है भले ही इसकी व्यापक शर्तें जैसा कि वे प्रथम दृष्टया कर सकते हैं, में शामिल हैं

सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाले राज्य मंत्रियों के खिलाफ पूछताछ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऊपर बताए गए तर्क का पहला कदम

यह एक सिद्धांत है कि संविधान में अनिवार्य रूप से क्या शामिल होना चाहिए

साधारण कानून के साथ। इस प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए, एक मार्ग था

आई. सी. गोलक नाथ एंड ओआरएस में न्यायमूर्ति वांचू के निर्णय से उद्धृत किया गया है।

वी. पंजाब और अन्र राज्य। ( 1) जिसमें निम्नलिखित प्रश्न शामिल है

"कानून और संविधान" (1933 एडन) पर आइवर जेनिंग्स से।

पी पर। 51 आगे):

" एक लिखित संविधान इस प्रकार एक का मौलिक कानून है

देश, शासन के सिद्धांत का व्यक्त अवतार

कानून से। सभी सार्वजनिक प्राधिकरण-विधायी, प्रशासनिक

यह। . . . . लिखित संविधान की प्रकृति जो भी हो

स्पष्ट करें कि कॉन्स्टी के बीच एक मौलिक अंतर है

न्यायिक कानून और शेष कानून। एक स्पष्ट सेपा है

इसलिए, संवैधानिक कानून और बाकी के बीच अनुपात

कानून "।

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा:

" यह मौलिक के बीच इस अंतर के कारण है

कानून (अर्थात्, संविधान) और इसके तहत पारित कानून

संविधान के विधायी प्रावधान कि यह संभव नहीं है  
 उस आशय के स्पष्ट प्रावधान के अभाव में  
 मौलिक कानून को सामान्य रूप से बदलने के लिए मौलिक कानून  
 इसके तहत पारित कानून, ऐसे सामान्य कानून के लिए  
 हमेशा मौलिक कानून (अर्थात् संविधान) के अनुरूप होना चाहिए।  
 टचूशन) "।

( 1 ) [ 1967 ] 2 एससीआर 762 @828।

[ 1978 ] 2 एस. सी. ई

72

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोलकनाथ के मामले में, जे. वांचू ने भी पेज पर इशारा किया था।

ए.

827 :

" संविधान मौलिक कानून है और संविधान द्वारा प्रदत्त केवल विधायी शक्ति के तहत कोई कानून नहीं है।

यह संविधान में किसी भी परिवर्तन को तब तक प्रभावित कर सकता है जब तक कि संविधान में ही इस आशय की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं दी गई हो। लेकिन संविधान द्वारा दी गई इस तरह की व्यक्त शक्ति के अधीन, मौलिक कानून, अर्थात् संविधान, को संविधान में निहित विधायी प्रावधानों के तहत पारित कानून द्वारा बदला नहीं जा सकता है क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत पारित सभी विधायी अधिनियम संविधान के अनुरूप होने चाहिए। संविधान में कई अनुच्छेद हैं जो स्पष्ट रूप से कानून द्वारा संशोधन का प्रावधान करते हैं, उदाहरण के लिए, 3,4,10,

3

59 ( 3 ) , 65 ( 3 ) , 73 ( 2 ) , 97 , 98 ( 3 ) , 106 , 120 ( 2 ) , 135 , 137 , 142 ( 1 ) , 146 ( 2 ) , 148 ( 3 ) , 149 , 169 , 171 ( 2 ) , 186 , 187 ( 3 ) , 189 ( 3 ) , 194 ( 3 ) , 195 , 210 ( 2 ) , 221 ( 2 ) , 225 , 229 ( 2 ) , 239 ( 1 ) , 241 ( 3 ) , 283 ( 1 ) और (2), 285 (2), 287,300 (1), 313,345,373, एससी। वी. सीएल. 7 और एस. VI सी. एल. 21 ; और जहाँ तक इन अनुच्छेदों का संबंध है, उन्हें पार्लिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

साधारण विधि-निर्माण प्रक्रिया द्वारा। लेकिन जहाँ तक अन्य अनुच्छेदों का संबंध है, उन्हें केवल अनुच्छेद के तहत संविधान के संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 368. अब कला। 245 जो संसद द्वारा भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, वह "इस संविधान के प्रावधानों" और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है, चाहे वह अनुच्छेद के तहत हो। 246 सूची 1 के साथ या कला के तहत पढ़ें। 248 सूची I की मद 97 के साथ पढ़ा जाए तो यह संविधान के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। यदि इसलिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद में निहित है। 248 सूची I की मद 97 के साथ पढ़ा जाए तो उस शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अधीन किया जाना चाहिए और इसका उपयोग संविधान को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है।

मौलिक कानून (अर्थात्, संविधान) स्वयं।

ऊपर उद्धृत अंश इस सिद्धांत के लिए एक आधार प्रदान नहीं कर सकते हैं कि "संवैधानिक कानून" और शेष कानून को उनकी सामग्री या विषय वस्तु के संदर्भ में दो स्पष्ट रूप से विभाजित या विशिष्ट और जल-तंग डिब्बों में रखा जा सकता है जिनके बीच कोई अतिव्यापी या अनिश्चित क्षेत्र नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जे. वान चू ने कोष्टक के भीतर "संविधान" नाम के शब्दों को डालते हुए बार-बार समझाया कि वह वास्तव में हमारे जैसे बहुत विस्तृत या व्यापक संविधान की विशेष विशेषताओं को इंगित करने के लिए चिंतित थे। वास्तव में जहां तक संविधान में निहित कानूनों की विषय वस्तु और जो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा शुरू की जा सकती हैं, न्यायाधीश वांचू का उपरोक्त निर्णय स्वयं इंगित करता है कि हमारे लिखित संविधान में पाए जाने वाले कानून के कुछ हिस्सों को भी सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है। इस परिच्छेद का उपयोग वादी के विद्वान वकील द्वारा कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.) में परिवर्धन या परिवर्तन का आग्रह करने के लिए किया गया था।

"संवैधानिक कानून" प्रक्रिया बनाने वाली सामान्य कानून द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यह केवल अनुच्छेद 368 में पाए गए प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए, जब तक कि संविधान स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, यह तर्क इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि संविधान का अनुच्छेद 368 केवल "संविधान" के संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है, और कानूनों को लागू करने या उनमें परिवर्तन करके अन्य कानूनों के किसी भी संशोधन के बारे में कुछ नहीं कहता है, जिन्हें उनके विषय वस्तु के कारण "संवैधानिक कानूनों" के रूप में वर्गीकृत या समझा जा सकता है। इस परिच्छेद को इसके संदर्भ से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें

प्रक्रिया में अंतर, अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदान किए गए "संविधान" के संशोधन के लिए और सामान्य विधान के लिए, अनुच्छेद 245 से 248 द्वारा अनुध्यात, विचाराधीन था।

यह उस संबंध में था कि अवलोकन सही किया गया था कि,

जब तक कि संवैधानिक प्रावधानों द्वारा दिया गया विशिष्ट अधिकार न हो

स्वयं "संविधान" द्वारा निर्धारित कानून को बदलकर, अपनाकर

केवल सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून में एक परिवर्तन शामिल है

संविधान के स्पष्ट प्रावधानों में "स्वयं नहीं लाया जा सका

संविधान के अनुच्छेद 368 का पालन किए बिना। यह

यह स्पष्ट रूप से एक अवतार के रूप में संविधान की धारणा से मिलता है।

एक "मौलिक कानून" जो अन्य सभी के लिए एक कसौटी के रूप में कार्य करता है

"कानून"। संविधान के बीच "मौलिक अंतर"

कानून "या" मौलिक कानून "और सामान्य कानून, जिनका वहां उल्लेख किया गया है,

इसका उद्देश्य केवल कानूनों के उपयोग में इस अंतर को सामने लाना था

जो, "मौलिक" होने के नाते, अन्य सभी कानूनों की वैधता का परीक्षण कर सकता है

एक निम्न मानक स्तर और ये अन्य कानून जिनका इस प्रकार परीक्षण किया जाता है। में। वह बहुत ही विशेष या प्रतिबंधित अर्थ, कानून जो संविधान में नहीं पाया जाता है

शिक्षा "संवैधानिक" या "मौलिक" कानून नहीं हो सकता था। अन्य  
कुछ भाग, भले ही वे महत्वपूर्ण प्रावधानों से संबंधित हों

कानून के

न्यायिक मामले, "संविधान" के अंग नहीं हैं, और इसलिए,

संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता का परीक्षण नहीं कर सके। क्या कहा गया?

संविधान के वास्तविक प्रावधानों के संदर्भ में,

हालाँकि, विधायी शक्ति पर कुछ प्रतिबंध का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है जो नहीं है

संविधान में ऊपर बार-बार बताए गए कारणों के लिए।

इस निर्णय के पूर्व भाग में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 जैसे प्रावधान को अधिनियमित करने की विधायी शक्ति, किसी भी स्थिति में, सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 248 में पाई जा सकती है, भले ही यह संभवतः आग्रह किया जा सके कि यह सूची I की प्रविष्टियों 94 और सूची III की 45 में शामिल नहीं है, जो जहां तक पूछताछ के विषय का संबंध है, तीन सूचियों को समाप्त करती प्रतीत होती है। वादी के विद्वान वकील ने इस आधार पर कुछ संदेह प्रस्तुत करने की कोशिश की कि सरकारी कार्यों के संबंध में राज्य सरकारों में मंत्रियों के आचरण को शामिल करने के लिए किसी भी सूची में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है। और, यह प्रस्तुत किया गया था, सूचियों में निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ से उन लोगों का पता चलेगा जो अनिर्दिष्ट हैं। उत्तर में यह आग्रह किया जा सकता है कि,

जैसा कि दिल्ली के मामले (ऊपर) में इंगित किया गया है, एक विधायी प्रविष्टि केवल शक्ति के संचालन के क्षेत्र को इंगित करती है, लेकिन सामान्य विधायी शक्ति के स्रोत संविधान के अनुच्छेद 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252 या 253 में से एक में पाए जाते हैं, और जहां तक विधायी शक्ति के संचालन के क्षेत्र का संबंध है, सूची I की प्रविष्टि 94 और सूची III की प्रविष्टि 45 दोनों को इतने व्यापक रूप से कहा गया है कि पूछताछ [1978] 2 एस. सी. आर.

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74

सूचियों में से किसी भी प्रविष्टि द्वारा इंगित किसी भी क्षेत्र को स्पर्श करना।

एक मंत्री को अनिवार्य रूप से संबंध में सरकारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

इन क्षेत्रों में से एक। यह निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है कि वह कौन सा क्षेत्र है

है। पूछताछ के बारे में कानून बनाने की शक्ति का क्षेत्र व्यापक रूप से इंगित किया गया है कानून में क्षेत्र को निर्दिष्ट करना अनावश्यक बनाने के लिए पर्याप्त शब्द स्वयं बनाया गया, जिससे जांच का संबंध होना चाहिए। यह पर्याप्त है अगर जांच स्थापना "सार्वजनिक महत्व" के मामले से संबंधित है। फिर से, यह एक नहीं है

3 विधायी सूची में एक प्रविष्टि का आवश्यक हिस्सा, जो केवल मोटे तौर पर भारतीय है कानून के एक क्षेत्र का उल्लेख करता है, कि इसे प्रति के वर्गों को भी निर्दिष्ट करना चाहिए बेटे जो कानून से प्रभावित हो सकते हैं। वह न तो एक स्थायी बात है ट्यूशनल और न ही एक उचित आवश्यकता।

यह न्यायालय पहले ही अभिनिर्धारित कर चुका है कि संचालन के क्षेत्रों का अतिव्यापी होना

विधायी शक्ति विधायी शक्ति को नहीं छीनती है। वास्तव में,

जैसा कि हमने कहा है, सूची I की 94 और सूची III की 45 दोनों प्रविष्टियों की आवश्यकता है

विधायी शक्ति के संचालन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए।

और, किसी भी मामले में, भले ही "सार्वजनिक महत्व" के मामले की जांच हो।

यह एक अनिर्दिष्ट क्षेत्र से संबंधित है, इसे सूची की प्रविष्टि 97 द्वारा कवर किया जाना चाहिए

मैं खुद। इसलिए, यह मायने नहीं रखता कि क्या हम उस प्रविष्टि 97 को धारण करते हैं।

सूची I की एकल प्रविष्टि या वह प्रविष्टि, जिसे सूची I की प्रविष्टि 94 के साथ पढ़ा जाता है,

ऐसे विधान के संचालन के क्षेत्र को शामिल करने के लिए माना जा सकता है,

जो सामग्री और महत्वपूर्ण है वह यह है कि तीन प्रविष्टियाँ-संख्या। 94 और

97 सूची I और सूची III के 45 के बीच, कानून शामिल होने के लिए बाध्य हैं।

एल. ए. एन. ए. द्वारा प्राधिकृत पूछताछ जैसे कि ग़ोवर को सौंपी गई पूछताछ

आयोग। यदि राज्य में मंत्रियों के खिलाफ जांच का विषय है किसी भी लेख में सरकारों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है संविधान या विधायी सूचियों में इसका पालन नहीं किया जाता है। कि इस तरह की पूछताछ को शामिल करने वाला कानून साधनों को छोड़कर अक्षम है एक संवैधानिक संशोधन। इसके विपरीत, ऐसा विषय होगा प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 248 की व्यापक शर्तों द्वारा कवर किया जाए कारण यह है कि संविधान में कोई स्पष्ट या निहित बाधा नहीं है जो हमारे कानून की संभवतः पूर्ण शक्तियों को कम कर सकता है संसद।

एक बार जब हम किसी एक अनुच्छेद में विधायी शक्ति का पता लगा लेते हैं संसद द्वारा सामान्य विधान को प्राधिकृत करने के लिए संविधान का अधिनियम की धारा 3 द्वारा कवर की गई पूछताछ, और हम अनुमोदन भी पाते हैं ओपेरा के क्षेत्रों को इंगित करने वाली विधायी सूचियों I और III में मूल्यवान् प्रविष्टियाँ संसद की उस विधायी शक्ति का, मान्यता प्राप्त राजकुमार सिद्धांत जो पूर्ववर्ती के खिलाफ एक निहित बार को लागू करेगा और बाहर करेगा उस पूर्ण शक्ति का आधार इस न्यायालय द्वारा और इसके द्वारा भी कहा गया है कई अवसरों पर राष्ट्रमंडल देशों में अन्य न्यायालय। कि सिद्धांत आर. वी. से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बुरा (1878) (3 ए. सी. 889) जो इस विषय पर लोकस क्लासिकस है। सामान्य सिद्धांत रखा गया बुराह के मामले में यह था कि एक बार एक पार्लिया को क्या प्रदान किया जाता है या अन्य विधानमंडल विधायी शक्ति है, इसका पूर्ण चरित्र है। यह माना जाना चाहिए कि जब तक शक्ति प्रदान करने वाला साधन न हो स्वयं विधान बनाने के अभ्यास पर कुछ स्पष्ट सीमाएँ हैं -

विधायी शक्ति, उस शक्ति के दायरे को अप्रत्यक्ष रूप से नहीं काटा जा सकता है अनुमानित प्रभावों से नीचे। इस विषय पर मामले कॉम थे केशवानंद भारती के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले से विचार किया गया ( ऊपर) जहाँ बहुमत का विचार था कि कोई केवल इम नहीं हो सकता है स्पष्ट रूप से प्रदान की गई विधायी शक्तियों पर सीमाएँ लगाएँ।

यह न्यायालय कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी. जे.)

75

बुराह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया और उन्हें अपनाया गया

( में

( ऊपर)। जे. पालेकर ने पी. में केशवानंद भारती के मामले से निम्नलिखित अंश उद्धृत किया।  
607 ) :

" स्थापित न्यायालय, जब कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

क्या निर्धारित सीमाएँ पार कर दी गई हैं,

आवश्यकता उस प्रश्न को निर्धारित करती है; और एकमात्र तरीका जिसमें

वे ठीक से ऐसा कर सकते हैं, शर्तों को देखकर है

साधन जिसके द्वारा, सकारात्मक रूप से, विधायी शक्तियाँ थीं

बनाया गया, और जिसके द्वारा, नकारात्मक रूप से, वे प्रतिबंधित हैं। अगर

जो किया गया है वह सामान्य दायरे में कानून है।

सकारात्मक शब्दों का जो शक्ति देते हैं, और यदि यह वायो है

कोई स्पष्ट शर्त या प्रतिबंध नहीं है जिसके द्वारा वह शक्ति

यह किसी भी न्यायालय के लिए आगे की जांच करने के लिए सीमित नहीं है, या उन शर्तों और प्रतिबंधों को रचनात्मक रूप से विस्तारित करना।

उस मामले में, इस न्यायालय के न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल पर भी भरोसा किया था

ऑटारियो प्रांत के लिए v. कनाडा डोमिनियन के लिए अटॉर्नी जनरल (1) जहां अर्ल लॉरबर्न ने कहा था (पी। 583):

" एक पूरी तरह से स्व-शासित कॉन की व्याख्या में

एक लिखित जैविक उपकरण पर स्थापित कथन जैसे कि

ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, यदि पाठ स्पष्ट है यह निर्णायक है, समान रूप से कि यह क्या निर्देशित करता है और क्या मना करता है।

जब पाठ अस्पष्ट होता है, उदाहरण के लिए, जब शब्द

दो पारस्परिक रूप से अनन्य क्षेत्राधिकार स्थापित करना व्यापक है

दोनों में से किसी एक के भीतर एक विशेष शक्ति लाने के लिए पर्याप्त, अधिनियम के संदर्भ और योजना के अनुसार होना चाहिए।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दृढ़ता से भरोसा किया है

विक्टोरिया राज्य बनाम। राष्ट्रमंडल (2) जहां बुराह के मामले (उपरोक्त) में निहित तर्क को लागू करने वाले पहले के मामलों का सर्वेक्षण किया गया था और बारविक सी. जे. ने हमारे द्वारा ऊपर बताए गए दो अंशों का हवाला दिया, एक बुराह के मामले (उपरोक्त) में लॉर्ड सेलबोर्न के फैसले से और दूसरा ऑटारियो प्रांत के मामले में अर्ल लोरबर्न के फैसले से।

( ऊपर) कनाडा से। बारविक। सी. जे. ने अमालगामेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स बनाम के निम्नलिखित अंश का भी हवाला दिया। एडिलेड स्टीमशिप कं. लिमिटेड (3)।

" " विधान की प्रकृति और सिद्धांत '(को नियोजित करने के लिए)

बुराह के मामले में लॉर्ड सेलबोर्न के शब्द), डोमी की प्रकृति

गैर-स्व-सरकार और निर्णय जो पूरी तरह से पहले उद्धृत किए गए थे

क्लूड, हमारी राय में, एक प्राथमिक तर्क है कि अनुदान

प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रमंडल संसद को विधायी शक्ति सभी राज्यों के सभी लोगों की इच्छा को भेजना

राष्ट्रमंडल और गणना की सीमाओं के भीतर  
निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा निर्धारित शक्तियाँ,

अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों और उनकी एजेंसियों  
क्षेत्र से "।

( 1 ) [ 1912 ] ऐप. कैस। 571 .

( 2 ) 45 ऑस्ट्रेलियन लॉ जर्नल की रिपोर्ट 251-22 C. L. R. 353,

( 3 ) [ 1920 ] 28 सी. एल. आर. 129 @152-153।

6-1042 उच्चतम न्यायालय 77 76

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1978 ] 2 एससीआर।

विक्टोरिया के मामले में (ऊपर), बारविक सी. जे., हालांकि पूरी तरह से नहीं

जिस तरह से सर ओवेन डिक्सन, सी. जे. ने वेस्ट बनाम में खुद को व्यक्त किया था, उसके साथ  
समझौता। कराधान आयुक्त (एन. एस. डब्ल्यू. (1) ने कहा कि यह बुरा के मामले (ऊपर) के बाद  
से ब्रिटिश स्वशासित उपनिवेशों के संविधान की व्याख्या के सिद्धांत के रूप में लगातार निर्धारित  
किया गया था। इस प्रकार समझाया गया अंश था:

सिद्धांत यह है कि जब भी संविधान किसी विशिष्ट उप के संबंध में कानून बनाने की  
शक्ति प्रदान करता है

प्रथम दृष्टया इसे राज्यों और उनकी एजेंसियों के संचालन को प्रभावित करने वाले  
कानून बनाने में संसद को सक्षम बनाने के रूप में समझा जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया अर्थ को  
उस शक्ति की प्रकृति या विषय वस्तु या उस भाषा के आधार पर विचार करके रखा जा सकता है  
जिसमें इसे संविधान में किसी अन्य प्रावधान पर प्रदान किया गया है।

हमने ऊपर समझाया है, हम एक आवश्यक निहितार्थ से ऐसी कोई सीमा की खोज नहीं कर सके।  
हालाँकि, मूल संरचना का सिद्धांत अगर हम ऐसा कहें तो संविधान समय-समय पर

संवैधानिक प्रावधानों के पीछे से "जैक इन द बॉक्स" की तरह "उभरता" रहा। कहा जाता था कि यह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

इस प्रकार, वादी के विद्वान वकील ने "संविधान की मूल संरचना" के रूप में वर्णित पर निर्भरता को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, हालांकि उन्होंने बहुत चतुराई से और सही तरीके से संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को सामने रखने की कोशिश की। "संविधान की मूल संरचना" के सिद्धांत का उपयोग करने के इस तरीके के वादी के लिए रणनीतिक मूल्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता है, वह हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं करता है कि क्या इस तरह के सिद्धांत का अनुप्रयोग हमारे सामने मामले में शामिल किया जा सकता है। हम केशवानंद भारती के मामले (उपरोक्त) पर अधिक ध्यान नहीं दे सकते हैं, जहां इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों का एक विशाल समूह, जिसने संविधान संशोधन की स्पष्ट पूर्ण विधायी शक्तियों पर "अपनी सीमाओं" के सिद्धांत को खारिज कर दिया था, फिर भी हम इसे स्वीकार करते हैं, मैं इसे अत्यंत सम्मान के साथ कहता हूं, फिर भी बहुमत से, ऐसी सीमाएं जो पूर्ण विधायी शक्तियों पर निहित सीमाओं से आसानी से अलग नहीं लगती थीं।

भले ही उन्हें "संविधान की मूल संरचना" के भागों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हम केशवानंद भारती के मामले (उपरोक्त) में बहुमत के दृष्टिकोण से बंधे हैं जिसका हमने अन्य मामलों में पालन किया है। हम. हालांकि, यह स्पष्ट और स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि बिना किसी विसंगति के और कुछ विश्वास के साथ, यह किस प्रकार के मामलों पर लागू हो सकता है और अन्य जिन पर यह विशेष मामलों के रूप में लागू नहीं हो सकता है, विचार के लिए हमारे सामने आते हैं।

( 1 ) ( 1937 ) 56 सी. एल. आर. 657 @682

कर्नाटक वी. यूनिन (बेग, सी. जे.)

77

इसलिए, "मूल संरचना" का यह सिद्धांत क्या है?

हमारा

जिसका संविधान कुछ विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार

अदालत, इस सिद्धांत पर बहुमत के विचारों को व्यक्त करते हुए, "संघवाद" एक हिस्सा है? हम इस प्रश्न का उत्तर केवल उन विद्वान न्यायाधीशों की राय के कुछ अंशों से उद्धृत करके दे सकते हैं जो केशवानंद भारती के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के पक्षकार थे।

सीकरी सी. जे., जिन्होंने निहित सीमाओं के सिद्धांत को स्वीकार किया, और,

अपने तर्क के अनुरूप, यह पाया गया कि संविधान की मूल संरचना शक्ति के प्रयोग की एक कक्षा बनाती है जो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है, जिसमें पाए गए अवलोकनों और निर्देश पर निर्भर करती है

मेलबर्न निगम बनाम। द कॉमनवेल्थ (1) और ऑस्ट्रेलियन नेशनल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. राष्ट्रमंडल (2)।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने स्टार्क जे. के व्यक्त किए गए विचारों का हवाला दिया

में

मेलबर्न निगम का मामला (ऊपर):

" ऑस्ट्रेलियाई संविधान का संघीय चरित्र

इसके अपने निहितार्थ हैं।

XX

XX

XX

XX

" मैं जो स्थिति लेता हूँ वह यह है: कई विषय मैट

जिनके संबंध में राष्ट्रमंडल सशक्त है

संविधान द्वारा शांति, व्यवस्था के लिए कानून बनाना और

राष्ट्रमंडल की अच्छी सरकार संकीर्ण नहीं होनी चाहिए

निहित या निहितार्थ द्वारा सीमित। इनका दायरा और आयाम

यह केवल उन शब्दों पर निर्भर करता है जिनके द्वारा वे व्यक्त किए जाते हैं।

लेकिन राज्यों के अस्तित्व से उत्पन्न होने वाले निहितार्थ  
राष्ट्रमंडल के भागों और संघ के संविधानकों के रूप में  
यह संसद के तरीके को सीमित कर सकता है।

कर सकते हैं

कानूनी रूप से एक के संबंध में कानून बनाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग  
विशेष विषय-वस्तु। ये निहितार्थ, या शायद  
कॉन्स्टी की अंतर्निहित धारणाओं को कहना बेहतर था  
ट्यूशन, एक शक्ति के उपयोग से संबंधित है न कि अंतर्निहित प्रकृति से  
कानून की विषय वस्तु। बेशक या नहीं  
एक कानून शांति, व्यवस्था और अच्छी सरकार को बढ़ावा देता है  
संसद, अदालत के लिए नहीं, निर्णय लेने के लिए। लेकिन एक कानून हालांकि  
यह एक निर्दिष्ट विषय वस्तु के संबंध में हो सकता है  
आम जनता की शांति, व्यवस्था और अच्छी सरकार के लिए  
धन यदि राज्यों को उनके वहन को रोकने के लिए निर्देशित किया जाए  
राष्ट्रमंडल के भागों के रूप में उनके कार्यों को बाहर निकालें।

गिब्स जे को फिर से उद्धृत किया गया:

" वैधानिक निर्माण के सामान्य सिद्धांत नहीं हैं।

आवश्यकता पड़ने पर प्रभाव डालने से रोकें  
विधानमंडल के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए जैसा कि में प्रकट किया गया है

कानून समग्र रूप से "

( 1 ) ( 1947 ) 74 सी. एल. आर. 31

( 2 ) ( 1945 ) 71 सी. एल. आर. 29

[ 1978 ] 2 एस.

8

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" इस प्रकार, संविधान का उद्देश्य और

योजना जिसके द्वारा इसे प्रभावी बनाने का इरादा है, अनिवार्य रूप से

कॉम के तरीके के रूप में निहितार्थ को जन्म दें

राष्ट्रमंडल और राज्य क्रमशः अपना अभ्यास कर सकते हैं

शक्तियाँ, एक-दूसरे की तुलना में।

कई मामलों पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि

निहित सीमाओं पर निम्नलिखित रूप में समावेशन (पी। 163-164 ) :

" सभी प्रावधानों से आवश्यक निहितार्थ क्या है?

संविधान के सिद्धांत?

मुझे ऐसा लगता है कि प्रस्तावना को पढ़ना, फंडा

व्यक्ति की स्वतंत्रता का मानसिक महत्व, वास्तव में

इसकी अपरिवर्तनीयता, और आर्थिक, सामाजिक महत्व

और प्रस्तावना में उल्लिखित राजनीतिक न्याय, महत्वपूर्ण

निर्देशक सिद्धांतों का आचरण, कला में गैर-समावेश। 368

कला जैसे

प्रावधान। 52 , 53 और विभिन्न अन्य प्रावधान

जिसके संदर्भ को पहले ही एक अप्रतिरोध्य कॉन बना दिया गया है

अटकलबाजी से पता चलता है कि इस शब्द का उपयोग करने का इरादा नहीं था  
' व्यापक अर्थ में 'संशोधन'।

यह आम समझ थी कि मौलिक

अधिकार वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं और वे जाएगा। ऐसा भी लगता है कि

अस्तित्व से बाहर संशोधित नहीं किया

एक आम समझ है कि की बुनियादी विशेषताओं लोकतंत्र और

संविधान, अर्थात्, धर्मनिरपेक्षता,

व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा कल्याण में बनी रहेगी।

राज्य।

उपरोक्त कारणों को देखते हुए, एक आवश्यक निहितार्थ

उत्पन्न होता है कि की शक्ति पर निहित सीमाएँ हैं

संसद ने कहा कि इस संविधान का 'संशोधन' अभिव्यक्ति

परिणामस्वरूप हमारे संविधान में 'ट्यूशन' का एक सीमित अर्थ है।

उत्तरदाताओं द्वारा सुझाए गए अर्थ का नहीं।

सी. जे. सीकरी ने केशवनार में मूल संरचना पर अपनी खोज दर्ज की।

आरती का मामला (ऊपर) इस प्रकार है (पीपी पर। 165-166) :

" वास्तविक स्थिति यह है कि प्रत्येक प्रावधान

संविधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप बुनियादी

संविधान की नींव और संरचना बनी हुई है

एक ही। कहा जा सकता है कि मूल संरचना में शामिल हैं -

निम्नलिखित विशेषताएँ:

- ( 1 ) संविधान की सर्वोच्चता;
- ( 2 ) सरकार का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप;
- ( 3 ) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र;
- ( 4 ) विधानमंडल के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

कार्यपालिका और न्यायपालिका; कर्नाटक बनाम संघ (बेग, सी.

जे.)

79

( 5 ) संविधान का संघीय चरित्र ।

उपरोक्त संरचना मूल नींव पर बनाई गई है,

अर्थात् व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता । यह बात है

सर्वोच्च महत्व । यह किसी भी प्रकार के संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता है ।  
नष्ट हो जाएंगे ।

उपरोक्त आधार और उपरोक्त बुनियादी विशेषताएं हैं -

न केवल प्रस्तावना से बल्कि पूरे से आसानी से देखा जा सकता है

संविधान की योजना, जिस पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ " ।

इसी तरह, शेलट और ग्रोवर जे. जे., अंतर के सिद्धांतों का सर्वेक्षण करने के बाद

संविधान के ढोंग और निर्माण ने विभाजन की शक्ति पर निहित सीमाओं के सिद्धांत के साथ-साथ  
बुनियादी संरचना के सिद्धांत को स्वीकार किया । उन्होंने अपना निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किया  
(पीपी पर। 280-281 ) :

" संविधान की मूल संरचना अस्पष्ट नहीं है ।

अवधारणा और उसकी ओर से व्यक्त की गई आशंकाएँ

उत्तरदाताओं ने कहा कि न तो नागरिक और न ही संसद

यह समझने में सक्षम होना कि यह निराधार है । अगर ऐतिहासिक

पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, कॉन्स्टी की पूरी योजना

शिक्षा, कला सहित इसके प्रासंगिक प्रावधान । 368

यह ध्यान में रखा जाता है कि यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि

निम्नलिखित को मूल तत्वों के रूप में माना जा सकता है

संवैधानिक संरचना।

( इन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है

लेकिन

केवल सचित्र किया जा सकता है)।

1. संविधान की सर्वोच्चता।
2. सरकार का प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक रूप और देश की संप्रभुता।
3. संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र।
4. विधायिका के बीच शक्ति का सीमांकन, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
5. विभिन्न द्वारा सुरक्षित व्यक्ति की गरिमा

भाग III में स्वतंत्रताएँ और बुनियादी अधिकार और व्यक्ति भाग IV में निहित कल्याणकारी राज्य के निर्माण की तारीख।

6. राष्ट्र की एकता और अखंडता "।

हेगड़े और मुखर्जी, जेजे। के सिद्धांतों पर भी विचार किया जाता है

इस देश में और आम में व्याख्या और निर्माण

समृद्ध देश। उन्होंने इस न्यायालय के पहले के मामलों को अलग किया। उन्होंने व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को लागू करने का इरादा किया और

निर्माण जैसे कि हेडन के मामले में शरारत नियम, की आवश्यकता

संविधान को समग्र रूप से देखें, और इसके इतिहास और उद्देश्यों को देखें। उन्होंने कहा (पृ. 307):

" किसी कानून में किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय, या

न्यायपालिका का प्राथमिक कर्तव्य कानून का पता लगाना है।

भावात्मक इरादा। वर्तमान मामले में हमारा कर्तव्य [1978] 2 एस. सी. आर. का पता लगाना है।

80

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 368 को अधिनियमित करने में संस्थापक पिताओं का इरादा। आम तौर पर विधायी आशय भाषा से एकत्र किया जाता है। उपयोग किया जाता है। यदि प्रयुक्त भाषा सरल और असंदिग्ध है, उसी को प्रभाव दिया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो प्रश्न जो उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर भाषा का उपयोग किया जाता है एक से अधिक अर्थों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है, तो न्यायालय को विभिन्न सुव्यवस्थित नियमों की सहायता लेनी होगी निर्माण और विशेष रूप से, कानून का इतिहास उस बुराई का पता लगाने के लिए जिसे ठीक करने की कोशिश की गई थी और कुछ मामलों में कानून का अंतर्निहित उद्देश्य - विधायी योजना और संभावित परिणाम

व्याख्याओं में से एक या दूसरी को स्वीकार करने से प्रवाह क्योंकि किसी भी विधायी निकाय को शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं माना जाता है

जो दुरुपयोग करने में सक्षम है "।

उन्होंने प्रस्तावना और संविधान के अंतर्निहित उद्देश्यों का हवाला दिया और पाया (पी पर। 316):

" अधीन प्रदत्त शक्तियों पर निहित सीमाएँ

एक कानून सभी कानूनों की एक सामान्य विशेषता है। द.  
 प्रदत्त शक्तियों के मामले में स्थिति अलग नहीं हो सकती है।  
 एक संविधान के तहत। सामान्य रूप से शक्ति का अनुदान  
 या यहां तक कि पूर्ण शब्दों में भी अन्य एक्सप्रेस द्वारा योग्य हो सकता है  
 एक ही अधिनियम में प्रावधान या द्वारा योग्य हो सकता है  
 संदर्भ के निहितार्थ या यहां तक कि उत्पन्न होने वाले विचारों से भी  
 जो कानून की सामान्य योजना प्रतीत होती है "।

उन्होंने संविधान की सभी बुनियादी विशेषताओं को सूचीबद्ध नहीं किया, लेकिन अपने निष्कर्ष को निम्नानुसार दर्ज किया (पृ. 356)।:

" यद्यपि संविधान में संशोधन करने की शक्ति

अनुच्छेद 368 एक बहुत व्यापक शक्ति है, इसमें अभी तक शामिल नहीं है

मूल तत्वों को नष्ट करने या नष्ट करने की शक्ति या

संविधान की मूलभूत विशेषताएँ "।

जगमोहन रेड्डी, जे, एक विस्तृत विचार के दौरान

संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, प्रस्तावना पर बड़े पैमाने पर और

अपने मूल्यों की स्थिरता के लिए राष्ट्र की आवश्यकताएँ और "संशोधन" शब्द को एक संकीर्ण अर्थ दिया जो संविधान की पहचान को नष्ट कर सकता था। उन्होंने कहा (पृ. 517):

" पूर्व में कुछ भी अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं है

यह अनुच्छेद में जो कहा गया है, उसके बारे में भी उतना ही सच होगा।

39 (ख) और (ग) क्योंकि ये भी मौलिक उद्देश्य हैं।

उस देश का शासन जिसका राज्य को आदेश दिया गया है

मूल संरचना के तत्वों को पूर्व में इंगित किया गया है

संविधान के विभिन्न प्रावधानों में लागू और अनुवादित

ट्यूशन। हमारे संविधान की इमारत इस पर बनी है और

कई प्रॉप्स पर खड़ा है, उनमें से किसी को भी हटा दें, संविधान यह टूट जाता है। ये हैं: ( 1 ) संप्रभु लोकतांत्रिक री (2) न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; (3)

कर्नाटक वी. यूनिन (बेग, सी. जे.)

81 .

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; (4) स्थिति और अवसर की समानता। इनमें से हर एक

महत्वपूर्ण और सामूहिक रूप से वे जीवन के एक तरीके का आश्वासन देते हैं भारत के लोग जिनकी संविधान गारंटी देता है। को।

उपरोक्त तत्वों में से किसी को भी हटा दें संरचना नहीं करेगी

जीवित रहें और यह वही संविधान नहीं होगा, या यह

संविधान और न ही यह अपनी पहचान बनाए रख सकता है, अगर कुछ भी हो।

काफी अलग इसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है, जो संप्रभु है केवल लोगों की इच्छा ही कर सकती है।

खन्ना, जे., निश्चित रूप से निहित लिमि के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए

कानून की पूर्ण शक्तियों पर देशों ने, फिर भी, सोचा कि संविधान के संशोधन की व्यापक शक्ति पर भी निरंतरता की आवश्यकता के साथ परिवर्तन के आग्रह को मिलाने की आवश्यकता यह सीमा है कि इसे अपनी मूल संरचना द्वारा परिभाषित कक्षा के भीतर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, और मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ, स्पष्ट रूप से निहित सीमाओं पर अपने विचारों के बीच सुलह का प्रयास करते हैं।

मूल संरचना पर, जो कम से कम विधान की पूर्ण शक्ति पर निहित सीमाओं से मिलती-जुलती थी। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पर भी बहुत अधिक भरोसा किया। उन्होंने बाद में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम में समझाया। राज नारायण (1) ने कहा कि उन्होंने मौलिक अधिकारों पर अध्याय में ऐसे संशोधनों को बाहर नहीं किया जो संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित

संशोधन की शक्ति के दायरे से "मूल संरचना" के भाग हो सकते हैं। जे. खन्ना के फैसले ने संतुलन को एक संकीर्ण बहुमत से झुका दिया।

एक, संशोधन की स्पष्ट रूप से प्रदत्त विधायी शक्ति पर एक सीमा के रूप में संविधान की "मूल संरचना" के पक्ष में

मन में।

मुझे रे, पालेकर, मैथ्यू के विचारों को इसी तरह से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बेग, द्विवेदी और जे. जे. चंद्रचूड़ ने इस निर्विवाद प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कि संविधान में वह है जो बुनियादी था,

इस दृष्टिकोण को धारण किया, जो हमारे कॉन के इतिहास के संदर्भ में भी समर्थित है

या संविधान को किसी भी तरह से और किसी भी तरह से वांछित रूप से बदलें। लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा भी उस बुनियादी का एक हिस्सा था

संरचना या लोगों के आग्रह जो अभिव्यक्ति में पाए गए थे संविधान का अनुच्छेद 368 और जिसे पूरी तरह से मान्यता दी जानी थी

इसे सबसे व्यापक संभव आयाम देकर। इसलिए वे भी

इस बात का संज्ञान लिया कि संविधान में "एक बुनियादी संरचना" थी इसके इतिहास और सामग्री का प्रकाश और अच्छी तरह से स्थापित एक अनुप्रयोग द्वारा

निर्माण के नियम। बहुमत के बीच अंतर

और अल्पसंख्यक विचार केवल इस सवाल पर थे कि क्या एक व्यापक दायरा है

जन-प्रतिनिधियों को दिए गए संशोधन की शक्तियाँ

इस मूल संरचना या इसके कार्य का हिस्सा था या नहीं था

संविधान की स्पष्ट घोषणाओं और प्रावधानों से प्रमाणित यह।

मुझे नहीं लगता कि उन विद्वान न्यायाधीशों ने, जो केशवन में

आंडा भारती के मामले (ऊपर) ने विधायी के लिए एक संकीर्ण कक्षा पाई स्वयं संविधान में संशोधन करने की शक्ति

[ 1978 ] 2 एस सी आर ।

82

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान की सतह के ऊपर और उसके बाहर आसमान में एक बादल की तरह तैरती हुई एक अस्पष्ट बुनियादी संरचना या सतह के नीचे दबी हुई संरचना के बारे में कुछ सिद्धांत निर्धारित करें, जिसके लिए हमें इसे खोजने के लिए खुदाई करनी होगी। मैं यह सोचना पसंद करता हूँ कि "एक बुनियादी संरचना" का सिद्धांत कुछ और नहीं बल्कि संविधान निर्माताओं के इरादों से संबंधित स्पष्ट निष्कर्षों के एक समूह से अधिक था, जो निर्माण के स्थापित सिद्धांतों को व्यापक रूप से लागू करके आए थे, क्योंकि वे एक जैविक संवैधानिक दस्तावेज के रूप में होने चाहिए, जो एक राष्ट्र के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए है। लेकिन, प्रत्येक मामले में जहां उस पर निर्भरता रखी जाती है, कानून पर हमले के दौरान, चाहे वह सामान्य हो या घटक (इस अर्थ में कि यह संविधान का एक संशोधन है), जिसे "एक बुनियादी संरचना" के हिस्से के रूप में सामने रखा गया है, उसे संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के संदर्भों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए। वह संरचना रिक्तिका में मौजूद नहीं है। इसके निष्कर्षों को अंतर्निहित दिखाया जाना चाहिए और उस संरचना के आधार से तार्किक और प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह संविधान के प्रावधानों और उस तरीके से संबंधित होना चाहिए जिसमें उन्हें स्वाभाविक रूप से और तर्कपूर्ण रूप से कार्य करने के लिए माना जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो यह सिद्धांत संविधान की व्याख्या करने के एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त तरीके को आगे बढ़ाने के एक तरीके से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका उपयोग उचित सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसकी कोई भी व्याख्या जो इसे न्यायिक कल्पना के रूप में या इस तरह की व्यक्तिपरक व्याख्याओं में सक्षम बना सके कि उचित निश्चितता के साथ इसके अर्थ को समझना या ठीक करना संभव हो, हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह इसकी निरर्थकता की घोषणा करने के बराबर होगा। केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अपने सभी अनुप्रयोगों में बुनियादी संरचना सिद्धांत के निहितार्थ पर काम नहीं किया था

टियोन। इसलिए, यह अत्यंत सम्मान के साथ कहा जा सकता है कि इसे शायद एक अनाकार स्थिति में छोड़ दिया गया था जो संभावित गलतफहमी को जन्म दे सकता है कि क्या इसे बहुत अस्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है या इसके अर्थों या निहितार्थों की बुनियादी एकरूपता का प्रयास किए बिना बहुत शिथिल और विभिन्न रूप से तैयार किया गया है। मूल संरचना सिद्धांत, जिसका उपयोग इस न्यायालय द्वारा संवैधानिक संशोधन की शक्ति को भी सीमित करने के लिए किया

गया है, के सभी अनुप्रयोगों में अनुमान लगाने योग्य एक सिद्धांत यह है कि विधायी शक्ति पर मूल सीमा के रूप में जो कुछ भी सामने रखा गया है, वह संविधान के एक या अधिक स्पष्ट प्रावधानों से सहसंबद्ध होना चाहिए, जिनसे सीमा स्वाभाविक रूप से और आवश्यक रूप से उत्पन्न होनी चाहिए। जैसा कि ऊपर समझाया गया है, मूल संरचना के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि विधायी शक्ति पर कोई भी सीमा संविधान के प्रावधानों से ही इतनी निश्चित रूप से स्पष्ट होनी चाहिए कि इसमें कोई संदेह या गलती नहीं हो सकती है कि निषेध मूल संरचना का एक हिस्सा है जो संवैधानिक संशोधन की शक्ति पर भी एक सीमा निर्धारित करता है। और जब भी

हम।

किसी भी दस्तावेज का अर्थ, इसके प्रावधानों को समग्र रूप से पढ़कर, इसकी वैमनस्यताओं को खत्म करने या हल करने की कोशिश करके, क्या हम इसे इसकी "मूल संरचना" या उद्देश्यों के अनुसार ढोंग करने का प्रयास नहीं करते हैं? यह सिद्धांत न तो अद्वितीय है और न ही नया।

1 यहाँ श्रीमती में यह इंगित किया जा सकता है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज

नारायण (ऊपर), जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों पर हमला करने के लिए संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का आह्वान किया गया था, तो रे. सी. जे. ने मूल संरचना के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया।

यूनियन (बेग, सी. जे.)

इसके अनुप्रयोग में या तो कोर के निर्माण या साधारण विधान के निर्माण के लिए। उन्होंने कहा (पीपी में। 436-437) :

" बुनियादी विशेषताओं या बुनियादी संरचना सिद्धांत को स्वीकार करना।

साधारण विधान के संबंध में इसका अर्थ होगा कि

विधायी उपायों के लिए दो प्रकार की सीमाएँ होंगी।

एक अनुच्छेद 245 के तहत विधायी शक्ति से संबंधित होगा और विधायी प्रविष्टियाँ और अनुच्छेद में प्रावधान

246 और

13. दूसरा यह होगा कि कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है या बुनियादी संरचनाओं को नुकसान पहुँचाना या नष्ट करना।

बुनियादी विशेषताओं

इसका मतलब होगा संविधान को फिर से लिखना और संविधान को लूटना ।

संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करने वाली विधायिका यह । इस पर कोई भी कानून चुनौती से मुक्त नहीं हो सकता है ।

भले ही विधायी उपाय के भीतर है

विधायिका की पूर्ण शक्तियाँ " ।

निरीक्षण करने के लिए चला गया (पी पर । 437):

" बुनियादी संरचनाओं या बुनियादी विशेषताओं का सिद्धांत एक है

अभेद में व्यायाम करें । बुनियादी संरचनाएँ या बुनियादी सुविधाएँ

संस्कार अक्षम्य होते हैं । विधायी प्रविष्टियाँ क्षेत्र हैं

कानून । पिथ और पदार्थ सिद्धांत किया गया है

कानून की शक्ति से वंचित करना और उन्हें वंचित करना विधायी नीतियों को निर्धारित करना । यह अतिक्रमण होगा ।

शक्तियों के पृथक्करण पर " ।

मैथ्यू, जे. ने श्रीमती में अवलोकन किया । इंदिरा गांधी का मामला (ऊपर)

525-526 ) :

" मुझे लगता है कि बुनियादी को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने के लिए अवरोध

संविधान के संशोधन द्वारा संरचना से प्रवाहित होती है

अनुच्छेद के तहत संशोधन की शक्ति पर सीमा

368 भारती के मामले में बहुमत से इसे पढ़ें क्योंकि उनकी धारणा है कि कुछ निश्चित बुनियादी हैं

संविधान की विशेषताएँ जो इसके निर्माताओं का इरादा था

वहाँ हमेशा के लिए रहें । लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता ।

जहाँ तक संसद या राज्य विधान की शक्ति का संबंध है

शक्ति और शक्ति पर सीमा भी प्रदान करता है इन अंगों से कानून पारित करने के लिए। यह केवल विशिष्ट प्रावधान है

संविधान में अधिनियमित किए गए नियम जो के रूप में कार्य कर सकते हैं

संविधान का, न तो शक्ति का स्रोत है और न ही एक सीमा शक्ति पर ध्यान देना। प्रस्तावना विचारधारा को निर्धारित करती है।

लोगों की आकांक्षाएँ। की आवश्यक विशेषताएँ

में चित्रित

प्रस्तावना में निर्धारित महान अवधारणाएँ हैं - संविधान के विभिन्न प्रावधान। यह है।

ये

संविधान के निकाय में विशिष्ट प्रावधान जो

लोकतंत्र के प्रकार का निर्धारण करें जो [1978] 2 एस. सी. आर. के संस्थापक करते हैं।

84

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वह साधन स्थापित; न्याय की गुणवत्ता और प्रकृति,

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो उनकी इच्छा थी,

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सामग्री जो वे

उस दस्तावेज़ में निहित, स्थिति की समानता का दायरा

और अवसर जो उन्होंने उसमें निहित किया। ये विशिष्टताएँ

केवल संविधान में अधिनियमित कुछ प्रावधान ही निर्धारित कर सकते हैं

स्थापित संविधान की मूल संरचना। ये

विशिष्ट प्रावधान, या तो अलग से या संयोजन में  
में निर्धारित महान अवधारणाओं की सामग्री का निर्धारण करें  
प्रस्तावना। किसी भी ठोस अवधारणा को प्रस्तुत करना असंभव है।  
में निर्धारित गौसमर अवधारणाओं से मूल संरचना का

प्रस्तावना। संविधान के विशिष्ट प्रावधान हैं -  
वह सामान जिससे मूल संरचना को बुना जाना है।

श्रीमती में। इंदिरा गांधी का मामला (ऊपर), चंद्रचूड़, जे., के बाद

प्रस्तावना की प्रकृति पर इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए और यह इंगित करते हुए कि  
केशवानंद भारती (ऊपर) में बहुमत का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दी गई संविधान  
की बुनियादी विशेषताओं की कोई सहमत सूची नहीं थी, सामान्य विधान की शक्ति के लिए  
बुनियादी संरचना सिद्धांत के लागू होने पर कहा। ( पीपी में। 669. 670):

" संवैधानिक संशोधन, के अनुपात पर हो सकता है

बुनियादी संरचना। लेकिन इस सिद्धांत के अलावा कि एक मामला  
यह केवल एक प्राधिकरण है जो यह तय करता है, यह तार्किक रूप से नहीं है

मौलिक में बहुमत के फैसले का पालन करें

संवैधानिक संशोधन के रूप में एक ही परीक्षण। सामान्य कानून  
उनकी वैधता के लिए दो परीक्षणों का उत्तर देना होगा: ( 1 ) कानून.

विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर होना चाहिए  
संविधान के अध्याय I, भाग XI में परिभाषित और निर्दिष्ट

शिक्षा और (2) यह प्रावधानों के खिलाफ अपराध नहीं करना चाहिए

संविधान का अनुच्छेद 13 (1) और (2)। बेसिक स्ट्रक

बहुमत के फैसले के अनुसार 'ट्यूअर' फंड का हिस्सा नहीं है।

मानसिक अधिकार और न ही वास्तव में संविधान का कोई प्रावधान।

बुनियादी संरचना का सिद्धांत कॉन्सपेक से बुना गया है

संविधान की जिम्मेदारी और संशोधन की शक्ति विषय है क्योंकि यह एक घटक शक्ति है। संशोधन करने की शक्ति

मूल यंत्र अपने साथ शक्ति नहीं ले जा सकता है।

मूल संरचना का सिद्धांत। यह पूरी तरह से जगह से बाहर है बनाए गए सामान्य कानूनों की वैधता से संबंधित मामलों में

संविधान के तहत "।

तथापि, जे. खन्ना और मैं दोनों ने वहाँ अपने विचार व्यक्त किए।

प्रस्तावना के साथ-साथ संविधान के अन्य भागों में निर्धारित भारत के लोगों की आकांक्षाओं ने सभी कानूनों की संवैधानिकता का निर्णय करने में सामान्य मार्गदर्शन प्रदान किया, चाहे वह संवैधानिक हो या सामान्य। मैंने वहाँ विशेष रूप से कहा कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उपयोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है या तो इसकी घटक या साधारण कानून बनाने की क्षमताओं में।

कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

85

क्योंकि "साधारण कानून बनाना निरंतरता की सीमा से परे नहीं जा सकता है।

टचून्ट पावर "।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दस्तावेज़ से निष्कर्षों के एक समूह के रूप में (यानी कॉन्स्टी

केवल संविधान से संबंधित है और उस अर्थ में, इससे संबंधित नहीं है साधारण विधियों का क्षेत्र या उन्हें उसी में लागू करने के लिए उत्पन्न होता है

रास्ता। लेकिन, अगर, सिद्धांत के परिणामस्वरूप, कुछ अनिवार्यताएँ हैं

या तार्किक रूप से और आवश्यक रूप से संविधान से प्रवाहित होता है

' बुनियादी संरचना ", जैसे कि वे इसके स्पष्ट जनादेश हैं, वे

साधारण कानूनों की वैधता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए

जैसा कि संविधान के अन्य भागों का उपयोग किया जाता है।

श्रीमती में। इंदिरा गांधी का मामला (ऊपर), दृष्टिकोण के अंतर

विद्वान न्यायाधीशों के बीच इस सवाल पर इतना कुछ नहीं था कि क्या " मूल संरचना को वास्तव में एक अतिरिक्त हिस्सा माना जाना था।

संविधान का (इस पर सहमति है कि वह नहीं कर सकता) या

केवल इसके निर्माण का एक सिद्धांत, लेकिन इस सवाल पर कि क्या, एक बार

यह दोनों संवैधानिक की वैधता का परीक्षण करने के लिए लागू था साथ ही साधारण कानून-निर्माण। विद्वान न्यायाधीशों का बहुमत का दृष्टिकोण

इस न्यायालय का ऐसा प्रतीत होता था कि, यह वली का परीक्षण करने के लिए उपलब्ध नहीं था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विवादित प्रावधानों की स्थिति

संसद काफी स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, यह माना जाता था यहाँ इस दृष्टिकोण पर लागू होता है कि हल करने के लिए कोई अस्पष्टता नहीं थी

संसद की सामान्य कानून बनाने की शक्तियों के बारे में। यह था। संविधान शक्ति के दायरे की व्याख्या करने के लिए लागू किया गया जैसा कि था

इसके दायरे के बारे में कुछ अनिश्चितता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों" और "कानून के समक्ष समानता" की परीक्षा थी

इस न्यायालय द्वारा श्रीमती में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विवादित प्रावधानों की वैधता का न्याय करने में उपयोग किया गया। इंदिरा नेहरू गाँधी

हालांकि पीठ के अधिकांश विद्वान न्यायाधीशों ने इन विशेषताओं को संविधान की मूल संरचना के भागों के रूप में चिह्नित किए बिना ऐसा करना पसंद किया। लेकिन, इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि क्या कथित संवैधानिक संशोधन इस न्यायालय की सुनवाई करने और उसके समक्ष लंबित चुनाव अपीलों के गुण-दोष पर निर्णय लेने की शक्तियों को छीन सकता है, उस मामले के निर्णय में भाग लेने वाले सभी विद्वान न्यायाधीश, अलग-अलग मात्रा में, या तो पूर्व या निहित रूप से, संविधान के "मूल ढांचे" पर भरोसा करते प्रतीत होते हैं, जैसा कि इसके स्पष्ट प्रावधानों द्वारा प्रकट किया गया है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि, एक विधायी शक्ति का प्रयोग

करने की आड़ में, संसद, वास्तव में, संविधान के तहत एक व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं ले सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों की बहुमत की राय

केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) में निर्णय में भाग लिया और जिन्होंने श्रीमती में निर्णय में भाग लिया। इंदिरा गांधी का मामला (ऊपर), कुछ संवैधानिक संशोधनों को अमान्य करते हुए, संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के बहुत विस्तृत संदर्भों द्वारा संविधान की मूल संरचना पर आधारित सीमाओं को स्पष्ट करता है। श्रीमती में। इंदिरा नेहरू गाँधी का मामला (ऊपर), संविधान के भाग (1978) 2 एस. सी. आर.

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

86

( 1975 के तीस-नौवीं संशोधन) अधिनियम को मुख्य रूप से इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के विशिष्ट प्रावधानों ने इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि संसद के दोनों सदनों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत पर संविधान द्वारा जो प्रदान किया गया था, वह एक विधायी शक्ति थी, न कि एक न्यायिक शक्ति जो इसकी सामग्री और प्रक्रिया दोनों द्वारा आंकी गई थी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित विधायी शक्तियों के कथित प्रयोग में, विशिष्ट शक्ति की शर्तों पर, न्यायिक शक्ति का प्रयोग, प्रथम दृष्टया वैकल्पिक अधिकार था। शक्ति का इस तरह का प्रयोग संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा इंगित शक्ति की विधायी कक्षा भी एक आवश्यक हिस्सा है। जिस सिद्धांत पर जोर दिया गया था, वह मेरे द्वारा इस प्रकार कहा गया था:

" तीन संवैधानिक रूप से अलग-अलग अंगों में से कोई भी नहीं

राज्य, हमारे संविधान की मूल योजना के अनुसार कर सकता है

आज, अपने संविधान की सीमाओं से बाहर कूदें  
क्षेत्रीय रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र या प्राधिकरण की कक्षा

दूसरा "।

इन कक्षाओं में पाए गए नियम द्वारा स्पष्ट रूप से चाक आउट किया गया था

संविधान। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। समग्र रूप से संविधान के प्रावधानों को पढ़ने पर, कि विधायी और न्यायिक शक्ति के दायरे समान नहीं हैं। लेकिन, जहां तक विधायी शक्तियों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि संसद की विधायी शक्तियां

और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक मामले में पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

पेक्ट। कानून बनाने का एक समवर्ती क्षेत्र भी है। और, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण विधायी के रास्ते में आ सकता है हमारी संसद को सौंपे गए क्षेत्रों में प्रदत्त शक्ति। ये एक आवश्यक या अपरिहार्य निहितार्थ द्वारा अधिक से अधिक सीमित हो सकते हैं।

जैसे कि वह जो न्यायपालिका की नियुक्ति से प्रवाहित होना चाहिए और विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ अलग-अलग, स्पष्ट रूप से अलग-अलग

विशेषताएँ, विभिन्न प्राधिकरणों पर। मूल योजना

संविधान को निश्चित रूप से कानून को अमान्य करने के लिए लागू किया जा सकता है

संसद, एक विषय पर अपनी सामान्य कानून बनाने की क्षमता में कार्य करती है। जो या तो विशेष रूप से एक संशोधन की कक्षा के भीतर आता है

संविधान "या विशेष रूप से सातवीं अनुसूची की सूची II में

राज्य के विषय। लेकिन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, यहाँ ऐसा नहीं है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब भी मूल संरचना का सिद्धांत

व्याख्या या लागू किया गया है यह केवल व्याख्या के सिद्धांत के रूप में है संविधान का जैसा कि यह वास्तव में मौजूद है और किसी संविधान का नहीं जो

विभिन्न व्यक्तियों के मन में केवल व्यक्तिपरक रूप से मौजूद हो सकता है संविधान क्या है, इसके बारे में केवल सिद्धांत। सिद्धांत ने नहीं किया

संविधान की सामग्री में जोड़ें। इसने, सिद्धांत रूप में, कटौती नहीं की

जो कुछ भी वहाँ था। यह केवल बाहर लाने के लिए अभिप्रेत है और जो पहले से ही वहाँ था उसका अर्थ समझाएँ। वास्तव में यह था,

सभी न्यायाधीशों द्वारा केवल इस उद्देश्य के लिए अलग-अलग परिणामों के साथ उपयोग किया जाता है

क्योंकि उनके आकलन या निष्कर्ष के रूप में क्या हिस्सा था  
 हमारे संविधान की बुनियादी संरचना अलग थी। मुझे लगता है कि यह  
 कर्नाटक बनाम संघ की मूल संरचना के सिद्धांत की सही व्याख्या (बेग, सी. जे.)

87

संविधान। इसे केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब यह स्पष्ट हो, संदेह के क्षेत्र से परे, कि जिसे अन्य बुद्धिमान स्पष्ट और पूर्ण विधायी शक्ति पर प्रतिबंध के रूप में रखा गया है, वह एक संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में है।

यदि यह मूल संरचना के बारे में सही दृष्टिकोण है, तो एक मोड के रूप में

केवल संविधान की व्याख्या करते हुए, तथाकथित संघवाद को विधायी शक्ति पर एक बंधन के रूप में कुछ स्पष्ट प्रावधानों में अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए -

न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) का फैसला करने वाले अधिकांश न्यायाधीशों ने "संघवाद" को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं माना है।

ट्यूशन। और, उनमें से किसी ने भी "संघीय" के विस्तार पर चर्चा नहीं की है।

इस संरचना का हिस्सा। के अनुच्छेद 1 की ओर इशारा करना पर्याप्त नहीं है

संविधान इस बात पर जोर देता है कि हमारा गणराज्य राज्यों का एक "संघ" है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सच है। लेकिन, कॉन में "यूनियन" शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

हमारे संघीय गणराज्य के विशिष्ट चरित्र का पाठ इसके द्वारा प्रकट किया गया

प्रावधानों को व्यक्त करें। हमें अभी भी अन्य एक्सप्रेस प्रोवी से खोजना है

सायंस, इस "संघ" का क्या अर्थ है या इसकी सीमा या प्रकृति क्या है

" संघवाद "इसके द्वारा निहित है। संविधान स्वयं इसका उपयोग नहीं करता है

शब्द "संघ" बिल्कुल भी। किसी भी मामले में, सभी पूर्व की जांच करने के बाद

संविधान के प्रेस प्रावधान, विद्वान वकील द्वारा निर्भर वादी के लिए, मैं वहाँ ऐसी कोई बंधन खोजने में असमर्थ हूँ जो

एक आवश्यक निहितार्थ से, संसद को अधिनियमित करने से रोक सकता है अधिनियम की धारा 3।

वास्तव में, यदि आवश्यक निहितार्थ के सिद्धांत को लागू किया जाना है

यहाँ, हमारे संविधान के निहित प्रावधान, जिनके लिए एक विशेष

संशोधन के लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के भीतर ही निर्धारित की गई है,

ऊपर चर्चा किए गए अन्य प्रावधानों के साथ, एक्सप्रेस दें

वे सीमाएँ जिनमें संघीय सिद्धांतों के संचालन सीमित हैं

हमारा संविधान। स्पष्ट रूप से उल्लिखित विशेषताओं में से कोई भी,

कोई भी आवश्यक निहितार्थ, स्पष्ट रूप से दिए गए और डिस पर प्रभाव डालता है

संकटग्रस्त विधायी शक्तियाँ। जिस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, वह इसमें शामिल नहीं है

जिसका इस प्रकार उल्लेख नहीं किया गया है, वह व्यक्त सीमाओं पर भी लागू होता है। अगर

विधायी शक्तियों के वितरण की योजना बुनियादी और स्पष्ट है,

अपनी स्पष्ट सीमाओं के साथ, "निहित" या अनिर्दिष्ट कथित सीमा उस योजना से परे जाने वाली राशियों को बहुत ही बल से समाप्त कर दिया जाता है

स्पष्ट प्रावधान।

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और

ओआरएस (1)। मैं पाता हूँ कि अधिनियम और अधिसूचना की वैधता

अधिनियम की धारा 3 को चुनौती दी गई थी लेकिन इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, हालांकि अधिसूचना के खंड 10 का एक भाग जो, आवश्यकता के अतिरिक्त

यह भविष्य में इसी तरह के मामलों को रोकने के उपायों की सिफारिश करने के लिए भी निर्देश देता है

आयोग की राय में उस कार्रवाई पर रिपोर्ट करने के लिए

निवारण या सजा प्राप्त करने के रूप में लिया जाना चाहिए ", जहां तक  
बाद वाले को अधिनियम के दायरे से बाहर माना गया था

हिस्सा जांच के विशुद्ध रूप से जांच चरित्र से परे चला गया

अधिनियम द्वारा प्राधिकृत। उस मामले में आयोग की आवश्यकता थी

कुछ मामलों के प्रशासन की जांच करें और रिपोर्ट करें

( 1 ) [ 1955 ] एस. सी. आर 279

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

88

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट कंपनियाँ। यह था।

वहाँ अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि केवल द्वारा दी गई शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना

अधिनियम अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति को दूषित नहीं कर सका। यह था।

वहाँ यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम संसद द्वारा खेतों में कार्य करते हुए बनाया गया था

सूची I की प्रविष्टियाँ 94 और सातवीं की सूची III की प्रविष्टियाँ 45 द्वारा इंगित  
अनुसूची ताकि पूछताछ का आदेश दिया जा सके "के उद्देश्यों के लिए

सूची I, सूची II और सूची III में से कोई भी मामला। की अक्षमता

बी.

उस सूची में विषयों से संबंधित पूछताछ का आदेश देने की शक्ति को दूषित करना। सूची III में प्रविष्टि 45 की स्पष्ट शर्तें। यह माना गया था कि दायरा

जाँच में उनकी जाँच के सहायक मामले भी शामिल हो सकते हैं। स्वयं को। इसके अलावा, काथी रानींग रावत बनाम पर भरोसा करना। की स्थिति

सौराष्ट्र, (1) यह इंगित किया गया था (पृ. 293):

सी.

" आयोग के पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है

एक आदेश पारित करने की भावना जिसे लागू किया जा सकता है

जोरदार। अधिकारियों पर एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए

एक निर्णय के बीच खींचा गया, जिसका अपने आप में कोई बल नहीं है

और कोई दंडात्मक प्रभाव नहीं और एक निर्णय जो लागू हो जाता है

तत्काल सक्षम या जो कुछ लोगों द्वारा प्रवर्तनीय हो सकता है

कार्रवाई की जा रही है "।

यह सच है कि आर. के. डालमिया के मामले में (ऊपर) के प्रावधान

अधिनियम पर उन सभी व्यापक आधारों पर हमला नहीं किया गया था जिन पर वे

अब हमारे सामने पूछताछ की गई है। फिर भी, वस्तुओं के

अधिनियम पर विचार किया गया और वहां संकेत दिया गया।

जिन उद्देश्यों के लिए आयोग की स्थापना की जा सकती है

नागपुर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने बहुत पहले इस अधिनियम पर विचार किया था।

एम. वी. राजवाडे बनाम में न्यायालय डॉ. एस. एम. हसन और अन्य (2), जो थे

ब्रजनंदन सिन्हा बनाम में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत। ज्योति

नारायण (3) और निम्नलिखित अंश को फैसले से उद्धृत किया गया था:

" विचाराधीन आयोग को स्पष्ट रूप से नियुक्त किया गया था  
राज्य सरकार द्वारा इसकी जानकारी के लिए

स्वयं के

मन', ताकि यह कार्य न करे, अपने exe के अभ्यास में

क्यूटिव पावर, 'डिक्टेट्स के अनुसार के अलावा

विभागीय जाँच के आदेश में 'न्याय और समता'

अपने अधिकारियों के खिलाफ। इसलिए यह एक तथ्य खोजने वाला निकाय था।

' इसका मतलब केवल बिना सरकार के दिमाग को निर्देश देना है

न्यायिक प्रकृति का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना।

यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि ए. संजीवी नायडू आदि में। वी.

व्यक्तिगत मंत्री जो नीति और कार्यक्रमों के मामलों को निर्धारित करता है उनके  
मंत्रालय का, सरकार की प्रमुख नीतियों के ढांचे के भीतर

अपने प्रभार वाले विभाग के अधिकारियों के साथ, जो मौखिक रूप से दिए गए निर्देशों के  
अधीन सरकार की ओर से कार्य करना।

( 1 ) [ 1952 ] एस. सी. आर 435

( 2 ) [ 1954 ] आई. एल. आर. नागपुर पी. 1 @ 13 .

( 3 ) [ 1955 ] 2 एससीआर 955।

( 4 ) [ 1970 ] 3 एस. सी. आर. 505 @512

कर्नाटक वी. यूनियन (बेग, सी. जे.)

या संबंधित मंत्री द्वारा लिखित रूप में। इसलिए, किसी विशेष मामले में, संबंधित मंत्री और उनके निर्देशों के तहत काम करने वाले अधिकारियों के बीच किसी भी कार्य या निर्णय के लिए दोष या जिम्मेदारी को विभाजित करना, जो कथित रूप से गलत है, काफी कठिनाई, नाजुकता और महत्व का विषय बन सकता है। इस तरह के विभाजन। सुरक्षित रूप से केवल उन विशेषज्ञों को सौंपा जा सकता है जिनके पास काफी न्यायिक अनुभव है और वे उठाए गए मुद्दों के साथ पूरी तरह से निष्पक्षता और निपुणता से निपट सकते हैं। नैतिक या सामूहिक जिम्मेदारी जो राजनीतिक है, एक अलग मामला है जो निस्संदेह जांच आयोग की रिपोर्टों से प्रभावित हो सकता है। व्यक्तिगत दायित्व के संबंधित मंत्री के लिए सामूहिक दायित्व से भी अधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें केवल राजनीतिक निहितार्थ होते हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाम। बख्शी गुलाम मोहम्मद (1)

इस अदालत ने बताया कि भले ही बख्शी गुलाम मोहम्मद ने

जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया

अतीत के कार्य सार्वजनिक महत्व के मामले नहीं रहेंगे। यह.

निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया जब उसने कहा (पर पी। 407 ) :

" उच्च न्यायालय के इन विद्वान न्यायाधीशों ने व्यक्त किया कि

विचार है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के कृत्य

यदि वे पद पर होते तो सार्वजनिक महत्व के कार्य होते लेकिन

वे इस तरह से बंद हो गए क्योंकि वे पद से बाहर थे जब अधिसूचना

घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस दृष्टिकोण को लेते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर

राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर ने कहा कि एक व्यक्ति का आचरण इस तरह के एक खतरनाक पेशेवर मान सकता है

भाग और इस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित या प्रभावित करने की धमकी दे सकता है

इस तरह के आचरण को निश्चित करने के लिए सार्वजनिक कल्याण

सार्वजनिक महत्व का मामला, तत्काल पूर्ण आह्वान  
 पूछताछ "। विद्वान न्यायाधीशों ने महसूस किया कि बख्शी से  
 गुलाम मोहम्मद पद से बाहर थे, वे बन गए थे  
 हानिरहित; जाहिरा तौर पर, यह महसूस किया गया कि वह लंबे समय तक नहीं रह  
 सकता था

अपने कृत्यों से जनता की भलाई के लिए खतरा था और इसलिए बाहर हो गया था  
 डालमिया के मामले में अवलोकन का पक्ष लें। हम अपने में स्पष्ट हैं  
 ध्यान रखें कि यह इस न्यायालय की टिप्पणी का गलत अध्ययन है।  
 यह न्यायालय, जैसा कि विद्वान न्यायाधीशों ने स्वयं देखा था,

सार्वजनिक मामलों की एक विस्तृत परिभाषा निर्धारित नहीं करना  
 महत्व। किसी भी मामले में किस बात की जांच की जानी चाहिए  
 आवश्यक रूप से पिछले कार्य और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पहले से ही हैं  
 जनता के कल्याण को प्रभावित करता है या उनका प्रभाव ऐसा कर सकता है, कि  
 वे सार्वजनिक महत्व के मामले बन गए। यह अप्रासंगिक है  
 क्या उन कृत्यों को करने वाला व्यक्ति अभी भी है  
 उन्हें दोहराने में सक्षम होने की शक्ति।

अंतिम उल्लिखित उच्चारण का स्पष्ट निहितार्थ,

जिस पर मैं खुद को पूर्ण और सम्मानजनक समझौते में पाता हूं, वह यह था कि  
 आपराधिक अपराध हो सकते हैं, फिर भी, उनकी जांच की जा सकती है  
 सार्वजनिक महत्व के मामले के रूप में और न कि केवल निजी महत्व के रूप में।

( 1 ) [ 1966 ] सप. एस सी आर 401.

[

1978 ] 2 एससीआर

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

90

और, क्या किया जा सकता है जब वह पद से बाहर हो सकता है, एक दुर्भाग्य, हो सकता है आदेश दिया जब वह कार्यालय में होता है। इस न्यायालय ने यह भी कहा:

जिनसे मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ (पृ. 406):

..... यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक आयोग कैसा हो सकता है।

के कृत्यों की जांच के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा स्थापित

इसके प्रमुख, प्रधानमंत्री, जब वे कार्यालय में होते हैं। निश्चित रूप से

ऐसा होना सबसे असामान्य बात होगी। अगर बाकी

मंत्रिपरिषद ने किसी भी जांच का संकल्प लिया, प्रथम

मंत्री से उनका इस्तीफा मांगने की उम्मीद की जा सकती है। किसी भी मामले में मामला, वह खुद बाहर जाएगा। अगर वह पहला कोर्स करता है,

तब मंत्रियों के लिए कोई आयोग नहीं बनाया जाएगा।

जाँच करना चाहते तो चला गया होता। अगर वह बाहर जाता है

स्वयं, तब आयोग का गठन जांच के लिए किया जाएगा

एक व्यक्ति के कार्य जो अब कार्यालय में नहीं थे और उसके लिए

कारण, यदि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश सही थे,

ऐसे मामलों में जो सार्वजनिक महत्व के नहीं थे। इसका परिणाम

यह होगा कि एक प्रधानमंत्री के कार्य कभी नहीं हो सकते

अधिनियम के तहत पूछताछ की गई। हमें यह बहुत मुश्किल लगता है।

उस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए।

पी. वी. जगन्नाथ राव और अन्य में। वी. उड़ीसा राज्य और अन्य। ( 1)  
 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि नियुक्ति  
 अधिनियम की धारा 3 के तहत जांच आयोग का  
 सरकार को "उपयुक्त विधायी या विधायी" बनाने में सक्षम बनाने का कार्य  
 पोली की शुद्धता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक उपाय  
 राज्य में तकनीकी प्रशासन वैध था।

फिर से कृष्ण वल्लभ सहाय और ओआरएस में। वी. जाँच आयोग  
 & ओआरएस। ( 2) एक समान दृष्टिकोण लिया गया था और यह इस द्वारा देखा गया था  
 के आचरण में भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में न्यायालय  
 मंत्री (पृ. 394):

" यह पर्याप्त रूप से दृढ़ता से नहीं कहा जा सकता है कि जनता  
 अधिकारी व्यक्तियों के जीवन को कभी भी ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।  
 उनके खिलाफ फंसाया भी जा रहा है। अगर उन्हें बनाया जा सकता है तो  
 एक जांच कि क्या उन्हें स्थापित करना है या नाम को साफ करना है  
 आरोपित व्यक्ति को बुलाया जाता है। एक्सएक्स

XX

XX

XX

आधारों का अवलोकन हमें आश्वस्त करता है कि आरोप हैं  
 विशिष्ट, और मौखिक गवाही के बजाय वह अभिलेख होगा  
 उन्हें स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है।  
 मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ।

मद्रास उच्च न्यायालय के कैलासम सी. जे. ने एम. करुणानिधि बनाम. द.

भारत संघ और ए. एन. आर. ( 3)

मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि हमले के लिए हमारे सामने रखे गए विचार  
संसद की विधायी क्षमता को अस्वीकार कर दिया गया है

काफी असंगत होने के नाते, अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को "पढ़ने" के लिए उपयोग  
नहीं किया जा सका-एक प्रक्रिया जो कुछ हो सकती है

( 1 ) [ 1968 ] 3 एससीआर 789।

( 2 ) [ 1969 ] 1 एस सी आर 387.

( 3 ) ए. एल. आर. 1977 मैड, 192.

कर्नाटक बनाम। यूनियन (बेग, सी. जे.)

91

किसी प्रावधान को आंशिक या पूर्ण रूप से अमान्य होने से बचाने के लिए उपलब्ध समय। "नीचे  
पढ़ना, आखिरकार, निर्माण के सिद्धांत का केवल एक तार्किक परिणाम है-उट रेस मैजिस वालेत  
कम पेरेत (देखें): क्रेज ऑन। " संविधि कानून "6 वीं। एड। पी। 103 ) .

अंतिम प्रश्न जिसका मैं विज्ञापन करने का प्रस्ताव करता हूँ वह प्रारंभिक से संबंधित है  
के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे की रखरखाव पर आपत्ति

संविधान जिस पर मैं जे. चंद्रचूड़ के निष्कर्षों को साझा करता हूँ और जे. भगवती और जे.  
कैलासम के खिलाफ, उचित सम्मान के साथ,

हमारे विद्वान भाइयों में से जिन्होंने माना है कि वादी को होना चाहिए

इस आधार पर गैर-उपयुक्त कि एक सूट जैसा कि अब पहले था

हम पर

यह संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत बिल्कुल भी नहीं है।

मैंने उन सभी तर्कों पर विस्तार से चर्चा की है जो आगे बड़े थे।

कर्नाटक राज्य की ओर से क्योंकि मैं इसे सही मानता हूँ वादी के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना कि मामले में शामिल है

में

सरकारी शक्तियों के प्रयोग पर विचार करना जो निहित है

राज्य सरकार और उसके मंत्री, उनके संबंध में। केंद्र सरकार और उसके मंत्री। वे सवाल भी उठाते हैं

के अर्थ और परिधि और प्रयोज्यता से संबंधित मामले

संविधान के विशेष प्रावधान जिनके संचालन के हैं

प्रत्येक राज्य के लिए महत्वपूर्ण हित। वास्तव में, दी गई व्याख्याएँ

को

ये प्रावधान अनिवार्य रूप से संघ के लिए बहुत चिंता का विषय होने चाहिए क्योंकि ठीक है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें पूरे देश के हित शामिल हैं।

भारत के लोग जिन्होंने खुद को संविधान दिया

प्रावधानों की हमने व्याख्या की है।

भारत संघ, केंद्र सरकार के माध्यम से कार्य कर सकता है

कहा जाता है कि वे पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्ति ने

यह कहा जा सकता है कि राज्य अपनी सरकारों और मंत्रियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

प्रत्येक राज्य के लोगों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करना।

जब राज्य के प्रतिनिधियों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं

और व्याख्या के प्रश्नों पर भारत के पूरे लोगों के संविधान, जो पूरे लोगों के कल्याण को प्रभावित करता है,

और विशेष रूप से संबंधित राज्य के लोगों के लिए, ऐसा प्रतीत होता है मेरे लिए, बहुत सम्मान के साथ, बहुत अधिक तकनीकी होना एक तर्क है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है

हमारे द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 131 के तहत ऐसे मामले में मुकदमा नहीं है। संविधान से।

हमारे सामने मामले के दोनों पक्षों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत मांग की जाती है। वे केवल इस पर भिन्न हैं सवाल यह है कि क्या संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार सरकार भी, इस मामले के तथ्यों पर, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। उनके दावे विरोधाभासी हैं। एक लीस है। विवाद के पक्षकार हैं हमारे सामने। हमें यह तय करना था और हमने ऐसा किया है।

ऐसा लगता है।

मेरे लिए कि राज्य और उसकी सरकार के बीच एक अंतर है, सबसे अधिक, पूरे और पूरे के एक अविभाज्य हिस्से के बीच एक। यह किसी भी राज्य की ओर से दावों के संबंध में महत्वहीन होगा। या उसकी सरकार चाहे दोनों अलग-अलग न्यायिक संस्थाएं हों। यहां तक कि यदि वे स्पष्ट रूप से अलग हो सकते हैं, जो संदिग्ध है, का दावा सरकार राज्य की होगी।

7-

1042 एससीआई/77 [1978] 2 एस. सी. आर.

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य में v. भारत संघ (1) इस न्यायालय ने हाल ही में

अनुच्छेद 131 के दायरे पर विचार किया गया। वहाँ, मैंने कहा, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रश्न पर (पृ. 1393):

" मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक या एक लेने की आवश्यकता है

किसी भी अधिकार के लिए मुकदमा करने के राज्य के अधिकारों का अति-तकनीकी दृष्टिकोण,

वास्तविक या काल्पनिक जिसे राज्य सरकार लेना पसंद करती है।

कला के तहत एक मुकदमे में संबंधित राज्य की ओर से।

131. "

यहाँ यह समझाया जा सकता है कि इस अवलोकन का उद्देश्य नहीं था

जब राज्य सरकार द्वारा की गई किसी कार्रवाई के विरुद्ध संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मुद्दा उठाया जाता है, या केंद्र सरकार द्वारा विचार की गई किसी कार्रवाई के विरुद्ध, जो वहां थी, राज्य और उसके लोगों के हितों के लिए एक सांठगांठ होने का अनुमान लगाया जाएगा। मैं इस धारणा को दूर करना चाहूंगा कि अगर ऊपर उद्धृत टिप्पणियों में "वास्तविक या काल्पनिक" शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी किसी सांठगांठ की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, मेरा मानना है कि हमारे सामने मौजूद मामले में, प्रतिद्वंद्वी दावों और राज्य की जनता के हितों के बीच की सांठगांठ उचित रूप से बनाई गई है। यह एक अलग बात है कि मैं कर्नाटक राज्य की ओर से सामने रखे गए इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि मुख्य रूप से राज्य से संबंधित सार्वजनिक महत्व के मामले पर अधिनियम की धारा 3 के तहत आयोग का गठन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास नहीं, बल्कि उसके पास भी है।

यह याद रखना होगा कि अनुच्छेद 131 धारा का पता लगाने योग्य है।

204 भारत सरकार अधिनियम। इस प्रकार इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित संघीय संरचना का हिस्सा था। यह उस अधिनियम में पाए गए संघवाद का अवशेष है। इसलिए, इस कारण से भी इसकी व्यापक और उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इच्छित उपचार को आगे बढ़ाया जा सके। मेरी राय में, जब भी कोई राज्य और अन्य राज्य या संघ संविधान की व्याख्या के सवाल पर भिन्न होते हैं, तो इसे लागू किया जा

सकता है ताकि इसका कोई निर्णय सरकारी शक्तियों के दायरे या प्रयोग को प्रभावित करे जो किसी राज्य की विशेषताएँ हैं। यदि राज्य की शक्तियों, जो कि विशेष, विधायी और न्यायिक हैं, का प्रयोग विशेष भारतीय दृश्यों के माध्यम से किया जाता है, तो इससे कार्रवाई की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि उन्हें आवश्यक रूप से होना चाहिए। यह सच है कि एक अपराधी

कार्य करें

मंत्रि द्वारा किया गया कार्य उसके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। लेकिन, यदि राज्य का कोई भी अंग इसका संज्ञान लेने के लिए अनन्य शक्ति का दावा करता है, तो राज्य, अपने किसी एक अंग की कानूनी क्षमता या शक्तियों के विस्तार के बारे में विवाद में रुचि रखता है जो उभर सकता है।

मुझे नहीं लगता कि यह तथ्य कि राज्य अपने मंत्रियों के माध्यम से कार्य करता है

या अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे की रखरखाव क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 166 (3)

के रूप में

साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 59 (3) "व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेनदेन" के लिए मंत्रालयों के बीच सरकार के व्यवसाय के आवंटन के लिए उपबंध करती है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य केवल अपनी सरकार के माध्यम से ही कार्य नहीं कर सकता है

( 1 ) ए. एल. आर. 1977 एस. सी. 1361.

एम. कर्नाटक वी. यूनिन (बेग, सी. जे.)

93

लेकिन नियमों द्वारा प्रदान किए गए अपने व्यक्तिगत मंत्रियों के माध्यम से भी। भारत सरकार अधिनियम की धारा 49 (1) ने इस स्थिति को अधिनियमित करके पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया:

" प्रांत के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

महामहिम की ओर से राज्यपाल द्वारा, या तो सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से।

इसके बराबर हमारे संविधान का अनुच्छेद 154 (1) है जो इस प्रकार पढ़ता है:

" 154. राज्य की कार्यकारी शक्ति - ( 1 ) निष्पादक

राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और

उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।

इस संविधान के अनुसार उसके अधीन "।

राजा में-सम्राट वी। शिवनाथ बनर्जी और अन्य। ( 1 ) प्रिंसी काउंसिल

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "एक मंत्री राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी है" केवल भारत सरकार अधिनियम की धारा 49 के प्रयोजनों के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने ए. संजीवी नायडू के मामले में इस टिप्पणी पर भरोसा किया था।

आदि। वी. मद्रास और अन्र राज्य। ( 2 ) संविधान के अनुच्छेद 154 (1) के प्रयोजनों के लिए हमारे मंत्रियों की स्थिति के संबंध में।

इन प्रावधानों के बीच किसी भी विरोधाभास को स्थापित करने से दूर

एक मंत्री और उस राज्य की आधिकारिक क्षमता जिसके लिए वह कार्य करता है,

केवल

दिखाइए कि मंत्री के रूप में वह सरकार का प्रतिनिधि या अंग है।

पुर के लिए

राज्य का, और इसलिए, उसे एक "अधिकारी" के रूप में माना जा सकता है।

अनुच्छेद 154 (1) जो इस अधिनियम की धारा 49 के अनुरूप है।

भारत सरकार अधिनियम। परिणाम यह है कि एक मंत्री के आधिकारिक कार्य

जिसे उस राज्य के लोगों से अलग नहीं किया जा सकता है जिसकी ओर से वह मेरे विद्वान भाइयों के दृष्टिकोण के प्रति बहुत सम्मान के साथ जो एक मंत्री की शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है जो उसके आधार पर प्राप्त होती हैं कार्यालय। संविधान के अनुच्छेद 131 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को प्रतिबंधित करें, जिसे हमेशा अपने अधिकारियों के माध्यम से कार्य करना चाहिए या एजेंट या मंत्री, केंद्र सरकार पर मुकदमा करने से न केवल इसके एजेंटों, अधिकारियों या मंत्रियों में से किसी एक को आगे बढ़ने से बचाएँ केंद्र सरकार के खिलाफ, किसी भी तरह से, लेकिन अपनी पसंद करने के लिए उससे निपटने के लिए अनन्य शक्ति का दावा करें; और, यह वही है जो सादा है हमारे सामने सूट के माध्यम से झगड़ा हुआ है।

यह स्पष्ट है कि उद्धृत दो मामलों में एक मंत्री का इलाज किया गया है।

यह इंगित करने के बहुत सीमित उद्देश्य के लिए एक "अधिकारी" के रूप में हमारे सामने राज्य स्वयं उसके माध्यम से कार्य कर सकता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा पद है जो उसे सक्षम बनाता है।

वह इसके लिए कार्य करे। वे उसकी स्थिति की बराबरी या आत्मसात नहीं करते हैं या सरकारी कर्मचारी के साथ पद। मेरी राय में, मिनिस् संविधान द्वारा प्रदत्त पद के धारक के रूप में किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, पूर्व न्यायाधीश का उपयोग करने के लिए "राज्य का गणमान्य व्यक्ति" है।

प्रख्यात ब्रिटिश सर विलियम होल्ड्सवर्थ द्वारा प्रयुक्त दबाव संवैधानिक वकील और न्यायविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। उनकी गरिमा और पद उस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, उसका राज्य इस पर दावा करने का हकदार है।

( 1 ) एल. आर. 72 आई. ए. 241 @266।

( 2 ) [ 1970 ] 3 एस. सी. आर. 505 @512

[

1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

94

कभी-कभी विशुद्ध रूप से अंतर करना संभव हो सकता है

व्यक्तिगत

एक मंत्री द्वारा किया गया गलत या आपराधिक कार्य, जो पूरी तरह से गलत है उनके कानूनी अधिकार का दायरा, जैसा कि उनके कार्यालय से अलग है। लेकिन, यह भी, मेरी राय में, राज्य को मुकदमा करने से अक्षम नहीं कर सकता है। मंत्री से निपटने के लिए अपने स्वयं के अधिकार की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया। यह है, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है। एक अलग बात अगर

हम।

जैसा कि हमने यहाँ अभिनिर्धारित किया है कि राज्य का दावा अनन्य है अपने मंत्री से निपटने की शक्ति किसी कारण से टिकाऊ नहीं है। द. दावा करने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 131 में प्रदान किया गया है, कानून में उस दावे की ताकत से अलग किया जाना है। इतने लंबे समय तक जैसा कि दावा राज्य का है, तथ्य यह है कि एक मंत्री, शासन का प्रयोग करते हुए मानसिक शक्तियाँ, राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, कोई फर्क नहीं डाल सकती हैं राज्य द्वारा वाद की अनुरक्षण क्षमता के लिए।

मुझे लगता है कि संबंधित राज्य, जो इसकी वैधता को चुनौती देता है केंद्र सरकार की एक या अधिक मंत्रालयों के खिलाफ कार्रवाई अपनी सरकारी शक्तियों के प्रयोग से जुड़े कार्यों के संबंध में, अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त ब्याज होगा क्योंकि इसमें "राज्य" के रूप में राज्य से संबंधित दावे शामिल हैं।

यह हो सकता है कि, यदि किसी राज्य के अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़ता है, कानूनी इकाई के रूप में जो कानूनी रूप से स्थापित और मान्यता प्राप्त है

निश्चित क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों का सरकारी संगठन

किसी विशेष मामले के तथ्यों पर, हम यह मान सकते हैं कि यह मुकदमा बनाए रखने का हकदार नहीं है, इसकी सीमाएं बहुत दूर, अप्रत्यक्ष या असीम हैं।

अनुच्छेद 131 के तहत। लेकिन, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं।

वादी के वकील द्वारा निम्नलिखित मामलों का हवाला दिया गया था: द.

गवर्नर-जनरल इन काउंसिल v. मद्रास प्रांत; (1) संयुक्त प्रांत v. गवर्नर-काउंसिल में जनरल; (2) डेल और अन्य के संबंध में विक्टोरिया के लिए अटॉर्नी-जनरल। वी. राष्ट्रमंडल और ओआरएस। (3) अटॉर्नी-विक्टोरिया के लिए जनरल (विक्टोरियन चैंबर ऑफ मैनुफैक्चरर्स के संबंध में) v. राष्ट्रमंडल (4); राज्य राजा स्थान बनाम। भारत संघ (ऊपर)। अंतिम उल्लिखित मामले को छोड़कर वे अनुच्छेद 131 के दायरे में या इसके तहत मुकदमा करने के राज्य के अधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं हैं। हालाँकि वे इस प्रकार का संकेत देते हैं कि

सवाल यह है कि किस पर और किन व्यक्तियों के माध्यम से संघ में इकाइयाँ और केंद्रीय अधिकारी मुकदमा कर सकते हैं।

तैयार किए गए तीन मुद्दों पर मेरे जवाब इस प्रकार हैं:

1. सूट रखरखाव योग्य है।
2. केंद्र सरकार की अधिसूचना वैध है।
3. अधिनियम की धारा 3 वैध है।

रखे गए तथ्यों पर तैयार किए गए चौथे पूरक प्रश्न पर और

हमारे सामने तर्क दिए गए हैं, मेरा जवाब है कि राज्य और केंद्र सरकार की अधिसूचनाएं "समान" से काफी हद तक संबंधित नहीं हैं।

- ( 2 ) ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 58. (
- 3 ) 71 सी. एल. आर. 237
- ( 4 ) 1943-1934 ( 2 ) C.L.R.533।

#### 4 कर्नाटक वी. यूनिन (बेग, सी. जे.)

95

अधिनियम की धारा 3 (1) के परंतुक (बी) के अर्थ के भीतर। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा इस धारणा पर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के आयोग की नियुक्ति में कोई कानूनी दोष नहीं है। राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता को हमारे सामने किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी गई थी

जो भी हो। इसलिए, यहां व्यक्त किए गए विचारों का राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता से संबंधित प्रश्नों पर कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा, जिनका हमारे सामने प्रचार नहीं किया गया था। यह स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता को कुछ अन्य कार्यवाहियों में भी इस आधार पर चुनौती दी गई है कि हम उन पर तभी विचार कर सकते हैं जब वे हमारे सामने आएँ।

नतीजतन, इस मुकदमे को लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

चंद्रचूड़, जे.-हुए चुनावों के परिणाम पर परिणाम

1972 में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने श्री डी. देवराज उर्स को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनाई।

में से

वह पार्टी तब केंद्र में भी सत्ता में थी, लेकिन हार गई

राज्य। 1977 के लोकसभा चुनावों में अपने लंबे समय तक चले बहुमत के बाद जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि इसमें

लोकसभा के उन चुनावों में कर्नाटक राज्य को आवंटित 28 सीटों में से 26 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।

कर्नाटक विधान सभा के कुछ विपक्षी सदस्य

केंद्रीय गृह मंत्री को मुख्यमंत्री श्री देवराज उर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के आरोपों वाला एक ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुरोध के जवाब में मुख्यमंत्री ने अपनी टिप्पणी दी

लेकिन आरोपों को तुच्छ और राजनीति से प्रेरित बताते हुए मुख्यमंत्री ने एक मुद्दा उठाया जो हमारे सामने मुकदमे में पेश की गई दलीलों का केंद्र है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान में निहित संघीय संरचना राष्ट्रीय अखंडता की आधारशिला है; कि संविधान केंद्र और राज्यों की शक्ति का स्रोत है; कि सभी शक्तियों का प्रयोग, चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा, हमारे संविधान की संघीय योजना के तहत शक्तियों के वितरण की योजना के अनुरूप होना चाहिए कि राज्य सरकारों के गलती करने वाले मंत्री केवल राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह हैं; और यह कि, केंद्र सरकार का राष्ट्रीय अखंडता पर कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है।

किसी राज्य की सरकार उन मामलों के संबंध में जो राज्य के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हैं, अपवादात्मक समय को छोड़कर जब कोई आपात स्थिति चल रही हो। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच केवल राज्य सरकार द्वारा या उसके कहने पर ही की जा सकती है।

धारा 3 (1) के तहत 18 मई, 1977 को जारी अधिसूचना द्वारा

जाँच आयोग अधिनियम, 1952 का 60 कर्नाटक सरकार ने एक जाँच आयोग नियुक्त किया जिसमें शामिल थे -

श्री.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मीर इकबाल हुसैन ने

निर्दिष्ट आरोपों की जांच करने का उद्देश्य

अधिसूचना में। इसके कुछ दिनों बाद 23 मई को

भारत सरकार ने उसी अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 2 एस. सी. आर. की नियुक्ति की गई।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

96

श्री ए. एन. ग़्रोवर से मिलकर बना एक जांच आयोग, एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, आरोपों की जांच के लिए

बनाया गया।

मुख्यमंत्री के खिलाफ, जैसा कि अधिसूचना में वर्णित है। द.

इस अधिसूचना की वैधता को कर्नाटक राज्य द्वारा चुनौती दी गई है वर्तमान मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत लाया गया। द.

भारत संघ और श्री ए. एन. ग़्रोवर को सूट में शामिल किया गया है

प्रतिवादी क्रमशः 1 और 2।

कर्नाटक राज्य अपनी शिकायत के आधार पर तर्क देता है कि केंद्रीय सरकार आयोग के गठन के लिए सरकार के पास कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है आयोगों के तहत अपनी शक्तियों के कथित प्रयोग में पृच्छताच्छ अधिनियम, 1952; कि जांच आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध आरोपों की जांच करना राज्य सरकार के मंत्री जब तक पद पर बने रहते हैं और राज्य विधानमंडल का विश्वास प्राप्त करते हैं, तब तक यह राज्य सरकार के लिए विनाशकारी है।

संविधान की संघीय संरचना और इसके तहत प्रदान की गई शक्तियों के वितरण की योजना, कि सरकार की कैबिनेट प्रणाली जिसके तहत मंत्रिपरिषद राज्य के विधानमंडल के लिए जिम्मेदार है, अपने उद्देश्य में विफल हो जाएगी यदि केंद्रीय कार्यपालिका

राज्य के मंत्रियों के कार्यालय में रहने के दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच का निर्देश देने की शक्ति को अपने आप में ग्रहण करना; कि प्रावधान

1952 के अधिनियम की धारा 3 में निहित की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि केंद्र सरकार को आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाए।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए, जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है और संघ की कार्यपालिका को कोई शक्ति नहीं है।

कार्यकारी कार्रवाई करना; कि ऐसी व्याख्या अधिनियम की धारा 3 को संविधान के भाग 11 के प्रावधानों के अधिकार से बाहर कर देगी जो संघ के बीच संबंधों से पूरी तरह से संबंधित है।

और राज्य; और वह, जांच आयोग की रिपोर्ट नियुक्त करती है।

केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार कोई भी उपचारात्मक कार्यपालिका या कार्यपालिका लेने में अक्षम है।

राज्य सरकार या स्वयं राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ विधायी कार्रवाई।

इन विवादों को भारत संघ द्वारा पारित किया जाता है

लिखित कथन। इसने, पहली बार में, एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया है

यह आपत्ति कि मुकदमा स्वयं विचारणीय नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के व्यक्तिगत आचरण की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कर्नाटक राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। यह आगे तर्क देता है कि द्वारा जारी अधिसूचना

राज्य सरकार न तो केंद्र सरकार की अधिसूचना में शामिल प्रश्नों को शामिल करती है और न ही बाद की अधिसूचना में उल्लिखित सभी मामलों को शामिल करती है; कि केंद्रीय सरकार सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् राज्य सरकार के मंत्री के आचरण की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करने के लिए सक्षम है; और यह कि आयोग की नियुक्ति न तो संविधान के संघीय ढांचे के लिए विनाशकारी है और न ही इसकी किसी अन्य बुनियादी विशेषता के लिए।

इन दलीलों पर इस न्यायालय द्वारा तीन मुद्दे तैयार किए गए थे। द.

पहला मुकदमे की स्थिरता से संबंधित है, दूसरा इस सवाल से संबंधित है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कर्नाटक बनाम यूनियन (चंद्रचूड़, जे.) है।

97

1952 के अधिनियम की धारा 3 के तहत उसके पास जो शक्तियां हैं और तीसरी इस तर्क के अधिकार से बाहर है कि क्या धारा 3 केंद्र सरकार को विवादित अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत करती है, तो वह धारा स्वयं बिल्कुल भी संवैधानिक है।

मुकदमे की रखरखाव के बारे में प्रारंभिक आपत्ति पर,

मैं उस दृष्टिकोण का पालन करना पसंद करता हूँ जो मैंने राज्य ओ. जे. राजस्थान बनाम में लिया था। भारत संघ, जहां संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राजस्थान राज्य और कुछ अन्य राज्यों द्वारा दायर मुकदमों पर केंद्र सरकार द्वारा इसी तरह की आपत्ति जताई गई थी, केंद्रीय गृह मंत्री के एक निर्देश को चुनौती देते हुए राज्य विधानसभा को भंग करने की सलाह दी गई थी। मुझे तैयार किए गए निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है

और

शिंंगल

भाई उन्तवालिया अपनी ओर से और

भाइयों।

जसवंत सिंह जिसमें उन्होंने यह विचार रखा है कि आयोग

केंद्र सरकार द्वारा गठित जांच राज्य के खिलाफ नहीं है।

या राज्य सरकार लेकिन एक व्यक्तिगत मंत्री या मिनी के खिलाफ है

और चूंकि आयोग की स्थापना में कोई शामिल नहीं है

राज्य या राज्य सरकार के कानूनी अधिकारों का आक्रमण,

राज्य के कहने पर मुकदमा अनुच्छेद 131 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है।

मैं यह स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हूँ कि मुझे काफी लाभ हुआ है।

कर्नाटक से।

उनके दृष्टिकोण के कारण मेरे विद्वान भाइयों के निर्णय से, सम्मान के साथ, केवल इसलिए अनदेखी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही पूर्व है

एक पूर्व निर्णय में एक विपरीत राय को दबाया। लेकिन दे दिया

उनके द्वारा और इस मामले में एक पूर्ण तर्क द्वारा आगे बढ़ाया गया विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, मैं इस राय के लिए इच्छुक हूँ कि

यहां तक कि मामले का कड़ाई से कानूनी दृष्टिकोण लेते हुए, प्रारंभिक ओ. बी.

मुकदमे की स्थिरता को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 131 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता

जो निर्धारित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू होते हैं क्या सूट रखरखाव योग्य है। अनुच्छेद 131 निस्संदेह प्रदान करता है

' सर्वोच्च न्यायालय पर 'मूल अधिकार क्षेत्र' और सबसे सामान्य रूप

सामान्य अधिकार क्षेत्र एक मुकदमा है। लेकिन एक संवैधानिक प्रावधान, जो एक के विवादों पर विचार करने के लिए इस न्यायालय पर विशेष अधिकार क्षेत्र देता है

अपने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कुछ प्रकृति, नहीं हो सकता है

दीवानी अदालत को मनोरंजन करने का अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान के बराबर

एक सामान्य मुकदमा ताकि अनुच्छेद के तहत एक मूल कार्यवाही पर लागू हो

निम्नतम श्रेणी की अदालत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता इसे आजमाने के लिए तम्बू। सलाह दी जाती है कि संविधान इसका वर्णन नहीं करता है

कार्यवाही जिसे अनुच्छेद 131 के तहत 'वाद' और संकेत के रूप में लाया जा सकता है

विशेष रूप से, अनुच्छेद 131 उन शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करता है जो आम तौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं!

पहली बार के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए और एक सूट आजमाएँ। यह 'कार्रवाई के कारण', एक अभिव्यक्ति की बात नहीं करता है। गवाह कार्रवाई की दुनिया में ज्ञात और निश्चित कानूनी महत्व। इसके बजाय, यह 'विवाद' शब्द का उपयोग करता है, जो अण्डाकार का कोई हिस्सा नहीं है। कानून की शब्दावली। लेकिन सबसे बढ़कर, अनुच्छेद 131 जो एक तरह से बोलना इसके दायरे में आने वाले मामलों पर एक स्व-निहित संहिता है, स्पष्ट रूप से उस स्थिति के लिए प्रावधान करता है जिसके अधीन एक कार्रवाई हो सकती है [1978] 2 एस. सी. आर.

98

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसके नीचे। उस शर्त को खंड द्वारा व्यक्त किया गया है: " यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न (कानून या तथ्य का) शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। अतः अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार, इस न्यायालय की मूल अधिकारिता को लागू करने के लिए एकमात्र शर्त जो संतुष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट पक्षों के बीच विवाद में एक ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार हो। निर्भर करता है।

अनुच्छेद 131 का सार यह है कि विवाद होना चाहिए।

किसी ऐसे प्रश्न के संबंध में पक्षकारों के बीच, जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती देने में स्पष्ट रूप से एक ऐसा प्रश्न शामिल है जिस पर जांच आयोग नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य द्वारा लाई गई कार्यवाही को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। "स्पष्ट शब्दों को हटाने" का मामला होने की जगह, अनुच्छेद 131 में शब्दों को पढ़ने को उचित ठहराते हुए, जो वहां नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि संविधान ने इस न्यायालय को उद्देश्यपूर्ण रूप से एक ऐसा न्यायशास्त्र प्रदान किया है जो उन विचारों से अनियंत्रित है जो

पहली बार के न्यायालय के न्यायशास्त्र को बाधित करते हैं, जो किसी न्यायालय के मुकदमों को स्वीकार करता है और उनका परीक्षण करता है।

अनुच्छेद के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों की प्रकृति

नागरिक प्रकृति। 131 यह रूप और सार दोनों में उन दावों की प्रकृति से अलग है जिनके लिए सामान्य मुकदमों में निर्णय की आवश्यकता होती है।

संविधान का उद्देश्य न केवल एक वित्तीय संतुलन बनाए रखना है

शक्ति के तीन अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, लेकिन यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों के बीच एक समान संतुलन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सातवीं अनुसूची की विधायी सूचियों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का सीमांकन होता है। केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, जबकि राज्य की शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। संविधान का भाग 11 विशेष रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों के चित्रण के लिए समर्पित है। यह एक नाजुक संबंध है, विशेष रूप से अगर केंद्र और राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता में हैं। अनुच्छेद 131 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च शक्ति संपन्न तंत्र प्रदान करना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अधिकार के संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्य करें और एक दूसरे के संवैधानिक कार्यों या शक्तियों का अतिक्रमण न करें। इसलिए, 'प्रतिवादी' की संवैधानिक क्षमता को एक इच्छित व्यक्ति के रूप में कार्य करने की चुनौती अनुच्छेद 131 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, विशेष रूप से जब वादी विशेष रूप से अपने लिए उस अधिकार का दावा करता है। अगर यह विफल हो जाता है

को

उस अधिकार को स्थापित करते हुए, इसकी चुनौती गुण-दोष के आधार पर विफल हो सकती है, लेकिन कार्यवाही को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि विवादित आदेश की गणना वादी के कानूनी अधिकार को प्रभावित करने या बाधित करने के लिए नहीं की गई है।

द.

एक साधारण दीवानी मुकदमे में, द्वारा प्रतिपादित अधिकार की अस्वीकृति

प्रतिवादी तदनुसार और अपने स्वयं के बल से स्थापित नहीं कर सकता है

वादी द्वारा दावा किया गया अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 131 के तहत कार्यवाही कर्नाटक बनाम में निहित संवैधानिक शक्ति की सीमाओं का न्यायनिर्णायक है।

यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

99

केंद्र और राज्य सरकारें। यह दावा कि प्रतिवादी (यहाँ केंद्र सरकार) के पास इस दावे में अपेक्षित शक्ति नहीं है कि पूछताछ आयोग नियुक्त करने की शक्ति विशेष रूप से वादी (यहाँ राज्य सरकार) में निहित है। दीवानी मुकदमे में वादी को अपने बल पर सफल होना पड़ता है।

स्वयं के

उपाधि, अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी पर नहीं क्योंकि प्रतिवादी एक रैंक अतिचारक हो सकता है और फिर भी वह कानूनी रूप से सच्चे मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ अपने अधिकार को बनाए रख सकता है। यदि वादी वास्तविक मालिक नहीं है, तो उसका मुकदमा विफल होना चाहिए। अनुच्छेद 131 के तहत एक कार्यवाही एक साधारण दीवानी मुकदमे के बिल्कुल विपरीत है। इस तरह की कार्यवाही में संयोजन दो या दो से अधिक सरकारों के बीच होता है। एक या दूसरे के पास कार्य करने की संवैधानिक शक्ति है। दीवानी मुकदमे की तरह कोई तीसरा विकल्प नहीं है जिसमें वादी द्वारा दावा किया गया अधिकार न तो उसमें रह सकता है और न ही प्रतिवादी में बल्कि किसी अजनबी में रह सकता है। एक सीमांकन और संवैधानिक शक्ति की परिभाषा प्रतिद्वंद्वी दावेदारों पर दांव लगाती है और केवल उन तक ही सीमित होती है और अनुच्छेद 131 के तहत एक कार्यवाही अनिवार्य रूप से शामिल होती है। इस तरह ऐसी कार्यवाही में, प्रतिवादी के अधिकार से इनकार करने के साथ वादी का दावा भी होता है।

सबसे पहले, इसलिए, मैं इस बात की सराहना करने में असमर्थ हूँ कि यदि कोई राज्य शासन करता है

यदि कोई विशेष कार्यवाही करने के लिए केंद्रीय सरकार के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी जाए, तो अनुच्छेद 131 अभी भी आकर्षित नहीं होगा। दूसरा, वर्तमान कार्यवाही में राज्य सरकार का तर्क केवल यह नहीं है कि केंद्रीय सरकार के पास राज्य के मंत्रियों के आचरण की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह कि ऐसा अधिकार विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है। इसलिए, न केवल केंद्र सरकार द्वारा दावा किए गए

अधिकार से इनकार किया जाता है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि यह अधिकार विशेष रूप से राज्य सरकार के पास है।

ए में

इस मायने में, तत्काल मामला राजस्थान की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में है

मामला क्योंकि वहाँ राज्य सरकारों द्वारा की गई चुनौती को शायद विशुद्ध रूप से नकारात्मक प्रकृति के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि

बुनियादी तर्क यह था कि केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं थी

को

राज्य विधानसभाओं को भंग करना। इसलिए, वहाँ सभी बड़ा है

प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करने का कारण वहाँ है।

कर्नाटक राज्य ने एक वैकल्पिक राहत का दावा किया है कि यदि

जाँच आयोग अधिनियम की धारा 3 को अधिकृत माना जाता है।

केंद्र सरकार को विवादित अधिसूचना जारी करने के लिए, यह

है।

यह संविधान में सन्निहित अनुच्छेद 164 (2) और संघीय योजना का उल्लंघन है। यह विवाद अच्छी तरह से स्थापित है या नहीं, यह एक अलग मामला है, लेकिन मुझे यह मानना मुश्किल लगता है कि कर्नाटक राज्य के पास कानूनी अधिकार भी नहीं है। यह तर्क देना कि केंद्र सरकार को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाले संसदीय कानून का प्रावधान असंवैधानिक है।

अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका का उपशामक जिसका सुझाव दिया गया है

केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के मामलों में एक संप्रभु उपचार के रूप में अनुच्छेद 131 के तहत कार्यवाही के लिए शायद ही कोई विकल्प हो।

यह.

यह कुख्यात है कि रिट याचिका की अपनी सीमाएँ हैं और वास्तव में अनुच्छेद 226 के तहत कई याचिकाओं को परिचित चुटकी के साथ खारिज कर दिया जाता है: क्यों?

क्या आप मुकदमा नहीं दायर करते हैं? भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों के अलावा, अनुच्छेद 131 में [1978] 2 एस. सी. आर. के अनुसार अन्य पर विचार किया गया है।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

100

दलों की श्रृंखला के मामले में उत्परिवर्तन और संयोजन। ए.

एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या एक ओर भारत सरकार और एक राज्य के बीच और दूसरी ओर दूसरे राज्य या अन्य राज्यों के बीच विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत उचित रूप से नहीं किया जा सकता है और यह संविधान का इरादा नहीं हो सकता था। अनुच्छेद 131 में वर्णित प्रकृति के विवाद आमतौर पर तत्काल प्रकृति के होते हैं और उनके निर्णय में कोई देरी नहीं हो सकती है। इसलिए न्याय के हित में यह समीचीन है कि उन्हें, जहां तक संभव हो, इस न्यायालय के समक्ष लाया जाए और इस पर निर्णय लिया जाए ताकि संभावित अपील के विस्तार को रोका जा सके। इस न्यायालय द्वारा तय की गई मूल कार्यवाही का फैसला हमेशा के लिए किया जाता है।

इन कारणों से मैं उनके द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करता हूँ।

केंद्र सरकार और यह मानते हुए कि कर्नाटक राज्य द्वारा लाई गई कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत बनाए रखने योग्य है,

एक अन्य बिंदु, जो प्रारंभिक प्रकृति का भी है, अब निपटा दिया जा सकता है।

जाँच आयोग अधिनियम की धारा 3 (1) 'उपयुक्त सरकार' को सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जाँच करने के उद्देश्य से जाँच आयोग नियुक्त करने और ऐसे कार्यों को करने के लिए और ऐसे समय के भीतर जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 3 (1) के परंतुक के खंड (ए) और (बी) ने उस शक्ति की चौड़ाई में कटौती की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसा न करें।

समानान्तर आयोग जो एक ही मामले की एक साथ जांच करेंगे। चूंकि, इस मामले में कर्नाटक राज्य ने केंद्र सरकार के समक्ष एक जांच आयोग नियुक्त किया था

विवादित अधिसूचना जारी करने पर परंतुक का खंड (बी) आकर्षित किया जाएगा। उस खंड में कहा गया है कि यदि किसी मामले की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया गया है:

" (ख) राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा

जांच के लिए कोई अन्य आयोग नियुक्त नहीं करेगा

जब तक आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है तब तक एक ही मामला

राज्य सरकार काम कर रही है, जब तक कि केंद्र सरकार

यह राय है कि जाँच का दायरा होना चाहिए

दो या दो से अधिक राज्यों तक विस्तारित।

विचार के लिए सवाल यह है कि क्या नियुक्ति

केंद्र सरकार द्वारा जाँच आयोग इस खंड में निहित निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों पर विचार करते हुए

केंद्र सरकार और जिन मामलों में संबंधित आयोगों को जांच करने का निर्देश दिया जाता है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों जांचों का उद्देश्य और उद्देश्य मूल रूप से अलग-अलग है। दोनों अधिसूचनाओं की प्रस्तावना इस अंतर को उजागर करती है और दिखाती है कि वे अलग-अलग छोरों पर निर्देशित हैं।

कर्नाटक अधिसूचना की प्रस्तावना में कहा गया है:

" जहाँ सदन में आरोप लगाए गए हैं

राज्य विधानमंडल के सदन और अन्य स्थान जो अप्रचलित हैं

ग्युलरिटी की गई है/सी. ई. आर. में अतिरिक्त भुगतान किया गया है

अनुबंध, भूमि अनुदान, आबंटन से संबंधित मामले

स्थल, फर्नीचर की खरीद, खाद्यान्न का निपटान आदि।

कर्नाटक वी. यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

101

अब वहाँ। कर्नाटक सरकार

एतद्वारा जाँच आयोग की नियुक्ति  
आरोपों की जांच करने का उद्देश्य, पार्टी

उक्त

नीचे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है।

दूसरी ओर केंद्र सरकार की अधिसूचना की प्रस्तावना

हाथ पाठ करता है:

" जबकि केंद्र सरकार की राय है कि इसकी आवश्यकता है  
के उद्देश्य के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए  
सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करना,  
अर्थात्, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात या दुराचार के आरोप।  
मुख्यमंत्री के खिलाफ सरकारी शक्तियों का उपयोग और  
कर्नाटक राज्य के कुछ अन्य मंत्री, यहाँ  
निर्दिष्ट किए जाने के बाद।

29

दोनों आयोगों के संदर्भ की शर्तें एक ही बात का खुलासा करती हैं।

मौलिक अंतर। आयोग की नियुक्ति में राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है  
कि क्या यह अनुचित है।

या

अत्यधिक भुगतान किए गए, अनुचित अनुग्रह दिखाए गए, आधिकारिक कार्य आदि के  
संचालन में अनियमितता या धोखाधड़ी हुई और यह पता लगाने के लिए कि "उपरोक्त के संबंध  
में चूक, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं और किस हद तक हैं"। दूसरी ओर, केंद्र

सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को विशेष रूप से यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या मुख्यमंत्री ने अधिसूचना में उल्लिखित विभिन्न मामलों के संबंध में पक्षपात और भाई-भतीजावाद का अभ्यास किया था। इसलिए यह राज्य सरकार के लिए गलत है।

को

तर्क दें कि केंद्र सरकार ने आयोग की नियुक्ति की है

उसी मामले की जांच के उद्देश्य से जांच, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग। पूछताछ करने के लिए निर्देशित किया जाता है। वास्तव में, केंद्र सरकार की अधिसूचना खंड 2 (ए) (ii) द्वारा पूर्व प्रेस में प्रदान करती है कि आयोग कर्नाटक राज्य विधानमंडल के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में निहित आरोप की जांच करेगा, "कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले को छोड़कर।"

यह तर्क कि दोनों अधिसूचनाएँ एक ही मामले को कवर करती हैं

सामान्य राजनीतिक वास्तविकताओं की मान्यता की कमी से पीड़ित है।

यह.

काल्पनिक परिस्थितियों को छोड़कर शायद ही कभी यह संभव हो कि राज्य सरकार अपने मुख्यमंत्री की ओर से भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के कृत्यों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी। यह दिलचस्प है कि सर थॉमस मोरे ने 'यूटोपिया' नाम ग्रीक शब्द ou (नहीं) और topos (स्थान) से गढ़ा है जिसका एक साथ अर्थ है "कोई जगह नहीं"। यह अकल्पनीय है कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जाएगा

मुख्यमंत्री की सहमति के बिना राज्य सरकार और यदि राजनीतिक माहौल इतना प्रतिकूल है कि वह अपने स्वयं के आचरण की जांच के लिए बाध्य है, तो वह सहमत होने के बजाय इस्तीफा दे देगा। वास्तव में। मंत्रिपरिषद, जो यह समझती है कि उसके मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों के आचरण की सार्वजनिक जांच में जांच की आवश्यकता है, ने विधानमंडल का विश्वास खो दिया होगा और उसे आम तौर पर अपना इस्तीफा देना होगा। इस प्रकार, राज्य सरकार की यह आपत्ति कि केंद्रीय सरकार की अधिसूचना अधिनियम की धारा 3 (1) के परंतुक के खंड (बी) के खिलाफ है, तथ्यात्मक रूप से निराधार और सैद्धांतिक रूप से निराधार है।

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रारंभिक आपत्तियों का निपटारा करने के बाद

स्वभाव से, अब 2 और 3 के मुद्दों पर प्रतिद्वंद्वी विवादों के गुणों पर विचार करना आवश्यक है।

श्री लाल नारायण सिन्हा जो राज्य की ओर से उपस्थित होते हैं

कर्नाटक का तर्क है कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 (1) को केंद्र सरकार को राज्य सरकार के किसी मौजूदा मंत्री के आचरण की जांच के उद्देश्य से जांच आयोग नियुक्त करने के लिए अधिकृत करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। खंड के एक सादे पठन पर, इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है। अधिनियम की धारा 2 (ए) (आई) और (बी) में 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ परिभाषित किया गया है:

( (i) नियुक्त आयोग के संबंध में केंद्र सरकार

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I या सूची II या सूची III में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित किसी भी मामले की जांच करना; और

( (ii) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के संबंध में

संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II या सूची III में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित किसी भी मामले की जांच करना। धारा 3 (1) 'उपयुक्त सरकार' को अधिकार देती है यदि उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, और उसे बाध्य करती है यदि उस ओर से कोई प्रस्ताव लोक सभा या राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया जाता है, तो सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए। संवैधानिक विचार जिनके लिए

विद्वान वकील का तर्क है कि धारा 3 (1) को एक सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए और उसके प्रस्तुत करने की बारीकियों पर बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन, उन विचारों को इस समय के लिए अलग रखते हुए, मुझे धारा 3 (1) के प्रावधानों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं दिखता है ताकि केंद्र सरकार की जांच आयोगों के संचालन की जांच करने की शक्ति को सीमित किया जा सके।

केवल केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में व्यक्ति। धारा 3 (1) केंद्र सरकार को सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त

करने का अधिकार देती है। यह निर्विवाद है कि राज्य सरकारों के मंत्रियों का अपने आधिकारिक कार्यों के कथित निर्वहन में आचरण धारा 3 (1) के अर्थ के भीतर सार्वजनिक महत्व का एक निश्चित मामला नहीं है। इस तरह के निर्माण से संघवाद का सिद्धांत किस हद तक प्रभावित होगा, निश्चित रूप से इसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी, लेकिन मुझे इस तर्क में कोई सार नहीं दिखता कि केंद्र सरकार के पास राज्य विधानमंडल के एक वर्ग द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में तथ्य एकत्र करने की शक्ति भी नहीं है।

राज्य सरकार के वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ। उस शक्ति का प्रयोग निस्संदेह संयम और संयम के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि धारा 3 (1) के तहत जांच का निर्देश देने की आड़ में केंद्र सरकार राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस बात का भी खंडन नहीं किया जा सकता है कि जो सत्ता का उचित उपयोग प्रतीत होता है, उसमें कभी-कभी सत्ता का परोक्ष दुरुपयोग हो सकता है। चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। लेकिन वैधानिक, निर्माण नहीं हो सकता है

उन लोगों के अविश्वास और संदेह पर आगे बढ़ें जिन पर कानूनों को प्रशासित करने का कर्तव्य है। इसलिए, धारा 3 (1) को इस आरक्षण के साथ इसका उचित निर्माण प्राप्त करना चाहिए जो सभी अधिनियमों को दुर्भावनापूर्ण रूप से दूषित करता है।

कर्नाटक वी. यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

103

ईमानदारी की कमी का आरोप लगाया गया था लेकिन इस मामले में दबाव नहीं डाला गया था। इसलिए, मेरी राय में, धारा 3 (1) को एक प्रतिबंधित माध्य नहीं दिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रचार किया गया।

इस दृष्टिकोण पर, यह तर्क कि धारा 3 (1) को पढ़ा जाना चाहिए

और आक्षेपित अधिसूचना को इसके बाहर पड़ने के रूप में अलग रखा जाना चाहिए

उस धारा के दायरे को खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन फिर यह आग्रह किया जाता है कि

बता दें कि यदि धारा को एक सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता है और व्यापक रूप से समझा जाए ताकि केंद्र सरकार को अधिकृत किया जा सके

राज्य के वर्तमान मंत्रियों के आचरण की जांच करने का निर्देश देना, प्रावधान को विभिन्न प्रकार के कारणों के लिए असंवैधानिक बना दिया जाएगा बेटों। उन कारणों पर अब विचार किया जाना चाहिए।

सबसे पहले यह कहा जाता है कि यदि धारा 3 (1) की भाषा है व्यापक रूप से माने जाने पर, यह न केवल केंद्र सरकार को सक्षम बनाएगा

को

बैठक के संचालन की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करें राज्य सरकारों के मंत्री लेकिन यह उसी नियम को लागू करेगा निर्माण, राज्य सरकार को समान काम नियुक्त करने में भी सक्षम बनाता है केंद्रीय मंत्रियों के आचरण की जांच करने के लिए जांच के मिशन।

राज्य के वकील के अनुसार, यह प्रावधान के खिलाफ अपराध होगा।

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) और 164 (2)। ये कलाकृतियाँ

सी. एल. ई. एस. क्रमशः यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोक सभा और राज्य के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी।

राज्य की विधानसभा। तर्क यह है कि नियुक्त करने की शक्ति

आचरण की जांच के उद्देश्य से जांच आयोग किसी अन्य सरकार के वर्तमान मंत्रियों का होना रियासत के लिए विनाशकारी है।

इन अनुच्छेदों में सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। यह तर्क को इस परिस्थिति से समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि पुण्य से

अनुच्छेद 194 (3) का, यह विधान सभा का विशेषाधिकार है -

राज्य किसी के आचरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए

एक मंत्री सहित इसके सदस्य। उस विशेषाधिकार के अनुसार विद्वान परामर्श, सामूहिक प्रतिरोध के सिद्धांत के रूप में अलंघनीय है

प्रायश्चित्त ।

मुझे इस तर्क को स्वीकार करना असंभव लगता है। अनुच्छेद 75 (3) और 164 ( 2 ) मिनिस परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की बात करें एक निकाय के रूप में, लोक सभा या विधान सभा के लिए राज्य से। आयोग के निष्कर्ष जो भी हों प्रश्नकर्ता, मंत्रपरिषद, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, सामूहिक रूप से सदन के प्रति जवाबदेह या जवाबदेह बना रहता है जनता या विधान सभा की। वास्तव में, न ही एपी आयोग का संकेत और न ही आयोग द्वारा अस्वीकृति इसकी जांच के लिए भेजे गए सभी या किसी भी आरोप की जांच होगी। मंत्रपरिषद को उन निकायों के प्रति कम जवाबदेह बनाएं। संविधान के दो अनुच्छेदों का उद्देश्य जिस पर राज्य कर्नाटक द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के लिए यह प्रावधान करना निर्भर है मंत्रिमंडल, प्रत्येक मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है इसके अलावा, पूरी मंत्रपरिषद को सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है विधायिका के लिए। यदि कोई व्यक्तिगत मंत्री अपने पद का उपयोग एक अवसर के रूप में करता है भ्रष्टाचार के कृत्यों को करने का नाटक करने के लिए, वह [1978] 2 एस. सी. आर. होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

104

अपने गैरकानूनी कृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह और सामूहिक का कोई सवाल नहीं

ऐसे मामले में मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी उठ सकती है। के रूप में हेगड़े जे द्वारा इस पर एक संविधान पीठ के लिए बोलते हुए टिप्पणी की गई ए. संजीवी नायडू आदि में न्यायालय बनाम मद्रास और अन्र राज्य।, ( 1) द. मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सार यह है कि मंत्रिमंडल प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी मंत्रालय। दूसरे शब्दों में, सामूहिक रेस का सिद्धांत उत्तरदायित्व केवल उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो एक मंत्री करता है या कर सकता है। उचित रूप से कहा जाए कि उसने अपने वैध निर्वहन में प्रदर्शन किया है आधिकारिक कार्य।

इंग्लैंड में सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का इतिहास

टीआरएस ने राजा के खिलाफ एक आम मोर्चा बनाए रखा, संयुक्त और स्वीकार किया उनके निर्णयों के लिए कई जिम्मेदारियाँ चाहे वे सहमत हों

उन्हें या नहीं, और एक निकाय में इस्तीफा दे दिया अगर राजा ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया सलाह देते हैं। ब्रिटिश संसद के संबंध में, सामूहिक जिम्मेदारी

इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल एक साझा मोर्चा प्रस्तुत करता है। मेलबर्न के प्रसिद्ध

वाक्यांश, 'सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक ही बात बोलनी चाहिए'। राजकुमार

सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत शायद मंत्रियों को समझाने के लिए मजबूर करता है

अपनी अंतरात्मा से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन नीति के मामलों में उन्हें बोलना पड़ता है

एक आवाज के साथ, उनमें से प्रत्येक निर्णय के लिए जिम्मेदार है

कैबिनेट द्वारा लिया गया। ( 2)

"संवैधानिक और प्रशासनिक कानून" पर अपनी पुस्तक में (एड। 1971 ,

पृष्ठ 175), एस. ए. डी. स्मिथ का कहना है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी को कभी-कभी एक डेमो के रूप में कहा जाता है।

ब्रिटिश संविधान का गढ़। विद्वानों के अनुसार लेखक, सामूहिक जिम्मेदारी का तात्पर्य है कि सभी कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के फैसलों और उन्हें लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की जिम्मेदारी लेते हैं

उन निर्णयों को। एक मंत्री किसी निर्णय या उसके कार्यान्वयन के तरीके से असहमत हो सकता है, लेकिन अगर वह सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करना चाहता है तो उसे पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए।

सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, सर आइवर जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक "कैबिनेट गवर्नमेंट" (थर्ड एड, 1959 पी। 277) कहते हैं:

" कैबिनेट में पारित होने वाले सभी के लिए (लॉर्ड सैलिसबरी ने कहा)

1878 ) इसका प्रत्येक सदस्य जो इस्तीफा नहीं देता है वह पूरी तरह से है

और अपरिवर्तनीय रूप से जिम्मेदार है, और बाद में इसका कोई अधिकार नहीं है

यह कहने के लिए कि वह एक मामले में एक समझौते के लिए सहमत हुए, जबकि

एक और उन्हें उनके सहयोगियों ने मना लिया। यह.

केवल इस सिद्धांत पर है कि पूर्ण जिम्मेदारी

मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया जाता है जो, किसी निर्णय पर पहुँचने के बाद, वह इसका सदस्य बना रहता है, कि

आयोजित, और संसदीय के सबसे आवश्यक सिद्धांतों में से एक जिम्मेदारी तय की गई। "

( 1 ) [ 1970 ] 3 एससीआर 505,512

( 2 ) चैंबर्स एनसाइक्लोपीडिया, 1973 एड। खण्ड. 2 , शीर्षक के तहत पृष्ठ 736

' कैबिनेट। सामूहिक उत्तरदायित्व।

कर्नाटक बनाम। यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

105

विद्वान लेखक का कहना है कि शायद श्री जोसेफ चेम्बरलेन सामूहिक जिम्मेदारी की समाप्ति बेहतर थी क्योंकि उनके पास अवसर था श्री ग्लैडस्टोन के अधीन और उनके अधीन दोनों मामलों का अध्ययन करें। लॉर्ड सैलिसबरी के अधीन उनकी मध्य आयु। श्री चेम्बरलेन के अनुसार।

" हमारे निजी संबंधों में पूरी तरह से स्पष्टता और पूरी तरह से स्पष्टता

समान हित के सभी मामलों पर विचार करना. निर्णय

स्वतंत्र रूप से आने वाले लोगों को वफादारी से समर्थन दिया जाना चाहिए और माना जाना चाहिए  
पूरी सरकार के निर्णय। बेशक वहाँ

ऐसे अवसर हो सकते हैं जिनमें अंतर इतना महत्वपूर्ण हो

चरित्र कि अल्पसंख्यकों के लिए जारी रखना असंभव है।

उनका समर्थन, और इस मामले में मंत्रालय टूट जाता है या

अल्पसंख्यक सदस्य या सदस्य इस्तीफा दे देते हैं।

इस प्रकार यह तर्क कि अधिनियम की धारा 3 (1) इसके विरुद्ध अपराध करेगी।

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जब तक कि इसे संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाता है

बिना किसी पदार्थ के। प्रस्तावित भागीदारी के संबंध में

अनुच्छेद 194 (3), संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में कि विधायिका के  
किसी सदस्य के आचरण की जांच की जाएगी

केवल विधायिका द्वारा, यह मानना असंभव है कि नियुक्ति

अधिनियम के तहत जांच आयोग का हस्तक्षेप

विधायिका के विशेषाधिकार के साथ। से संबंधित अंग्रेजी पूर्ववर्ती

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार, जो अनुच्छेद के तहत प्रासंगिक हैं

194 ( 3 ) , राज्य के तर्क का समर्थन न करें।

यह राज्य के समर्पण के एक महत्वपूर्ण अंग का निपटान करता है। द.

दिखाने की दिशा में निर्देशित राज्य सरकार की अन्य दलीलें

कि विवादित अधिसूचना असंवैधानिक है, ये हैं:

(क) आक्षेपित अधिसूचना में निहित आरोप संबंधित हैं।

भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और शासन का दुरुपयोग  
मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा मानसिक शक्ति

प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाने वाली कार्यकारी शक्तियों के संबंध में या

अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से और न ही केंद्रीय कार्यपालक

न ही संसद इस पर कोई नियंत्रण रख सकती है

राज्य कार्यपालिका, आपातकाल के दौरान को छोड़कर;

(ख) भारत राज्यों का संघ होने के नाते व्याख्या करते समय यह आवश्यक है कि

संविधान, आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखता है और

हमारे संघीय या अर्ध-संघीय संविधान की सामान्य योजना

जिसमें भारत संघ की शक्तियाँ और

राज्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया है। रखने के

लिए।

अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि संघ की कार्यपालिका

राज्य कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें जो इसका विरोध

करती है

हमारे संघीय संविधान की मूल योजना;

((c) न तो संविधान का अनुच्छेद 248 जो विशेष अधिकार प्रदान करता है।

संसद पर कानून बनाने की मायावी अवशिष्ट शक्तियाँ

समवर्ती में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में

सूची या राज्य सूची और न ही सूची I में अवशिष्ट प्रविष्टि 97

केंद्र में निहित कानून बनाने की शक्ति शामिल हो सकती है

## राज्य सरकार पर सरकार का पर्यवेक्षी नियंत्रण

मेंट; [1978] 2

एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(घ) सूची-1 में प्रविष्टि 94 स्पष्ट रूप से संसद में अप्रासंगिक है।

विवादित कानून पारित करने की शक्तियाँ। यह शक्ति प्रदान करता है

संसद इस विषय पर कानून बनाएगी; "पूछताछ, सर्वेक्षण"

और किसी भी मामले के उद्देश्य के लिए आँकड़े

सूची I. राज्य सरकारों के मंत्रियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग,

जिसे सार्वजनिक महत्व के मामलों में से एक कहा जाता है

आयोगों की धारा 3 (1) में वर्णित कार्य  
दायरे में नहीं आता है

जाँच अधिनियम, किसी के

सूची I में गिने गए मामले;

ई) सूची III की प्रविष्टि 45: " के लिए पूछताछ और आँकड़े

सूची II या सूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले का उद्देश्य

आई. आई.

आई. "संसद को विवाद को पारित करने का अधिकार भी नहीं दे सकता है।

एड कानून। कारण यह है कि यदि, जैसा कि द्वारा तर्क दिया गया है

केंद्र सरकार, जारी अधिसूचना का सार

केंद्र सरकार द्वारा लेन-देन का वर्णन नहीं किया गया है

लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता का दुरुपयोग

या कर्नाटक सरकार के मंत्री, कोई नहीं है  
संबंधित सूची II या सूची III में प्रविष्टि

शासन के दुरुपयोग से

राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा मानसिक शक्ति;  
संसद या केंद्र को शक्ति प्रदान करने वाला कानून  
एक बैठक के संचालन की जांच करने के लिए कार्यपालक  
आरोप के संबंध में राज्य सरकार के मंत्री  
चुनी गई एजेंसी द्वारा सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग  
केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा, "विधायी" से परे है  
संसद की क्षमता क्योंकि वास्तव में, ऐसी  
कानून भाग 11, अध्याय के प्रावधानों का पूरक है।  
संविधान का दूसरा भाग जो प्रशासकों से संबंधित है  
संघ और संघ के बीच संबंधों का तृतीय भाग  
राज्य और संवैधानिक श्रेणी में आते हैं कानून। संसद के पास उप में जोड़ने या  
बदलने या बदलने की कोई शक्ति नहीं है।  
संविधान के प्रावधानों को इसके माध्यम से लागू करना  
एक साधारण विधान सिवाय जब संविधान  
उस प्रभाव को विशेष रूप से प्रदान करता है;  
संघ की कार्यपालिका को प्रदान करने के लिए  
के लिए शक्ति  
राज्य कार्यपालिका से जवाब देने का आह्वान करें  
व्याख्या  
इसके कार्यकारी कार्यों और आगे की शक्ति  
राज्य कार्यपालिका को अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें संघ  
कार्यपालिका द्वारा चुने गए किसी प्राधिकारी के लिए  
राज्य कार्यपालिका के खिलाफ आरोप लगाना लाता है

केंद्र के बीच एक नया संबंध अस्तित्व में आया  
 कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका जो एक प्रति नहीं है  
 विधायी शक्ति का त्रुटिपूर्ण प्रयोग। इस तरह के  
 घटक के प्रयोग में शक्ति दी जा सकती है  
 निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही शक्ति  
 संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा; और  
 के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध  
 संघ और राज्यों को परिभाषित किया गया है  
 संविधान, उससे संबंधित प्रावधान हैं  
 उस विषय के बारे में और इसलिए कर्नाटक बनाम संघ (चंद्रचूड़, जे.) में कानून बनाना।

107

केंद्र-राज्य संबंधों के संबंध में  
 आवश्यक प्रभाव। अनुच्छेद 164 (2) द्वारा उपबंध करके  
 कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से होगी  
 राज्य की विधान सभा के लिए उत्तरदायी, द्वारा  
 अनुच्छेद द्वारा विधान सभा को प्रदान करना  
 194 ( 3 ) उस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ  
 दायित्व, भाग 11 में स्थितियों की गणना करके,  
 अध्याय II के बारे में कि केंद्रीय कार्यपालिका कब निर्णय ले सकती है

राज्य कार्यपालिका को अपमानित करना, और अंत में इसके लिए प्रावधान करना

संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 में आपात स्थिति

निहित रूप से नियंत्रण लागू करने पर प्रतिबंध लगा दिया है राज्य कार्यपालिका पर केंद्रीय कार्यपालिका का

किसी अन्य तरीके से। यदि कोई यंत्र गणना करता है

जिन चीजों पर इसे काम करना है, बाकी सब कुछ है

अनिवार्य रूप से और निहितार्थ द्वारा इससे बाहर रखा गया है

संचालन और प्रभाव।

इन प्रस्तुतियों का प्रमुख नोट केवल एक और एक है कि

केंद्रीय कार्यपालिका को, एक संवैधानिक संशोधन के अलावा, जांच आयोग के माध्यम से राज्य कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जा सकती है। क्या संसद के पास अपने विधान के प्रयोग में विवादित कानून को पारित करने की क्षमता है, जैसा कि घटक शक्ति से अलग है, यह एक अलग मामला है, लेकिन इसमें राज्य के तर्क की वैधता पर विचार करने से पहले

इस ओर से, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या उस विवाद में अंतर्निहित धारणा बिल्कुल भी उचित है, अर्थात् कि विवादित कानून द्वारा, संसद ने केंद्र सरकार को राज्य सरकार के कार्यकारी कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान की है। उस उद्देश्य के लिए जांच आयोग अधिनियम की योजना और उद्देश्य और इसके अधिक महत्वपूर्ण प्रावधानों के वास्तविक प्रभाव की उचित समझ होना आवश्यक है।

जांच आयोग अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था

1952 आयोगों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करने के लिए

जाँच और उन्हें कुछ शक्तियाँ सौंपने के लिए। उस अधिनियम की धारा 2 (ए) के साथ पठित धारा 3 (1), जहां तक प्रासंगिक है, केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देती है। सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच करने और अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए कार्यों को करने के उद्देश्य से जांच। आयोग को जांच करनी है और अपने कार्यों को पूरा करना है, जिनमें से एक निश्चित रूप से सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। धारा 3 (4) में यह अपेक्षा की गई है कि केंद्र सरकार जांच आयोग की रिपोर्ट को

आयोग द्वारा रिपोर्ट के उप-मिशन के छह महीने की अवधि के भीतर उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ लोक सभा के समक्ष रखेगी। धारा 4 में कहा गया है कि

मुकदमा चलाते समय दीवानी अदालत के पास मौजूद कुछ शक्तियों को कमीशन करें।

एक मुकदमा, जैसे गवाहों की उपस्थिति को लागू करना, उन पर जाँच करना

शपथ, खोज और दस्तावेजों का उत्पादन, साक्ष्य प्राप्त करना

किसी भी सार्वजनिक अभिलेख आदि की मांग करने वाले शपथ पत्र। को ध्यान में रखते हुए

जाँच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियाँ,

सरकार धारा 5 (1) के तहत निर्देश दे सकती है कि सभी या कोई भी प्रो

धारा 5 की उप-धारा (2), (3) (4) और (5) में निहित दर्शन

8-

1042 एससीआई/77 [1978] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

108

आयोग पर लागू होगा। इनमें से कुछ उप-अनुभाग सशक्त बनाते हैं।

आयोग किसी भी व्यक्ति से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है

आयोग और किसी भी भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिए जहाँ कोई दस्तावेज हो जाँच के विषय से संबंधित जानकारी मिल सकती है। के लिए

जाँचसँ सम्बन्धित कोनो जाँच करबाक उद्देश्य,

आयोग धारा 5 ए द्वारा सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी का आयोग या

केंद्र सरकार की जाँच एजेंसी।

इन प्रावधानों और सामान्य योजना से यह स्पष्ट है कि

अधिनियम कि अधिनियम के तहत नियुक्त जांच आयोग विशुद्ध रूप से एक है

तथ्य-खोज निकाय जिसके पास बाध्यकारी या अवज्ञा का उच्चारण करने की कोई शक्ति नहीं है

नकारात्मक निर्णय। इसे साक्ष्य के माध्यम से तथ्य एकत्र करने होते हैं।

इसके पहले और उस पर विचार करने पर उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।  
जिसे नियुक्त प्राधिकारी स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। वहाँ हैं।

सार्वजनिक महत्व के संवेदनशील मामले जो, यदि सामान्य पर छोड़ दिए जाते हैं

जांच एजेंसियां, अनावश्यक विवाद पैदा कर सकती हैं और उत्पन्न कर सकती हैं

संदेह का माहौल। समुदाय के व्यापक हित

आवश्यकता है कि ऐसे मामलों की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए

आयोगों में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके निष्कर्ष लोगों का विश्वास बढ़ा सकते हैं।  
लियोनेल कोहेन व्याख्यान में अपने संबोधन में,

सर सिरिल सैल्मन ने "ट्रिब्यूनल्स ऑफ इन्क्वायरी" पर बोलते हुए कहा:

" सभी देशों में, निश्चित रूप से उन लोगों में जो स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं

भाषण और एक स्वतंत्र प्रेस, ऐसे क्षण आते हैं जब आरोप और

अफवाहें फैलती हैं जिससे देश भर में विश्वास का संकट पैदा होता है

सार्वजनिक जीवन की अखंडता में या अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में  
सार्वजनिक महत्व। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा शायद ही कभी होता है, लेकिन जब

क्या यह आवश्यक है कि जनता का विश्वास बहाल हो

क्योंकि इसके बिना कोई भी लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यह

आत्मविश्वास को प्रभावी रूप से केवल पूरी तरह से बहाल किया जा सकता है

अफवाहों और आरोपों का पता लगाना और उनकी जांच करना ताकि

सत्य की खोज करें और उसे स्थापित करें। सच साबित हो सकता है

कि बुराई मौजूद है, इस प्रकार इसे नोट करने में सक्षम बनाता है, या कि

अफवाहों और आरोपों का कोई आधार नहीं है  
जिसे जनता परेशान कर चुकी है। किसी भी मामले में, विश्वास

डेंस बहाल हो गया है "।

पुलिस जाँच, अपने सबसे अच्छे रूप में, एक आरोप की एकतरफा जाँच है क्योंकि वह व्यक्ति जिसका आचरण विषय है -

जाँच को उस गवाह से जिरह करने का कोई अधिकार या अवसर नहीं है जिसके गवाह से पूछताछ की जाती है। पुलिस द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अधिनियम की धारा 8 सी,

दूसरी ओर, प्रतिपरीक्षा का अधिकार, दर्शकों का अधिकार और एक कानूनी व्यवसायी के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करता है।

उपयुक्त सरकार, धारा 8 ख में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति पर और आयोग की अनुमति से, किसी अन्य व्यक्ति पर

जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा दर्ज किया जाता है। धारा 8 बी के खंड (ए) और (बी) क्रमशः उन व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जिनके आचरण को आयोग जांच करना आवश्यक समझता है और ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रतिष्ठा, आयोग की राय में, जांच से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और अगर वह मुख्यमंत्री या मंत्री है, तो खुद सरकार के कार्यों को प्रचार के भयंकर प्रकाश से उजागर किया जाता है। लेकिन यह एक जोखिम है जो प्रत्येक निर्देशित जांच में निहित है।

यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

109

सच्चाई का पता लगाने के लिए। हालाँकि, यह इस विशिष्ट कथन को उचित नहीं ठहराता है कि जाँच राज्य सरकार के विशिष्ट कार्यों में हस्तक्षेप करती है या यह केंद्र सरकार को राज्य कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। आखिरकार, यह उन लोगों के हित में है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खुले आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें एक प्रशिक्षित और विचाराधीन जांच आयोग के समक्ष उन आरोपों को दूर करने का अवसर

मिलना चाहिए जो सबूत के तकनीकी नियमों से बंधा नहीं है। यह केवल इस सच्चाई को स्थापित करने से ही सार्वजनिक जीवन की शुद्धता और अखंडता का पता लगाया जा सकता है और यही वह उद्देश्य है जिसे जांच आयोग अधिनियम प्राप्त करना चाहता है।

एम. वी. राजवाडे बनाम डॉ. एस. एम. हसन और अन्य।, ( 1) द्वारा आयोजित किया गया था

नागपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 आयोग को केवल दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियों से लैस करती है, लेकिन उसे न्यायालय का दर्जा प्रदान नहीं करती है और आयोग केवल काल्पनिक है।

धारा 5 (4) में उल्लिखित सीमित प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय।

न्यायालय ने कहा कि कोई अभियुक्त नहीं है, कोई अभियुक्त नहीं है और कोई नहीं है

आयोग के समक्ष परीक्षण के लिए विशिष्ट आरोप, और न ही सरकार

कानून के तहत, एक या दूसरे तरीके से उच्चारण करना आवश्यक है

आयोग के निष्कर्षों पर। दूसरे शब्दों में,

" आयोगों द्वारा शासित आयोग

जाँच अधिनियम, 1952 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

यह है,

' अपने मन की जानकारी के लिए '

इसलिए, एक तथ्य खोजने वाले निकाय का उद्देश्य केवल निर्देश देना है

बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए सरकार का ध्यान।

न्यायिक प्रकृति का "।

इन टिप्पणियों को निकाला गया और अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया

इस न्यायालय ने ब्रजनंदन सिन्हा बनाम. ज्योति नारायण। ( 2 )

अतः यह स्पष्ट है कि संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति

केंद्र सरकार के तहत एक जांच आयोग नियुक्त करना

अधिनियम की धारा 3 (1) के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के उद्देश्य से

एक के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के आरोप वर्तमान  
मुख्यमंत्री या मंत्रियों को अंतर-मंत्री का गठन करने के लिए नहीं रखा जा सकता है

राज्य सरकार के कार्यकारी कार्यों के प्रति संवेदनशीलता। उस पर

आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति, केंद्र सरकार या

निष्कर्षों की प्रकृति के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है  
आयोग द्वारा अभिलिखित। अगर वह कोई कार्रवाई करने का फैसला करती है। द.

इसकी वैधता का परीक्षण संवैधानिक के आलोक में किया जा सकता है  
प्रावधान। लेकिन जब तक वह चरण नहीं आता, तब तक यह मानना मुश्किल है कि

केंद्र सरकार किसी भी नियंत्रण या पर्यवेक्षी न्यायशास्त्र का प्रयोग कर रही है।

राज्य सरकार के कार्यकारी कार्यों पर बोलचाल। के रूप में

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम में इस न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई। श्री न्याय

एस. आर. तेंदुलकर और अन्य, (3) "आयोग के पास आदिउदी की कोई शक्ति नहीं है।  
कैशन एक आदेश पारित करने के अर्थ में जिसे प्रोप्रियो लागू किया जा सकता है

जोरदार "।

( 1 ) एयर 1954 नाग। 71 .

( 2 ) [ 1955 ] एससीआर

955,975।

( 3 ) [ 1959 ] एस. सी. आर. 279,293

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार, वही धारणा जिस पर राज्य के वकील ने निर्माण किया है

( उनके तर्क की इमारत मुझे भ्रामक लगती है। उस धारणा की अस्वीकृति उनके अधिकांश अन्य प्रस्तुतियों का तुरंत जवाब देती है, लेकिन चूंकि इस मामले पर दोनों पक्षों द्वारा पूरी तरह से और ईमानदारी से बहस की गई है, इसलिए सभी प्रतिद्वंद्वी गुटों पर विचार करना और विवाद को शांत करना वांछनीय है। श्री सिन्हा के तर्क का अगला अंग यह है कि भारत राज्यों का एक संघ है और संविधान की व्याख्या करते समय, हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताओं और सामान्य योजना को ध्यान में रखना चाहिए।

संघीय या अर्ध-संघीय संविधान जिसके द्वारा भारत संघ और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और

सीमांकित। "भारत के संवैधानिक कानून" खंड पर एक विद्वान लेखक का हवाला देते हुए। 1 , पृष्ठ 1074, वकील का तर्क है कि अन्यथा आयोजित करने का मतलब यह होगा कि संघ की कार्यपालिका प्रभावी रूप से

राज्य कार्यपालिका को अपमानित करना, जो हमारे संघीय संविधान की मूल योजना का विरोध करती है। "भारत के संवैधानिक कानून" का बयान, जिस पर वकील भरोसा करते हैं, संदर्भ से बाहर है क्योंकि यह इस सवाल के संबंध में आता है कि क्या मंत्रालय को बर्खास्त करने में या कानून को भंग करने में, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में या उनके निर्देशों के तहत कार्य करता है। यह राय व्यक्त करते हुए कि एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय को केवल इसलिए राज्यपाल को हटाने की सलाह देना उचित नहीं होगा क्योंकि वह ऐसी कार्रवाई करता है जो केंद्रीय मंत्रालय की नीति के अनुरूप नहीं है, विद्वान लेखक का कहना है कि कोई अन्य विचार राज्य पर केंद्रीय कार्यपालिका के प्रभावी नियंत्रण में निहित होगा।

कार्यकारी, जो हमारे संघीय संविधान की मूल योजना का विरोध करता है। इस विचार के अलावा कि जिस बयान पर भरोसा किया गया है वह संदर्भ से बाहर है, मैंने पहले ही इस दलील को खारिज कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के मौजूदा मंत्रियों के आचरण की जांच के लिए एक तथ्य-खोज आयोग की नियुक्ति को केंद्रीय कार्यपालिका में राज्य कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण निहित करने के लिए माना जा सकता है। इसलिए मामले के इस पहलू को अलग रखते हुए वकील के निवेदन की जांच करनी होगी।

भारत, निस्संदेह, राज्यों का एक संघ है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 (1) स्पष्ट रूप से यही प्रदान करता है। चाहे हम अपने संविधान को संघीय या अर्ध-संघीय के रूप में वर्णित करें, कोई भी इस कठोर वास्तविकता के प्रति अपनी दृष्टि को कभी भी अंधा नहीं कर सकता है कि भारत राज्यों का संघ है। द.

संविधान में एक ओर केंद्र सरकार और दूसरी ओर राज्य सरकारों के बीच विधायी और कार्यपालिका की शक्तियों का सावधानीपूर्वक सीमांकन किया गया है। उस शक्ति के संतुलन को कभी भी बाधित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह कहने से अलग बात है कि अंतर्निहित या निहित सीमाओं को विधायी शक्तियों में पढ़ा जाना चाहिए या क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए किसी को संविधान की शक्तियों और प्रावधानों को पढ़ना चाहिए जो उसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों से तार्किक रूप से अनुसरण करते प्रतीत हो सकते हैं।

कर्नाटक वी. यूनियन (चंद्रचूड़, जे.)

111

पहला सवाल जिससे निपटा जाना चाहिए वह यह है कि क्या

संसद

जांच आयोग अधिनियम, 1952 को अधिनियमित करने के लिए विधायी क्षमता है। यह प्रश्न, मेरी राय में, श्री राम कृष्ण डालमिया (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के एक फैसले से समाप्त होता है, जिसमें उसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी।

जिस मामले में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत कुछ कंपनियों के मामलों की जांच के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 94 और सूची III की प्रविष्टि 45 के तहत कानून पारित करने की विधायी क्षमता है। सूची I की प्रविष्टि 94 सूची I में "किसी भी मामले के उद्देश्य के लिए पृच्छताछ, सर्वेक्षण और सांख्यिकी" से संबंधित है, जबकि सूची III की प्रविष्टि 45 "सूची II या सूची III में निर्दिष्ट किसी भी मामले के उद्देश्यों के लिए पृच्छताछ और सांख्यिकी" से संबंधित है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विधायी सूचियों में प्रविष्टियों को एक संकीर्ण या पांडित्यपूर्ण नहीं बल्कि एक व्यापक और उदार संरचना प्राप्त होनी चाहिए और, उस दृष्टिकोण से, दोनों प्रविष्टियों में आने वाले 'पृच्छताछ' शब्द को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए।

जांच आयोगों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम पारित करने की शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 पारित किया है। चूंकि वर्तमान मंत्रियों के आचरण की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति

राज्य सरकारों की, जो अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत समझी जाती हैं, राज्य की मंत्रपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के खिलाफ या लेजिस लेटिव असेंबली के विशेषाधिकारों के खिलाफ नहीं है और क्योंकि यह केंद्र को भी प्रदान नहीं करती है।

सरकार राज्य कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, प्रांत

सायन को विधायी क्षमता का एक वैध अभ्यास माना जाना चाहिए।

संसद से।

श्री राम कृष्ण डालमिया (ऊपर) जहाँ तक यह तय करता है कि

जांच आयोग अधिनियम, 1952 विधायी संघ के अंतर्गत आता है। सूची I की प्रविष्टि 94 और सूची I की प्रविष्टि 45 को ध्यान में रखते हुए संसद का गठन

सूची III की, सम्मान के साथ, पुष्टि की जानी चाहिए और इसे अच्छे कानून के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 1

हालाँकि, यह जोड़ा जा सकता है कि यदि किसी भी कारण से यह दिखाई देने वाला था, तो यह

सूची I की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 किसी भी स्थिति में विधान का समर्थन करेगी। अधिनियम की वैधता। वह प्रविष्टि संसद को शक्ति प्रदान करती है

'कोई अन्य विषय जो सूची II या सूची III में सूचीबद्ध नहीं है' पर विधान बनाना। प्रविष्टि 97 अवशिष्ट प्रविष्टि की प्रकृति में है और

शब्द 'कोई अन्य पदार्थ' जो उसमें दिखाई देता है उसका अर्थ है 'कोई भी पदार्थ'

सूची I में सूचीबद्ध लोगों के अलावा। यदि प्रविष्टि 94 में शामिल नहीं है

विवादित अधिनियम, अधिनियम द्वारा अनुध्यात प्रकृति की 'पूछताछ'

विवरण 'कोई अन्य विषय' के अंतर्गत आता है; और यदि सूची की प्रविष्टि 45 III और, निश्चित रूप से, पूरी राज्य सूची को बाहर रखा जाना चाहिए।

विचार करने पर, अधिनियम 'सूची में सूचीबद्ध नहीं किए गए मामले' से संबंधित होगा।

II या सूची III '। श्री सिन्हा ने प्रवेश के लिए सहारा लेने पर आपत्ति जताई

97 सूची I का इस आधार पर कि यह अन्य प्रविष्टियों से अधिक नहीं हो सकता है

सूची I और III में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

राज्य निष्पादन पर केंद्रीय कार्यकारी पर्यवेक्षी नियंत्रण

आप। उस तर्क को खारिज कर दिया गया है, प्रविष्टि 97 किसी भी स्थिति में होगी

अधिनियम की विधायी वैधता को बनाए रखना।

अनुच्छेद 248 के निहितार्थ पर विचार करना अनावश्यक है।

क्योंकि इसके लिए प्रश्न की जांच की आवश्यकता हो सकती है, जो कि [1978] 2 एस. सी. आर. है।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

112

श्री राम कृष्ण डालमिया के फैसले को देखते हुए यहां कोई आवश्यकता नहीं है।

(ऊपर) क्या वह अनुच्छेद ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो इसमें नहीं पाई जाती है

सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (1) और क्या एक सकारात्मक इस प्रश्न का उत्तर सूची I के 1 से 96 तक की प्रविष्टियों को प्रस्तुत करेगा।

संसद के कानून के सवाल पर चर्चा का सारांश दिया जा सकता है।  
कहकर लैटिव क्षमता कि "निर्माण को अपनाना सबसे अधिक"

यह

संविधान और विधायी प्रविष्टियों की व्याख्या "एक व्यापक  
भावना", विवादित अधिनियम को पीड़ित नहीं माना जा सकता है

और उदार

इसे अधिनियमित करने के लिए संसद में विधायी क्षमता की इच्छा। प्रविष्टि  
94 सूची I की प्रविष्टि, सूची III की प्रविष्टि 45 और इनमें विफल रहने पर, सूची 1 की  
प्रविष्टि 97

अधिनियम को बनाए रखना चाहिए।

वह ऊपर दिए गए अंकों (ए) से (ई) का निपटान करता है, जिसके लिए छोड़ दिया  
जाता है

विचार बिंदु (एफ), (जी) और (एच)। आसान संदर्भ के लिए,

इन बिंदुओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: प्रशासनिक संबंधों का दांव संघ और राज्यों के बारे में भाग 11 के अध्याय 2 में चर्चा की गई है।

संविधान का; (ii) जांच आयोग अधिनियम, व्याख्या के रूप में

ऊपर उल्लिखित, अध्याय में निहित प्रावधानों के पूरक के लिए अभिप्रेत है

II, भाग 11; (iii) संसद के किसी भी प्रावधान का पूरक नहीं हो सकता है

संविधान के संशोधन को छोड़कर संविधान; (iv)

जांच आयोग अधिनियम केंद्र और राज्य के बीच एक नया संबंध बनाता है केंद्रीय कार्यपालिका को राज्य पर अतिरिक्त नियंत्रण सौंपना

संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है और (v) प्रावधान के बाद से

भाग XI के अध्याय II में निहित सिद्धांत संपूर्ण मामले हैं।

संघ और संघ के बीच प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करना

राज्यों को इसमें कोई भी विधायी जोड़ या उसके पूरक होना चाहिए।

निहित रूप से निषिद्ध माना जाए।

ऊपर दिए गए पहले चार बिंदुओं, (i) से (iv) का संक्षिप्त उत्तर यह है कि

हालाँकि यह सच है कि संघ के बीच प्रशासनिक संबंध

और राज्यों को संविधान के अध्याय II भाग XI द्वारा निपटाया जाता है।

यद्यपि उसमें निहित प्रावधानों को बदला नहीं जा सकता है सिवाय इसके कि

एक संवैधानिक संशोधन द्वारा, जांच आयोग अधिनियम करता है

परिकल्पना के अनुसार केंद्र-राज्य संबंधों में कोई बदलाव नहीं लाएगा।

भाग XI द्वारा निर्धारित। यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार को अधिकार देता है

अपने मन को सूचित करने की दृष्टि से; और आयोग की रिपोर्ट सायन, किसी पर  
बाध्यकारी नहीं होने के कारण, इसका अपना कोई बल नहीं है। रेवेला

आयोग के समक्ष स्थितियाँ संभवतः प्रभाव पैदा कर सकती हैं -  
विश्वसनीयता, लेकिन जांच का निर्देश नहीं है

राज्य सरकार की

जिस तरीके से राज्य सरकार या राज्य कार्यपालिका समझौता करती है

अपने संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में खुद को नलिका करता है लेकिन

जिस तरह से, यदि बिल्कुल भी हो, तो इसके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार और पक्षपात के कृत्यों को करने के लिए अपने कार्यालय का उपयोग किया है। यह संभव है कि एक आयोग मंत्री के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करे और निष्पक्षता से इस बात पर जोर दे कि मंत्री के निजी कार्यों का राज्यों के कार्यकारी मामलों के सार्वजनिक प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, आयोग आरोपों को पूरी तरह से निराधार और तुच्छ बताकर खारिज कर सकता है। ये सभी अविश्वसनीय हैं और ये आयोग के कार्यों की प्रकृति के बारे में मूल प्रश्न के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसलिए, यह तर्क कि केंद्रीय कर्नाटक को सशक्त बनाकर v.

यूनियन (चंद्रचुआ, जे.)

113

सरकार राज्य सरकार के वर्तमान मंत्रियों के आचरण की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी, संसद ने केंद्र-राज्य संबंधों पर कानून बनाया है जो एक संवैधानिक विषय है, बिना किसी बल के।

हालांकि, कुछ हद तक उपन्यास के बारे में एक शब्द कहना आवश्यक है

राज्य सरकार का तर्क है कि, साधारण विधान द्वारा, संसद एक का पूरक भी नहीं हो सकती है। संवैधानिक प्रावधान, जब तक कि संविधान इसे ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं करता है। सामान्य विधान, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा तर्क दिया गया है, को केवल दो परीक्षणों का उत्तर देना होता है: सबसे पहले, कानून विधायिका की वैधानिक क्षमता के भीतर होना चाहिए, और दूसरा, कानून को भाग III के प्रावधानों के खिलाफ या संविधान के किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक बार जब विधायी क्षमता स्थापित हो जाती है और किसी विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की वैधता पर इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि यह एक संवैधानिक प्रावधान का 'पूरक' है। राज्य के तर्क की भ्रांति इस धारणा में निहित है कि प्रत्येक कानून में

संविधान द्वारा निपटाए गए किसी विषय का सम्मान अनिवार्य रूप से संविधान के संशोधन के बराबर है। एक या दो उदाहरण सही स्थिति को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। संविधान के

अनुच्छेद 297 में प्रावधान है कि भारत के क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर समुद्र में निहित सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के उद्देश्यों के लिए रखी जाएंगी। यह निर्विवाद है कि चूंकि "क्षेत्रीय जल या भारत के महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर समुद्र में निहित भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें" लेख का विषय है। 297, कोई भी विधायिका, भले ही उसके पास ऐसा करने की विधायी क्षमता हो, उस विषय पर कानून नहीं बना सकती है। यह प्राथमिक बात है कि विधायिका, प्रासंगिक सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर कानून बनाते समय, संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं कर सकती है। लेकिन जब तक ऐसा कोई उल्लंघन नहीं होता है, तब तक अनुच्छेद 297 द्वारा माने गए विषय पर कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि यह उस अनुच्छेद के प्रावधानों का पूरक है। संविधान का अनुच्छेद 299 अनुबंधों से संबंधित है। मुझे यह भी उतना ही निर्विवाद लगता है कि अनुबंधों के विषय से संबंधित एक कानून, भले ही विधायी क्षमता में कमी न हो, असंवैधानिक हो जाता है। राष्ट्रीय इस कारण से कि यह अनुबंधों के विषय से संबंधित है। इसलिए इस ओर से राज्य का तर्क पूरी तरह से सारहीन है, इस विचार के अलावा कि विवादित कानून केंद्र-राज्य संबंधों पर असर नहीं डालता है।

पाँचवाँ और अंतिम विवाद भी निपटाया जा सकता है।

इस उत्तर के साथ कि जांच आयोग अधिनियम केंद्र-राज्य संबंधों के विषय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसलिए, संघ और राज्यों के बीच एक नया संबंध बनाने का कोई सवाल ही नहीं है जो संविधान को ज्ञात नहीं है या संविधान के अध्याय 2, भाग 11 में दिए गए प्रावधानों से असंगत है।

प्रतिस्थापन। न केवल यह कि अधिनियम का सार और सार "पूछताछ" है, बल्कि यह संयोग से अतिक्रमण या अतिक्रमण भी नहीं करता है।

भाग 11 द्वारा कब्जा किए गए संवैधानिक क्षेत्र पर। यदि यह केंद्र-राज्य के विषय को नहीं छूता है

वहाँ संबंध है

नहीं।

कॉन्स्टी [1978] 2 एस. सी. आर. द्वारा निपटाए गए विषय पर इसके प्रभाव का प्रश्न।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

114

ट्यूशन। इसलिए, यह मानते हुए भी कि केंद्र-राज्य संबंधों के प्रश्न पर कानून अनिवार्य रूप से वर्जित है, विवादित अधिनियम उस नियम के प्रतिकूल दायरे में नहीं आता है और इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है।

फिर भी, राज्य के इस तर्क की वैधता की संक्षेप में जांच करना आवश्यक है कि चूंकि अध्याय II, भाग XI के प्रावधान संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले मामलों के संपूर्ण हैं, इसलिए इसमें कोई विधायी जोड़, या उसके पूरक, यदि निहित रूप से निषिद्ध है। पहले से ही ओ. बी.

यदि कोई कानून विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर है, तो इसे इस कथित आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि उसने किसी संवैधानिक प्रावधान में कुछ जोड़ा है, या पूरक किया है, जब तक कि जोड़ या पूरकता संविधान के किसी भी समर्थक दृष्टिकोण के साथ असंगत नहीं है। इसलिए, मैं क्रॉफर्ड के वैधानिक निर्माण (एड।) से मार्ग पर राज्य की निर्भरता की प्रासंगिकता की सराहना करने में असमर्थ हूँ। 1940 पृष्ठ 334-335) इस प्रभाव के लिए कि यदि कोई कानून उन चीजों की गणना करता है जिन पर उसे काम करना है, तो बाकी हर चीज को आवश्यक रूप से और निहितार्थ द्वारा इसके संचालन और इसके प्रभाव से बाहर रखा जाता है। जैसा कि मैंने अपने निर्णय में एक से अधिक बार कहा है, एक सामान्य सूत्र जो राज्य के तर्क के माध्यम से चलता है, वह यह है कि संविधान ने आपात स्थितियों को छोड़कर राज्य कार्यपालिका पर केंद्रीय कार्यपालिका के नियंत्रण को लागू करने को निहित रूप से प्रतिबंधित किया है, और चूंकि जांच आयोग अधिनियम उस संवैधानिक निषेध का उल्लंघन करता है, इसलिए यह अमान्य है। यह धारणा निराधार होने के कारण, अनुमानित परिणाम को अस्वीकार करना होगा। इसके अलावा, निहित निषेध के सिद्धांत को जो अनिवार्य रूप से अंतर्निहित सीमाओं के सिद्धांत पर आधारित है, इस न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार मामले (1) और श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम में खारिज कर दिया गया है। श्री राज नारायण (2)।

इसलिए, मेरी राय है कि हालांकि कर्नाटक राज्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत बनाए रखने योग्य है।

तथापि, भारत सरकार द्वारा 23 मई, 1977 को जारी अधिसूचना जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1) के दायरे में है और यह अधिनियम राज्य सरकार की ओर से उल्लिखित किसी भी कारण से असंवैधानिक नहीं है। तदनुसार, मैं मामले में अपने लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। भगवती, जे.-जहाँ तक मुकदमे में दावे के गुण-दोष का संबंध है, मैं अपने विद्वान भाई चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ,

लेकिन संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे की स्थिरता के सवाल पर, मैं एक अलग फैसले में अपनी राय व्यक्त करना चाहूँगा, न केवल इसलिए कि इससे उत्पन्न होने वाला संवैधानिक मुद्दा कुछ महत्व का है, बल्कि इसलिए भी कि मैं पाता हूँ कि हालांकि राजस्थान राज्य में मेरे विद्वान भाई गुप्ता और मेरी ओर से दिए गए फैसले में इस लेख के दायरे और दायरे के बारे में कुछ चर्चा हुई थी।

( 1 ) [ 1973 ] सप. एस. सी. आर. 1,608,916-917,977-78।

( 2 ) [ 1976 ] 2 एस. सी. आर. 347

कर्नाटक वी. यूनियन (भगवती, जे.)

115

वी. भारत संघ (1) ने प्रश्न के कुछ पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा और एक पूर्ण विचार स्पष्ट रूप से आवश्यक प्रतीत होता है। मुकदमे को जन्म देने वाले तथ्य मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले में विस्तार से दिए गए हैं और इसलिए उन्हें दोहराना आवश्यक नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कर्नाटक राज्य ने भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन करने वाली केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए भारत संघ के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और मुख्यमंत्री और कर्नाटक राज्य के कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ भाई-भतीजावाद। सवाल यह है कि क्या सूट को कला के तहत बनाए रखा जा सकता है। 131, भारत संघ की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा मुकदमे की बनाए रखने की क्षमता के खिलाफ प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है।

सवाल का जवाब मुख्य रूप से सही अंतर पर निर्भर करता है।

कला का प्रदर्शन। 131. यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी विवाद में अनन्य मूल अधिकारिता प्रदान करता है-(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या (ख) भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक राज्यों के बीच दूसरी तरफ, या (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच, यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न (कानून या तथ्य का) शामिल है, जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। इस अनुच्छेद के एक स्पष्ट पठन पर यह स्पष्ट है कि यह अपने द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कार्यवाही का कोई विशेष तरीका निर्धारित नहीं करता है। निस्संदेह, उच्चतम न्यायालय के नियमों के भाग III में यह विचार किया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता को एक वाद के

माध्यम से लागू किया जाएगा, लेकिन यह अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं है और इसकी व्याख्या करते समय, हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण को 'कार्रवाई के कारण' के विचारों से प्रभावित न होने दिया जाए जो एक मुकदमे में स्पष्ट हैं। मूल अधिकारिता का दायरा और दायरा किसी भी प्राथमिक विचार द्वारा बाधित किए बिना लेख की स्पष्ट शर्तों पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

अब, स्पष्ट रूप से विवाद के संबंध में दो सीमाएँ हैं

जिसे अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। एक पक्षकारों के संबंध में है और दूसरा विषय वस्तु के संबंध में है। इस अनुच्छेद में इतने शब्दों में प्रावधान किया गया है कि विवाद भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच होना चाहिए या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होना चाहिए। अनुच्छेद का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि चूंकि किसी संघीय या अर्ध-संघीय ढांचे में, जिसे संविधान स्थापित करना चाहता है, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया जाना चाहिए और वह मंच देश का सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष को न्यायालयों के पदानुक्रम के माध्यम से लंबी, कठिन और समय लेने वाली यात्रा शुरू किए बिना ऐसे विवादों का अंतिम निर्णय तेजी से और तेजी से प्राप्त किया जा सके। यह अनुच्छेद संघीय या अर्ध-संघीय सरकार का एक आवश्यक सहवर्ती है और यह केवल तभी आकर्षित होता है जब विवाद के पक्षकार भारत सरकार या दोनों तरफ से एक या एक से अधिक राज्य हों। यह पार्टियों के लिए सीमा है। विषय के रूप में दूसरी सीमा-पदार्थ से बहती है

( 1 ) ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361.

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

116

शब्द "यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है (क्या तथ्य) जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार हो

कानून या

निर्भर करता है "। ये शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विवाद एक होना चाहिए

किसी कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा को प्रभावित करना और उस पर विवाद नहीं राजनीतिक स्तर जिसमें कोई कानूनी पहलू शामिल नहीं है। इसे रखा गया था चंद्रचूड़, जे., राजस्थान राज्य में अपने निर्णय में बहुत उपयुक्त हैं।

वी. भारत संघ (ऊपर) जब उन्होंने कहा: बस आपस में झगड़ा उस अनुच्छेद की योजना के तहत सरकारों का कोई स्थान नहीं है। यह केवल तभी होता है जब एक कानूनी मुद्दा, जो केवल एक राजनीतिक मुद्दे से अलग हो। एक कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा को छूते हुए उत्पन्न होता है कि लेख आकर्षित होता है। अतः वर्तमान मामले में मुकदमा स्पष्ट रूप से होगा यह तब तक बनाए रखने योग्य नहीं होगा जब तक कि यह इन दोनों सीमाओं का पालन नहीं करता है।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क

भारत संघ की ओर से यह था कि निर्धारित करने के लिए परीक्षण मुखदमे की रखरखाव क्षमता यह नहीं थी कि क्या केंद्र का अधिकार है

कर्नाटक राज्य के मंत्री और अन्य मंत्रियों से पूछताछ की गई। मुखदमे में, लेकिन क्या केंद्रीय सरकार की विवादित कार्रवाई

यह राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करता है। भले ही असंतुष्ट

इस प्रकार होने के लिए सूट की रखरखाव को निर्धारित करने के लिए यह है कि किसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा

कार्रवाई का कारण? क्या राज्य कह सकता है कि उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है?

और इसलिए, क्या मुकदमा बनाए रखने का अधिकार है? सीखा अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि चूंकि की आक्षेपित कार्रवाई केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ निर्देश दिया गया था

राज्य के मंत्रियों के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा

मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री और उनके पास एक होगा  
कार्रवाई का कारण क्योंकि वे पूर्व होंगे

भारत संघ के खिलाफ

केंद्र सरकार की कार्यकारी कार्रवाई से न्यायिक रूप से प्रभावित

जिसे संविधान और संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है

कानून। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग के अधीन होने से प्रतिरक्षा का कानूनी अधिकार है और यह अधिकार निश्चित रूप से उनके द्वारा लागू किया जा सकता है। लेकिन यह अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका के माध्यम से होगा, यदि यह एक मौलिक अधिकार है।

शामिल है, और कला के तहत नहीं। 131. यहाँ तक कि राज्य सरकार भी

इसे इस आधार पर कार्रवाई का कारण कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की आक्षेपित कार्रवाई उसके कर्मियों को प्रभावित करती है, अर्थात्, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री और राज्य सरकार अनुच्छेद के तहत एक याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हित होने का वैध रूप से दावा कर सकती है। 226 विवादित कार्रवाई को चुनौती देने के लिए। लेकिन यह अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर नहीं कर सकता है क्योंकि यह केवल राज्य है जो इस तरह के मुकदमे को बनाए रख सकता है न कि राज्य सरकार। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 131 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'राज्य' है न कि 'राज्य सरकार' और 'राज्य' और 'राज्य सरकार' के बीच एक मौलिक अंतर है और इसलिए, यह अनुच्छेद 131 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि राज्य

सरकार के पास कार्रवाई का कारण होना चाहिए। यह वह राज्य है जिसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाना चाहिए और जिसके पास अनुच्छेद 131 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए कार्रवाई का कारण होना चाहिए। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में केंद्र सरकार की विवादित कार्रवाई, मुख्यमंत्री कर्नाटक वी. यूनियन (भगवती, जे.) के कानूनी अधिकार को प्रभावित करती है।

117

और संबंधित मंत्री और संभवतः राज्य सरकार के भी, लेकिन यह अपने कार्यकारी अभिकर्ता के कानूनी अधिकार से अलग एक कानूनी इकाई के रूप में राज्य के कानूनी अधिकार का उल्लंघन

नहीं करता है, अर्थात् राज्य सरकार और राज्य, इसलिए, अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे को मुख्य रूप से दायर करने का हकदार नहीं है। विद्वान आदी का यह तर्क राष्ट्रीय सॉलिसिटर जनरल, मेरी राय में, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

विद्वानों के तर्क में दो भ्रान्तियां अंतर्निहित हैं।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। एक अपेक्षाकृत कठोर, पानी खींचने में है

अनुच्छेद 131 और दूसरे के संदर्भ में 'राज्य' और 'राज्य सरकार' के बीच कड़ा अंतर, यह मानते हुए कि यह केवल वहीं है जहां वादी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है कि वादी द्वारा उस अनुच्छेद के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। सबसे पहले 'राज्य' और 'राज्य सरकार' के बीच के अंतर की ओर मुड़ते हुए, यह सच है कि सैद्धांतिक रूप से यह अंतर मौजूद है और इसे सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 की उप-धाराओं (58) और (60) में मान्यता मिलती है। बहुसंख्यक न्यायाधीश

राजस्थान राज्य में v. भारत संघ (उपरोक्त) ने भी स्वीकार किया कि राज्य और राज्य सरकार के बीच अंतर है।

विलोबी पृष्ठ 49 पर "सार्वजनिक कानून की मौलिक अवधारणाओं" में इंगित करते हैं: "राज्य और उसकी सरकार के बीच का अंतर एक मानव व्यक्ति, एक नैतिक और बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, और उसके भौतिक शरीर के बीच के अंतर के समान है। 'राज्य' शब्द से राजनीतिक व्यक्ति या इकाई को समझा जाता है जिसके पास कानून है।

सही करते हैं। 'सरकार' शब्द से उस एजेंसी को समझा जाता है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा को तैयार किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार सरकार राज्य के तंत्र के रूप में कार्य करती है, और जो इस तंत्र को संचालित करते हैं वे राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और इसी प्रभाव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ पॉइन्डेक्सटर v में हैं। ग्रीनहाउ: ( 1) "राज्य स्वयं एक आदर्श व्यक्ति है, अमूर्त, अदृश्य और अपरिवर्तनीय। सरकार एक एजेंट है।" इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार वह अभिकर्ता है जिसके माध्यम से राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। अब, यदि राज्य सरकार वह अभिकर्ता है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा व्यक्त करता है, तो यह देखना मुश्किल है कि राज्य को कैसे असंबद्ध कहा जा सकता है जब इसके किसी भी अधिकार या क्षमता या कमी का श्रेय राज्य को दिया जाता है।

सरकार। यह कहना पूरी तरह से गैर-यथार्थवादी होगा कि चूंकि राज्य सरकार राज्य से अलग है, इसलिए राज्य सरकार में इसकी कोई भी कार्यवाही या क्षमता या कमी राज्य को प्रभावित नहीं करेगी और राज्य को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। यह 'राज्य' और 'राज्य सरकार' के बीच

अभिन्न संबंध को नजरअंदाज करने के लिए है। कोई भी कार्रवाई जो राज्य सरकार या मंत्रियों को मंत्री के रूप में उनकी क्षमता को प्रभावित करती है-क्योंकि उस क्षमता में वे उनकी ओर से कार्य करेंगे।

राज्य-एक ऐसा मामला उठाएगा जिसमें राज्य का संबंध होगा। यह सच है कि समानताएं और रूपक गुमराह करने के लिए उपयुक्त हैं और उन पर एक तर्क को आधार बनाना असुरक्षित होगा, लेकिन मैंने जो कहा है उसे मजबूत करने के लिए, मैं उपरोक्त उद्धृत अंश में विलोबी द्वारा दी गई उपमा को ले सकता हूं और सवाल पूछ सकता हूं: यदि किसी क्रिया या क्षमता या कमी के लिए "भौतिक भौतिक शरीर" को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो क्या यह उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिसका शरीर यह है और क्या वह इससे प्रभावित नहीं होगा? मैं डॉ. राजीव धवन और प्रो. एलिस

( 1 ) 29 कानून. एड।, 185 .

[ 1978 ] 2 एससीआर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

118

जेकब जब वे विधानसभा विघटन मामले पर अपने अगले लेख में कहते हैं, अर्थात् राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ: " मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को और मंत्री के रूप में समान रूप से एक मंत्री को जो भी संचार किया जाता है, उसे एक ऐसा मामला बनाना चाहिए जिसमें राज्य शामिल हो। एस. मुर्तजा फजल

राजस्थान राज्य में अली, जे. बनाम। भारत संघ ने राज्य के स्थायी संस्थानों और उनके बीच अंतर करने की मांग की

कर्मचारियों को बदलते हुए और देखा: " इन संस्थानों को चलाने के लिए कर्मियों के बारे में सवाल 'राज्य' और 'भारत सरकार' के बीच विवाद के अस्तित्व से पूरी तरह से असंबद्ध है। यह तभी हो सकता है जब किसी राज्य की किसी भी स्थायी संस्था का पूर्ण उन्मूलन हो जाए तो वास्तविक विवाद उत्पन्न हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह यह निर्धारित करने के लिए एक वैध अंतर है कि विवाद को कब कहा जा सकता है राज्य सरकार का गठन करने वाले व्यक्तियों से अलग राज्य के साथ। डॉ. राजीव धवन और प्रो. एलिस जैकब: " यह विभाजन राज्य की स्थायी संस्थाओं और राज्य की गैर-स्थायी संस्थाओं के बीच नहीं हो सकता है और न ही

यह उन कार्यों के बीच हो सकता है जो राज्य सरकार के अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करते हैं और जो राज्य की संस्थाओं को समाप्त करते हैं। बालों को विभाजित करने का अंतर उन कार्यों के बीच है जो राज्य या उसके किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उन कार्यों के बीच है जो व्यक्तिगत हैं और राज्य के अधिकारियों के रूप में उनकी क्षमता में अधिकारियों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं—मुख्यमंत्री को भेजे गए एक पत्र में उनकी क्षमता पर सवाल उठाया गया है।

मुख्यमंत्री के रूप में शहर या शासन करने की शक्ति व्यक्ति, पत्नी, पति, पिता या मित्र के रूप में मुख्यमंत्री में विश्वास की कमी का आरोप नहीं लगा सकती है। यह मुख्यमंत्री पर अपनी क्षमता में विश्वास की कमी का आरोप लगाता है क्योंकि "मुख्यमंत्री"। मैं खुद को इस राय से सहमत पाता हूँ और मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूँ। इसलिए, मेरा मानना है कि जब किसी भी अधिकार या क्षमता या कमी का श्रेय किसी संस्था या कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है

राज्य की ओर से, यह एक ऐसा मामला उठाता है जिसमें राज्य शामिल या संबंधित है। इन परिस्थितियों में राज्य प्रभावित होगा या किसी भी तरह से इच्छुक होगा, यदि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपनी क्षमता में, या इसे अलग तरीके से कहें तो, अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को एक विशेष तरीके से राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश जारी करती है, तो राज्य स्पष्ट रूप से प्रभावित होगा यदि ऐसा निर्देश असंवैधानिक है और इसके खिलाफ शिकायत करने का हकदार होगा। तब स्थिति कोई भी है

अलग, अगर केंद्र सरकार, इसके बजाय, बिना किसी संवैधानिक अधिकार के, यह जांचने के लिए आगे बढ़ती है कि किस तरह की कार्यकारी शक्ति

राज्य का प्रयोग मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा किया जाता है और क्या इसका प्रयोग उचित तरीके से किया जाता है। राज्य को स्पष्ट रूप से ऐसे मामले में केंद्र की असंवैधानिक कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार होगा।

सरकार।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 131 के उचित निर्माण पर,

यह आवश्यक नहीं है कि वादी को उस अनुच्छेद के तहत मुकदमा दायर करने से पहले उसे लागू करने का अपना कुछ कानूनी अधिकार होना चाहिए।

यह.

क्या अनुच्छेद 131 की प्रयोज्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है कि

क्या?

वादी।

के कुछ कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि विवाद वह होना चाहिए जिसमें कर्नाटक बनाम संघ (भगवती, जे.) शामिल हो।

119

प्रश्न "जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है"। लेख में यह नहीं कहा गया है कि कानूनी अधिकार वादी का होना चाहिए। यह वादी या प्रतिवादी का हो सकता है। आवश्यक बात यह है कि पक्षों के बीच विवाद में कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार मुद्दा होना चाहिए। हम अनुच्छेद 131 का अर्थ ऐसे मामलों के लिए जुमाने के रूप में नहीं लगा सकते हैं जहां विवाद वादी के कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा से संबंधित है, ऐसा करने के लिए, लेख में उन शब्दों को पढ़ना होगा जो वहां नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवाद लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के नियमों के भाग III में प्रदान की गई कार्यवाही का तरीका एक मुकदमा है, कि हम अनजाने में अनुच्छेद 131 की व्याख्या में 'कार्रवाई के कारण' की धारणा को आयात करने के लिए प्रभावित हैं, जो एक मुकदमे में निहित है और इस लेख को केवल उन मामलों तक सीमित के रूप में पढ़ने के लिए जहां वादी के कुछ कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी के खिलाफ 'कार्रवाई का कारण' है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 131 में किसी वाद या 'कार्रवाई के कारण' का कोई संदर्भ नहीं है और वह अनुच्छेद विवाद के स्वरूप के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है जिसे न्यायनिर्णयन के लिए उसके समक्ष लाया जा सकता है। 'कार्रवाई के कारण' की आवश्यकता, जो इसमें इतनी आवश्यक है

एक सूट, इसलिए, दायरे का अर्थ लगाते हुए आयात नहीं किया जा सकता है और

अनुच्छेद 131 की परिधि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्वारा दिया गया निर्णय

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ इस समझौते पर आगे बढ़ता है कि अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमा केवल तभी शुरू किया जा सकता है जब कुछ अधिकार

वादी का उल्लंघन किया गया है, लेकिन इस पर कोई उचित चर्चा नहीं हुई उस मामले में तर्कों के दौरान और पूर्ण रूप से प्रश्न

विचार करते हुए, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई प्रतिबंध आयात नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 131 का निर्माण ताकि इसके दायरे को कम किया जा सके और

उस लेख का कवरेज। आकर्षित करने के लिए आवश्यक एकमात्र आवश्यकता

अनुच्छेद 131 की प्रयोज्यता यह है कि विवाद एक अंतर्विरोध होना चाहिए ऐसा कोई प्रश्न जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार हो।

यह निर्भर करता है, भले ही कानूनी अधिकार का दावा एक पक्ष द्वारा किया गया हो या दूसरा और यह आवश्यक नहीं है कि मैदान का कुछ कानूनी अधिकार

उस अनुच्छेद के तहत मुकदमा दायर करने से पहले विवाद का उल्लंघन किया जाना चाहिए।

वादी को निश्चित रूप से विवाद का एक पक्ष होना चाहिए और जाहिर है

यह विवाद का एक पक्ष नहीं हो सकता है जब तक कि यह इससे प्रभावित न हो। द. वादी किसी ऐसे मामले के संबंध में विवाद नहीं उठा सकता है जो

व्यस्त व्यक्ति उन चीजों में हस्तक्षेप करता है जो उससे संबंधित नहीं हैं। लेकिन अगर वादी विवाद को इस अर्थ में उठाने में रुचि रखता है कि यह प्रभावित है

की गई कार्रवाई से, यह विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ला सकता है

अनुच्छेद 131 के तहत, भले ही इसके किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन न किया गया हो, बशर्ते

बेशक विवाद किसी कानूनी व्यवस्था के अस्तित्व या सीमा से संबंधित है। सही है।

इस स्तर पर यह विचार करना भी सुविधाजनक होगा कि क्या है

अनुच्छेद 131 में प्रयुक्त 'कानूनी अधिकार' अभिव्यक्ति का अर्थ। यह है।

स्पष्ट है कि 'सही' शब्द का उपयोग यहाँ सामान्य अर्थों में किया गया है और नहीं इसके सख्त अर्थ के अनुसार। अपने संकीर्ण अर्थों में 'सही' का गठन करता है

राइट स्ट्रिक्टो सेंसु, लेकिन एक को एक लाभ या लाभ प्रदान किया जाता है कानून के शासन द्वारा व्यक्ति "। डायस अपने न्यायशास्त्र में, 1976 संस्करण।, पृष्ठ

33-34 . कहते हैं कि 'सही' शब्द में लगातार बदलाव हुए हैं

अर्थ और होहफेल्ड ने अपनी मौलिक कानूनी अवधारणाओं के रूप में लागू [1978] 2 एस. सी. आर.

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

120

'कानूनी तर्क' शब्द 'सही' शब्द के चार अलग-अलग अर्थ देता है।

एक सही स्ट्रिक्टो सेंसु है, दूसरा स्वतंत्रता है, तीसरा शक्ति है और

चौथा प्रतिरक्षा है। अपने सख्त अर्थों में 'अधिकार' को व्याज के रूप में परिभाषित किया गया है।

जिसकी कानून दूसरों पर संबंधित कर्तव्य लागू करके रक्षा करता है।

'स्वतंत्रता' दूसरे के अधिकार से छूट है और इसका सहसंबंध है

'नहीं-सही' और उसी तरह शक्ति 'कानूनी स्थिति को बदलने की क्षमता है।

दूसरे के संबंध और उसका सहसंबंध देयता है। इसी तरह, 'इम्मू'

'नीति' दूसरे की कानूनी शक्ति और सहसंबंध से छूट है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता अक्षमता है। उदाहरण के लिए, जहाँ एक सही स्ट्रिक्टो है

सेंसु ए में, बी में एक्स करने के लिए एक सहसंबंधी कर्तव्य है। इसी तरह, जहाँ ए को एक्स करने की स्वतंत्रता है, बी में हस्तक्षेप करने का एक सहसंबंधी नहीं-अधिकार है।

इस संबंध में। ए में शक्ति का सहसंबंध बी में देयता है

एक्स के संबंध में और इसी तरह, जहाँ ए में कानूनी से प्रतिरक्षा है

बी की शक्ति, इसका सहसंबंध एक्स के संबंध में बी में अक्षमता है। ये हैं

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त चार अलग-अलग न्यायिक संबंध और वे हैं सामान्य शब्द 'सही' के भीतर समझा जाता है। अब, वहाँ हो सकता है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'अधिकार' शब्द का उपयोग इस सामान्य में अनुच्छेद 131 में किया गया है।

भावना। यदि, उदाहरण के लिए, राज्य पूर्व में कानून बनाने का हकदार होने का दावा करता है

किसी विशेष मामले पर इस आधार पर कि वह सूची में आता है

संविधान और भारत संघ की सातवीं अनुसूची का द्वितीय

राज्य के इस अधिकार पर सवाल उठाते हुए, विवाद एक संबंधित होगा, न कि

पद के सख्त अर्थों में राज्य के किसी भी अधिकार के लिए, लेकिन

' राज्य की इस तरह के मामले पर कानून बनाने की स्वतंत्रता और यह आएगा

सीधे कला की शर्तों के भीतर। 131. यहाँ तक कि एक विवाद से संबंधित

भारत संघ की विधान सभा को समाप्त करने की शक्ति

इसे बताना या भंग करना

कला के दायरे और दायरे में आएगा।

131 जैसा कि चंद्रचूड़, जे., गुप्ता, जे. और मैं और

निहित रूप से बेग, सी. जे., राजस्थान राज्य में बनाम। भारत संघ।

इसलिए,

प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए क्या देखा जाना चाहिए

कला की। 131 क्या इसमें शामिल कोई संबंधपरक कानूनी मामला है

विवाद के पक्षकारों का अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति या प्रतिरक्षा। अगर

वहाँ है, सूट बनाए रखने योग्य होगा, लेकिन अन्यथा नहीं।

इस व्याख्या पर विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है

कला की। 131 क्या राज्य के बीच कोई विवाद है

कर्नाटक और भारत संघ ने एक

प्रश्न को शामिल करते हुए

'अधिकार' शब्द के सामान्य अर्थ के भीतर एक संबंधपरक कानूनी पैटर्न का विस्तार या विस्तार।

यह सच है कि यह कहना संभव नहीं है कि

मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ जांच आयोग का गठन करने में केंद्र सरकार की विवादित कार्रवाई के कारण

राज्य सरकार का गठन करने वाले मंत्री, राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करते हैं, लेकिन, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। 131, कि राज्य को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि उसके कुछ कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि राज्य एक व्यस्त निकाय या हस्तक्षेप करने वाले मध्यस्थ के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक अर्थों में इस तरह के जांच आयोग के गठन के लिए केंद्र सरकार की शक्ति पर सवाल उठाने में रुचि रखता है। यदि हम वाद में किए गए कथनों को देखें, और अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से हमें इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि कथन सही हैं, तो यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा किए गए दावे के अनुसार, केवल राज्य के विधानमंडल और राज्य सरकार के पास मुख्यमंत्री कर्नाटक वी. यूनियन (भगवती, जे.) द्वारा सरकारी शक्ति के दुरुपयोग की जांच और नियंत्रण करने की शक्ति है।

121

और राज्य और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों के पास इसकी जांच करने या जांच आयोग गठित करने की कोई शक्ति नहीं है।

उस उद्देश्य के लिए। राज्य का यह दावा स्पष्ट रूप से एक विवाद पैदा करता है

राज्य की शक्ति की सीमा और एक के अस्तित्व के रूप में

जांच करने के लिए केंद्र सरकार में श्रेष्ठ या समन्वय शक्ति

मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के आचरण में

उनके शासक ताल कार्यों के निर्वहन में। इस तरह का विवाद  
की सामग्री से संबंधित है और

राज्य की संबंधित शक्तियों

भारत संघ और दोनों संस्थाओं के बीच अंतर संबंध

और राज्य इसमें बहुत रुचि रखता है। राज्य बहुत है

इस बात से चिंतित है कि क्या इस में इसकी मंत्रिपरिषद का आचरण

सरकारी कार्यों के प्रभार की जांच केवल स्वयं ही की जा सकती है।

अपनी स्वयं की एजेंसी के माध्यम से या इसे जांच के अधीन भी किया जा सकता है

भारत संघ। राज्य को निश्चित रूप से यह कहने का अधिकार होगा कि भारत संघ को अपनी अनन्य शक्ति का अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है -

इसकी परिषद द्वारा सरकारी शक्ति के दुरुपयोग की जांच मंत्री। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इसकी मिनी परिषद के अलावा

राज्य भी सक्षम रूप से यह दावा कर सकता है कि इसकी ओर से कार्य करने वाले मंत्री सत्ता के अधीनता से मुक्त हैं।

केंद्र सरकार के मंत्रियों के रूप में उनके आचरण की जांच करने के लिए।

मंत्रिपरिषद के संबंध में दावा की गई यह प्रतिरक्षा हो सकती है राज्य से संबंधित है और यह निश्चित रूप से किसी विवाद को उठा सकता है

इस प्रतिरक्षा का अस्तित्व। जहाँ तक विवाद का दायरा है राष्ट्रमंडल और राष्ट्रमंडल के बीच संबंधित विधायी क्षेत्र

ऑस्ट्रेलिया में राज्यों का संबंध है, यह अब अच्छी तरह से बसा हुआ है

महान्यायवादी के निर्णय का परिणाम। विक्टोरिया वी।

राष्ट्रमंडल (1) कि किसी राज्य का महान्यायवादी

संघीय विधान की अयोग्यता की घोषणा के लिए मुकदमा कर सकते हैं

विधायी शक्ति के विशुद्ध रूप से राज्य क्षेत्र के आक्रमण के रूप में और

इसी तरह राष्ट्रमंडल का महान्यायवादी किसी राज्य पर मुकदमा कर सकता है। राज्य विधान की अयोग्यता की घोषणा प्राप्त करने के लिए

जहाँ यह सौंपी गई विधायी शक्ति का अतिक्रमण करता है राष्ट्रमंडल। ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने इस बात की ओर इशारा किया

मामला कि स्थिति को गोवन डफी द्वारा सही ढंग से संक्षेपित किया गया था,

सी. जे., इवेट और मी टियरन, जे. जे. अटॉर्नी में-विक्टोरिया बनाम के लिए जनरल।

राष्ट्रमंडल (2) निम्नलिखित शब्दों में: यह अब होना चाहिए  
 स्थापित के रूप में लिया गया है कि अटॉर्नी-राज्य के जनरल  
 के पास प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार है राष्ट्रमंडल  
 सामान्य की वैधता को चुनौती देने के उद्देश्य से संविधान  
 धन कानून जो राज्य तक फैला हुआ है और राज्य के भीतर संचालित होता है  
 जिनके हितों का वह प्रतिनिधित्व करता है। अब, यदि किसी राज्य के पास पर्याप्त अधिकार  
 संघ विधान की वैधता को इस आधार पर चुनौती दें कि यह  
 राज्य विधायी शक्ति के प्रयोग के साथ, यह एक का पालन करना चाहिए  
 कि राज्य के पास असंवैधानिक को चुनौती देने का अधिकार होगा  
 केंद्र सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग जो अतिक्रमण करता है  
 इसकी परिषद के संचालन के संबंध में इसका अनन्य क्षेत्र  
 मंत्री। राज्य को विवादित लोगों को चुनौती देने का भी अधिकार होगा।  
 केंद्र सरकार की कार्रवाई असंवैधानिक है, क्योंकि यह पूर्व  
 राज्य को मामलों की जांच करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है।  
 जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट हैं

( 1 ) 71 सी. एल. आर. 237

( 2 ) 52 सी. एल. आर 533

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के परंतुक (ए) के कारण। भारत संघ के खिलाफ राज्य द्वारा दायर किए गए मुकदमे को, इन परिस्थितियों में, निम्नानुसार माना जाना चाहिए -

अनुच्छेद 131 के तहत बनाए रखा जा सकता है।

हालाँकि, चूंकि मुकदमे में राज्य द्वारा किया गया दावा गुण-दोष के आधार पर टिकाऊ नहीं है, जैसा कि मेरे विद्वान भाई चंद्र 3 चुड ने अपने फैसले में बताया था, इसलिए मैं उनसे सहमत हूँ कि मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

खर्चों से वंचित।

जे. अंतवालिआ-हम सहमत हैं कि इस मुकदमे को लागत के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, हमें संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे की स्थिरता के संबंध में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद है। इसके बाद बताए गए कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मुकदमा विचारणीय नहीं है। हमने मुकदमे के अन्य मुद्दों पर भी संक्षेप में चर्चा की है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया है। आम तौर पर विद्वान मुख्य न्यायाधीश के प्रमुख निर्णय के साथ सम्मानपूर्वक सहमत होने के बावजूद, हम समझते हैं कि इसे जोड़ना उचित होगा।

हमारे सहमति पत्र के माध्यम से कुछ पृष्ठ।

इस मुकदमे में पहला मुद्दा है:

" क्या सूट रखरखाव योग्य है? "

हालाँकि इस मुद्दे का निर्णय अन्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है।

न्यायनिर्णयन के लिए तय किया गया, इसे अलग से भी निपटाया जा सकता है।

वास्तव में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत यह मुकदमा क्या दायर किया गया है? मुख्यमंत्री और कर्नाटक राज्य के कुछ अन्य मंत्रियों के प्रशासनिक कार्यों के संबंध में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के कुछ आरोप उस राज्य के कुछ विधायकों द्वारा लगाए गए थे। राज्य के 46 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन जिसमें आरोप हैं, केंद्र सरकार को भेजा गया था। इसके गृह मंत्री ने 26 अप्रैल, 1977 को अपने पत्र में मुख्यमंत्री से जानकारी देने का अनुरोध किया और उनकी टिप्पणियों में लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने 13 मई, 1977 के अपने उत्तर पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार के इस मामले में स्पष्टीकरण मांगने और कोई भी जांच करने के अधिकार को चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करना राज्य का अनन्य अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि

केंद्र सरकार द्वारा किसी भी जांच आयोग की नियुक्ति को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी प्रकार की जांच स्थापित करने के लिए 18 मई, 1977 को एक अधिसूचना जारी करने में जल्दबाजी की, हालांकि, संदर्भ में जांच विशेष रूप से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ किए गए कदाचार और कुशासन के विभिन्न आरोपों के संबंध में नहीं थी। अधिसूचना जारी की गई है।

आयोगों की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा

जांच अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 60) (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मीर इकबाल हुसैन को राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग का एकमात्र सदस्य नियुक्त किया गया था। पांच दिन

बाद में, 23 मई, 1977 को, केंद्र सरकार ने अपने

अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्ति, एक और आयोग नियुक्त किया गया एक एकल सदस्य से मिलकर, अर्थात्, श्री न्यायमूर्ति ए. एन. ग़ोवर, कर्नाटक बनाम संघ (उन्तवालिया, जे.)

123

भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिसूचना के अनुलग्नक 'I' और 'II' में निर्दिष्ट विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिए, हालांकि, कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले को मुख्य सचिवालय सं. डी. पी. ए. आर. 7 जी. ए. एन. 77, दिनांक 18 मई, 1977 "। इसके बाद कर्नाटक राज्य ने मुख्य रूप से दो आधारों पर कुछ राहतों का दावा करते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया (1) अधिनियम की उचित व्याख्या पर जांच आयोग का गठन करने के लिए राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है न कि केंद्र सरकार; और (2) वैकल्पिक रूप से अधिनियम के प्रावधान जहां तक वे केंद्र सरकार को विवादित अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत करते हैं, वे इसके विपरीत हैं।

संविधान का अधिकार। मुकदमे में पहला प्रतिवादी संघ है

भारत के श्री ए. एन. ग़ोवर दूसरे स्थान पर हैं। प्रतियोगिता द्वारा है

केवल पहला प्रतिवादी और इसके बाद इस निर्णय में यह होगा

प्रतिवादी के रूप में संदर्भित। सार और प्रभाव में दावा

प्रतिवादी यह है कि उसे आरोपित को जारी करने का कानूनी अधिकार मिला है।

अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे को मुख्य रूप से जमीन पर चुनौती दी गई है। कि  
वाद में विवाद की प्रकृति ऐसी है कि यह प्रभावित नहीं करता है

राज्य का कोई भी कानूनी अधिकार।

संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत, भारत राज्यों का एक संघ है। कर्नाटक राज्य भारत संघ की घटक इकाइयों में से एक है। राज्य की अवधारणा यह है कि यह अपने आप में एक आदर्श व्यक्ति है, एक कानूनी इकाई है। यह अमूर्त, अदृश्य और अपरिवर्तनीय है। शासन, एक अर्थ में, एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा को तैयार किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और निष्पादित किया जाता है। सामान्य खंड अधिनियम, 1917 में दोनों अभिव्यक्तियों को अलग-अलग परिभाषित किया गया है। एक ओर भारत संघ और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद के अस्तित्व के संबंध में, अनुच्छेद 131 में पूर्व के लिए उपयोग की गई अभिव्यक्ति भारत सरकार है, जिसका अर्थ है कि विवाद भारत सरकार के साथ हो सकता है, लेकिन विवाद का दूसरा पक्ष केवल राज्य होना चाहिए, न कि राज्य का कोई अंग-सरकार, विधानमंडल या न्यायपालिका। अनुच्छेद 300 भारत सरकार को किसी मुकदमे में भारत संघ के रूप में वर्णित करने और किसी राज्य की सरकार को राज्य के नाम पर मुकदमा करने या मुकदमा करने में सक्षम बनाने के लिए एक सक्षम प्रावधान है। यदि किसी राज्य के कानूनी अधिकार पर आक्रमण होता है तो जिस एजेंसी के माध्यम से कार्रवाई शुरू की जाएगी, वह राज्य सरकार हो सकती है। सरकार के अधिकार पर एक अतिक्रमण, कुछ संदर्भ स्थितियों में, राज्य के कानूनी अधिकार पर एक अतिक्रमण हो सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 300 केवल मुकदमे के पक्षकार का वर्णन करने का तरीका निर्धारित करता है। हालांकि, प्रबंधनीयता के सवाल का वास्तविक जवाब अनुच्छेद 131 के शब्दों से ही मिल सकता है। उक्त अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तें मौजूद होनी चाहिए:

( 1 ) विवाद भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होना चाहिए।

अधिक राज्य; और

1042 एससीआई/77 [1978] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

124

( 2 ) विवाद में कोई भी प्रश्न शामिल होना चाहिए कि क्या

कानून या तथ्य जिसका अस्तित्व या विस्तार  
कानूनी अधिकार निर्भर करता है।

इस संबंध में संबंधित से कुछ विचलन है

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 204 का प्रावधान, जिसे यहाँ इंगित करना आवश्यक नहीं है। विशिष्ट शब्दों में अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया है कि विवाद में शामिल प्रश्न किसके कानूनी अधिकार से संबंधित होना चाहिए और किस संबंध में। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस संबंध में राजस्थान और अन्य राज्यों के मामले में अपनी राय व्यक्त की है। वी. पेज 1396 पर भारत संघ (1) इस प्रकार है:

" यह पर्याप्त है ताकि इसके प्रावधान लागू हो सकें कि

वादी कानूनी या संवैधानिक अधिकार पर सवाल उठाता है

प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया, चाहे वह भारत सरकार हो

या कोई अन्य राज्य "।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपने प्रमुख निर्णय में इस प्रश्न का निर्णय नहीं किया। हममें से एक (जे. उन्तवालिया) सहित अन्य पाँच न्यायाधीशों ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। फिर भी, भगवती और गुप्ता जे. जे. उस मामले के तथ्यों पर अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य के कानूनी अधिकार, वादी का उल्लंघन किया गया था। योग्यता के आधार पर भी अन्य तीनों ने एक विपरीत विचार व्यक्त किया। यदि हम बहुत सम्मान के साथ ऐसा कह सकते हैं, तो हम न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। आम तौर पर और आम तौर पर, अनुच्छेद 131 के तहत एक सहित किसी भी मुकदमे में प्रतिस्पर्धा वादी और बचाव पक्ष के कानूनी अधिकार के बीच है। लेकिन मुख्य रूप से, और लगभग हमेशा, वादी को मुकदमे में सफल होने के लिए अपने कानूनी अधिकार को स्थापित करना पड़ता है। वादी के दावे के विपरीत, यदि प्रतिवादी का कानूनी अधिकार स्थापित हो जाता है, तो मुकदमा विफल होने के लिए बाध्य है। लेकिन दोनों में से कोई भी अपना कानूनी अधिकार स्थापित करने में विफल रहने पर, मुकदमा तब भी विफल रहेगा क्योंकि वादी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह

अपना कानूनी अधिकार स्थापित नहीं करता। कानून का यह प्रस्ताव इतना स्पष्ट और स्वयंसिद्ध है कि अनुच्छेद 131 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति-"कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार"-निस्संदेह इस परिणाम को लाने के लिए है। लेख में आगे यह बताना न तो आवश्यक था और न ही शायद उचित था कि विवाद में कोई भी प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर वादी का कानूनी अधिकार निर्भर होना चाहिए। यह आम अनुभव की बात है कि अक्सर एक पक्ष में कानूनी अधिकार की अनुपस्थिति दूसरे पक्ष को अपना कानूनी अधिकार स्थापित करने में मदद करती है। सही और इसके विपरीत।

राजा के मामले में-सम्राट बनाम। शिवनाथ बनर्जी और अन्य। ( 2 ) प्रभु।

थैंकर्टन ने पृष्ठ 266 पर कहा कि "एक मंत्री भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अर्थ के भीतर राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी होता है।" ए. संजीवी नायडू आदि के मामले में जे. हेगड़े ने भी यही विचार व्यक्त किया था। वी. मद्रास राज्य और ए. एन. आर. ( 3 ) संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में।

वर्तमान मामले में केंद्र सरकार द्वारा गठित जांच

यह राज्य या राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। यह मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ है जो राज्य के अधिकारी हैं।

( 1 ) ए. एल. आर. 1977 एस. सी. 1361.

( 2 ) 72 भारतीय अपील, 241.

( 3 ) [ 1970 ] 3 एस. सी. आर, 505.

कर्नाटक वी. यूनियन (उन्तवालिया, जे.)

125

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका जैसी उचित कार्यवाही में याचिका लेने के लिए उनके लिए यह खुला हो सकता है कि केंद्र सरकार की कार्यवाही अवैध और अधिकार से बाहर है। अनुच्छेद 131 ए के तहत (संविधान द्वारा प्रस्तुत)। 42 वां संशोधन), अधिनियम की धारा 3 के अधिकारों के प्रश्न को तब उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन यह किसी भी तरह से राज्य को अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार नहीं है। वादी की ओर से श्री लाल नारायण

सिन्हा द्वारा किया गया निवेदन-यह कहना कि विवादित अधिसूचना द्वारा राज्य के कानूनी अधिकार पर हमला किया गया है, सही नहीं है। वकील ने प्रस्तुत किया कि यह केवल राज्य का अधिकार है कि वह अपनी सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे अपने मंत्रियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 3 के तहत जांच का आदेश दे, कि केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है, कि उसने जांच के दायरे को बढ़ाने या स्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के संशोधन या बाद की अधिसूचना जारी करने के अधिकार में बाधा डाली है और इस प्रकार इसने राज्य के कानूनी अधिकार को प्रभावित किया है। हम इसमें कोई सार नहीं पाते हैं।

तर्क। एक प्राधिकरण और दूसरे की शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है, यहाँ इस मामले में केंद्रीय सरकार के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है।

और राज्य सरकार। लेकिन जब तक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है

केवल इसलिए कि ऐसा करना उसकी शक्ति के भीतर था, इसका कानूनी अधिकार है अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति के अवैध प्रयोग से प्रभावित होता है।

एक चित्रण द्वारा प्रस्ताव। मान लीजिए, केंद्र सरकार, प्रविष्टि के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसरण में

सूची II में, मान लीजिए, प्रविष्टि 8, मादक शराब से संबंधित, एक आदेश देती है

किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध। यह आदेश

स्पष्ट रूप से खराब होगा, जैसा कि एक अमान्य कानून के तहत जारी किया गया है

संसद द्वारा। इस आदेश को कौन चुनौती दे सकता है? जाहिर है कि आदेश से प्रभावित या व्यथित व्यक्ति। यदि आदेश नहीं है

राज्य या राज्य सरकार के कानूनी अधिकार को प्रभावित करना (के लिए

तर्क का परीक्षण करने का उद्देश्य, दोनों को बराबर किया जा सकता है), क्या

राज्य अनुच्छेद 131 के तहत केवल इसलिए मुकदमा दायर करता है क्योंकि आदेश दिया गया है

अतिक्रमण करने वाले कानून के अनुसार अपने निवासी के खिलाफ किया गया

राज्य के अनन्य विधायी क्षेत्र पर? जवाब में, हमारे

राय नकारात्मक होनी चाहिए। तत्काल मामले में अगर स्टैंड

सही में राज्य मंत्रियों की ओर से लिए गए गुणों पर, तो  
 विवादित अधिसूचना उनके कानूनी अधिकार पर आक्रमण है। वे कर सकते हैं।  
 राज्य सरकार की आदेश देने की शक्ति को सेवा में डालना  
 जांच करें और विवादित अधिसूचना को चुनौती दें, लेकिन उक्त अधिसूचना  
 इसे किसी भी तरह से राज्य को प्रभावित या बाधित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।  
 सरकार अपनी अधिसूचना को प्रभावी बनाने से।

कुछ मदद शब्द की परिभाषा से ली जा सकती है।

" खंड के पृष्ठ 856-57 पर दिया गया "बताएँ। 81 कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम।

इसमें कहा गया है:

" 'राज्य' शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, लेकिन जैसा कि इसमें उपयोग किया जाता है।

संघीय संविधान, कांग्रेस के अधिनियम, और राज्य कानून, [1978] 2 एस. सी.

आर.

126

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका एक निश्चित, निश्चित और निश्चित कानूनी अर्थ है

संघ के एक सदस्य को इसके विपरीत स्थापित करना

एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका

राज्य है

एक कानूनी इकाई, और मौलिक अधिकारों का हकदार है,

प्रत्येक कानूनी इकाई से संबंधित विशेषाधिकार और उन्मुक्ति।

यदि मुकदमे के दायरे को एक प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया जाना था जो अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया जा सकता है, बहुत विसंगत है, और कभी-कभी

इस तरह के परिणामस्वरूप सूट के बहुत व्यापक दायरे के लिए रेखा और एक पड़ाव एक व्याख्या। केंद्र सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई

अधिनियम के तहत या अन्यथा, किसी भी निवासी नागरिक के खिलाफ, या राज्य के अधिकारी को मुकदमा दायर करके चुनौती दी जा सकती है

कि राज्य अपने लोगों और अधिकारियों की रक्षा करने में रुचि रखता है जब उनके कानूनी अधिकार पर केंद्र सरकार द्वारा अवैध रूप से हमला किया गया है

और इसलिए, हमारी राय में, अनुच्छेद 131 को लागू करने का अधिकार है,

यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के लिए बहुत गलत है।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मंत्री राज्य का अधिकारी होता है। अ.

उसे प्रभावित करने वाला आदेश राज्य को मुकदमे का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 131। इसलिए वर्तमान मुकदमा, हमारी राय में, बनाए रखने योग्य नहीं है।

हालाँकि, हम इस आधार पर वादी पर मुकदमा न करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। अकेले, और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ें।

इस वाद में विचार के लिए बनाए गए अन्य दो मुद्दे इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित शर्तें हैं:

" 2. क्या विवादित अधिसूचना के अधिकार समाप्त हो गए हैं?

सेक के तहत केंद्र सरकार। 3 कॉम के

मिशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट?

3. यदि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 अधिकृत है

केंद्र सरकार ने विवादित को जारी करने के लिए उठाया अधिसूचना, क्या यह धारा स्वयं असंवैधानिक है?

इन दोनों मुद्दों को आसानी से एक साथ निपटाया जा सकता है।

श्री लाल नारायण सिन्हा द्वारा वादी के लिए अपनी सामान्य स्पष्टता और सटीकता के साथ कई दृष्टिकोणों का प्रचार किया गया था, लेकिन कभी-कभी, इसमें शामिल बिंदुओं की अंतर्निहित कठिनाइयों के कारण और मामला पहला प्रभाव होने के कारण, वह अपने तर्क के जुर्माने को बदलने और संशोधित करने के लिए बाध्य था। श्री सोली सोराबजी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

जनरल ने वादी की दलीलों का बहुत कुशलता से मुकाबला किया और

संक्षेप में। आखिरकार, वादी के हमले के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया:

1. हमारा संविधान स्पष्ट रूप से एक संघीय चरित्र का है

विधायी और निष्पादन को परिभाषित और विभाजित करना

केंद्र और राज्यों के महत्वपूर्ण कार्य और उनके

आपस में संबंध। के न्यायिक कार्य

न्यायपालिका एक अच्छी तरह से परिभाषित और सीमांकित है।

अलग डिब्बे।

कर्नाटक वी. यूनियन (उन्तवालिया, जे.)

1

संविधान द्वारा अनुमत सीमा के अलावा केंद्र विधायी पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है या

राज्य का कार्यकारी क्षेत्र।

यह अधिनियम केंद्र को राज्य के खिलाफ जांच आयोग गठित करने के लिए अधिकृत नहीं करता है और न ही कर सकता है। कार्यकारी; धारा 3 को इससे बचाने के लिए पढ़ा जाना चाहिए

संवैधानिक रूप से अमान्य होना।

यदि अधिनियम में पढ़ना संभव नहीं है

जिस तरह से यह सुझाव दिया गया है कि अधिनियम अब तक अमान्य है क्योंकि यह केंद्र को एक आयोग स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है

राज्य कार्यकारिणी के खिलाफ जांच।

. इस तरह का कानून केंद्रीय संसद की विधायी क्षमता से परे है और वास्तव में यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ का उल्लंघन करता है।

संविधान के कुछ प्रावधान, इसकी मूल योजना, या केंद्र-राज्य का मूल आधार

संविधान में निहित संबंध।

. उपरोक्त प्रभाव वाला कानून वास्तव में एक संवैधानिक कानून होगा जो संविधान में संशोधन लाएगा जो स्पष्ट रूप से अनुमेय नहीं है; एक साधारण कानून जब तक कि संविधान के प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, वह किसी भी तरह से संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है।

. यह अधिनियम केंद्रीय संसद की विधायी क्षमता से परे है यदि इसका अर्थ केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार या मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री के कार्यकारी कार्यों में पूछताछ करने के लिए किसी भी तंत्र को अधिकृत करना है।

सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से।

. कड़ाई से कहें तो प्रश्न में वर्तमान का विषय अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया जाता है यदि यह माना जाता है कि यह सूची I की प्रविष्टि 94, सूची III की प्रविष्टि 45 या अनुच्छेद 248 के साथ पठित सूची I की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है।

संविधान से।

. अंत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि दो जांचों का दायरा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। & दूसरा केंद्र सरकार द्वारा। कमोवेश एक ही हैं। जांच के लगभग सभी मामले खत्म हो चुके हैं और इसलिए, विवादित अधिसूचना उस कारण से भी खराब है। जहाँ तक संभव हो, चर्चा करने और संक्षेप में विचार करने के लिए आगे बढ़ें, लेकिन सख्ती से उस क्रम में नहीं जो हमने [1978] 2 एस. सी. आर. निर्धारित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कड़ाई से कहें तो हमारा संविधान संघीय चरित्र का नहीं है  
जहाँ अलग, स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों को कहा जा सकता है  
संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक राष्ट्र बनाने के लिए शामिल हुए या जैसा भी हो सकता  
है  
दुनिया के कुछ अन्य देशों में स्थिति हो। इसकी वजह यह है कि  
यही कारण है कि कभी-कभी इसे अर्ध-संघीय के रूप में चिह्नित किया गया है  
प्रकृति में। न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर अलग रखना।  
केंद्र और राज्यों के विधायी और कार्यकारी कार्य  
परिभाषित और वितरित किया गया है, लेकिन, फिर भी, इसके माध्यम से सभी एक चलता है  
दोनों क्षेत्रों में केंद्र के हाथों में समग्र धागा या लगाम। द.  
संसद के पास संबंधित मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है।  
सूची I में मूल्यांकन किया गया है। इसलिए राज्य विधानमंडल के पास विशेष विधायी है  
सूची II में विभिन्न प्रविष्टियों के संबंध में शक्ति। दोनों के पास कॉन है  
सूची III की प्रविष्टियों के संबंध में वर्तमान शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्ति  
केंद्रीय संसद। इसके संबंध में एक प्रमुख हाथ मिला है समवर्ती सूची में मामले  
जैसा कि अनुच्छेद 254 से स्पष्ट है। लेख  
249 संसद को किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है  
राज्य सूची में, राष्ट्रीय हित में। जब एक घोषणा  
आपातकाल लागू है जैसा कि अनुच्छेद 250, पार्लिया में प्रदान किया गया है  
में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति मिली है  
राज्य सूची। केंद्र द्वारा राज्य के विधायी क्षेत्र में कुछ अंतरराज्यीय है  
जैसा कि कुछ स्थितियों में अनुच्छेद 254 में प्रावधान किया गया है, राज्य के अधीन है  
राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित रखने का दायित्व और

कानून बनने से पहले उसकी सहमति प्राप्त करें।

" प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा।

बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति और यह सुनिश्चित करने के लिए कि

प्रत्येक राज्य की सरकार प्रो के अनुसार चलती है।

इस संविधान के दर्शन "। ( वीडियो आर्ट। 355, जोर दिया गया)। में।

राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में, प्रावधान है

अनुच्छेद 356 में केंद्र को विधायी कार्य करने के लिए बनाया गया था और

विभाजक शक्तियाँ लेकिन उच्च द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य शक्तियाँ नहीं

किसी राज्य को उस तरीके के बारे में निर्देश देने के लिए जिसमें अनुच्छेद में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है।

353. स्पष्ट कारणों से ऐसा कोई प्रो नहीं हो सकता था।

केंद्र के प्रशासन के संबंध में दृष्टिकोण।

केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध हैं -

भाग 11 के अध्याय 2 के प्रावधानों द्वारा शासित

संविधान। अनुच्छेद 256 में यह प्रावधान करते हुए कि "कार्यकारी शक्ति

प्रत्येक राज्य का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके

संसद द्वारा बनाए गए कानून और कोई भी मौजूदा कानून जो उस में लागू होते हैं

", यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसे आगे उसमें उत्कीर्ण किया गया है।

किसी राज्य को दिए गए निर्देश जो भारत सरकार को प्रतीत हों - यह उस उद्देश्य के लिए आवश्यक है। राज्यों पर संघ का नियंत्रण

कुछ मामलों में अनुच्छेद 257 में प्रावधान किया गया है। श्री सिन्हा की बात

द्वारा संविधान में प्रस्तुत अनुच्छेद 258 ए का उल्लेख किया गया है संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, उनके कर्नाटक बनाम संघ (उन्तवालिया, 1) को समर्थन देने के लिए।

129

तर्क। लेकिन, हमारी राय में, आग्रह किए गए बिंदु को मजबूत करने के बजाय, यह इसे कमजोर कर देता है क्योंकि उक्त अनुच्छेद प्रदान करता है:

" 258 ए. राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति

संघ। - संविधान में कुछ भी होने के बावजूद,

किसी राज्य का राज्यपाल, सरकार की सहमति से

भारत की ओर से, या तो सशर्त या बिना शर्त

कि सरकार या उसके अधिकारी इसके संबंध में कार्य करते हैं -

कोई भी मामला जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति पूर्व

प्रवृत्तियाँ "।

बेशक, किसी राज्य के राज्यपाल का मतलब राज्य सरकार या मंत्रिपरिषद से होगा और इसका उद्देश्य राज्यपाल को इस संबंध में अपने विवेक से कार्य करने के लिए अधिकृत करना नहीं है।

अब हम कुछ अन्य विशेषताओं और विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं

हमारा संविधान हमारे संघीय ढांचे के कमजोर चरित्र और कुछ मामलों में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण हाथ को प्रदर्शित करता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

और अपनी खुशी से पद धारण करता है। केवल कुछ मामलों में

उसे विवेकाधीन शक्ति मिली है लेकिन अन्य सभी में

राज्य प्रशासन उनके द्वारा या उनके नाम पर चलाया जाता है।

मंत्रियों द्वारा या उनकी सहायता और सलाह से। प्रत्येक

कार्रवाई, यहां तक कि एक व्यक्तिगत मंत्री की भी, कार्रवाई है।

पूरी परिषद की और के सिद्धांत द्वारा शासित है  
 संयुक्त और सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन राज्यपाल  
 वहाँ, राज्य के प्रमुख के रूप में, कार्यपालिका और  
 विधायिका, प्रशासन के बारे में केंद्र को रिपोर्ट करेगी  
 राज्य का राज्य।

## 2. संबंधित प्रावधान से विचलन करना

सातवीं अनुसूची संसद को अधिकार देती है कि -  
 "पूछताछ" के विषय पर कानून बनाएँ। . . . . पुर के लिए

सूची II में निर्दिष्ट किसी भी मामले की स्थिति "  
 सूची III और सूची I के अलावा, जैसा कि की प्रविष्टि 94 में उल्लेख किया गया है

उस सूची में। के संशोधन की घटक शक्ति

संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास है।  
 की आधी संख्या से सहमति प्रदान करना

कुछ मामलों में राज्य।

## 3. अनुच्छेद 2 संसद को कानून द्वारा स्वीकार करने का अधिकार देता है।

ऐसी शर्तों पर संघ में प्रवेश करना या नए राज्यों की स्थापना करना  
 और परिस्थितियाँ जो वह उचित समझती हैं।

## 4. संसद को अनुच्छेद 3 द्वारा भी अधिकार प्राप्त है कि वह

नए राज्यों के गठन और परिवर्तन के लिए कानून  
 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, नामों की सीमाएँ।

हमारे संघीय ढांचे की प्रकृति ऐसी है।

- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। भारत संघ (1) बहुमत में

बी. पी. सिन्हा, सी. जे. द्वारा दिया गया निर्णय, चरित्र और प्रकृति

( 1 ) [ 1964 ] 1 एस. सी. आर. 371.

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

130

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पृष्ठ 396 के बाद से हमारे संघीय ढांचे पर चर्चा की गई है।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने पृष्ठ 397 पर कहा कि हमारे संविधान में

संविधान की व्याख्या करने और संविधान का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई को अमान्य करने का न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकार पूरी तरह से लागू पाया जाना चाहिए। आवंटित क्षेत्रों में विधायी और कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कई प्रतिबंधों द्वारा किया जाता है, ताकि राज्यों की शक्तियां संघ के साथ समन्वय न कर सकें और कई मामलों में स्वतंत्र न हों। पृष्ठ 398 पर यह देखा गया है कि "राजनीतिक संप्रभुता भारत संघ और संघ के पक्ष में अधिक महत्व वाले राज्यों के बीच विभाजित है, जैसा कि हम वर्तमान में डी मॉन्स्ट्रेट करेंगे।"

यदि संविधान का कोई अनुच्छेद केंद्र को अनुमति देता है

राज्य के विधायी और कार्यपालिका क्षेत्र का अतिक्रमण करना, जैसा कि कुछ अनुच्छेदों में किया गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अतिक्रमण पूरी तरह से कानूनी और वैध है। हालाँकि, यदि कानून या उसके तहत की गई कार्रवाई संविधान के किसी भी प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए राज्य की कार्यकारी शक्ति पर अतिक्रमण करती है या, यह मानते हुए भी कि जैसा कि श्री सिन्हा ने तर्क दिया था, प्रो का उल्लंघन करती है।

आवश्यक निहितार्थ द्वारा संविधान के दृष्टिकोण, तो ऐसी विधि या उसके तहत की गई कार्रवाई अमान्य होगी। संविधान केंद्र को किसी भी मामले में इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता है।

लेकिन यह समझने के लिए कि क्या अधिनियम या कार्रवाई

केंद्र द्वारा उसकी धारा 3 के तहत लिया गया संविधान के खिलाफ या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, किसी को किए गए प्रावधानों की प्रकृति और विचाराधीन आयोग के दायरे और कार्यों की सराहना करनी होगी। संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार संसद की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। की कार्यकारी शक्ति के संबंध में स्थिति

राज्य समान है (क्रमशः अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 के अनुसार)। संघ सूची में प्रविष्टि 94 संसद को उस सूची के किसी भी मामले के उद्देश्य के लिए पृच्छताछ से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है, अर्थात्, यदि सूची I के किसी भी मामले के साथ किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की जांच आवश्यक है, तो संसद को उक्त जांच के उद्देश्य के लिए एक तंत्र या न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सूची II में ऐसा नहीं है ऐसी किसी भी प्रविष्टि को दर्ज करें। इसके बाद सूची III में प्रविष्टि 45 आती है जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यह केंद्रीय और राज्य दोनों विधानमंडलों को, निश्चित रूप से संविधान के अन्य प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 254 के अधीन, सूची II और सूची III में निर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रयोजनों के लिए जांच के तंत्र को प्रदान करने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। इस तरह से आयोजित किया गया है

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य। ( 1 ) जहां दास सी. जे. ने इस मामले पर स्पष्ट रूप से चर्चा की है, अगर हम पृष्ठों पर बहुत सम्मान के साथ ऐसा कहते हैं।

इस उद्देश्य के लिए कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधानमंडल को सशक्त बनाना।

सूची-2 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में जांच किसी भी अर्थ में ऐसे मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए सशक्त नहीं है। यह केवल इस संबंध में स्थापित की जाने वाली जांच के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से है।

( 1 ) [ 1959 ] एस. सी. आर 279

कर्नाटक वी. यूनियन (उन्तवालिया, जे.)

131

सूची-2 में उल्लिखित मामलों के बारे में। उद्देश्य विभिन्न राज्यों द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावित विधान के संबंध में नीतिगत विषय के रूप में हो सकता है या ऐसे मामलों के लिए प्रस्तावित उनकी कार्यकारी कार्यवाइयों के संबंध में हो सकता है। हम सूची II की प्रविष्टि 6 का उल्लेख करके अपने विचार को स्पष्ट कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के पास "सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पतालों और औषधालयों" पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है; निश्चित रूप से, उस राज्य के क्षेत्र के भीतर। निष्पादन शक्ति व्यापक होने के कारण, अस्पतालों की स्थापना की जा सकती है और राज्य सरकार द्वारा या तो उस संबंध में बनाए गए कानून के अनुसार या यहां तक कि कार्यकारी शक्ति के शुद्ध प्रयोग में डॉक्टरों की नियुक्ति की जा सकती

है। यदि राज्य सरकार की उक्त कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात या कुशासन हुआ है, तो समवर्ती सूची की प्रविष्टि 45 के तहत बनाया गया कानून निस्संदेह ऐसे मामलों में जांच को शामिल कर सकता है। वह भी नहीं।

राज्य की विधायी शक्ति और न ही इसकी कार्यकारी कार्रवाई में हस्तक्षेप करता है। एक नियुक्त आयोग द्वारा अधिनियम के तहत केवल एक जांच

इसके तहत जो एक तथ्य-खोज निकाय है, तथ्यों को खोजने के उद्देश्य से है। कोई भी निकाय अभियोजक नहीं है; कोई भी निकाय अभियुक्त नहीं है; आयोग द्वारा गठित जांच के दायरे में आवश्यक तथ्यों का पता लगाने में सहायता करने के लिए सभी को आमंत्रित और स्वागत किया जाता है।

पारित करते समय हम सातवीं में सूची I की प्रविष्टि 8 का भी उल्लेख कर सकते हैं।

संविधान की अनुसूची। यह "केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो" के संबंध में है। इसलिए केंद्रीय संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है और केंद्र सरकार केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो को किसी भी राज्य के किसी भी अधिकारी या मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति के मिशन और चूक के कृत्यों के संबंध में कोई भी जांच करने के लिए एक कार्यकारी आदेश दे सकती है। यदि ऐसा है तो क्या यह कहना उचित होगा कि अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को किसी राज्य के मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है? जाहिर है, नहीं।

वादी की ओर से यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा कोई नहीं है

न्यायपालिका के खिलाफ या तो अधीनस्थ या उच्चतर तथ्य-खोज जांच आयोग का गठन किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम के मामलों का संदर्भ दिया गया था। नृपेंद्र नाथ बागची, (1) और शमशेर सिंह और अनुर। वी. इस प्रस्ताव के समर्थन में पंजाब राज्य (2)। लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ अधिनियम के तहत जांच का बहिष्कार पूरी तरह से अलग सिद्धांतों पर आधारित है। जहाँ तक अधीनस्थ न्यायपालिका का संबंध है, इस प्रकार की जांच अनुच्छेद 235 की स्पष्ट भाषा के आधार पर अनुज्ञेय नहीं होगी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो मामलों और विभिन्न अन्य मामलों में व्याख्या की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ ऐसी जांच की स्थापना अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में निहित संवैधानिक प्रावधानों के कारण बाधित होगी। वास्तव में अनुच्छेद 124 के खंड (5) के अनुसार संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम 51) अधिनियमित किया है।

( 1 ) [ 1966 ] 1 एससीआर 771।

( 2 ) [ 1975 ] 1 एससीआर 841 ।

132

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1978 ] 2 एससीआर ।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, अधिनियम के तहत स्थापित एक जांच में कहा गया है कि

जाँच आयोग के समक्ष कोई अभियोजन नहीं है, कोई औपचारिक आरोप नहीं है, कोई अभियुक्त नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी पर्यवेक्षी या अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, और न ही राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य का कोई दुरुपयोग होता है। इस संबंध में निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया जा सकता है:

एम. वी. राजवाडे बनाम डॉ. एस. एम. हसन और अन्य; (1) ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ।

ज्योति नारायण (2) श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम । श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य (3) जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम । बख्शी गुलाम मोहम्मद; (1) पी. वी. जगन्नाथ राव और अन्य । वी. उड़ीसा राज्य और अन्य (3) और कृष्ण वल्लभ सहाय और अन्य । वी. जांच आयोग और अन्य । ( 6 ) हालाँकि, केंद्र को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए और होना चाहिए ।

किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री या राज्य के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यों को जानने और उनका पता लगाने में रुचि रखते हैं। राज्य सरकार ।

आइए अब हम इस मामले की थोड़ी और सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ें ।

श्री लाल नारायण सिन्हा के अन्य तर्कों का संदर्भ । अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न तो मंत्रिपरिषद और न ही कोई व्यक्तिगत मंत्री केंद्र सरकार के अनुशासनात्मक नियंत्रण में है, मंत्रियों के कथित कदाचार या कुशासन के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग का गठन, सार और प्रभाव में, उन पर अनुशासनात्मक नियंत्रण का अभ्यास है । उन्होंने आगे कहा कि राज्य विधानमंडल जिसके लिए मंत्री जिम्मेदार हैं, अनुच्छेद 194 में प्रदान की

गई शक्तियों और विशेषाधिकारों के अनुसार उनके खिलाफ जांच स्थापित करने के लिए सक्षम है। ऐसा हो सकता है। यह हो सकता है, जैसा कि श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया है,

कि न केवल राज्य विधानमंडल बल्कि राज्य सरकार स्वयं अपने या अपने मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच आयोग नियुक्त करने के लिए सक्षम है। लेकिन यह असंगत और अत्यधिक विसंगत लगता है कि राज्य सरकार अपने खिलाफ जांच शुरू करने के बारे में सोचेगी। यह सोचना भी उतना ही अजीब है कि मंत्रियों ने

शक्ति, कार्यालय में रहते हुए। के मामले में उनके कथित कुकर्मों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा

इसका

उद्देश्य

राज्य का प्रशासन। हम मान लेंगे कि

यहां तक कि

तर्क है कि कानूनी और तकनीकी रूप से स्थिति सही है।

तो, यह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचता है कि उनकी शक्ति अनन्य है और अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्ति को बाहर करती है?

हमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है कि

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में संशोधन। हालांकि तकनीकी रूप से और शाब्दिक रूप से मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

उनकी खुशी पर कार्यालय, वास्तव में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में

संसदीय लोकतंत्र, राज्यपाल अपने विवेक से नहीं कर सकते

( 2 ) [ 1955 ] 2 एस. सी.

आर. 955

( 1 ) [ आई. एल. आर.] 1954, नागपुर 1.

( 4 ) [ 1966 ] सर्पिल। एस

सी आर 401.

( 3 ) [ 1959 ] एस. सी. आर 279

( 6 ) [ 1969 ] 1 एस सी

आर 387.

( 5 ) [ 1968 ] 3 एस. सी. आर \* 789

कर्नाटक वी. यूनियन (उन्तवालिया, जे.)

133

स्वयं वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ एक जांच आयोग का गठन किया, और न ही राष्ट्रपति उन्हें ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं-भाग XVIII में आपातकालीन प्रावधानों के अलावा। फिर किस बात में किसी विशेष राज्य सरकार के मंत्रियों या अधिकारियों के कथित कुशासन के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच आयोग गठित करने की केंद्र सरकार की शक्ति शामिल नहीं है? तथ्यों का पता लगाने के बाद, संविधान या कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन निश्चित रूप से अधिनियम न तो किसी मंत्री को उसके खिलाफ कथित तथ्यों की सच्चाई का पता लगाने पर केंद्र द्वारा पद से हटाने या पेंशन को निलंबित करने जैसी किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान कर सकता है और न ही यह आपातकालीन अध्याय के प्रावधानों के अलावा। यदि यह अन्यथा होता तो निस्संदेह यह राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल की शक्ति का अतिक्रमण होगा। भारत समग्र रूप से एक ही देश है। राष्ट्र एक और अकेला है। जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को छोड़कर, कोई दोहरी नागरिकता नहीं है; कोई अलग राष्ट्रीयता नहीं है।

विवादित अधिसूचना पर हमला करते हुए श्री लाल नारायण सिन्हा

सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के वास्तविक महत्व और अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित बातें ए. एच. बिर्च द्वारा "प्रतिनिधि और जिम्मेदार सरकार" में इस विषय पर दिए गए विचार इस संबंध में उपयोगी पाए जाएंगे:

" संसद के प्रति मंत्रिस्तरीय जवाबदेही दो प्रकार की होती है -

मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी तय करता है

सरकार की नीतियां और उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

अपने विभागों के काम के लिए। प्रतिक्रिया के दोनों रूप योग्यता उन सम्मेलनों में सन्निहित है जो कानूनी रूप से नहीं हो सकते हैं। लागू किया गया। दोनों सम्मेलनों को नौ के दौरान विकसित किया गया था दसवीं शताब्दी, और दोनों मामलों में प्रथा स्थापित की गई थी इस सिद्धांत की घोषणा से पहले (पृष्ठ 131)।

टी. सी. हार्टले और जे. ए. सी. ग्रिफिथ द्वारा "सरकार और कानून" में, विधान-मंडल के प्रति मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी के संबंध में स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार बताई गई है:

" मंत्रियों को सामूहिक रूप से जिम्मेदार कहा जाता है। यह अक्सर लेखकों द्वारा एक 'सिद्धांत' के स्तर तक बढ़ाया जाता है लेकिन है वास्तव में एक राजनीतिक प्रथा से थोड़ा अधिक जो आम है स्थान और अपरिहार्य। आम तौर पर मंत्री शासन का गठन करते हैं। मानसिक दल, सभी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जा रहा है एक राजनीतिक दल। एक कैबिनेट मंत्री अपना काम खुद करता है। नीति का क्षेत्र और आम तौर पर इसके साथ बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है अन्य मंत्रियों का क्षेत्र। निश्चित रूप से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं सार्वजनिक बयान देने की संभावना होगी जो 134 को प्रभावित करती है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

किसी अन्य मंत्री के विभाग के काम पर। कुछ पर महत्वपूर्ण मुद्दे, नीति कैबिनेट द्वारा निर्धारित की जाती है

चर्चा करें। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिमंडल निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों को बाध्य करते हैं, भले ही वे तर्क देते हों मंत्रिमंडल में विपरीत दिशा। लेकिन इसका मतलब है नहीं। एक कैबिनेट मंत्री से अधिक जो खुद को अल्पमत में पाता है या तो बहुमत के विचार को स्वीकार करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। टीम ने इसे इसके कुछ सदस्यों द्वारा स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से कि वे सरकार की नीति को अस्वीकार करते हैं। और स्पष्ट रूप से कैबिनेट मंत्रियों के लिए जो सच है वह समान है अन्य मंत्रियों के लिए अधिक सही। अगर उन्हें क्या पसंद नहीं है टीम कर रही है, उन्हें या तो चुप रहना चाहिए या चले जाना चाहिए "(पृष्ठ 60) .

मिनिस परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी से निपटना राज्य की विधानसभा में, सरकार सी. जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए पृष्ठ 405 पर जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम में कहा। बख्शी गुलाम मोहम्मद (1):

" धारा 37 मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी की बात करती है।

विधान सभा तक। इसका मतलब केवल यह है कि

मंत्रिपरिषद को एक साथ खड़ा होना होगा या गिरना होगा, हर सदस्य किसी अन्य की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होना।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि सामूहिकता का सिद्धांत

जिस जिम्मेदारी पर श्री लाल नारायण सिन्हा का इतना अधिक झुकाव है, वह राज्य के मंत्रियों को जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होने से छूट नहीं देता है और वादी इससे कोई मदद नहीं ले सकता है।

यदि अधिनियम वास्तव में एक संवैधानिक कानून है जैसा कि समझा और समझाया गया है

प्रख्यात विद्वानों द्वारा, निश्चित रूप से संसद ने इस तरह के कानून को लागू करने में अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। यह स्वयंसिद्ध है कि संविधान के संशोधन की अनुमति अनुच्छेद

368 में दिए गए प्रावधान के अलावा नहीं दी जा सकती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवादों के उदाहरण

बहुत कम हैं। न्यायमूर्ति वांचू द्वारा दिए गए ऐसे कई उदाहरण, जैसा कि वे उस समय गोलक नाथ (2) मामले में पृष्ठ 827 पर दिए गए थे, यदि हम बहुत सम्मान के साथ ऐसा कह सकते हैं, तो काफी सटीक नहीं हैं। संबंधित सूचियों में से किसी भी प्रविष्टि के तहत किसी विशेष विधानमंडल को दी गई शक्तियां

सातवीं अनुसूची या संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद द्वारा एक ही प्रकार और गुणवत्ता के होते हैं; उदाहरण के लिए, जब अनुच्छेद 10,59 (3) और 65 (3) संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून के बारे में बात करते हैं तो यह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। शक्ति एक साधारण विधायी शक्ति है। लेकिन न्यायमूर्ति वांचू द्वारा दी गई सूची में कुछ आरती क्लेस हैं, जो संसद को एक साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा संविधान के एक विशेष प्रावधान में संशोधन करने के लिए सार और प्रभावी रूप से सशक्त बनाते हैं और यह कहने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता होती है कि उपरोक्त कोई भी कानून ऐसा नहीं करेगा।

( 1 ) [ 1966 ] पूरक। एस सी आर 401.

जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 37 अनुच्छेद के अनुरूप है।

164 भारत का संविधान।

( 2 ) [ 1967 ] 2 एस. सी. आर. 762

कर्नाटक वी. यूनियन (उन्तवालिया, जे.)

135

अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 4 (2) और 169 (3)। यद्यपि अनुच्छेद 4 के खंड (1) और अनुच्छेद 169 के खंड (1) और (2) के तहत बनाई गई विधि संविधान के संशोधन के समान होगी, तथापि उक्त अनुच्छेदों के कानूनी काल्पनिक खंड (2) और (3) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी विधि को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं होगा।

हुड फिलिप्स के संवैधानिक कानून से एक उद्धरण दिया गया था

श्री सिन्हा का कहना है:

" राज्य का संवैधानिक कानून इन से संबंधित कानून है -  
 उस राज्य का संविधान (पृष्ठ 1)। ए का संविधान  
 राज्य कानूनों, रीति-रिवाजों और परंपराओं की प्रणाली है जो  
 राज्य के अंगों की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करना और  
 विभिन्न राज्य अंगों के संबंधों को एक के साथ विनियमित करना  
 एक और और निजी नागरिक के लिए "। ( पी। 4)

उद्धरणों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। किसी भी मायने में नहीं

अवैध कानून एक संवैधानिक कानून है।

श्री सिन्हा ने यह भी तर्क दिया कि एक सामान्य कानून इसके खिलाफ नहीं जा सकता है

केंद्र-राज्य की मूल योजना या मूल आधार

संविधान में निहित संबंध। उन्होंने अपना तर्क रखा यह सम्मान बहुत ही  
 सरल तरीके से किया गया क्योंकि उन्हें काम करने में कठिनाई महसूस हुई।

संविधान की मूल संरचना। श्रीमती के मामले में। इंदिरा नेहरू गांधी  
 बनाम. श्री राज नारायण (1) ऐसा तर्क स्पष्ट रूप से

इस अदालत ने खारिज कर दिया। हम किसी अंश का उल्लेख करके विषय-वस्तु पर विराम  
 लगा सकते हैं।

हमारे विद्वान भाई जे. चंद्रचूड़ के निर्णय से, पृष्ठों पर

669-670 जो इस प्रकार चलता है:

" संवैधानिक संशोधन, के अनुपात पर हो सकता है

मौलिक अधिकारों के मामले का मूल आधार पर परीक्षण किया जाए

संरचना। लेकिन इस सिद्धांत के अलावा कि एक मामला केवल है

एक प्राधिकरण जो यह तय करता है, वह तार्किक रूप से पालन नहीं करता है  
 मौलिक अधिकार मामले में बहुमत के फैसले से

कि साधारण विधान को भी उसी परीक्षण का उत्तर देना चाहिए

उनकी वैधता के लिए दो परीक्षण: ( 1 ) कानून के दायरे में होना चाहिए  
विधायिका की परिभाषित और विशिष्ट विधायी क्षमता

संविधान के अध्याय I, भाग XI में लिखा गया है और (2) यह आवश्यक है कि

अनुच्छेद 13 (1) और (2) के प्रावधानों के खिलाफ अपराध नहीं

संविधान का '। बुनियादी संरचना ', बहुमत के निर्णय से।

यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है और न ही वास्तव में  
संविधान का प्रावधान। बुनियादी संरचना का सिद्धांत

प्रकृति संविधान के परिप्रेक्ष्य से बुनी गई है और

संशोधन करने की शक्ति इसके अधीन है क्योंकि यह एक स्थायी है।

ट्यून्ट पावर। मौलिक संशोधन करने की शक्ति

यंत्र अपने साथ उसे नष्ट करने की शक्ति नहीं ले जा सकता है।

आवश्यक विशेषताएँ '-यह, संक्षेप में, सिद्धांत का कमान है।

( 1 ) [ 1976 ] 2 एस. सी. आर. 347

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1978 ] 2 एस सी आर।

136

बुनियादी संरचना। यह मामलों में पूरी तरह से अनुचित है।

के अधीन बनाए गए साधारण कानूनों की वैधता से संबंधित

संविधान "।

"निहित निषेध" का सिद्धांत, जिस पर श्री सिन्हा ने भरोसा किया,

इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में अदालतों द्वारा बार-बार खारिज किया गया है और इस न्यायालय द्वारा। ऐसे मामलों का एक वास्तविक रोल कॉल है। हम केवल कुछ का उल्लेख हो सकता है: वेब और आउट्रिम, (1) द अमल में अनुसरण किया गया गेमेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स और द एडिलेड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड और अन्य (2) जिसमें पृष्ठ 150 पर यह कहा गया है:

" पूर्ववर्ती के खिलाफ "निहित निषेध" का सिद्धांत

एक बार सामान्य के अनुसार निर्धारित की गई शक्ति का आकार निर्माण के नियम, निश्चित रूप से प्रिवी द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे वेब बनाम में परिषद। आउट्रिम, (1907) ए. सी., 81 "।

द स्टेट ऑफ विक्टोरिया और द कॉम का भी संदर्भ दिया जा सकता है।

पवित्रता केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य, (\*) जिसे मौलिक अधिकारों के मामले के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ उल्लेख कर सकते हैं जे. पालेकर, पृष्ठ 608 पर, जे. द्विवेदी, पृष्ठ 916 पर और जे. चंद्रचूड़, पृष्ठ 977 पर। एक ही प्रभाव के लिए दृश्य है

राय जे. द्वारा व्यक्त किया गया, जैसा कि वे तब थे, खन्ना जे. और अन्य। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 45 के तहत केंद्रीय विधानमंडल को दी गई शक्ति सूची II के किसी भी मामले के संबंध में जांच का कानून पारित करने के लिए स्पष्ट और स्पष्ट है। ऐसा होने पर, "निहित निषेध" के सिद्धांत पर शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इस मामले में इस सिद्धांत को लागू करने का आधार भी व्यर्थ में खोजना पड़ा।

वाइन्स ने अपनी पुस्तक "लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशियल पॉवर्स इन ऑस्ट्रेलिया, "चौथे संस्करण ने पृष्ठ 12 और 13 में कहा है:

" एकमात्र तरीका जिसमें न्यायालय निर्धारित कर सकता था

क्या विधायी शक्ति की निर्धारित सीमाएँ थीं

प्रशिक्षक की शर्तों को देखकर या नहीं किया गया था

जिसके द्वारा, सकारात्मक रूप से, विधायी शक्तियाँ थीं

बनाया गया, और जिसके द्वारा नकारात्मक रूप से, वे प्रतिबंधित हैं।

" राष्ट्रमंडल राज्य संबंधों पर इंजीनियरों के मामले के प्रभावों पर अध्याय में विचार किया गया है। IX. क्या महत्वपूर्ण है?

वर्तमान उद्देश्यों के लिए वहाँ व्याख्या के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और तब से उन पर कार्य किया जा रहा है। आपसी हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों और राज्य द्वारा आरक्षित शक्तियों की अस्वीकृति का संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

( 1 ) ( 1907 ) ए. सी. 81

( 2 ) 28 राष्ट्रमंडल विधि रिपोर्ट, 129। ( 3 ) 122 राष्ट्रमंडल कानून रिपोर्ट 353।

( 4 ) [ 1973 ] पूरक। एस. सी. आर. 1

कर्नाटक बनाम। यूनियन (उन्तवालिया, जे.)

137

अनिवार्य रूप से प्रोफेसर सॉवर के रूप में वर्णित करने के लिए अग्रणी संघीय शक्तियों की एक "विस्तृत" व्याख्या। इसके लिए इस सिद्धांत का पालन किया कि डोमिनियन और औपनिवेशिक विधायी शक्तियाँ पूर्ण हैं (एक सिद्धांत जिससे उच्च न्यायालय कभी विचलित नहीं हुआ) और एक व्याख्या बिना किसी परवाह के शक्ति के विशिष्ट अनुदानों को पूरी तरह से पढ़ा जाता है। सभी गैर-निर्दिष्ट शक्तियों के आरक्षण के लिए, कि संविधान में ही उन पर निहित निहितार्थ द्वारा। और राष्ट्रमंडल की सर्वोच्चता के लिए स्पष्ट प्रावधान संघर्ष की स्थिति में राज्य के कानूनों ने प्रक्रिया को पूरा किया; जैसे डिक्सन सी. जे. ने 1947 में टिप्पणी की, राष्ट्रमंडल बाध्य है।

बेहतर स्थिति में होने के लिए, क्योंकि यह एक सरकार है  
गिनाई गई शक्तियाँ "। 99

हमारी राय में इसे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है।

अधिनियम के प्रावधान, अर्थात् धारा 2 और 3, और न ही उक्त प्रावधान किसी भी कारण से  
संवैधानिक रूप से अमान्य हैं।

हमारे लिए किसी भी विवरण पर चर्चा करना या उससे निपटना आवश्यक नहीं है।

वादी की ओर से अंतिम निवेदन। केंद्र द्वारा नियुक्त जांच आयोग से बचने के लिए यह एक क्षीण,  
कमजोर और संकोचपूर्ण तर्क था। दुर्भावना के आधार, कुछ हद तक अस्पष्ट और

वाद में अस्पष्ट रूप से आरोपित, मुकदमे की सुनवाई के समय दबाया नहीं जा सकता था और न  
ही किया जा सकता था। हालाँकि, हमारे लिए क्या तर्क दिया गया था

विचार यह था कि दो पूछताछ-एक राज्य द्वारा स्थापित की गई थी

केंद्र द्वारा पहले और बाद में नियुक्त किए गए लोग लगभग एक हैं। और वही; उन्हें  
साथ-साथ जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि

तथ्य यह है कि केंद्र द्वारा नियुक्त जांच आयोग है

जनता के निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से

अधिनियम की धारा 3 (1) के अर्थ के भीतर महत्व नहीं हो सका

हो और विवादित नहीं था। बहस का एकमात्र बिंदु यह था कि क्या

उसी मामले में जिसके लिए पहले ही एक आयोग का गठन किया जा चुका था राज्य  
सरकार द्वारा धारा 3 (1) के परंतुक (बी) का उल्लंघन है।

लेकिन इस तर्क में कोई सार नहीं है। सबसे पहले, अधिसूचना

राज्य सरकार ने किसी भी आयोग की नियुक्ति नहीं की है।

कथित भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात के मामलों की जांच के लिए  
हठधर्मिता और दुर्भावना-मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री का प्रशासन

कर्नाटक सरकार। खंडों में निर्दिष्ट मर्दाने

( I ) से (XXXII) को "की गई अनियमितताएँ या अधिकता" कहा जाता है।

अनुबंधों, भूमि अनुदान से संबंधित कुछ मामलों में किए गए भुगतान,  
स्थल का आवंटन, फर्नीचर की खरीद, खाद्यान्नों का निपटान आदि।

"

उन खंडों में से किसी में भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किसे उत्तरदाता कहा जाता है  
कथित अनियमितताओं या कुशासन के लिए दोषी ठहराया गया। वहाँ कोई नहीं है  
किसी भी कथित कदाचार, भ्रष्टाचार या कुशासन का संदर्भ  
मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री का। अंतिम खंड  
( XXXIII) बहुत अस्पष्ट और सुविधाजनक रूप से शब्दबद्ध है। इसमें कहा गया है

" चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं, यदि कोई हो,  
उपरोक्त के संबंध में और किस हद तक? "

138

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1978 ] 2 एस. सी. आर

केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में संदर्भ की शर्तें हैं -

अनुलग्नक I में उल्लिखित विशिष्ट मामलों की जांच करें, जिनमें से कोई भी नहीं  
जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा कवर किया गया है

उदाहरण के लिए, अनुलग्नक I की मद 1 इस प्रकार है:

" क्या मुख्यमंत्री पक्षपात का अभ्यास करते थे और  
अपने ही भाई श्री डी. कोम्पराज को नियुक्त करके भाई-भतीजावाद  
उर्स, कर्नाटक राज्य फिल्म उद्योग के निदेशक के रूप में

श्री आर. जे. रेबेलो के स्थान पर विकास निगम,  
1974 में सरकार के चीफ सचिव, और बाद में

सभी शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियों के साथ प्रभारी निदेशक  
प्रबंध निदेशक "।

अनुलग्नक II में विशिष्ट मामलों के संबंध में पाया जा सकता है कुछ सामान्य  
मामले जो विषय हैं-द्वारा जांच का विषय

राज्य सरकार लेकिन फिर, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं,

अनुलग्नक II के मामलों के लिए अधिसूचना में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है

कर्नाटक सरकार की अधिसूचना द्वारा कवर किया गया कोई भी मामला दिनांक 18  
मई, 1977। इसलिए, ग्रोवर आयोग होगा

ऐसे मामलों को अपनी जांच के दायरे से बाहर करने के लिए सक्षम।

कैलेसाम, जे.-यह मुकदमा कर्नाटक राज्य द्वारा दायर किया गया है।

भारत सरकार के सचिव के माध्यम से भारत संघ,

और श्री ए. एन. ग्रोवर, आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग

भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और सरकारी शक्ति का दुरुपयोग कर्नाटक राज्य  
के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत। राहत के लिए प्रार्थना की गई

सूट में हैं:

( क ) यह घोषणा करने के लिए कि अधिसूचना सं. सो. सं. 365 (ई) दिनांकित

23 मई, 1977 में जांच आयोग का गठन

आयोग की धारा 3 के तहत शक्तियों का कथित प्रयोग  
जांच अधिनियम के मिशन अवैध, अधिकार से बाहर; और अनुचित

शीर्षक और कानून द्वारा अधिकृत नहीं;

( ख ) यह घोषणा करना कि आयोगों के प्रावधान

जाँच अधिनियम, 1952 केंद्रीय सरकार को अधिकृत नहीं करता है।

के संबंध में एक जांच आयोग का गठन करने के लिए

विशेष रूप से राज्य के दायरे में आने वाले मामले

विधायी और कार्यकारी शक्ति; या

( ग ) वैकल्पिक रूप से, आयोग के उक्त प्रावधानों की घोषणा करें।

जांच अधिनियम के मिशन दोनों शर्तों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं

संविधान के साथ-साथ संघीय संरचना निहित और

संविधान की अलंघनीय मूल विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया;

( घ ) उत्तरदाताओं को रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए

अधिसूचना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना या कोई और कदम उठाना।

फिकेशन नं. एस. ओ. सं. 365 (ई) दिनांक 23 मई, 1977।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं: केंद्रीय गृह मंत्री

26 अप्रैल, 1977 को कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिसमें विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है।

कर्नाटक राज्य विधानमंडल में पार्टी ने उस पर उनकी टिप्पणी मांगी।

टी

कर्नाटक वी. यूनियन (कैलासम, जे.)

कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने 13 मई, 1977 को केंद्रीय गृह मंत्री को विभिन्न आरोपों और आरोपों का जवाब दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी राज्य की शक्तियों पर सवाल उठाए

केंद्र सरकार राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगेगी। 18 मई, 1977 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट विभिन्न आरोपों और अनियमितताओं की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1) के तहत एक जांच आयोग नियुक्त

किया। मुख्यमंत्री ने 18 मई, 1977 को केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र भी लिखा था जिसमें आयोग की नियुक्ति की जानकारी दी गई थी। 23 मई, 1977 को एक अधिसूचना द्वारा भारत संघ ने आरोपों की जांच के उद्देश्य से एक और जांच आयोग नियुक्त किया। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात और सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग।

इस मुकदमे में धारा 3 (1) के तहत जांच आयोग के गठन में केंद्र सरकार की कार्रवाई को अवैध, अधिकार से परे और असंवैधानिक के रूप में चुनौती दी गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि केंद्र सरकार के पास जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच आयोग का गठन करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है। वादी ने तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना संविधान के संघीय ढांचे और शक्तियों के वितरण की योजना के लिए विनाशकारी है कि संविधान राज्य सरकार या उसके मंत्रियों पर केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा कोई पर्यवेक्षी या अनुशासनात्मक नियंत्रण प्रदान नहीं करता है और संविधान केंद्रीय सरकार को संबंधित क्षेत्रों के भीतर राज्य सरकारों के कामकाज पर किसी भी सामान्य पर्यवेक्षी या जांच शक्ति के साथ निहित नहीं करता है। चूंकि विवादग्रस्त मामला राज्य के कानूनी अधिकार को प्रभावित करता है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में बनाए रखा जा सकता है।

प्रथम प्रतिवादी, भारत संघ की ओर से, यह प्रतिवाद किया गया था कि कर्नाटक राज्य का मुकदमा उतना विचारणीय नहीं है जितना कि 23 मई, 1977 की आक्षेपित अधिसूचना वादी राज्य को प्रभावित नहीं करती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ जांच व्यक्तियों के खिलाफ है न कि कर्नाटक राज्य के खिलाफ भारत सरकार और राज्य के बीच कोई विवाद नहीं होने के कारण, एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि यह मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुख्य रूप से मान्य नहीं था। वादी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित अधिसूचना केंद्र की शक्तियों के भीतर थी।

सरकार और यह कि राज्य के कार्यकारी कार्यों में कोई उल्लंघन या हस्तक्षेप नहीं हुआ था।

दलीलों पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे: 1. क्या सूट रखरखाव योग्य है?

2. क्या विवादित अधिसूचना आयोगों की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों से परे है। जांच अधिनियम?

3. यदि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को विवादित अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत करती है, तो क्या यह धारा स्वयं असंवैधानिक है?

10-1042 एससीआई/77 [1978] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

140

मुकदमे में शामिल मुख्य प्रश्न केंद्र-राज्य संबंध का है। संबंध और क्या विवादित अधिसूचना की शक्तियों के भीतर है जांच आयोग की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार एक्ट करें। हालाँकि शिकायत में कुछ आरोप लगाए गए हैं कि विवादित आदेश दुर्भावनापूर्ण था जिसे बहस के दौरान नहीं दबाया गया था। तो भी राज्य सरकार की एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति वे कारण जिन्होंने राज्य सरकार को एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया पूछताछ का सिलसिला। विभिन्न विवादों से निपटने से पहले राज्य और केंद्र सरकार की ओर से वकील की आवश्यकता है की पृष्ठभूमि और प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए केंद्र-राज्य संबंधों और दायरे से संबंधित संविधान जांच आयोग अधिनियम, 1952।

ब्रिटिश क्राउन ने पूर्व से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की।

1858 में इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद ने पहला अधिनियम लागू किया।

भारत शासन अधिनियम, 1858 (21 और 22 विक्ट।, 106)।

इस अधिनियम ने बिना किसी लोकप्रिय पार्टी के पूर्ण शाही नियंत्रण प्रदान किया।  
 देश के प्रशासन में गोपनीयता की शक्तियाँ  
 क्राउन का प्रयोग भारत के राज्य सचिव द्वारा किया गया था जिसकी सहायता से  
 सदस्यों की एक परिषद। तत्पश्चात् भारतीय परिषद अधिनियम, 1861,  
 1892 और 1909 पारित किए गए। बाद में भारत सरकार के अधिनियम 1912  
 और 1915 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था।

भारत सरकार अधिनियम, 1919, द्वारा उठाया गया पहला कदम था

भारतीयों के संगठन को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार प्रशासन की हर शाखा  
 और स्वयं का क्रमिक विकास

आर. एस. की प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से शासी संस्थान  
 ब्रिटिश भारत में जिम्मेदार सरकार। भारत सरकार अधिनियम,  
 1919 प्रांतों में पहली बार राजतंत्र की शुरुआत की गई। द सेन  
 त्राल विषयों को विशेष रूप से केंद्रीय के नियंत्रण में रखा गया था  
 सरकार। प्रांतीय विषयों को 'स्थानांतरित' में विभाजित किया गया था। और  
 'आरक्षित' विषय। स्थानांतरित विषयों को प्रशासित किया गया था  
 राज्यपाल ने मंत्रियों की सहायता से जबकि आरक्षित विषय थे राज्यपाल और उनकी  
 कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित

विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अधीन बनाए गए हस्तांतरण नियमों द्वारा  
 भारत सरकार अधिनियम, 1919 के विषयों का पृथक्करण  
 मध्य और प्रांतीय में प्रशासन बनाया गया था। कुछ हद तक  
 प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण के संबंध में ढील दी गई थी। के तहत  
 1919 के अधिनियम में प्रांत केंद्र के प्रतिनिधि थे और केंद्रीय विधायिका ने पूरे  
 भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति बरकरार रखी।

किसी भी विषय से संबंधित। भारत सरकार का पारित होना

एक्ट करें। 1935 पहली बार से एक बदलाव के लिए पेश किया गया सरकार अर्थात् सरकार जो सरकार के अधीन एकात्मक थी भारत अधिनियम, 1919 ने प्रांतों के साथ एक संघ का मार्ग प्रशस्त किया और भारतीय राज्य इकाइयों के रूप में। एकात्मक प्रणाली के तहत प्रो विनस प्रशासनिक के साथ-साथ विधायी नियंत्रण में थे। केंद्र सरकार की। गवर्नर-जनरल इन काउंसिल थे पूरे संवैधानिक भवन की आधारशिला और ब्रिटिश संसद ने राज्य सचिव के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और गवर्नर-परिषद में जनरल।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 का उद्देश्य एकजुट होना था। प्रांतों और भारतीय राज्यों को क्राउन के तहत एक संघ में।

कर्नाटक बनाम। यूनियन (कैलासम, जे.)

141

एकात्मक राज्य को कई स्वायत्त निकायों में विभाजित किया जाना था जो केंद्र सरकार के बजाय सीधे क्राउन से अपना अधिकार प्राप्त करते थे और फिर उन्हें एक संघीय ढांचे के रूप में तैयार करते थे जिसमें संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारें सीधे क्राउन से शक्तियां प्राप्त करती थीं। परिवर्तन का आधार ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में या उन पर सभी अधिकार, अधिकार और न्यायशास्त्र क्राउन के हाथों में फिर से शुरू करना और केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों का पुनर्वितरण है। हालांकि सरकार के तहत विचार की गई संघीय संरचना

में से

राज्यों

भारत अधिनियम, 1935 अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि भारतीय ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जहां तक प्रांतों का संबंध है, यह प्रभावी हुआ। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया और इसके परिभाषित क्षेत्र के भीतर, प्रांत अब केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि प्रशासन की स्वायत्त इकाइयाँ थीं। भारत सरकार ने संघीय सरकार की भूमिका निभाई। प्रांतीय सरकारों के संबंध में प्रांतों के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग राज्यपाल द्वारा क्राउन की ओर से किया जाता था, न कि गवर्नर-जनरल के अधीनस्थ के रूप में, विधानमंडल के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह के साथ। केंद्र में कार्यकारी अधिकार गवर्नर जनरल के पास निहित था और पुनः सेवा प्राप्त विषयों, रक्षा, विदेश मामलों आदि के संबंध में, गवर्नर जनरल को अपने विवेक से कार्य करना था, उनके द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद से, विधायिका के प्रति उत्तरदायी हुए बिना। गवर्नर-जनरल को आरक्षित विषयों के अलावा अन्य विषयों के संबंध में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करना था। गवर्नर जनरल को अपनी विशेष जिम्मेदारियों के संबंध में राज्य सचिव के नियंत्रण और निर्देशों के तहत कार्य करना था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय विधानमंडल और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण करते हुए (i) संघीय सूची जिस पर संघीय विधानमंडल को कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ थीं; (ii) एक प्रांतीय सूची जिस पर प्रांतीय विधानमंडल को विशेष अधिकार क्षेत्र था; और (iii) एक समवर्ती सूची जिस पर संघीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों की क्षमता थी।

द.

संघीय कानून एक प्रांतीय कानून पर हावी था यदि 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल के पास कोई प्रतिनिधि और कानून की अवशिष्ट शक्ति थी। इस योजना के तहत, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं की विधायी शक्तियाँ विभिन्न सीमाओं के अधीन थीं और उनमें से कोई भी संप्रभु विधायिका नहीं थी। 1935 के अधिनियम की एक अन्य विशेषता यह थी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी

मुख्य रूप से इकाइयों और संघ के बीच विवादों का निर्धारण करने के लिए। संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों के रूप में विधायी शक्तियों का पृथक्करण और केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन और 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना सभी को भारत के संविधान में अपनाया गया था।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अंतरिम रूप से पारित किया गया था।

संविधान के लागू होने से पहले उपाय।

द.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का उद्देश्य एक अंतरिम संविधान के लिए प्रावधान करना था जब तक कि संविधान सभा भविष्य का संविधान तैयार नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने 15 अगस्त, 1947 से [1978] 2 एस. सी. आर. का अधिराज्य घोषित करके संवैधानिक स्थिति को बदल दिया।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

142

भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा और उस तारीख से किंगडम के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

यूनाइटेड

ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्रों की सरकार। द.

14 अगस्त, 1947 से भारत का केंद्रीय विधानमंडल समाप्त हो गया। सभा की रचना के लिए अस्तित्व में आई

संविधान

संविधान और केंद्रीय विधानमंडल के रूप में भी कार्य किया

डोमिनियन। नए संविधान ने अधिकांश प्रावधानों को अपनाया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935। संबंधित प्रावधान

इकाइयों और केंद्र के बीच शक्तियों के वितरण को अपनाया गया

और वास्तव में विस्तारित। संविधान निर्माताओं ने एकात्मकता को छोड़ दिया

पक्षपात और वितरण के संबंध में अपनाए गए विस्तृत प्रावधान

में से

संघ और राज्यों के बीच सभी पहलुओं में शक्तियाँ और कार्य

उनकी प्रशासनिक और अन्य गतिविधियाँ। अंतर-राज्य संबंध,

राज्यों के बीच विवादों का समन्वय और निर्णय थे -

भी प्रदान किया।

भारतीय संविधान को संघीय संविधान नहीं कहा जा सकता है।

भारतीय संघ के रूप में शिक्षा एक समझौते का परिणाम नहीं है

विभिन्न राज्यों और राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं है।

राज्यों के क्षेत्रों को बदला जा सकता है या एक राज्य पूरी तरह से

संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसे सहन करना पड़ता है।

यह ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद,  
भारतीय राज्य जो भारत अधिराज्य में शामिल हुए, उन्हें लाया गया।

संविधान द्वारा परिकल्पित संघ के भीतर। डोमिनियन में शामिल होने वाले भारतीय राज्यों को  
संघीय प्रणाली के तहत लाया गया था

संघ की अन्य इकाइयों, अर्थात् प्रांतों के समान आधार।

संविधान में राज्यों की स्थिति कई मायनों में है

के गठन में केंद्र सरकार के अधीनस्थ

संघ राज्यों और संघों के बीच किसी संधि के परिणामस्वरूप नहीं था।

संघ, और यह कि राज्य में सुधार किया जा सकता है या पूरी तरह से

कला के तहत हटा दिया गया। 4 संविधान से। हालांकि संविधान  
राज्यों के बीच कार्यकारी शक्ति को विभाजित करता है

संघ और राज्यों,

संघ के कुछ निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। कार्यपालक  
द्वारा बनाए गए कानूनों के संबंध में शक्ति

समवर्ती उप में संघ

राज्यों द्वारा नियमों का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि संसद अन्यथा निर्देश नहीं  
देती और संघ के विषयों के संबंध में संघ उन्हें प्रत्यायोजित कर सकता है। संसद द्वारा  
विधान द्वारा या राज्य सरकार की सहमति से किसी राज्य के लिए इसके कार्यकारी कार्य। संघ के  
कानून को लागू करना राज्य का कर्तव्य है और राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह से  
किया जाना चाहिए कि वह कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप न करे।

संघ और राज्य संघ के निर्देश के अधीन होंगे।

संघ के कानूनों के बारे में। लागू करने में राज्य की विफलता

संघ के निर्देश संघ को राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में लेकर राज्य सरकार का स्थान लेने का अधिकार देंगे। ये विशेषताएं संविधान को सख्ती से संघीय संविधान नहीं बनाती हैं। इसे विभिन्न रूप से अर्ध-संघीय या संरचना में संघीय या एक मजबूत केंद्रीय पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। लेकिन संविधान को संघीय के रूप में पुनर्गठित किया गया है या नहीं, राज्यों की स्थिति को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। कला के तहत। 1 भारत के संविधान के अनुसार, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों के बिना कोई संघ नहीं हो सकता। ऐतिहासिक रूप से भारतीय रियासतों के संघ में शामिल होने और अन्य कारणों से राज्य को एक इकाई के रूप में मान्यता दी गई थी। संविधान संघ के साथ-साथ राज्यों के लिए भी शक्ति का स्रोत है।

कर्नाटक वी. यूनियन (कैलाशम, जे.)

143

जबकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय और प्रांतीय सरकार के लिए शक्ति का स्रोत क्राउन था, भारत के संविधान के तहत, राज्यों के साथ-साथ संघ के लिए शक्ति का स्रोत संविधान है। अपने स्वयं के क्षेत्र में अर्थात्

राज्य को प्रदत्त शक्ति सर्वोच्च है, इसलिए केंद्रीय भी

सरकार। लेकिन यह निर्धारित करने में कि संघ की शक्तियाँ क्या हैं

और राज्य को संविधान पर गौर करना होगा और कहीं और नहीं।

राज्य केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं और

केंद्र सरकार राज्य पर किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है जो

संविधान में इसका प्रावधान नहीं है।

संविधान का भाग V संघ से संबंधित है। अध्याय I

कार्यपालिका से संबंधित, संसद के साथ अध्याय II, के साथ अध्याय III

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय IV-संघ न्यायपालिका  
 और अध्याय V भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ।  
 संविधान का भाग VI राज्यों से संबंधित है। अध्याय I जीन है  
 आरएएल, अध्याय II कार्यकारी, सीएच से संबंधित है। राज्य विधायिका के साथ III  
 प्रौढ़। च. IV राज्यपाल की विधायी शक्ति के साथ, Ch. वी के साथ  
 राज्यों में उच्च न्यायालय और च। VI अधीनस्थ न्यायालयों के साथ।

संघ और राज्यों के बीच। इनमें से कुछ लेख अध्यायों का विस्तार से उल्लेख बाद  
 में किया जाएगा। लेकिन इतना ही काफी है।

यह ध्यान में रखने के लिए कि भाग V संघ की कार्यपालिका को सौंपा गया है और  
 राज्यों के लिए भाग VI, भाग XI राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है।

संघ और राज्य। संघ के बीच शक्तियों का वितरण

और राज्यों को विभिन्न प्रावधानों से समझा जा सकता है

संविधान। उनके निपटान के लिए एक मशीनरी भी प्रदान की जाती है।

संविधान में डाल दिया। शक्तियों के वितरण में यह स्पष्ट है

कुछ आकस्मिकताओं के तहत राज्य प्रशासन को संभालना संविधान में इसका  
 समर्थन किया गया। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

किसी भी शक्ति का दावा करें जो इसके प्रावधानों के तहत निहित नहीं है

संविधान। संघ सरकार के पास कोई प्रमुख शक्ति नहीं है

मन में। यह राज्य सरकार के साथ अपने प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि

संघ के साथ-साथ राज्य के लिए शक्ति का स्रोत, कॉन्स्टी है

राज्य और केंद्र सरकार इस पर किसी भी शक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं

राज्य जो संविधान में नहीं पाए जाते हैं।

हमारे संविधान की प्रकृति पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है

कुछ निर्णयों में न्यायालय जिन्हें इस स्तर पर संदर्भित किया जा सकता है। में।

अतिबाड़ी चाय कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य और अन्य, (1) गजेंद्र

जे. गडकर, जैसा कि वे उस समय कला के निर्माण में थे। 301 देखा गया: " हम.

एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

शक्तियों का पृथक्करण जिस पर हमारा संविधान आधारित है। यह एक

संघीय संविधान जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, और इसलिए इसका प्रभाव

कला. 301 तदनुसार न्याय किया जाना चाहिए। " मामला सुलझा लिया गया एस. के. दास जे. द्वारा ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम। द.

( 1 ) [ 1961 [ 1 एससीआर 809।

( 2 ) [ 1963 ] 1 एससीआर 491।

[ 1978 ] 2.सी. आर.

144

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य और अन्य। ( 2) विद्वान न्यायाधीश ने भारतीय संविधान के इतिहास का पता लगाने के बाद कहा: एक संघीय संरचना या एक अर्ध-संघीय संरचना का विकास अनिवार्य रूप से शामिल है, उस समय की स्थितियों के संदर्भ में, शक्तियों का वितरण और हमारे संविधान का एक मूल भाग सातवीं अनुसूची में तीन विधायी सूचियों के साथ उस वितरण से संबंधित है। संविधान ने यह स्वयं कला द्वारा कहते हैं। 1 कि भारत राज्यों का संघ है और व्याख्या में है। संविधान को किसी भी संघीय या अर्ध-संघीय संविधान की आवश्यक संरचना को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात्, संघ की इकाइयों के पास भी कुछ शक्तियां हैं जैसा कि संघ के पास है। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा: " इस उप-संप्रदाय पर एक एकीकृत नीति विकसित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने तीन मुख्य विचारों को ध्यान में रखा है जिन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार कहा जा सकता है: पहला, भारत के व्यापक हित में अंतर-राज्य और राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर-मार्ग का मुक्त प्रवाह होना चाहिए; दूसरा, क्षेत्रीय हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज

नहीं किया जाना चाहिए; और तीसरा, भारत के किसी भी हिस्से में उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं से निपटने के लिए संकट की किसी भी स्थिति में संघ द्वारा हस्तक्षेप करने की शक्ति होनी चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला: " इसलिए, भाग XIII में प्रासंगिक अनुच्छेदों की व्याख्या करते समय हमें भाग III (मौलिक अधिकार), भाग XII (वित्त, संपत्ति आदि) के विशेष संदर्भ के साथ भारत के संविधान की सामान्य योजना को ध्यान में रखना चाहिए। 276 और 286) और एक संघीय या अर्ध-संघीय संविधान के संदर्भ में भाग XIII के साथ उनका अंतर-संबंध जिसमें राज्यों के पास कुछ शक्तियां हैं जिनमें शामिल हैं -

कराधान द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए राजस्व बढ़ाने की शक्ति। यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए स्पष्ट अधिकार है कि भारत सरकार की आवश्यक संरचना संघीय या अर्ध-संघीय प्रकृति की है, इन इकाइयों को भी संघ के रूप में कुछ शक्तियां हैं।

इस पहलू पर विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने बहुत दृढ़ता से भरोसा किया

पश्चिम बंगाल राज्य में कुछ मार्गों पर v. भारत संघ, (1) कला का उल्लेख करते हुए सिन्हा सी. जे. द्वारा दिए गए बहुमत निर्णय में। 4 संविधान जो संसद को राज्य के क्षेत्र को बदलने या इसे समाप्त करने के लिए कानून द्वारा सशक्त बनाता है, सिन्हा सी. जे. ने कहा: जब संसद को किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने और उसके क्षेत्रों को कम करने का अधिकार दिया जाता है, ताकि वह अपनी पूरी शक्ति और अधिकार के साथ किसी राज्य को नष्ट कर सके, तो यह मानना मुश्किल होगा कि संसद जो राज्य की पूर्ण संप्रभुता के बारे में कुछ धारणाओं के कारण किसी राज्य को नष्ट करने में सक्षम है, उस उद्देश्य के लिए बनाए गए कानून द्वारा प्रभावी रूप से अधिग्रहण करने में असमर्थ है, जो सरकारी उद्देश्यों के लिए राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि "भले ही संविधान को एक संघीय माना जाता था और राज्यों ने संघ को माना।

के रूप में

राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में कानून बनाने की संघ की संप्रभु शक्ति अप्रतिबंधित रहेगी। अदालत ने

था।

संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 पर विचार करते हुए, भारत संघ को पश्चिम बंगाल राज्य में कुछ कोयला धारक क्षेत्रों का अधिग्रहण करने में सक्षम बनाता है। राज्य ने यह तर्क देते हुए एक मुकदमा दायर किया कि यह

अधिनियम राज्य में निहित या उसके स्वामित्व वाली भूमि पर लागू नहीं होता है और यदि यह ऐसी भूमि पर लागू होता है, तो

( 1 ) [ 1964 ] 1 एस. सी. आर. 371.

कर्नाटक वी. यूनियन (कैलासम, जे.)

145

अधिनियम संसद की विधायी क्षमता से परे था।

द.

निर्णय जहाँ तक इसका मानना है कि भले ही संविधान को एक संघीय संविधान माना गया था और राज्यों ने संघ को इस रूप में माना

संप्रभु होने के नाते, प्रतिभूति के संबंध में कानून बनाने की संघ की शक्ति अप्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि यह प्रविष्टि 42, सूची III और सूची I की प्रविष्टि 52 और 54 के तहत संसद की शक्ति के भीतर आना सही हो सकता है। लेकिन बहुत सम्मान के साथ यह अवलोकन कि "भारत का संविधान वास्तव में संघीय चरित्र का नहीं है. कि केवल वे शक्तियां जो स्थानीय समस्याओं के विनियमन से संबंधित हैं, राज्यों में निहित हैं" अतिबाड़ी टी कंपनी में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार नहीं है। लिमिटेड वी. असम और अन्य राज्य (ऊपर) और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम. राजस्थान राज्य और अन्य (उपर्युक्त) जो इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। न्यायालय का यह अवलोकन कि अनुच्छेद के तहत संसद को दी गई शक्तियों से। 4 यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि संसद के लिए राज्यों की पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत पर राज्यों के स्वामित्व वाले अधिकार टीवी को कानून द्वारा प्राप्त करना अक्षम है, इसे इस रूप में नहीं समझा जा सकता है कि राज्यों की अपने क्षेत्र में भी कोई संप्रभुता नहीं है या संसद के पास कोई प्रबल या पर्यवेक्षण शक्तियां हैं।

सुब्बा राव का अवलोकन

जे. क्योंकि तब वे इस असहमतिपूर्ण निर्णय में थे कि भारतीय संविधान संघीय अवधारणा को स्वीकार करता है और संप्रभु शक्तियों को समन्वित संवैधानिक संस्थाओं, अर्थात् संघ और राज्यों के बीच वितरित करता है और इस अवधारणा का तात्पर्य है कि कोई भी दूसरे के सरकारी कार्यों या उपकरणों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, जब तक कि संविधान स्पष्ट रूप से इस तरह के

हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं करता है, इस न्यायालय के स्वीकृत दृष्टिकोण के साथ एकरूपता में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अतिबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के पहले के निर्णय। असम राज्य और अन्य और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड v. राजस्थान राज्य और अन्य को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित 1964 (1) के विशेष संदर्भ संख्या 1 में इस न्यायालय ने कहा:

" हमारे विधानमंडलों के पास निस्संदेह पूर्ण शक्तियाँ हैं,

स्वयं लिखित संविधान और इसके भीतर प्रयोग किया जा सकता है  
तीनों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्र

सातवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध; लेकिन उससे परे

सूची में, विधानमंडल यात्रा नहीं कर सकते हैं। वे कोई संदेह नहीं कर सकते

अपने पूर्ण विधायी अधिकार और निर्वहन का प्रयोग करें

प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उनके विधायी कार्य

संविधान के सुसंगत प्रावधानों द्वारा उन पर; लेकिन

शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। इसके अलावा,

सहित हमारे विधानमंडलों की विधायी सर्वोच्चता

संसद आम तौर पर इन प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है -

संविधान के भाग III में निहित। यदि विधायिकाएँ  
उन्हें सौंपे गए विधायी क्षेत्रों से परे कदम, या कार्य करना

अपने-अपने क्षेत्रों में, वे फंडा पर अतिक्रमण करते हैं

नागरिकों के मानसिक अधिकार इस तरह से उचित नहीं हैं

उक्त मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक लेख।

उनके विधायी कार्यों को अदालतों द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

( 1 ) [ 1965 ] आई. एस. सी. आर. 413

[ 1978 ] 2 एस सी आर ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

146

भारत में। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि हालांकि हमारे विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं, वे इसके भीतर कार्य करते हैं सामग्री और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित सीमाएँ संविधान "।

यह आगे देखा गया:

" एक लिखित संविधान द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में

यह संविधान है जो सर्वोच्च और संप्रभु है। यह.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान में स्वयं संशोधन किया जा सकता है

संसद, लेकिन यह कला के कारण संभव है। 368 में से

संविधान स्वयं इस संबंध में एक प्रावधान करता है और

संविधान के संशोधन केवल वैध रूप से किए जा सकते हैं

उक्त अनुच्छेद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके।

यह दर्शाता है कि भले ही संसद का इरादा हो

संविधान को लागू करने के लिए, इसे प्रासंगिक का पालन करना होगा

स्वयं संविधान का अधिदेश "।

ब्रिटिश भारत के राजनीतिक विकास ने इसका रूप ले लिया

एकात्मक संविधान बनाना और हस्तांतरण नियमों और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से एक संघीय योजना शुरू करना। हमारे संविधान ने विशाल उप-महाद्वीप में मौजूद क्षेत्रीय हितों, संसाधनों, भाषा और अन्य विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक संघीय योजना को स्वीकार किया, हालांकि इसकी सीमा सीमित थी। इन तथ्यों को संविधान निर्माताओं द्वारा ध्यान में रखा गया है और एक सीमित संघवाद को कला द्वारा संविधान का हिस्सा बनाया गया

था। 1 स्वयं यह प्रावधान करते हुए कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। सूचियों को अलग करके और संविधान के अलग-अलग अध्यायों में संघ और राज्यों को विधायी और कार्यकारी शक्ति प्रदान करके इस इरादे को प्रभाव दिया जाता है। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अतिबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड बनाम के निर्णयों में स्वीकार किया गया है। असम राज्य और

अन्य और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान 1) लिमिटेड v. राजस्थान राज्य और अन्य का उल्लेख पहले किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के मामले (उपरोक्त) में की गई टिप्पणियां, जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उच्चतम न्यायालय के इस अन्यथा सुसंगत दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं हैं कि संविधान सर्वोच्च है और संघ के साथ-साथ राज्यों को भी संविधान के प्रावधानों से अपनी शक्तियों का पता लगाना होगा और संघ सर्वोच्च नहीं है और राज्य संघ के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है।

इस विषय पर केशवर्द (1) और चुनाव (1) मामलों में न्यायालय। उन मामलों में जो सवाल उठा वह यह था कि संविधान में कितना संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद के मामले में, बहुमत का विचार था कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। चुनाव का मामला केशवानंद के मामले के आधार पर आगे बढ़ा कि मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सका। वादी के विद्वान वकील श्री लाल नारायण सिन्हा ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी अनिर्धारित बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए अदालत को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह इंगित करने के लिए अपनी दलीलों को सीमित कर रहे हैं कि सीमित अर्थों में संघीय संरचना संविधान का एक अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार सर्वोच्च नहीं है और जो पाया जाता है उसके अलावा इसके पास कोई शक्ति नहीं है।

( 1 ) [ 1973 ] सप. एस. सी. आर. 1 ( )  
2 ) [ 1976 ] 2 एस. सी. आर. 347

कर्नाटक वी. यूनियन (कैलासम, जे.)

147

संविधान में। केशवानंद के मामले में यह बहुमत द्वारा माना गया था कि कला। 368 संसद को संविधान के मूल ढांचे या ढांचे में बदलाव करने में सक्षम नहीं बनाता है। संविधान की मूल संरचना क्या है, इस पर चर्चा करते हुए मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा

कि इसमें (1) संविधान की सर्वोच्चता, (2) सरकार का लोकतांत्रिक रूप, (3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, (4) विधायिकाओं, विशेष और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, और (5) संविधान का संघीय चरित्र शामिल था।

वर्तमान चर्चा के उद्देश्यों के लिए इसमें जाना अनावश्यक है।

सवाल यह है कि क्या संघीय संरचना कॉन्स्टी में पाई जाती है

केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार।

संविधान में राज्यों की स्थिति से निपटने से पहले,

यह ध्यान में रखना होगा कि के बीच शक्तियों के वितरण में संघ और राज्य संघ के पक्ष में एक मजबूत पूर्वाग्रह रखते हैं।

आपातकाल की स्थिति में संघीय सरकार इसे परिवर्तित कर सकती है।

एक एकात्मक में स्वयं। केंद्र सरकार उस राज्य सरकार का स्थान ले सकती है जिसने कला के तहत अधिकृत अपने निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। 365 संविधान से। जबकि केंद्र सरकार को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्देश देने की शक्तियां दी गई हैं।

अनुच्छेद 256 और 257 के तहत मामले, जब आपातकाल की घोषणा की जाती है

जेन्सी कला के तहत बनाई जाती है। 352, संघ की कार्यपालिका की शक्ति

राज्य सरकार को निर्देश देना किसी भी मामले पर लागू होगा और संघ संसद की विधायी शक्ति मामलों तक विस्तारित होगी।

कला के तहत राज्य सूची में। 250. संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो वित्त के मामले में संघ को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं।

आकस्मिक आपातकाल। संघ का कार्यकारी प्राधिकरण बन जाता है

राज्य को आवश्यक निर्देश देने के लिए संघ को सक्षम बनाना

वित्तीय अनुशासन। संघ संसद एक प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधायी शक्तियों को ग्रहण कर सकती है।

कला के तहत। 249 यदि ऐसा कानून राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है

ब्याज। जब भी राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति

पदभार ग्रहण करने के लिए सशक्त और संघ कार्यपालिका को ग्रहण कर सकता है और

अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायी शक्तियाँ। 356. यद्यपि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, फिर भी राज्य के प्रशासन और विधान दोनों पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण के लिए अनुकूल दृष्टिकोण है। ये कला के तहत प्रदान किए जाते हैं। 201 जो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य विधान को अस्वीकार करने का अधिकार देता है जो उनकी सहमति के लिए आरक्षित है। कला के तहत संविधान द्वारा राज्यों पर एक कर्तव्य डाला गया है। 256 और 257 संघ के कानूनों को लागू करने के लिए। प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि -

संघ की कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप करना और इन मामलों में राज्य संघ के निर्देशों के अधीन होंगे। इन शक्तियों का संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार इनका प्रयोग कर सकती है।

विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या संघ

सरकार राज्य के सरकारी कार्यों की जांच का आदेश दे सकती है जो विशेष रूप से संघ को 1.

[ 1978 ] 2 एससी. आर.

148

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान। केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्ति।

कि यह राज्य नहीं है, बल्कि केवल राज्य की सरकार या

पीड़ित मंत्रियों से उचित समय पर निपटा लिया जाएगा।

द.

राज्यों की स्थिति कला में दर्शाई गई है। 1 जो घोषित करता है कि भारत।

राज्यों और राज्यों और उनके क्षेत्रों का एक संघ होगा

पहली अनुसूची और भारत के राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा।

राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल होंगे और ऐसे अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सके। संविधान का भाग VI

या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के साथ। कला. 162 उस विषय को प्रावधान प्रदान करता है

संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा:

जिन मामलों के संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास है

कानून बनाने की शक्ति। कला के लिए एक प्रावधान है। 162 जो प्रदान करता है

कि किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में किसी राज्य का विधानमंडल

और संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, इसकी कार्यकारी शक्तियाँ

राज्य कार्यकारी शक्तियों के अधीन और उनके द्वारा सीमित होगा।

इस संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा छलपूर्वक प्रदत्त

संघ या उसके प्राधिकारियों पर। कला. 163 वहाँ प्रदान करता है कि

एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे।

राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देना, सिवाय इसके कि

जहाँ तक वह इस संविधान द्वारा या उसके तहत प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है

कला के तहत अपने विवेक से उसके कार्य या उनमें से कोई भी। 164 द.

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्री - राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री की सलाह पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

यह आगे प्रावधान करता है कि मंत्री इस अवधि के दौरान पद धारण करेंगे

टेर।

राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की खुशी

राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना।

अध्याय III राज्य विधानमंडल से संबंधित है। कला. 168 संबंधित

को।

राज्यों में विधानमंडलों का गठन। यह अध्याय इस बात का उल्लेख करता है -

राज्यपाल में राज्य की विभाजक शक्तियाँ जो इसका प्रयोग करेंगे -

मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह

सिर पर। यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति

उन मामलों तक विस्तारित होगा जिनके संबंध में विधानमंडल

राज्य के पास कानून बनाने की शक्ति है। जहाँ तक कार्यपालिका और विधायिका का संबंध है:

राज्य की शक्ति का संबंध है कि यह केवल दूसरे के अधीन है। संविधान के भाग 11  
के प्रावधानों से संबंधित है -

संघ और राज्यों के बीच संबंध: च. में विधायी संबंध के साथ

टियान्स और च। II संघ और संघ के बीच प्रशासनिक संबंधों के साथ

4

राज्यों को। विधायी शक्ति के वितरण की योजना

संघ और राज्यों के बीच सरकार से लिया गया है भारत अधिनियम, 1935 और  
कला। 245 और 246 कम या ज्यादा प्रजनन करते हैं

1935 के अधिनियम की धारा 99 और 100। अनुच्छेद 245 (1) में उप-प्रावधान है।

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संसद कानून बना सकती है।

भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए, और विधानमंडल

राज्य पूरे या राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है। कला.

246 संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है

सातवीं योजना की सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में युगल। राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है - सूची-2 अर्थात् राज्य सूची में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में राज्य। राज्य की संसद और विधानमंडल के पास शक्ति होगी - सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाएँ। कोन कर्नाटका वी. यूनियन (कैलाशम, जे.)

149

वर्तमान सूची। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसके तहत प्रदत्त शक्तियाँ अनुच्छेद 245 और 246 संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं। इसलिए किसी विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून दोनों के लिए मान्य नहीं हो सकते हैं। विषय वस्तु के संबंध में या जमीन पर अधिकार क्षेत्र की कमी कि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अवशेष कानून बनाने की शक्ति संसद को अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है। 248 जो यह प्रावधान करता है कि संसद के पास कोई भी बनाने की अनन्य शक्ति है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून या राज्य सूची में। कला के तहत। 246 ( 1 ) और (2) और कला। 254 ( 1 ) जब कोई राज्य का कानून राज्य के कानून के साथ टकराव में हो या संघ के प्रतिकूल हो कानून जो संसद संघ कानून बनाने के लिए सक्षम है, प्रबल होगा। और राज्य का कानून प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगा। लेकिन एक यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या संघर्ष से बचा जा सकता है सातवीं अनुसूची यह स्पष्ट करती है कि अवशिष्ट शक्ति के पास है संसद और जब किसी मामले को कानून बनाने की मांग की जाती है तो उसे शामिल नहीं किया जाता है।

सूची II या सूची III में संसद को कानून बनाने की शक्ति है।

उस मामले या कर को लागू करें। लेकिन सूचियों का कार्य प्रदान करना नहीं है

विधानमंडल की शक्तियाँ। वे केवल विधायी का सीमांकन करते हैं मैदान। फेडरल कोर्ट, गवर्नर-जनरल इन काउंसिल v.

रैले निवेश कंपनी (1) ने देखा कि "का उद्देश्य

सूची शक्ति बनाने या प्रदान करने के लिए नहीं थी, बल्कि केवल संघीय को वितरित करने के लिए थी।

99 और अधिनियम का 100 "। की टिप्पणियों को मंजूरी देते हुए भारत संघ में संघीय न्यायालय बनाम। एच. एस. डिल्लन (\*) के लिए बहुमत

जिनके बारे में मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि "यह (कला)। 248) को व्यापक संभव शब्दों में तैयार किया गया है। इसकी शर्तों पर केवल एक ही सवाल पूछा जाना है

क्या इस मामले को सूची II में शामिल करने की मांग की गई है या

यह है:

सूची III या सूची II या सूची III में उल्लिखित कर लगाया जाना चाहिए? सूची I के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। यदि उत्तर नकारात्मक है, तो इसका मतलब यह है कि संसद को उस मामले या कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन यह अवलोकन इस प्रश्न का निर्णय नहीं करता है कि क्या संघ की अवशिष्ट विधायी शक्ति में राज्य के सरकारी कार्यों की प्रत्यक्ष जांच का अधिकार शामिल है जैसा कि संघीय न्यायालय द्वारा सरकार में निर्धारित किया गया है और न ही परिषद में जनरल v. रैले निवेश कंपनी सूची का उद्देश्य शक्तियों का निर्माण या प्रदान करना नहीं है और अनुच्छेद 245 और 246 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं। चूंकि संविधान में संघ को राज्य के सरकारी कार्यों की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सूचियों के संदर्भ से समस्या का समाधान नहीं होगा।

विवाद की जड़ यह है कि कर्नाटक राज्य

यह तर्क देते हुए कि संघ और राज्यों के बीच संबंध संविधान का एक विषय है और यह तीन सूचियों में से किसी में भी शामिल विषय नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से तर्क यह है कि अधिसूचना संविधान के किसी भी विशिष्ट प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है और इस तरह

संघ की विधायी क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जबकि कर्नाटक राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक मंत्री के आचरण की जांच करने की शक्ति

( 1 ) [ 1944 ] एफ. सी. आर. 229,261।

( 2 ) [ 1972 ] 2 एस. सी. आर. 33

[ 1978 ] 2 एससीआर।

150

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, वह केवल राज्य के विधानमंडल के पास है, संघ की ओर से निवेदन यह है कि संघ की शक्ति संविधान के किसी भी प्रावधान द्वारा विशेष रूप से नहीं ली गई है और इसलिए विचारित जांच संघ की शक्तियों के दायरे में है। सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, पृच्छने के लिए सही सवाल यह है कि "क्या कानून किसी ऐसे मामले के लिए प्रावधान करता है जो संविधान के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत है या उससे असंगत है या इस तरह से बदलाव लाता है कि मूल और संशोधित प्रावधान अलग हैं और असंगत हैं?" यदि वह ऐसा करता है तो इसे संशोधन के रूप में माना जा सकता है, चाहे वह जोड़ा जाए, परिवर्तन किया जाए या निरस्त किया जाए। जिसमें

उसी समय केवल ऐसे प्रावधानों का अधिनियमन जो किसी भी तरह से नहीं हैं

संविधान के मौजूदा प्रावधानों के साथ गुणात्मक रूप से असंगत लेकिन विधायी विषयों या संविधान के कुछ पहलुओं से संबंधित है।

राष्ट्रीय विषय, के लिए घटक शक्ति के प्रयोग को अभिनिर्धारित नहीं करता है

उनके इस तर्क के समर्थन में कि

संविधान में संशोधन।

जब तक संविधान के एक स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक कानून पर निहित निषेध के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, विद्वान वकील ने वेब v पर भरोसा किया। आउट्रिम। ( 1 ) वह प्रश्न जो उत्पन्न हुआ

उस मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णय यह था कि क्या प्रतिवादी,  
 ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल का एक अधिकारी, विक्टोरिया में निवासी और  
 विक्टोरियन लेजिस के एक अधिनियम द्वारा लगाए गए आयकर के लिए इसका पी. टी.  
 प्रौढ़। न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया था कि प्रतिबंध  
 विक्टोरिया संविधान की शक्तियां किसी भी एक्सप्रेस पीआरसी द्वारा अधिनियमित की जाती  
 हैं।

राष्ट्रमंडल संविधान अधिनियम की दृष्टि लेकिन तर्क दिया गया था कि  
 जहाँ तक आय-कर लगाने से हस्तक्षेप हो सकता है  
 आम जनता की विधायी या कार्यकारी शक्ति का मुक्त प्रयोग  
 धन, इस तरह के हस्तक्षेप को कॉन्स्टी द्वारा निहित रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए  
 राष्ट्रमंडल का शासन, हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं हो सकता है  
 वहाँ पाया जाता है। अदालत ने कहा: वे अधिनियम जिन पर ध्यान दिया जाता है  
 यह निर्देश दिया गया है कि निहित प्रो के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं  
 हिबिशन "। यह आगे कहा गया कि "यह मानना असंभव है कि अब बहस में  
 प्रश्न एक निहित पर निर्णय करने के लिए छोड़ दिया गया था  
 निषेध जब किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल के समक्ष  
 था। " निर्माण के मूल सिद्धांत

जिसे अर्ल लॉरेबर्न एल. सी. ने वकील के रूप में स्वीकार और आवेदन किया है।  
 ओंटारियो प्रांत के लिए जनरल और अन्य बनाम। महान्यायवादी

कनाडा के डोमिनियन के लिए और दूसरा। ( 1) में निर्धारित नियम  
 आर वी। बुराह यह है कि "जब कोई सवाल उठता है कि क्या निर्धारित किया गया है  
 सीमाओं को पार कर लिया गया है एकमात्र तरीका है जिसमें इसे किया जा सकता है  
 उस साधन की शर्तों को देखकर जिसके द्वारा सकारात्मक रूप से  
 विधायी शक्तियों का निर्माण किया गया था और जिनके द्वारा वे नकारात्मक रूप से सक्षम हैं।  
 टिंक किया गया। यदि जो किया गया है वह सामान्य दायरे के भीतर कानून है

सकारात्मक शब्दों का जो शक्ति देते हैं और यदि यह कोई पूर्व का उल्लंघन नहीं करता है

प्रेस, शर्त या प्रतिबंध जिसके द्वारा वह शक्ति सीमित है, यह नहीं है न्याय के किसी भी न्यायालय के लिए आगे की जांच करना, या रचनात्मक रूप से विस्तार करना

( 2 ) [ 1878 ] 3 ए. सी. 889

( 3 ) [ 1912 ] 583 पर ए. सी. 571।

कर्नाटक वी. यूनियन (कैलासम, जे.)

151

उन शर्तों और प्रतिबंधों "। 1912 ई. स. 571 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "यदि पाठ स्पष्ट है तो पाठ निर्णायक है, समान रूप से यह क्या निर्देशित करता है और क्या मना करता है। जब पाठ अस्पष्ट होता है, उदाहरण के लिए, जब दो पारस्परिक रूप से अनन्य क्षेत्राधिकार स्थापित करने वाले शब्द हैं

दोनों में से किसी एक के भीतर एक विशेष शक्ति लाने के लिए पर्याप्त चौड़ी, सहारा होना चाहिए अधिनियम के संदर्भ और योजना के अनुसार था। का निर्णय

द अमालगामेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स बनाम में ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय।

एडिलेड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1) जिसमें यह

यह माना गया था कि अभ्यास के खिलाफ निहित निषेध का सिद्धांत

एक बार विपक्ष के सामान्य नियमों के अनुसार निर्धारित की गई शक्ति

वेब v में प्रिंसी काउंसिल द्वारा निर्माण को खारिज कर दिया गया था। आउट्रिम। ( 3)

द स्टेट ऑफ विक्टोरिया बनाम में निर्णय। आम-धन

ऑस्ट्रेलिया (1) को संदर्भित किया गया था लेकिन जैसा कि वह निर्णय प्रिंसी को दोहराता है

आर. वी. में निर्दिष्ट किया गया है। बुराह (1) का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। द.

निर्धारित सिद्धांत यह है कि यदि जो किया गया है वह कानून के अंतर्गत है।

सामान्य शब्द जो शक्ति देते हैं और यदि यह कोई अभिव्यक्ति का उल्लंघन नहीं करता है

शर्त या प्रतिबंध जिसके द्वारा वह शक्ति सीमित है, तो यह नहीं है

न्याय की अदालत के लिए पूछताछ करने के लिए लेकिन इसे मतलब के रूप में नहीं समझा जा सकता है

यह कहते हुए कि 'व्यक्त' शब्द आवश्यक रूप से निहित को बाहर नहीं करता है।

लियानगे वी। आर, (5) संविधान की व्याख्या करते हुए प्रिंसीपल काउंसिल

सीलोन के संविधान ने माना कि संविधान में स्पष्ट रूप से निहित नहीं है

न्यायिक शक्ति विशेष रूप से न्यायपालिका में होती है, लेकिन यह तथ्य निर्णायक नहीं था

संविधान की योजना के रूप में विशेष रूप से संबंधित प्रावधान

न्यायपालिका ने इस तथ्य के आलोक में देखा कि न्यायिक शक्ति थी

न्यायपालिका में सक्रिय। इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय का निर्णय है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। नृपेंद्र नाथ बागची (\*). सवाल यह है

उस मामले में जो उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या इंक्युरी द्वारा आदेश दिया गया था सरकार और सरकार के एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित

जिला और सत्र न्यायाधीश के खिलाफ के प्रावधानों का उल्लंघन किया

संविधान का अनुच्छेद 235 जो उच्च न्यायालय में नियंत्रण निहित करता है

जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर। द.

न्यायालय ने अनुच्छेद 235 में प्रयुक्त 'नियंत्रण' शब्द का अर्थ इस प्रकार लगाया कि

जिला न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र। इस पर भरोसा करें

न्यायालय द्वारा इन अनुच्छेदों के अधिनियमन के पीछे का इतिहास

इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'नियंत्रण' उच्च न्यायालय में निहित था एक उद्देश्य को प्रभावी बनाना, अर्थात्, स्वतंत्रता की सुरक्षा

अधीनस्थ न्यायपालिका और जब तक कि इसमें अनुशासनात्मक नियंत्रण भी शामिल न हो,

बहुत ही उद्देश्य निराश हो जाएगा। यह भी ध्यान में रखा गया कि

तथ्य यह है कि 'नियंत्रण' शब्द 'बनियान' शब्द के साथ है जो है एक मजबूत शब्द जो दर्शाता है कि उच्च न्यायालय को एकमात्र कस्टो बनाया गया है न्यायपालिका पर नियंत्रण। अदालत ने कहा: " यह निर्माण के लिए सहायता (वह इतिहास जो अधिनियम के पीछे है) है स्वीकार्य है क्योंकि किसी कानून के अर्थ का पता लगाने के लिए, कानूनी सहायता ली जा सकती है।

कानून की पूर्व स्थिति के अनुसार, बुराई को दूर करने की मांग की गई

और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कानून विकसित किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है

( 1 ) 28 सी. एल. आर. 129

( 2 ) [ 1907 ] ए. सी. 81

( 3 ) 122 सी. एल. आर. 353

( 4 ) सुप्रा।

( 5 ) [ 1967 ] ए. सी. 259

( 6 ) [ 1966 ] 1 एस. सी. आर. 771, [1978] 2 एस.

सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

152

अनुशासनात्मक नियंत्रण प्रदान करने वाले अनुच्छेद में प्रावधान व्यक्त करें और

ए.

जिला न्यायाधीश पर अधिकारिता यह अनुच्छेद के शब्दों से निहित थी। लियानगे बनाम में प्रिंसीपल काउंसिल के निर्णय को पढ़ना। आर. (सुप्रा) और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। नृपेंद्र नाथ बागची (सुप्रा), आर. वी. में 'एक्सप्रेस' शब्द है। बुराह (सुप्रा) को अनिवार्य रूप से निहित को शामिल करने के रूप में माना जाना चाहिए। संविधान के

इतिहास और योजना को ध्यान में रखते हुए राज्यों के संबंध में संविधान में बी सुरक्षा उपाय अनिवार्य रूप से हैं

निहित होने के लिए, हालांकि कर्नाटक राज्य की ओर से यह स्वीकार किया जाता है कि संविधान का कोई विशेष प्रावधान स्पष्ट रूप से संशोधित नहीं किया गया है

संशोधित या परिवर्तित किया गया।

संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कला में पाया जाता है। 73 और राज्य की बात कला में दी गई है। 162. भाग 11, अध्याय 2 में,

जो संघ और संघ के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है

राज्यों के अनुच्छेद 256 और 257 में राज्यों और संघ के दायित्वों और कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण को सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 256 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस उद्देश्य के लिए भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत हों। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी विशेष शक्ति का इस तरह से प्रयोग करे और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 257 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न आए और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस उद्देश्य के लिए भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत हों। उप-अनुच्छेद (2) राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के घोषित संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव के बारे में निर्देश देने के लिए संघ की शक्ति का विस्तार करता है उप-अनुच्छेद (3) संघ की शक्ति का विस्तार किसी राज्य को निम्नलिखित उपायों के बारे में निर्देश देने तक करता है -

राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए लिया जाना। के द्वारा  
दूसरा संशोधन। 257 ए द्वारा प्रस्तुत किया गया था

42 संविधान में

जिसे भारत सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल को तैनात करने का अधिकार है। अनुच्छेद 257 ए के उप-अनुच्छेद (2) में प्रावधान है कि कोई भी सशस्त्र बल या अन्य बल या कोई भी

किसी भी राज्य में खंड (1) के तहत हटाए गए आकस्मिक या इकाई ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी जो भारत सरकार जारी करे और ऐसे निर्देशों में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण के अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन नहीं होगी। भारत सरकार द्वारा इसके किसी भी अंतर्निहित या अधिस्थापक पर कोई निर्भरता नहीं रखी गई थी।

सत्ताएँ। अनुच्छेद 256 और 257 में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर और

257 ए, संविधान केंद्र सरकार के लिए प्रावधान नहीं करता है राज्य सरकार को कोई भी निर्देश दें। हालांकि अनुच्छेद के तहत

355 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा, यह संवैधानिक माना जाता था

सरकार को सक्षम बनाने के लिए संशोधन आवश्यक था।

भारत सरकार कर्नाटक वी. यूनियन (केलाशम, जे.) को तैनात करेगी

153

कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल। चूंकि संविधान में कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है जो केंद्र सरकार को राज्य के सरकारी कार्यों की जांच करने में सक्षम बनाता है, इसलिए शक्ति को सामान्य विधान द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन संवैधानिक संशोधन का सहारा लेना चाहिए।

आई. सी. गोलक नाथ और अन्य में। बनाम पंजाब राज्य और अन्र।, ( 1)

न्यायमूर्ति वांचू ने कहा है कि "संविधान मौलिक कानून है और संविधान द्वारा प्रदत्त केवल विधायी शक्ति के तहत पारित कोई भी कानून संविधान में किसी भी परिवर्तन को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि संविधान में ही उस प्रभाव के लिए कोई पूर्व प्रेस शक्ति नहीं दी गई हो। लेकिन संविधान द्वारा दी गई इस तरह की व्यक्त शक्ति के अधीन, मौलिक कानून, अर्थात् संविधान, को संविधान में निहित विधायी प्रावधानों के तहत पारित कानून द्वारा बदला नहीं जा सकता है क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत पारित सभी विधायी अधिनियमों को संविधान के अनुरूप होना चाहिए। में कई लेख हैं

संविधान जो स्पष्ट रूप से विधि द्वारा संशोधन का प्रावधान करता है, उदाहरण के लिए, 3,4,10,59 (3), 65 (3), 73 (2), 97,98 (3), 106,120 (2), 135,137,142 (1), 146 (2), 148 (3), 149,169,171 (2),

186 , 187 ( 3 ) , 189 ( 3 ) , 194 ( 3 ) , 195 , 210 ( 2 ) , 221 ( 2 ) , 225 , 229 ( 2 ) ,

239 ( 1 ) , 241 ( 3 ) , 283 ( 1 ) और (2), 285 (2), 287,300 (1), 313,345,

ऐसी शर्तों पर संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने के लिए कानून द्वारा और परिस्थितियाँ जो वह उचित समझती हैं और कला 1 3 संसद को सक्षम बनाता है

कोई भी राज्य और मौजूदा राज्यों के नाम। अनुच्छेद 4 प्रदान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में ऐसे प्रावधान होंगे

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए "

कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है और

इस प्रकार के पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान भी शामिल हैं।

यह प्रावधान करता है कि उपरोक्त किसी भी कानून को एक नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन। तो।

कला भी। 169 ( 1 ) संसद को कानून द्वारा प्रावधान करने में सक्षम बनाता है किसी राज्य की विधान परिषद और उप-अनुच्छेद (3) का उन्मूलन

यह प्रावधान करता है कि उपरोक्त किसी भी कानून को एक नहीं माना जाएगा

अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन। सिमी

एल. ए. आर. प्रावधान अनुसूची वी, सी. एल. में पाए जाते हैं। 7 और अनुसूची VI, क्ल। 21

जहाँ संसद द्वारा बनाई गई विधि को संशोधन नहीं माना जाता है।

कला के प्रयोजनों के लिए संविधान का। 368. जहाँ तक दूसरे ऊपर वर्णित लेख स्वयं इन लेखों से संबंधित हैं

संसद में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए कानून बनाने में सक्षम

विभिन्न लेख। उन अनुच्छेदों के संबंध में जिनमें कोई शक्ति नहीं है

कानून बनाने के लिए संसद पर चढ़ाया गया, संसद इसमें जोड़ नहीं सकती  
साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया द्वारा संविधान।

केंद्र सरकार ने सूची I और प्रविष्टि में प्रविष्टि 94 पर भरोसा किया  
45 इसे अधिनियमित करने के लिए सशक्त बनाने के रूप में सातवीं अनुसूची की सूची III में  
जांच आयोग अधिनियम, 1952 और विवादित अधिसूचना जारी करने के लिए  
कैशन। सूची I में प्रविष्टि 94 इस प्रकार है:

" 94. के उद्देश्य के लिए पूछताछ, सर्वेक्षण और सांख्यिकी

इस सूची में से कोई भी मामला "।

( 1 ) [ 1967 ] 2 एस. सी. आर. 762

} 154

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[

1978 ] 2 एससीआर।

सूची III, समवर्ती सूची में प्रविष्टि 45 इस प्रकार है:

" 45. किसी भी उद्देश्य के लिए पूछताछ और आँकड़े

सूची II या सूची III में निर्दिष्ट मामले।

सूची I में प्रविष्टि 94 के रूप में सूची I के विद्वान सोली के मामलों तक ही सीमित है।

महालेखाकार ने ठीक ही उस प्रविष्टि पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मुख्य रूप से इस पर  
भरोसा किया

सूची III में प्रविष्टि 45। प्रविष्टि 45 संघ को इसके लिए कानून बनाने में सक्षम बनाती है  
सूची II और III में निर्दिष्ट किसी भी मामले के उद्देश्य के लिए पूछताछ

अर्थात् राज्य सूची और समवर्ती सूची। सवाल यह है कि शब्द में जांच करने की शक्ति शामिल होगी

क्या 'पूछताछ'

मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करना और रहते हुए राज्य सरकार के अन्य मंत्री। सोना।

कार्यालय में

व्याख्या का नियम यह है कि शब्दों को उनके क्रम में पढ़ा जाना चाहिए।

नैरी, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ और शब्दों को एक में समझने में

शब्दों पर रखा जाना चाहिए ताकि वे प्रभाव डाल सकें आयाम। लेकिन यह नियम कुछ अपवादों के अधीन है। यह.

सबसे व्यापक

यह दो अनन्य न्यायशास्त्रों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए आवश्यक पाया गया है।

शब्दों को एक सीमित अर्थ दिया जा सकता है। संघीय

मध्य प्रांतों में न्यायालय और मोटर स्पिरिट की बेरार बिक्री और

स्नेहक कराधान अधिनियम, 1938 (मध्य प्रांत और बरार अधिनियम)

नहीं। 1938 का XIV) (1938 की धारा 233 के तहत एक विशेष संदर्भ में)

भारत सरकार अधिनियम, 1935) (1) अभिव्यक्तियों का अर्थ लगाने में

" सातवीं अनुसूची में सूची I की प्रविष्टि 45 में उत्पाद शुल्क और

" माल की बिक्री पर कर "सूची II की प्रविष्टि 48 में अर्थात् राज्य सूची, आयोजित

वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर। इस प्रकार यह अनुमत है कि भाषा को समझने में एक सीमित अर्थ दें

परस्पर विरोधी

प्रावधान। मद्रास बनाम। गैनन डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड (2),

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि एक विधायी प्रविष्टि को व्यापक रूप से लागू करने में

उपयोग किए गए शब्दों पर निर्देश दिया जाना चाहिए, क्योंकि "माल की बिक्री" अभिव्यक्ति माल की बिक्री से संबंधित सामान्य कानून में और संबंधित विधायी व्यवहार में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कानूनी महत्व का शब्द था।

उस विषय की व्याख्या प्रविष्टि 48, सूची II, श् में की जानी चाहिए। 7 अधिनियम का वही अर्थ है जो माल की बिक्री अधिनियम में है। यह नियम कि संविधान में शब्दों का अर्थ लगाने में

सबसे उदार निर्देश को शब्दों पर रखा जाना चाहिए, एक सार्वभौमिक नियम नहीं है जैसा कि लॉर्ड ब्लैकबर्न के रिवर वियर कमिशनर्स v में दिए गए निर्णय से देखा जाता है। एडमसन (3) जहाँ लॉर्ड ब्लैकबर्न ने अपना विचार व्यक्त किया कि शब्दों की व्याख्या करने में, उद्देश्य उपयोग किए गए शब्दों द्वारा दबाए गए इरादे का पता लगाना है और दस्तावेजों और कानूनों की व्याख्या का उद्देश्य "उन्हें बनाने वाले के इरादे" का पता लगाना है। हेडन के मामले में लॉर्ड कोक ने उस सिद्धांत को लागू किया जो लॉर्ड ब्लैकबर्न द्वारा निर्धारित किया गया था। आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम भारत संघ (1), "जे. वेंकटरामा अय्यर ने हेडन के मामले में अनुमोदन के साथ नियम का हवाला दिया और कहा कि सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

( 1 ) [ 1939 ] एफ. सी. आर. 18

( 2 ) [ 1959 ] एस. सी. आर 379

( 3 ) [ 1877 ] एस. ए. सी. 743

( 4 ) [ 1957 ] एससीआर 930।

कर्नाटक बनाम। यूनियन (कैलासम, जे.)

155

वी. बिहार राज्य (1), और यह देखा कि राज्य का विधायी इतिहास कानून ने दिखाया कि कौशल से जुड़ी पुरस्कार प्रतियोगिताओं में पहले से ही

विवादित

विधायिकाओं को कोई समस्या नहीं भेजी, और उस पर ध्यान देते हुए

इतिहास, और अधिनियम में उपयोग की जाने वाली भाषा, परिभाषा को,

निर्माण, जुआ प्रकृति की पुरस्कार प्रतियोगिताओं तक सीमित रहें।

इस प्रकार इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है कि कानूनों की व्याख्या में मुख्य उद्देश्य "उनके इरादे का पता लगाना है कि बी

बनाया "।

इसलिए संसद की मंशा को समझना आवश्यक है।

जाँच आयोग अधिनियम, 1952 को अधिनियमित करने में। यह पूछताछ प्रविष्टि 45 के तहत निर्दिष्ट किसी भी मामले के उद्देश्य के लिए है

सूची II या सूची III। यह देखा गया है कि एक्सईआर में कदाचार की जांच किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी कार्यों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

सूची II या सूची III की किसी भी प्रविष्टि से पहचाना जा सकता है। प्रविष्टि 45

समवर्ती सूची में है और क्या संसद द्वारा कोई कानून बनाया जा सकता है केंद्र सरकार को जांच करने का अधिकार देना

राज्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्यों का दुरुपयोग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य सरकार के पास सूची II और सूची III के मामलों से संबंधित केंद्रीय मंत्री द्वारा शासन की मानसिक शक्तियों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए राज्य को सशक्त बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। स्पष्ट रूप से प्रविष्टि 45 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह कभी भी अभिप्रेत नहीं हो सकता था। अन्यथा परिणाम संघ और राज्यों के सौहार्दपूर्ण कामकाज के लिए अनुकूल नहीं होगा। यह परिस्थिति एक मजबूत संकेत है कि सूची III 'पूछताछ' में प्रविष्टि 45 को एक व्यापक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों को दूसरे द्वारा सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में जांच शुरू करने के लिए एक प्रावधान लागू करने की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

जांच आयोग अधिनियम, 1952, अधिनियम 60 के प्रावधान

अब 1952 की जाँच की जाएगी। अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:

" आयोगों की नियुक्ति के लिए एक अधिनियम

जांच और ऐसे आयोगों को कुछ निश्चित अधिकार सौंपने के लिए

शक्तियाँ "।

धारा 2 "उपयुक्त सरकार" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I या सूची II या सूची III में सूचीबद्ध प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रविष्टि से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए नियुक्त आयोग के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी भी मामले की जांच करने के लिए नियुक्त आयोग। संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II या सूची III में सूचीबद्ध। धारा 3 (1) आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करती है। यह इस प्रकार चलता है:



लोक सभा या राज्य की विधान सभा द्वारा

जैसा कि मामला हो सकता है। आयोग का उद्देश्य एक

सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच।

अधिनियम के तहत संसद ने अपने विधायी कार्यों को सौंप दिया है

उपयुक्त सरकार को अधिकार दिए हैं और विवेकाधिकार प्रदान किया है आयोग  
नियुक्त करना यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक है और

सरकार पर आयोग नियुक्त करना अनिवार्य बनाता है यदि

संबंधित विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव है। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य किसी भी मामले की जांच करना है। सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला। जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच की जानी है, उसका कोई उल्लेख या निर्देश नहीं है। में।

परंतु जो राज्य सरकार को उसी मामले की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति करने से रोकता है, जब केंद्र सरकार पहले ही एक आयोग नियुक्त कर चुकी है और इसके विपरीत, यह स्पष्ट है कि यह धारा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति पर विचार नहीं कर सकती थी, इस तथ्य से अवगत होने के कारण कि ऐसा निर्माण राज्य सरकार को सूची II और III से संबंधित किसी भी मामले में केंद्रीय सरकार की शक्ति के दुरुपयोग की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने में सक्षम बनाएगा। इस तरह का निर्माण संसद की मंशा को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। एक प्रतिनिधि के रूप में उपयुक्त सरकार की शक्तियों के दायरे और इस धारा के तहत जांच आयोग की नियुक्ति के दायरे में रखे जाने वाले निर्माण पर पूरी तरह से विचार करने से पहले, अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है। धारा 3 की उप-धारा (4) उपयुक्त सरकार से अपेक्षा करती है कि वह लोक सभा या राज्य की विधान सभा के समक्ष, आयोग द्वारा की गई जांच पर आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ उस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने की अवधि के साथ रखे। उप.

इसलिए धारा (4) उपयुक्त सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाई पर विचार करती है। धारा 4 एक कॉम मिशन की शक्तियों से संबंधित है। कर्नाटक बनाम संघ (जे. कैलासम) के मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करते समय इसके पास दीवानी अदालत की शक्तियां होंगी।

157

खंड में उल्लिखित। धारा 5 आयोग को किसी भी व्यक्ति से जांच के विषय पर जानकारी देने के लिए फिर से अनुरोध करने में सक्षम बनाती है और इस तरह से आवश्यक किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और 177 के अर्थ के भीतर ऐसी जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य माना जाएगा। आयोग लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों की तलाशी ले सकता है और उन्हें जब्त कर सकता है या जहां तक वे लागू हों, उनसे अनुच्छेदों या प्रतियों को ले सकता है। आयोग को धारा 5 की उप-धारा (4) और (5) में उल्लिखित कुछ उद्देश्यों के लिए दीवानी न्यायालय माना जाता है। धारा 5 ए आयोग को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के मामले में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के मामले में राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमति से कुछ अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार देती है। आयोग किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है और उसके अटेन डांस को लागू कर सकता है और उसकी जांच कर सकता है, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रोडक्शन की आवश्यकता हो सकती है, और किसी भी कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग कर सकता है। धारा 8-बी में प्रावधान है कि यदि जांच के किसी भी स्तर पर आयोग किसी व्यक्ति के अपराध की जांच करना आवश्यक समझता है और उसकी राय है कि जांच से उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो आयोग उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा और धारा 8-सी अधिनियम की धारा 8-बी में निर्दिष्ट व्यक्तियों को कानूनी अभ्यासकर्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा और प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करती है।

अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ने पर आयोग को व्यापक शक्तियां दी जाती हैं।

गवाहों और उन व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए मजबूर करने वाली जांच, जिनके प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें प्रतिपरीक्षा का अधिकार देता है। जब आयोग द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो धारा 3 (4) उपयुक्त सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करती है।

सूची III में प्रविष्टि 45 के दायरे पर विचार करते हुए और विशेष रूप से

वस्तुतः 'पूछताछ' शब्द यह पाया गया है कि इस संदर्भ में एक संक्षिप्त अर्थ दिया जाना चाहिए और यदि इस शब्द को राज्य या संघ की सरकारी कार्रवाई की जांच के रूप में व्यापक अर्थ दिया जाता है, तो यह संविधान के सुचारू संचालन के लिए अनुकूल नहीं होगा। धारा 3 के तहत संसद

ने उपयुक्त सरकार को जनता के किसी भी निश्चित मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है।

महत्व। संघ की ओर से यह शब्द प्रस्तुत किए गए थे "। सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले में राज्य के सरकारी कार्यों के दुरुपयोग की जांच शामिल होगी और इस विवाद में कई निर्णयों का हवाला दिया गया था।

एम. वी. राजवाडे बनाम डॉ. एस. एम. हसन और अन्य (1) प्रश्न

यह प्रश्न उठा कि क्या जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त आयोग को न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। नागपुर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम इसे न्यायालय का दर्जा प्रदान नहीं करता है।

( 1 ) आई. एल. आर. (1954) नाग। 1 .

[ 1978 ] 2 एससीआर।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

158

जाँच आयोग के तहत जाँच आयोग नियुक्त किया गया अधिनियम, 1952, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति बी. के. चौधरी एकमात्र हैं।

सदस्य। आयोग को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था कि क्या

( i ) गोलीबारी उचित थी;

( ii ) अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया था; और

( iii ) गोलीबारी के बाद इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की गई थी।

शांति और व्यवस्था, परेशानी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और घायलों को पर्याप्त चिकित्सा और अन्य सहायता प्रदान करना।

जांच की प्रकृति से निपटने के लिए अदालत ने कहा कि आयोग

विचाराधीन सायन को स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था

अपने मन की जानकारी के लिए, ताकि वह कार्य न करे,

न्याय और समता के आदेशों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देते हुए। इसलिए यह एक तथ्य खोजने वाला निकाय था जिसका उद्देश्य केवल न्यायिक प्रकृति के किसी भी सुझाव को प्रस्तुत किए बिना सरकार के दिमाग को निर्देश देना था। जहाँ तक मामले में जाँच के दायरे का संबंध है, यह सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले से संबंधित जाँच के रूप में धारा 3 के भीतर सख्ती से आता है, न कि किसी मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री के सरकारी कार्यों के दुरुपयोग की जाँच। मामले के तथ्यों पर यह उचित था कि अदालत ने पाया कि यह केवल एक तथ्य खोजने वाला निकाय था जिसका उद्देश्य सरकार के दिमाग को निर्देश देना था। ब्रंजनंदन सिन्हा बनाम। ज्योति नारायण (1) सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या आयोग ने

लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के तहत नियुक्त न्यायालय, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 के अर्थ के भीतर एक न्यायालय नहीं है। न्यायालय ने नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार को मंजूरी दी कि आयोग केवल एक तथ्य खोज आयोग था जिसका उद्देश्य केवल सरकार के दिमाग को निर्देश देना था और पाया कि लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के तहत एक आयोग अदालत नहीं है। श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य (2) मामले में केंद्र सरकार ने अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में उल्लिखित कुछ कंपनियों की जांच करने और उन पर नियंत्रण और ब्याज की प्रकृति और सीमा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिसका उपयोग अधिसूचना में कुछ व्यक्तियों ने इन कंपनियों पर किया था। जांच आयोग अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम वैध और आंतरिक अधिकार था और अधिसूचना भी वैध थी, सिवाय इसके कि उसके खंड 10 में "जैसा भी हो और दंड या सजा प्राप्त करने के माध्यम से" शब्द अधिनियम के दायरे से बाहर थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह अधिनियम सरकार को किसी भी मनमाने या अनियंत्रित शक्ति से वंचित नहीं करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायालय ने आगे कहा कि जांच आयोग स्थापित करने के लिए सरकार को दिया गया विवेकाधिकार अधिनियम में निर्धारित नीति द्वारा निर्देशित है और विशिष्ट कार्रवाई केवल तभी की जानी चाहिए जब सार्वजनिक महत्व का कोई निश्चित मामला मौजूद हो जिसमें जांच आवश्यक हो। मामले के तथ्य यह हैं कि केंद्र सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया था

( 1 ) [ 1955 ] एससीआर 955 ।

( 2 ) [ 1959 ] एस. सी. आर 279

## कर्नाटक बनाम। यूनियन (कैलासम, जे.)

159

आदेश के खंड (2) से (11) में उल्लिखित अनुसूची और अन्य मामलों में निर्दिष्ट कंपनियों के मामलों के प्रशासन के संबंध में पूछताछ और रिपोर्ट करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत जांच। खंड (3) के तहत जांच ऐसी कंपनियों और फर्मों या उनमें से किसी पर श्री आर. के. डालमिया और 3 अन्य, उनके रिश्तेदारों, कर्मचारियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किए गए नियंत्रण की प्रकृति और विस्तार के बारे में है। खंड (10) के तहत जांच किसी भी अनियमितता, धोखाधड़ी या विश्वासघात आदि के खिलाफ थी और आयोग से उस कार्रवाई की सिफारिश करने की अपेक्षा की गई थी जो आयोग की राय में निवारण और व्यवस्था सुनिश्चित करने या भविष्य के मामलों में निवारक के रूप में कार्य करने के लिए की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामले में आयोग केवल जांच करने और अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए था और उन्हें लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी। यह था।

आगे यह माना गया कि सी. एल. के अंतिम भाग का एक हिस्सा। ( 10 ) जिसके बारे में सिफारिशें करने के लिए जांच आयोग का आह्वान किया गया

निवारण या सजा प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई को आयोग के उद्देश्य के लिए बिल्कुल भी आवश्यक या सहायक नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "निवारण या सजा प्राप्त करने के रूप में और उसके माध्यम से" शब्द स्पष्ट रूप से अधिनियम के दायरे से बाहर जाते हैं, और ऐसा प्रावधान संविधान में दो विधायी प्रविष्टियों द्वारा कवर नहीं किया गया था और इसलिए इसे हटा दिया जाना चाहिए। धारा 3 के दायरे पर विचार करते हुए इसने कहा कि "धारा के लिए कानून द्वारा स्वयं दिया गया उत्तर इंगित करता है कि उपयुक्त सरकार केवल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच के उद्देश्य से जांच आयोग नियुक्त कर सकती है और किसी अन्य मामले की नहीं। दूसरे शब्दों में, जांच का विषय केवल "सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला" हो सकता है। अपीलार्थी की ओर से इस तर्क का खंडन करते हुए कि उपयुक्त सरकार को प्राधिकरण का प्रत्यायोजन दिशाहीन और अनियंत्रित है, न्यायालय ने कहा कि "जांच आयोग के गठन की कार्यकारी कार्रवाई को धारा की शर्त के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात्, सार्वजनिक महत्व का एक निश्चित मामला मौजूद होना चाहिए जिसमें उचित सरकार की राय में, एक जांच आवश्यक है या उस ओर से लोक सभा या राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा आवश्यक है"। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि संसद ने पर्याप्त स्पष्टता के साथ नीति घोषित की थी और उपयुक्त सरकार को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के मार्गदर्शन के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एक

मनमानी और अनियंत्रित शक्ति उपयुक्त सरकार को सौंप दी गई थी। न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा निर्धारित नीति और अधिनियम की प्रस्तावना और धारा 3 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देश के भीतर किया गया था। फैसला

ऐसे मामले से निपट नहीं रहा था जिसमें जांच का आदेश दिया गया हो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यों का दुरुपयोग

राज्य के कार्यकारी कार्यों का प्रयोग करना। न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से इस याचिका को भी खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत व्यक्तियों के अधिनियम और आचरण को कभी भी सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले के रूप में नहीं माना जा सकता है, यह देखते हुए कि व्यक्तियों के कार्य और आचरण इतने खतरनाक अनुपात में हो सकते हैं जो पब के कल्याण को भी प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार सार्वजनिक आयात [1978] 2 एस. सी. के. का एक निश्चित मामला बन जाता है।

#### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

160

और भी। "सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले" की जांच हो सकती है

इस तरह की जांच के लिए आकस्मिक या सहायक जांच की आवश्यकता होती है

व्यक्तियों की नली। धारा 8-बी जिसे एक संशोधन द्वारा पेश किया गया था

1971 के अधिनियम 79 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि जांच के किसी भी स्तर पर

आयोग किसी के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है।

व्यक्ति या राय है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की संभावना है जांच से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने पर, आयोग देगा

उस व्यक्ति को जाँच में सुने जाने का उचित अवसर

और अपने बचाव में सबूत पेश करना। यह संशोधन लागू होगा

अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करें यदि जांच के दौरान

किसी भी व्यक्ति के आचरण की जाँच करना आवश्यक है। यह मुख्य रूप से जाँच एक मामले के संबंध में है यह सुझाव देगा कि

निश्चित सार्वजनिक महत्व। यह हो सकता है कि कुछ मामलों में आचरण

व्यक्तियों का सार्वजनिक महत्व का एक निश्चित मामला बन सकता है

आर. के. डालमिया के मामले में निर्धारित। लेकिन निर्णय समाप्त नहीं होता है

वह बिंदु जो इस मामले में उत्पन्न हुआ है, अर्थात् क्या निश्चित पदार्थ महत्व का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसमें अधिकार शामिल है सार्वजनिक

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के दुरुपयोग के लिए पूछताछ

जब ऐसा कोई इरादा उनके दिमाग में नहीं हो सकता था

संसद।

जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाम। बख्शी गुलाम मोहम्मद (')

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें संपत्ति की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। प्रथम प्रत्यर्थी और उसके कुछ निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा पूछताछ की गई

उनके कार्यकाल के दौरान परिवार। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य सरकार ने 'बख्शी' के बाद जांच आयोग का गठन किया था

गुलाम मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

राज्य।

उच्च न्यायालय के तीन में से दो न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया कि

संदर्भित मामला सार्वजनिक महत्व का नहीं था क्योंकि अधिसूचना की तारीख को बख्शी गुलाम मोहम्मद ने सरकार में कोई पद नहीं संभाला था और जिस आचरण की शिकायत की गई थी, उसके संबंध में सार्वजनिक आंदोलन का कोई सबूत नहीं था और इससे पता चलता है कि वे सार्वजनिक महत्व के मामले नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को यह कहते हुए खारिज कर दिया: यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक मंत्रिपरिषद द्वारा अपने प्रमुख, प्रधानमंत्री के कार्यों की जांच के लिए एक आयोग का गठन कैसे किया जा सकता है, जब वह कार्यालय में होते हैं। यह निश्चित रूप से एक सबसे असामान्य बात होगी। यदि बाकी मंत्रिपरिषद कोई जांच कराने का संकल्प लेती है, तो प्रधानमंत्री से उनका इस्तीफा मांगने की

उम्मीद की जा सकती है। जो भी हो, वह खुद बाहर जाता। अगर वह पहला कदम उठाते हैं तो जांच चाहने वाले मंत्रियों के लिए कोई आयोग गठित नहीं किया जाएगा

अगर वह खुद बाहर गए, तो आयोग

चला गया होगा। ऐसे व्यक्ति के कार्यों की जांच करने के लिए स्थापित किया जाएगा जो अब पद पर नहीं था और उस कारण से, यदि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश सही थे, तो उन मामलों में जो सार्वजनिक महत्व के नहीं थे। परिणाम यह होगा कि एक प्रधानमंत्री के कार्यों को अधिनियम के तहत कभी भी लागू नहीं किया जा सकता था। हमें यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है कि

( 1 ) [ 1966 ] सप. एस सी आर 401.

"

कर्नाटक वी. यूनियन (कैलासम, जे.)

161

देखें "। न्यायालय का निर्णय है कि पिछले कृत्यों की जांच

जो जनता के कल्याण को प्रभावित करते हैं, वे जनता के मामले होंगे।

महत्व और यह अप्रासंगिक था कि क्या वह व्यक्ति जिसने किया

उन कृत्यों को दोहराने में सक्षम होने के लिए वे अभी भी सत्ता में हैं। उच्चारण

के कृत्यों की जांच करने के प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है

एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नहीं रह गया था, वह सार्वजनिक महत्व का विषय बना रह सकता है।

बख्शी के मामले में राज्य सरकार ने जांच का निर्देश दिया था

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के आचरण के विरुद्ध। यह

अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के दायरे से बाहर है। यह था।

जम्मू की धारा 10 पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किया और

कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1962 ने जांच का निर्देश दिया बख्शी के आचरण  
में गुलाम मोहम्मद दायरे से बाहर थे

अधिनियम से। जम्मू और कश्मीर अधिनियम की धारा 10 जांच आयोग अधिनियम, 1952 की  
वर्तमान धारा 8-बी और 8-सी के समान है। अनुभाग में कहा गया है कि यदि जांच के किसी भी  
स्तर पर कॉम

मिशन किसी भी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है या यह राय रखता है कि  
जांच से किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, आयोग उस  
व्यक्ति को जांच में सुने जाने और उसके बचाव में सबूत पेश करने का उचित अवसर देगा। धारा के  
शब्दों के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया था कि जांच आम तौर पर केवल सार्वजनिक महत्व के  
एक निश्चित मामले में होती है और किसी व्यक्ति के आचरण में पूछताछ केवल ऐसी जांच के  
लिए आकस्मिक या सहायक के रूप में उत्पन्न हो सकती है। चूंकि यह धारा जांच आयोग की  
कार्यवाही के किसी भी चरण में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के आचरण की जांच की आवश्यकता पर  
विचार करती है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी व्यक्ति के आचरण की जांच केवल  
आकस्मिक है। इस न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 3 जो जांच  
आयोग नियुक्त करने की अनुमति देती है, किसी व्यक्ति के आचरण की जांच को शामिल करने के  
लिए पर्याप्त है और धारा 10 से निकाले गए निहितार्थ से धारा 3 के दायरे को कम करना  
अधिनियम का स्वाभाविक अध्ययन नहीं हो सकता है। यह अवलोकन, जैसा कि बाद के वाक्य से  
स्पष्ट होता है, इस याचिका को अस्वीकार करते हुए किया गया था कि धारा 10 उस व्यक्ति पर  
लागू नहीं होती है जिसका आचरण धारा 3 के तहत गठित आयोग के समक्ष सीधे जांच के लिए  
आता है। बख्शी के मामले में जब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के मामलों की जांच का आदेश दिया  
था, जो पद पर नहीं रह गए थे, तो अदालत को इस सवाल पर विचार करने के लिए नहीं कहा  
गया था कि क्या केंद्र सरकार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के आचरण की जांच के लिए एक आयोग  
नियुक्त कर सकती है जो संविधान के तहत केंद्र-राज्य संबंधों के निर्धारण का तात्पर्य है। इस  
मामले में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई थी। इस प्रश्न के  
अलावा यह देखा गया है कि यदि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 को राज्य के  
मुख्यमंत्री के कार्यालय में आचरण की जांच आयोग की नियुक्ति को सक्षम बनाने के रूप में माना  
जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार जो संसद की प्रतिनिधि है, को उन शक्तियों का  
प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा, जिन पर संसद द्वारा कभी विचार नहीं किया गया होगा,  
क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इस तरह के निर्माण का परिणाम राज्य सरकार को  
जांच आयोग (1978) 2 एस. सी. आर. नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करना होगा।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

162

सूची II के मामलों के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों के आचरण में और सूची III। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बख्शी के मामले के बाद

1966 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया, संशोधन पेश किए गए

1971 के अधिनियम 79 द्वारा जांच आयोग अधिनियम। धारा 8-बी इस प्रकार है:

" 8 बी. यदि जांच के किसी भी स्तर पर आयोग,

( क) के आचरण की जाँच करना आवश्यक समझता है

कोई भी व्यक्ति; या

( ख) यह राय है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है

सायन उस व्यक्ति को एक उचित अवसर देगा

जाँच में सुना जा रहा है और उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए

बचाव:

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा जहां

एक गवाह के श्रेय पर महाभियोग चलाया जा रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू और कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1962 की संबंधित धारा, धारा 10 थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बख्शी के मामले में विचार किया गया था, और न्यायालय ने माना था कि धारा 10 उस मामले में भी लागू होती है जिसमें किसी व्यक्ति के आचरण की सीधे जांच की जा रही थी। इसने पाया कि धारा 3 के दायरे को धारा 10 से निकाले गए निहितार्थ से कम नहीं किया जा सकता है। धारा 8-बी को लागू करके अधिनियम के बाद के संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आयोग जांच के किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है, या यह राय रखता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जांच से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, तो यह इंगित करेगा कि संसद ऐसे शब्दों के परिणामों से अवगत थी, और इसका उद्देश्य था कि अधिनियम मुख्य रूप से

सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले पर लागू हो, जबकि व्यक्तियों के मामलों की जांच की अनुमति होगी यदि यह ऐसी जांच के लिए आकस्मिक या सहायक के रूप में उत्पन्न होती है। यह निर्माण न्यायोचित प्रतीत होता है, अन्यथा धारा 3 का परिणाम प्रतिनिधि यानी केंद्र सरकार को किसी राज्य के मुख्यमंत्री के मामले की जांच का आदेश देने और राज्य सरकार से समान व्यवहार को आमंत्रित करने का अधिकार देना होगा।

पी. वी. जगन्नाथ राव और अन्य में निर्णय। वी. उड़ीसा राज्य और

ओआरएस। (1) मुख्यमंत्री और उन मंत्रियों के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति से भी संबंधित है, जिन्होंने अपने पद के कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताओं के संबंध में अधिसूचना की तारीख को पद धारण करना बंद कर दिया था और यह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा सरकारी कार्यों के दुरुपयोग की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग से संबंधित नहीं है।

यह ऊपर बताए गए मामलों की जांच पर देखा जाएगा कि

केंद्र सरकार ने कार्यालय में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की जांच का आदेश नहीं दिया था। कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने प्रताप सिंह के खिलाफ जांच का आदेश दिया था

कैरन, एक राज्य के मुख्यमंत्री, जब कार्यालय में थे, लेकिन इस तरह के आदेश की वैधता पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया गया था। संचालन की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था

जब मुख्यमंत्री ने उस पद को संभालना बंद कर दिया और राष्ट्रपति ने तमिलनाडु राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। कार्यालय में रहते हुए मुख्यमंत्री ने इस तरह के आयोग की नियुक्ति करने की केंद्र सरकार की शक्ति पर सवाल उठाया।

केंद्र सरकार द्वारा विवादित अधिसूचना चल थी

इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रावधान का उल्लंघन है। परंतु के तहत जब ए

राज्य सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है, केंद्र सरकार उसी मामले की जांच के लिए तब तक कोई अन्य आयोग नियुक्त नहीं करेगी जब तक कि राज्य द्वारा नियुक्त आयोग

सरकार तब तक काम कर रही है, जब तक कि केंद्र सरकार अफीम की न हो।

यह नहीं कि जांच का दायरा दो या दो से अधिक राज्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले में यह सामान्य आधार है कि राज्य सरकार

इससे पहले एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। का दायरा

केंद्र सरकार द्वारा आदेशित जांच दो या दो से अधिक राज्यों में नहीं होती है। इन परिस्थितियों में अधिसूचना की मांग की जाती है

केंद्र सरकार ने इस दलील का समर्थन किया कि जांच "एक ही मामले" से संबंधित नहीं है और इसलिए अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। परंतुक के साथ धारा 3 (1) को पढ़ते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम का इरादा उपयुक्त सरकार यानी केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक महत्व के किसी भी निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करने में सक्षम बनाना है। केंद्र सरकार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I, सूची II या सूची III में सूचीबद्ध प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संविधान की सूची II और सूची III में सूचीबद्ध प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है। चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास सूची II और सूची III में प्रविष्टियों से संबंधित जांच आयोग नियुक्त करने की शक्ति है, ऐसे अवसर उत्पन्न हो सकते हैं जब अतिव्यापी हो सकते हैं। इस तरह की आकस्मिकता से बचने के लिए धारा 3 (1) के पक्ष में (ए) और (बी) अधिनियम बनाते हैं कि जब केंद्रीय सरकार ने जांच आयोग नियुक्त किया है तो राज्य सरकार

जब तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है, तब तक केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उसी मामले की जांच के लिए कोई अन्य आयोग नियुक्त नहीं करेगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा है, तब तक केंद्र सरकार उसी मामले की जांच के लिए कोई अन्य आयोग नियुक्त नहीं करेगी। ये प्रावधान दोनों सरकारों द्वारा एक ही मामले की जांच के लिए दो अलग-अलग आयोगों की नियुक्ति द्वारा किसी भी संघर्ष से बचने के उद्देश्य से हैं। विधि मंत्री श्री सी. सी. बिस्वास द्वारा 6 अगस्त, 1952 को राज्यसभा में विधेयक पेश करते समय दिए गए एक भाषण में उन्होंने धारा 3 के अनुकूल दृष्टिकोण और इसके अंतर्निहित उद्देश्यों को इस प्रकार समझाया:

" फिर यह भी सवाल है कि क्या और कितनी दूर केंद्र द्वारा नियुक्त ओवरलैपिंग पूछताछ हो सकती है अपने दम पर एक आयोग और एक राज्य भी [1978] 2 एस. सी. आर. का आयोग। एक ही मामले से निपटने के लिए यह अपना है। इससे निपटा जाता है यहाँ परंतुक में। ओवरलैपिंग के खतरे से बचा जाता है यह उपबंध करते हुए कि यदि आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार पहले से ही काम कर रही है तो यह नहीं होगा राज्य सरकार के लिए खुला है, सिवाय इसके कि अनुमोदन के साथ केंद्र, जांच के लिए एक और आयोग नियुक्त करेगा

एक ही बात। इसी तरह, अगर पहले से ही एक आयोग है संबंध में कार्य करने वाली राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी ऐसे मामले के लिए जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, वह राज्य को ओवरराइड करने के लिए केंद्र सरकार के लिए खुला नहीं होना चाहिए। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आयोग जो भारतीय हैं कैटेड, अर्थात्, जब तक कि केंद्र सरकार की राय न हो कि जाँच का दायरा दो या दो से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए राज्यों। फिर निश्चित रूप से यह किया जाएगा, जाहिर है इसके साथ नहीं।

राज्य के संदर्भ में। तो, जैसा कि आप देखेंगे, सर, प्रोवी के बीच संघर्ष से बचने के लिए इस खंड में सायन बनाया गया है केंद्र और राज्य "।

यह देखा जाएगा कि संघ और राज्य के बीच संघर्ष से बचने के उद्देश्य से प्रावधानों को लागू किया गया था। धारा 3 के परंतुक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्माण से विफल हो जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति पर आपत्ति, जब राज्य के कामकाज द्वारा पहले से ही एक आयोग नियुक्त किया गया है, संघ द्वारा इस दलील पर समाप्त करने की मांग की जाती है कि विवादित अधिसूचना द्वारा उन्हीं मामलों के खिलाफ जांच का निर्देश नहीं दिया जाता है जिनके लिए राज्य ने जांच आयोग नियुक्त किया है। भारत संघ की ओर से दायर लिखित बयान में यह तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ग़्रोवर जांच आयोग को संदर्भित मामले वे हैं जो कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त हुसैन जांच आयोग के संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत नहीं आते हैं और 23 मई, 1977 की अधिसूचना के अनुलग्नक I में 11 अप्रैल, 1977 के ज्ञापन में निहित ऐसे आरोपों को सूचीबद्ध किया गया है जो हुसैन जांच आयोग के संदर्भ की शर्तों में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और अनुलग्नक II में निहित आरोपों से संबंधित उक्त आरोप निर्धारित किए गए हैं। कि ग़्रोवर जांच आयोग उक्त मामले की जांच करेगा।

आरोप-प्रत्यारोप 18 मई, 1977 की कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले को छोड़कर। यह प्रस्तुत किया गया था कि जबकि राज्य सरकार द्वारा संदर्भित मामला विभिन्न अनियमित भ्रष्टाचारों से संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित जांच मुख्यमंत्री और कर्नाटक राज्य के कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात या सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने के लिए है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति की अधिसूचना इस प्रकार है:

" जबकि आरोप जमीन पर लगाए गए हैं राज्य विधानमंडल के सदन और अन्य स्थान जो अनियमित हैं संबंध प्रतिबद्ध किए गए हैं/कुछ मामलों में अतिरिक्त भुगतान किए गए हैं अनुबंधों, भूमि अनुदान, स्थलों के आवंटन से संबंधित मामले, फर्नीचर की खरीद, खाद्यान्नों का निपटान आदि।

जबकि राज्य सरकार की राय है कि यह जाँच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है उक्त आरोपों में; अब वहाँ, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोगों की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा जांच अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 60) कर्नाटक सरकार न्यायमूर्ति श्री मीर इकबाल की नियुक्ति करती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुसैन होंगे जांच आयोग राज्य की ओर से याचिका यह है कि इसके खिलाफ जांच का निर्देश दिया गया है सदनों के पटल पर लगाए गए सभी आरोप राज्य विधानमंडल और अन्य स्थानों और इसलिए प्रभार विवादित अधिसूचना में पाए जाने वाले सभी मामलों को पहले से तय करें।

इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि आयोग को इसमें जाना है और हस्तक्षेप करना है जांच में खामियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप भी शामिल होंगे। पुर के रूप में धारा 3 (1) के दो प्रावधानों की स्थिति संघर्ष से बचने के लिए है, शब्द " प्रावधानों में एक ही मामले की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए।

और केवल वे मामले जो विषय वस्तु के लिए संदर्भित नहीं हैं राज्य द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा जांच की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा। हमें दोनों में जाने के लिए नहीं बुलाया गया था। अधिसूचनाएँ और यह निर्धारित करें कि केंद्र की अधिसूचना में कौन सी वस्तु है सरकार राज्य सरकार की अधिसूचना में शामिल नहीं है। में।

'एक ही बात' शब्दों को व्यापक अर्थ देते हुए टकराव से बचें, केंद्र सरकार का तर्क है कि उसी घटना के बारे में मुख्यमंत्री के आचरण की पृच्छताछ इसे एक अलग मामला बना देगा जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद के तहत मुकदमे की रखरखाव के बारे में विवाद 131 अब संविधान पर विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 131 इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

" इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, सु पूर्व न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को अपवर्जित करेगा, विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र

( क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच,

( ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है (क्या कानून या तथ्य) जिसका अस्तित्व या सीमा कानूनी सही निर्भर करता है:

मुद्दा यह है कि क्या विवाद में कोई सवाल शामिल है कि क्या कानून का है। या वह तथ्य जिस पर राज्य के कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, एक मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा यदि राज्य के कानूनी अधिकार का कोई उल्लंघन होता है। केंद्र सरकार की ओर से निवेदन यह है कि जो प्रभावित होता है वह राज्य का कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि

राज्य सरकार या संबंधित मंत्रालय का कानूनी अधिकार है। मंत्रियों के पास कार्रवाई का कारण हो सकता है जिस स्थिति में उपाय होगा। अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से।

सरकार व्यथित महसूस करती है कि वे अनुच्छेद 226 के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि राज्य का कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होता है। 131 नहीं हो सकता। सामान्य खंड अधिनियम और राज्य और राज्य सरकार के बीच संविधान में बनाए गए अंतर पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य स्वयं एक आदर्श व्यक्ति है जो अमूर्त, अदृश्य और अपरिवर्तनीय है और सरकार इसकी प्रतिनिधि है। पक्षकारों की दलीलों को समझने के लिए संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि इस सवाल को रोका जा सके कि क्या राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। संविधान का भाग VI राज्यों और अनुच्छेद से संबंधित है। 154 यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। अनुच्छेद 162 में प्रावधान है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों की सहायता और सलाह से राज्यपाल द्वारा राज्य की कार्यकारी शक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा। विवादित अधिसूचना के अनुसार, जांच आयोग की नियुक्ति सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री और कर्नाटक राज्य के कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात या सरकारी शक्ति के दुरुपयोग के आरोप शामिल हैं। इसलिए यह जांच अन्य बातों के अलावा मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के खिलाफ सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में है। राज्य का कार्यकारी कार्य जो राज्यपाल में निहित है, वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है। राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

राज्य के सरकारी कार्य राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुसार मंत्रियों की सहायता और सलाह से किए जाते हैं। जांच के दायरे में अनिवार्य रूप से राज्य की कार्यपालिका का कार्य शामिल होगा। राज्य सरकार की दलील है कि इसकी शक्तियां संविधान और इसके अस्तित्व से प्राप्त होती हैं और राज्य की कार्यपालिका के रूप में इसकी शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा गारंटीकृत है, और केंद्र निष्पादन कार्यों के इस तरह के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रश्न में राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा और केंद्र द्वारा उस शक्ति में कोई भी हस्तक्षेप शामिल है। सरकार राज्य के कानूनी अधिकार को प्रभावित करेगी। केंद्र सरकार की ओर से याचिका वह कला है। 154 राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुरूप अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने पर विचार करता है। निवेदन यह है कि जब मंत्रियों के

माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जो प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार अधिकारी होते हैं, तो ऐसे मंत्रियों या अधिकारियों के अधिकारों में केवल हस्तक्षेप किया जाता है, न कि राज्य के कानूनी अधिकारों में। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य किसी राज्य की सरकार से अलग है और यदि राज्य या राज्य के मंत्रियों की किसी भी कार्यवाही पर सवाल उठाया जाता है तो राज्य को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। जब राज्य के कार्यकारी कार्यों का प्रयोग। इसके अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य का कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी राजस्थान राज्य और अन्य में उच्चतम न्यायालय का निर्णय v. भारत संघ। ( 1) राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने कला के तहत मुकदमा दायर किया। 131 18 अप्रैल, 1977 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जारी एक पत्र में असंवैधानिक, अवैध और संविधान के अधिकार से बाहर के रूप में जारी किए गए निर्देश को चुनौती देते हुए और इस घोषणा के लिए कि विवादित राज्य उक्त पत्र में निहित निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक या कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। राज्य विधानसभाओं को भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति पर सवाल उठाए गए। रखरखाव पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी

इस आधार पर मुकदमा कि राज्य के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था और यह कि राज्य राज्य सरकार से अलग है और यदि बिल्कुल भी जो कोई भी व्यथित था, वह राज्य सरकार थी, न कि राज्य। मुख्य न्यायाधीश बेग ने कहा कि भले ही इसके लिए कुछ आधार हों किसी राज्य के हितों और अधिकारों के बीच अंतर करना उसकी सरकार या उसके सदस्यों, न्यायालय को बहुत अधिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है मुकदमा करने के राज्य के अधिकारों के बारे में अति-तकनीकी दृष्टिकोण किसी के लिए भी अधिकार, वास्तविक या काल्पनिक, जिन्हें राज्य सरकार लेने का विकल्प चुनती है कला के तहत एक मुकदमे में संबंधित राज्य की ओर से। 131. श्री. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का विचार था कि जब राज्य सवाल करते हैं राज्य को भंग करने का केंद्र सरकार का संवैधानिक अधिकार गृह मंत्री के पत्र में उल्लिखित आधारों पर सभाएँ मुख्यमंत्रियों के लिए एक कानूनी मुद्दा, राजनीतिक नहीं, जिससे उत्पन्न होता है कानूनी अधिकार का अस्तित्व और विस्तार स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है और मुकदमे कर सकते हैं कला के दायरे से बाहर होने के रूप में बाहर नहीं फेंका जाएगा। 131. द.

विद्वान न्यायाधीश ने अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया:

" संघ सरकार की शक्ति से स्वतंत्रता के अर्थ में राज्यों के कानूनी अधिकार में उनकी प्रतिरक्षा शामिल है। वे कला के तहत हकदार हैं। 131 , उस अधिकार का दावा करने के लिए या तो पूर्ण

रूप से यह तर्क देते हुए कि केंद्र के पास विधानसभाओं को भंग करने की कोई शक्ति नहीं है या इस योग्यता के साथ कि ऐसी शक्ति का प्रयोग आधार पर नहीं किया जा सकता है।

भगवती और गुप्ता जे. जे. उनका विचार था कि मामले में शक्ति का प्रयोग राज्य के इस बात पर जोर देने के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करेगा कि संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक ढांचे के संघीय आधार का अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक, हमले से उल्लंघन नहीं होगा। 356 (1)। चूंकि मुकदमे में संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले राज्य के कानूनी अधिकार को लागू करने की मांग की गई थी, इसलिए मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सका।

कला के दायरे और दायरे से बाहर होने के रूप में सीमित। 131. गोस्वामी और जे. जे. उन्तवालिया। उनका विचार था कि कानूनी अधिकार राज्य का होना चाहिए। जब गृह मंत्री मुख्यमंत्री से पूछते हैं

राज्यों की सरकार राज्यपालों को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह दे और मुख्यमंत्री इस सलाह को स्वीकार करने से इनकार कर दें कि यह एक ओर राज्य के बीच विवाद नहीं है और दूसरी ओर

दूसरी ओर भारत सरकार। यह एक वास्तविक विवाद है जिसके बीच राज्य सरकार और भारत सरकार। इसमें कोई शक नहीं राज्य सरकार के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल लेकिन अभी तक नहीं कानूनी इकाई के रूप में राज्य, विधानसभा के विघटन के बाद भी राज्य में कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार बनी रहेगी। संविधान में कहा गया है। फजल अली, जे. का विचार था कि केवल यह तथ्य कि राज्य सरकार को पत्र भेजे गए थे अनावश्यक सलाह से कोई विवाद पैदा नहीं होगा यदि कोई मौजूद नहीं था

न ही इस तरह के आचरण से राज्य सरकार को नुकसान होगा कला के तहत निर्धारण के लिए कॉल करने के कानूनी अधिकार के साथ। 131 के रूप में राज्य के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। राज्य सरकार जिनके पास है उठाए गए विवाद कला में दिखाई देने वाले 'राज्य' शब्द के दायरे में नहीं आते हैं। और इसलिए सूट उस जमीन पर भी बनाए रखने योग्य नहीं थे।

यह देखा जाएगा कि सात में से चार न्यायाधीशों का विचार था कि सूट भगवती और गुप्ता जे. जे. के बावजूद बनाए रखने योग्य हैं। देखने में आया था कि राज्य और राज्य सरकार के बीच अंतर है। विघटन के संबंध में जो भी सवाल उठा हो संघ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य का गठन शासन और राज्य के कानूनी अधिकार प्रभावित होते हैं। प्रारंभिक ओब इसलिए जेक्शन विफल हो जाता है। के विकास के इतिहास को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में

भारतीय संविधान और इसकी योजना विवादित अधिसूचना आई. एम. राज्य को अपने सीमित क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। फर। अन्यथा, आक्षेपित अधिसूचना को

प्रदत्त शक्तियों से परे है अधिनियम, 1952। इस दृष्टिकोण से सवाल यह है कि क्या कॉम की धारा 3 मिशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 पार्लिया की शक्तियों से परे है।

मन हो या न हो। यह आवश्यक है कि जांच आयोग की नियुक्ति की जाए। संघ और राज्य की शुद्धता बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का आदेश प्रशासन। लेकिन इस तरह का जांच आयोग सख्ती से होना चाहिए। संविधान के अनुसार और केंद्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए राज्य संबंध। प्रस्ताव अब संसद के समक्ष लंबित है

इस तरह की पूछताछ करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति अधिकार में एक कदम है निर्देश, यदि पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है लोक पाल की संस्था।

निर्णय को ध्यान में रखते हुए पहला मुद्दा यह है कि क्या मुकदमा मुख्य है टैनेबल का जवाब हां में दिया जाता है। मुद्दा संख्या 2 के तहत प्रस्तावित अधिसूचना जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 द्वारा उसे प्रदान की गई केंद्रीय सरकार की शक्तियों से परे है। इस दृष्टिकोण से मुद्दा संख्या 3 विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है। मुकदमे का फैसला प्रार्थना के अनुसार किया जाना चाहिए।

आदेश

बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार, मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

लागतों के साथ।

पीबीआर.